an>

Title: Discussion on the General Budget 2015-16 and demands for grants of Ministry of Environment, Forests and Climate change (motion adopted).

(ii)Ministry of Environment, Forests and Climate Change

HON. SPEAKER: The House will now take up discussion and voting on Demand No. 32 relating to the Ministry of Ministry of Environment, Forests and Climate Change.

Motion Moved:

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2016, in respect of the head of Demand entered in the Second column thereof against Demand No. 32 relating to the Ministry of Environment, Forests and Climate Change."

Demands for Grants (2015-16) in respect of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change submitted to the vote of Lok Sabha.

No. of Demand	Name of Demand	Amount of Demand for Grant submitted to the vote of Lok Sabha	
		Revenue (Rs.)	**Capital (Rs.)**
32	Ministry of Environment, Forest and Climate Change	314,80,00,000	8,13,00,000

HON. SPEAKER: Hon. Members present in the House whose cut motions to the Demand for Grant in respect of the Ministry of Ministry of Environment, Forests and Climate Change for the year 2015-2016 have been circulated may, if they desire to move their cut motions, send slips to the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the cut motions they would like to move. Only those cut motions, slips in respect of which are received at the Table within the stipulated time, will be treated as moved.

A list showing the serial numbers of cut motions treated as moved will be put up on the Notice Board shortly thereafter. In case members find any discrepancy in the list, they may kindly bring it to the notice of the Officer at the Table immediately.

Now, Shri Ninong Ering.

श्री निनोंग इरिंग (अरुणाचल पूर्व) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

14.39 hrs (Hon. Deputy Speaker *in the Chair*)

उपाध्यक्ष जी, आज वन और पर्यावरण मंत्रालय के विÂाय में हमारी पार्टी की ओर से बोलने के लिए समय देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हमारी पार्टी की लीडर, अध्यक्षा मैडम सोनिया गांधी जी और संसदीय दल के नेता श्री खड़गे जी का मैं बहुत ही आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस विÂाय पर बोलने का एक मौका दिया। मैं अरुणाचल प्रदेश से चुन कर आया हूं, वहां लगभग 83 प्रतिशत वन क्षेत्र है। जब हम दिल्ली या अन्य राज्यों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहां जिस प्रकार से प्रदूÂाण बढ़ रहा है, वनों का सर्वनाश हो रहा है, हमें दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमें उस पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। हमारे वित मंत्री अरुण जेटली जी ने बजट पेश करते समय कम से कम 26 बार इन्वेस्टमेन्ट के बारे में बोला है और 22 बार ग्रोथ के बारे में बोला है। हम भी चाहते हैं कि देश में विकास होना चाहिए और हम विकास की बातें बहुत करते हैं, लेकिन क्लाइमेट चेन्ज को लेकर सारी दुनिया चिंतित है, उन्होंने एक भी शब्द क्लाइमेट चेन्ज, एनवायरनमेन्ट या डिग्रेडेशन के बारे में नहीं कहा है। शायद, इस पर भी बहुत बहस होगी। मेरे बाद शायद बी.जे.पी. के सदस्य इस विÂाय पर बोलेंगे, वे हमारी स्वामियों के बारे में बोलेंगे। बहुत ही वरिÂाठ नेता जावेडेकर साहब, हमारे वन मंत्री हैं। हमारे एनवायरनमेन्टलिस्ट्स और वह भी इसकी बहुत चिंता करते हैं। इसमें रियासत वाली बात नहीं है, लेकिन सात महीने में आंकड़े के हिसाब से उन्होंने 650 प्रोडक्ट्स एक साथ अपूल कर दिये हैं। आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि इससे हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हम इसके लिए बहुत ही चिन्तित हैं। वÂाऩ 2013-14 का जो बजट था, उसमें हमारी एक उपलब्धि थी कि आंकड़े में 5.65 परसेन्ट की बढ़ोतरी हुयी थी लेकिन वÂाऩ 2014-15 में उसमें 15 प्रतिशत की कटौती हुयी है और वÂाऩ 2015-16 का जो बजट है, उसमें कम से कम 23.8 प्रतिशत की कटौती हुयी है जिससे हमें यह पता चलता है कि इसको हम गंभीरता से नहीं देख रहे हैं। हमारा और हमारी स्टैंडिंग कमेटी की यह निवेदन है कि पूरे वर्ल्ड में इस पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है लेकिन हम इसकी उपेक्षा कर रहे हैं जिससे एक गलत मैसेज जायेगा।

मैं आपके माध्यम से वित मंत्री जी से विनती करता हूं कि विकास का कार्यक्रम होना चाहिए लेकिन हमारे वन और पर्यावरण विभाग में जो कटौती हुयी है, वह उसको पूरा करने का प्रयास करें। जिस प्रकार से उन्होंने प्रपोजल दिया है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। प्लान आउटले में 4,440.20 करोड़ रुपये की मांग थी और आपने असल में क्या दिया, उसके लिए आपने 1,406 करोड़ रुपये का प्रोविजन रखा है। आप इसमे देख सकते हैं कि इसमें 2,993 करोड़ रुपये की कमी है। आप इसको कैसे मेक-अप करेंगे? आदरणीय मंत्री जी को इसके बारे में बहुत सोचना पड़ेगा। वित मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया था कि आर्थिक स्थिति को देखना पड़ता है, किस मंत्रालय को विशेÂाता दी जानी चाहिए, यह देखना पड़ता है। बजटरी एलोकेशन्स में अन्य विभागों में जो हो रहा है, वन विभाग को भी प्रॉयरिटी देनी पड़ेगी। डीग्रेडेशन है, आपने मेजर फैक्टर सिर्फ एग्रीकल्चर में दिया है। इससे किसान, जनजातीय लोग प्रभावित होते हैं। अगर हम ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज पर ध्यान नहीं देंगे तो शायद पूरे देश का नुकसान होगा।

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि हमारी पार्टी से दो और माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं। चौदहवीं फाइनैंस कमीशन की रिकमेंडेशन में कहा गया है कि राज्यों का ज्यादा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए और एलोकेशन स्पैशियली 25 प्रतिशत के एमाउंट को देखते हुए 1098 करोड़ रुपये यानी आठ राज्यों - गुजरात, गोवा, महाराÂट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ओड़िसा और जम्मू कश्मीर में किया है। जब आप कहते हैं कि राज्यों का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए तो नार्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम आदि कहां से कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे क्योंकि it is not a revenue earning State. अगर ऐसा प्रावधान रखेंगे तो हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में वहां का कारोबार बंद करवा दिया। वहां के टिम्बर के ऑपरेशन को बंद करवा दिया। हमारा रिवैन्यू अर्निंग सोर्स वही है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में 83 प्रतिशत एरिया में वन हैं। देश के 23 प्रतिशत वन नार्थ ईस्ट में हैं, 60 प्रतिशत फॉरैस्ट कवरेज में है और अरुणाचल प्रदेश में 83 प्रतिशत का कवरेज है। हम वहां के जनजातीय लोगों, दूरदराज के लोगों के विकास या प्रगति की बात किस प्रकार करेंगे।

जब कोयले की बात आती है तो गृह मंत्रालय से रुकावट आ गई, पर्यावरण विभाग से भी आ गई। हमारे स्टेट को आमदनी कहां से होगी। यहां तक भी बोल रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 9 टन की एक गाड़ी जा सकती है, उससे ऊपर लाद नहीं सकते। ये सब बातें सोचने वाली हैं। नार्थ ईस्टर्न इंडस्ट्रियल पॉलिसी में आपने रुकावट डाल दी। जब आप टूरिज़्म की बात करते हैं,...(व्यवधान) यहां वन मंत्री जी बैठे हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश में 1,100 करोड़ रुपये का कैम्पा का प्रोविजन है जिसमें 10 प्रतिशत की बात की जाती है। हमें 110 करोड़ रुपये मिलने चाहिए। वह पूरा नहीं हो रहा है। आप कैसे बोलते हैं कि अरुणाचल प्रदेश या उत्तर पूर्वी राज्यों पर ध्यान देना चाहते हैं। आज गृह मंत्री जी ने कहा कि हम नार्थ ईस्ट के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप अफस्पा जैसी चीज लागू करेंगे, इको टूरिज़्म को बंद करेंगे तो किस प्रकार वहां के लोगों के विकास के बारे में सोचेंगे। मेरी गुजारिश है कि आप अरुणाचल प्रदेश पर ध्यान दीजिए, खास तौर पर कैम्पा के विÂाय में निवेदन करूंगा कि उच्चतम न्यायालय का उसमें कंट्रोल क्यों होता है। अगर कंट्रोल है तो क्या इंटरस्ट को दूसरे काम में नहीं लगाते। मैं अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूंगा। दुनिया भारत को देख रही है। इस बार दिसम्बर में पैरिस में जो समिट होगी, उसमें विश्व के सब देश भारत को देखेंगे। हमें एक ऐसा उदाहरण दिखाना होगा कि भारत एक ऐसा देश है जो पर्यावरण की देख-रेख कर सकता है। 1.62 टन कार्बन डाइऑक्साइड भारत में उत्सर्जन होता है जबकि चीन में यह 6 टन है और अमेरिका में 18 टन उत्सर्जन होता है। अगर हम अमेरिका का मॉडल अपनाते हैं तो हमें 7 पृथ्वी की जरूरत होगी। आपने समय दिया, धन्यवाद।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, the time at our disposal is very short as at 6 o' clock, we are going to have guillotine. I would, therefore, request the hon. Members to be very brief in making their speeches. Those Members, who are interested to lay their written speeches on the Table of the House, are allowed to do so.

Now, Shri Bhagat Singh Koshyari. Please conclude your speech within 10 minutes.

SHRI BHAGAT SINGH KOSHYARI (NAINITAL-U.S.N.): Sir, whenever I stand up to speak, you always say: 'finish your speech within 10 minutes or two minutes or three minutes.'...(*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: We have to complete it early.

SHRI BHAGAT SINGH KOSHYARI : Let me see. It is about environment.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Why is he saying so is that the Home Minister has taken everybody to home. Nobody is there. That is why he is saying to conclude within 10 minutes.

SHRI BHAGAT SINGH KOSHYARI: But you are not in jungle; you are also in home, Kharge Saheb!...(*Interruptions*)

CUT MOTIONS

श्री भगत सिंह कोश्यारी (नैनीताल - उधम सिंह नगर): आदरणीय उपाध्यक्ष जी, पर्यावरण और वन आज चिंता का विÂाय हो गया है। अगर इस पर कम समय मिलेगा तो यह पर्यावरण के साथ अन्याय होगा। मैं वन और पर्यावरण पर अपने विचार व्यक्त करते हुए मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। मैं आदरणीय वन और पर्यावरण मंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं कि लीमा में जिस तरह से उन्होंने भारत का पक्ष रखा, वह निश्चित रूप से सराहनीय है और उसकी जितनी सराहना की जाए कम है। मैं आशा करता हूं कि आगामी पेरिस सम्मेलन में भी वह भारत का पक्ष सबलता से रखेंगे। मैं कल हिन्दु में पढ़ रहा था, गार्डियन के संपादक का इतना बड़ा इंटरव्यू आया है जिसमें कहा गया है फॉसिल फ्यूल का उपयोग को कम करने की बात कही गई है, आखिर फॉसिल फ्यूल के उपयोग कम क्यों होना चाहिए, हमें कोई भी इंडस्ट्री क्यों नहीं लगानी चाहिए।

अरूणाचल प्रदेश के माननीय सदस्य बोल रहे थे कि चीन में 9.8864 मिलियन टन, अमेरिका में 5.1944 मिलियन टन और भारत में 1.9674 मिलियन टन का पूÂाण इमिशन होता है। भारत में पर-कैपिटा इमिशन एक परसेंट या डेढ़ परसेंट ही है। पिछले बीस और तीस सालों से मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे संगठन तथा तथाकथित इन्टलेक्चुअल इतना अधिक छाप देते हैं जिससे लगता है कि भारत में पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, इमिशन ज्यादा हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन ज्यादा हो रहा है। मंत्री जी इसे देखें। कहीं साजिश के तहत हिन्दुस्तान के बारे में ऐसा कहा जा रहा है।

हमारे यहां जब ग्रीन हाउसेज का एमिशन पर कैपिटा इतना कम है, तो मैं सोचता हूं कि इस बारे में हमें निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। हमारे देश में विकास न हो, ऐसा नहीं चल सकता। मैंने पिछले कई वÂाों से देखा है कि जो भी पर्यावरण मंत्री बनता है, वह केवल पर्यावरण के बारे में ही सोचता है। आपने कम समय दिया, लेकिन फिर भी मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। प्रजापति ब्रह्मा जी की दो लड़कियां थीं। एक लड़की कुम्हार को ब्याही गयी और दूसरी लड़की माली को ब्याही गयी। जब दोनों से वरदान मांगने के लिए कहा गया, तो माली वाली लड़की ने कहा कि मुझे हमेशा बरसात दीजिए और कुम्हार वाली लड़की ने कहा कि मुझे हमेशा धूप चाहिए। अब ये दो प्रकार के जो एक्स्ट्रीम हैं, भारत में भी लगभग ऐसे ही एक्स्ट्रीम चल रहे हैं। यहां अतिवाद चल रहा है, यानी इतना अतिवाद चल रहा है कि मैं उसका गवाह हूं। मेरे यहां पहले उत्तराखंड में सरकार द्वारा पेड़ों का बहुत नुकसान किया गया। उसके खिलाफ जो चिपको आंदोलन चला, उस आंदोलन ने दुनिया में एक नयी जागृति पैदा की। उस वन एक्स्ट्रीम से हम दूसरे एक्स्ट्रीम में चले गये। हमने कहा कि सड़क भी नहीं बननी चाहिए, पानी भी नहीं आना चाहिए, बिजली भी नहीं आनी चाहिए। मैं सोचता हूं कि एक एक्स्ट्रीम से दूसरी एक्स्ट्रीम में आना उचित नहीं है। मेरा ख्याल है कि अगर हमें पर्यावरण बचाना है, तो यह पर्यावरण किसके लिए है? एक बात बहुत ध्यान देने वाली है कि यह पर्यावरण किसके लिए है? यहां पर मेनका गांधी जी नहीं हैं। उन्होंने हमारे यहां जो बहुत सी पशु बलि होती थी, उसे बंद किया है। उनका पशु प्रेम बहुत है। बहुत से लोग पशु प्रेमी हैं। यहां भी कुछ पशु प्रेमी होंगे, जिनमें से कुछ खाने के लिए होंगे और कुछ बचाने के लिए होंगे। ऐसे बहुत से पशु प्रेमी हैं। मैं देखता हूं कि आज क्या स्थिति है? आप ताज्जुब करेंगे कि एक एक्स्ट्रीम से दूसरी एक्स्ट्रीम कितनी होती है।

मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अरुणाचल में वह समस्या नहीं है जो हमारे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में है। इन दोनों प्रदेशों में केवल 33 प्रतिशत क्षेत्र में ही खेती होती है, जबकि 67 प्रतिशत क्षेत्र शुद्ध जंगल है। वहां बंदर और सुअरों का राज हो गया है, जिसके कारण वहां कोई भी आदमी खेती नहीं कर सकता। इस कारण उत्तराखंड और हिमाचल के लोग मैदानी क्षेत्रों में आ रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं, एवसोडस हो रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहीं न कहीं संतुलन होना चाहिए। इसके लिए तुरंत कोई उपाय करना चाहिए। अगर सारे लोग भागकर आ जायेंगे, तो पता लगेगा कि ऊपर

से, चीन से वहां लोग आ रहे हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि आप उन्हें मार दीजिए, लेकिन हमारा वन विभाग, हमारे पर्यावरणविद् जब पर्यावरण की बात करते हैं तो मनुÂय की बात करनी चाहिए। जब कभी-कभी हमारे जंगल के अधिकारी बैठते हैं तो मैं उनसे इस बारे में कहता हूं। बंगाल के सब साथी चले गये हैं। एक बार बंगाल से विद्यापति जी गये थे। वे कहते थे कि 'सबार ऊपर मानुस भाई, तहार ऊपर किछु नाहीं।' सबसे ऊपर मनुÂय है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। जंगल भी है, तो मनुÂय के लिए है, पशु भी है, तो मनुÂय के लिए है और जमीन भी है, तो वह भी मनुÂय के लिए है, क्योंकि मनुÂय ही सबकी रक्षा कर सकता है। प्रकृति की रक्षा भी मनुÂय ही कर सकता है। इस प्रकार से हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे आगे सब ठीक रहे।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि हमें जहां संतुलन चाहिए, बैलेंस चाहिए, वहां हमें समन्वय भी चाहिए, कोआपरेशन चाहिए। मैं बहुत बार देखता हूं कि डिपार्टमैंट्स में कोआपरेशन न होने से विकास के सारे कार्य लंबे समय तक रुके रहते हैं। जब से माननीय जावेडकर जी मंत्री बने हैं, हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी आये हैं, तब से काफी छूट दी गयी है। लेकिन मेरा फिर भी कहना है कि जल्दी से जल्दी सारे मामलों का निपटारा होना चाहिए, ताकि विकास की गति रुकने न पाये। अभी वहां के सदस्य बॉर्डर की बात कर रहे थे, तो बॉर्डर के बारे में मंत्री जी ने कहा कि रक्षा के लिए सौ किलोमीटर तक की जरूरत नहीं होगी। मैं सोचता हूं कि आपका यह बहुत प्रशंसनीय कदम है। आप चाहें तो इसे सौ की जगह डेढ़ सौ किलोमीटर कर

लीजिए, तब भी अच्छा रहेगा। यदि हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी, तो हमारे ऊपर जो ड्रैगन बैठा है, उसकी हम सब कल्पना कर सकते हैं। इसलिए उस संबंध में सावधानी रहनी चाहिए।

मैं माननीय मंत्री जी से यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे यहां जो प्राइवेट वन हैं, वन पंचायत हैं, शायद वह ग्रामीण लोगों की वन पंचायत हैं। यहां पर वन अधिकारी बैठे हुए हैं, वे समझ सकते हैं कि मेरे प्रदेश में वन पंचायत, जो जनता द्वारा रक्षित होते हैं, जनता लगाती है, जनता द्वारा उन्हें हक मिलते हैं, वे रिजर्व फॉरेस्ट से कहीं अधिक अच्छी स्थिति में हैं, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि हमारा वन है, हम इसमें से अधिकार प्राप्त करेंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश हो, उसे संशोधित करते हुए आप प्राइवेट वनों को प्रमोट कीजिए। प्राइवेट वनों में आप लोगों को अधिकार दीजिए, ताकि वे उन वनों की लकड़ी ला सकें।

15.00 hrs

वहां से घास ला सकें, पत्तियां ला सकें। इस प्रकार का प्रबंध करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सहभागिता, कोआपरेशन होना चाहिए। जनता की सहभागिता अधिकतम कैसे हो, इस पर विचार करना चाहिए।

मैं आपसे एक और विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। वास्तव में ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता है। आज ओज़ोन में कार्बन डाइ ऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई है। उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल जैसे हिमालय प्रदेश ऑक्सीजन की सुरक्षा कर रहे हैं, देश को ऑक्सीजन दे रहे हैं। इन राज्यों को कार्बन क्रेडिट कैसे दिया जाए, यह देखा जाए क्योंकि यहां कार्बन कम पैदा होता है। इन राज्यों को कार्बन क्रेडिट, ग्रीन बोनस दिया जाना चाहिए ताकि यहां के लोग जंगलों और पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें, नदियों को साफ रख सकें। मेरा निवेदन है कि आपको इन सब के बारे में विचार करना चाहिए।

महामहिम राÂट्रपति जी ने 2014 के अभिभाÂाण में हिमालय मिशन की बात कही थी। उत्तराखंड में इंस्टीट्यूट खोलने की बात कही थी। मैं पिछले बजट में देख रहा था कि हिमालय मिशन के लिए मात्र दस करोड़ रुपया अलॉट किया गया था लेकिन उसका भी उपयोग नहीं हुआ है। हिमालय मिशन की अभी तक कोई रूपरेखा भी नहीं रखी गई है। इस बार बजट में 100 करोड़ का इंतजाम है लेकिन इसका उपयोग कैसे होगा? आप हिमालय को कैसे बचाएंगे? अभी काठमांडू, नेपाल, केदारनाथ में क्या हुआ है? अभी मुझे कोई कह रहा था कि केदारनाथ में कुछ लोग जाते हैं तो भूकम्प आ जाता है। वे मजाक कर रहे थे, लेकिन यह मजाक की बात नहीं है। हिमालय की स्थिति के बारे में सोचना बहुत आवश्यक है।

मेरा निवेदन है कि हिमालय की परिस्थितियों को देखते हुए हिमालय इंस्टीट्यूट की स्थापना करनी चाहिए।

आई.सी.मोड एक संस्था है, मैं देख रहा था कि विदेशों की इस प्रकार की संस्थाओं को आपने क्या क्या प्रकार की सहायता दी है। आई.सी.मोड की संस्था आपने कम कर दी है। मैं आई. सी.मोड की हिस्ट्री को जानता हूं। ऐसी जो भी संस्थाएं हों, जो हमारे पर्यावरण के लिए काम कर रही हैं, उनके लिए मैं सोचता हूं कि हमें इन सब चीजों में सहयोग करना चाहिए।

पिछले कुछ वÂाोंा में जहां देश में लगातार फॉरेस्ट का क्षेत्र हमारा कम हो रहा है। उत्तराखंड और हिमाचल के अंदर इसका क्षेत्र बढ़ा है। ये आपके आंकड़े बताते हैं। ऐसे क्षेत्रों को क्योंकि आज हिमाचल और अरुणाचल, उनका 80 प्रतिशत से ज्यादा अरुणाचल में है। हमारे यहां 60 प्रतिशत से ज्यादा है। सारे देश में केवल 24 प्रतिशत है।

इसलिए कहीं न कहीं इसका भी उपयोग होना चाहिए। इसके साथ ही साथ मेरा निवेदन है कि कैम्पा के अंदर जो एनपीवी है, उसका बहुत सारा पैसा है। मैंने जयराम रमेश जी से भी निवेदन किया था कि इस कैम्पा का उपयोग राज्यों में करना चाहिए। वहां वृक्षारोपण में, नदियों की सफाई में या जो भी कारण हो, जिस कारण से भी हमारा पर्यावरण बढ़ सकता है, उसमें उस कैम्पा का उपयोग होना चाहिए और जिस राज्य का पैसा है, उस राज्य को पैसा देकर तथा न केवल पैसा ही देकर बल्कि उस पैसे की मोनीटरिंग भी होनी चाहिए कि उस पैसे का सदुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है ताकि आगे दिया जाए या कितना दिया जाए क्योंकि अगर वहां पैसा देंगे तो हिमालय राज्यों में जो गरीबी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, उसका भी हल हो सकेगा।

अंत में, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब आप वन की बात करें या पर्यावरण की बात करें तो कम से कम हम एक बार अपने भारत की ओर देखें। जिस भारत ने कहा था: "विÂणुपति नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे" अर्थात् हे मां भगवती, हे मां पृथ्वी, तू मुझे क्षमा कर। मैं तेरे ऊपर पैर रख रहा हूं। यह जो हमारे यहां तुलसी जी की और पीपल के पेड़ की पूजा जो हमारे प्राचीन लोग करते थे, आखिर क्या कारण था कि उस संस्कृति ने आज तक पर्वत बचाये रखे, हमारी नदियां बचाए रखीं और हमारे पेड़ और जंगल बचाये रखे अन्यथा क्या कारण है कि आज जो सभ्यता और संस्कृति आ गई है, जो सभ्यता हम लोग पश्चिम से ला रहे हैं, उस भोगवादी सभ्यता के कारण हम लोग ये सारी चीजें खोते जा रहे हैं। मेरा विश्वास है कि अगर हम फिर से उन चीजों में जाएंगे यानी यदि हम प्राचीन संस्कृति जिसमें हमारे पेड़-पौधों की भी देवताओं के रूप में पूजा की जाती है, गंगा, नर्मदा को भी मां के रूप में माना गया है, यदि हम उसी अपनी प्राचीन सभ्यता में जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा उद्देश्य सफल होगा। धन्यवाद।

□**SHRI SHIVKUMAR UDASI (HAVERI):** I thank you for giving me an opportunity to express my views on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for 2015-16. Now we are at a stage when we need to seriously ponder over the imperatives of sustainable development in the context of economic growth and intergenerational equities. Environment concerns cannot be construed as being at cross purposes with development. Genuine environmental concerns cannot be ignored. After all improving the quality of life of our people is at the heart of sustainable and equitable development.

The total central sector outlay for the Eleventh Plan is Rs. 10,96,860 crore (constant price) of which Rs. 8,841 crore and Rs. 10,000 crore (constant and current price respectively) is allocated for the environment, forest and wildlife sectors. The current allocation for the environment and forest sector is 0.70 per cent (0.91 per cent) of the total central sector outlay and in the states it varies between 0.021 per cent and 1.78 per cent of the state outlay for environment and 1.25 per cent for forestry and wildlife. An allocation of at least 5 per cent of the annual, state, and central sector outlay for the environment and forestry sectors separately needs to be ensured, preferably by the Twelfth Five Year Plan.

E-waste is the most toxic of all waste material and serious health and environment hazards are associated with it. It is increasing at an alarming rate and as such its management and handling has become a major challenge for us. Based on a survey carried out by Central Pollution Control Board, about 1,46,800 tonnes of e-waste was generated in the country in the year 2005 and it was estimated that the quantity of e-waste will increase to 8,00,000 tonnes by 2012. A yawning gap exists between the e-waste generated in India and its capacity to deal with it. Extended Producer's Responsibility (EPR) is the main feature of E-waste (Management & Handling) Rules, 2011, notified by the Ministry, according to which the producer is responsible for its product once the consumer discards them. But so far, 123 producers in 11 states and 111 collection centres in 15 states have been granted authorization. There are 126 registered e-waste recyclers/dismantlers in 12 states. Failure to recycle e-waste is also leading to shortage of rare earth minerals to make future generations of electronic equipment.

In view of e-waste management being a huge global problem (50 million tonnes of e-waste was generated worldwide or 7 kg for every person on the planet), there are numerous reports indicating that e-waste is being shipped to developing countries in Asia, Africa and Latin America from developed countries in the garb of import of "used goods" to pass on the hazards associated with e-waste and to avoid costs associated with legitimate recycling. Government should think of creation of necessary legislative and enforcement mechanism to prevent our country from becoming one of the dumping grounds of e-waste for developed nations.

The issue of illegal sand mining is a matter of serious concern because it is rampant across the country. The Standing Committee recommends that the Ministry should assess the quantum and forms of illegal sand mining so that the enormity of the problem can be assessed and remedial measures suggested. Thereafter, the action plan to curb it may be evolved.

E-radiation from cell towers is yet another issue on which depsite the fact that it has become a matter of great concern because of its reported impact on health of human beings, animals, birds and honeybees, the Ministry continues to maintain its indifference. In the absence of any creditable information from the Government, people feel agitated and worried. Department of Telecommunication in its deposition before the committee has informed that norms for exposure limit for radio frequency field has been reduced to $1/10^{th}$ of the existing limits prescribed by International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) and there was a difference of opinion on the impact of radiation from cell towers on health of citizens. However, there is a need to effectively monitor the effect of radiation from cell towers etc. and the number of inspectors available for the purpose needs to be significantly enhanced by the concerned administrative Ministry.

It has been informed that an amount to the tune of around Rs. 38,000 crore is lying in Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA). As per the directions of the Supreme Court, the Ministry is supposed to release funds only to the extent of ten per cent of the principal amount of about Rs.23,800 and that also from the interest accrued. This year although the Ministry was authorized to release about Rs.2,400 crore, it could release only Rs. 1,100 crore as Action Plans were not received from all the states. State should be given advisory to recommend their respective action plans to get approved at the earliest and the spending of CAMOA fund should be under rules and regulations so that for the purpose for which the funds are collected should be used for the same. Ministry should do some constructive action in this regard at the earliest.

The Ministry should evolve a mechanism to create awareness on the subject among the people. This issue has to be addressed comprehensively and public hearings with stakeholders should be the basis for further action in the matter. The judgments of various courts on this issue need to be implemented forthwith.

The challenge of environment protection and prevention of damage to our ecology is to be seen in a holistic perspective. The challenge is indeed grave and needs to be addressed as a matter of highest national priority as if tomorrow was today. The agenda for action cannot be hostage to compulsions of partisan politics or to lack of political will. Nor can the bureaucratic red tape and passing the buck attitude be an excuse for inaction. While pursuing our national goal of high economic growth as a means of poverty alleviation we need to reiterate in our actions to the primacy of environmental concerns.

Climate change resulting from ecological imbalance, a rapacious and unsustainable exploitation of our national resources and flawed priorities have had demonstrable adverse effects on the quality of life of the vast mass of our people living on the margins, particularly the farming community in rural areas and the urban poor.

The adverse impact of climate change on our agricultural productivity and the management challenge of water resources has added to the woes of millions of Indians, accentuating the misery that goes with poverty and absence of economic stability. The challenge to health and longevity for millions of Indians on account of air pollution and lack of potable water, sanitation and housing facilities in many parts of the country has deprived the affected people of their fundamental and constitutional right to life with dignity.

We need to unequivocally accept the demonstrated co-relation between sustainable development and living standards of the people. We need to formulate and implement policies that can integrate the imperatives of economic growth with environmental responsibility.

The Ministry of Environment, Forests and Climate Change has a central mandate of protecting our environment which is our common heritage. Flawed regulatory, regime, poor management of resources, inadequate use of technology, disincentives to environmental conservation, absence of a credible, effective and accountable machinery leading ultimately to lack of enforcement of environmental norms and laws, are challenges that are required to be addressed without any delay.

I personally feel that, the very purpose of long term planning in the form of Five Year Plan is to formulate long gestation projects and for their timely execution, for which inadequate allocation of funds should not b e a stumbling block. At the same time the Ministry needs to ensure that the funds are prudently and effectively utilized.

□**श्री सुधीर गुप्ता (मंदसौर) :** मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के बदलते पर्यावरण परिवेश में हिमालय स्टडी हेतु गठित नेशनल मिशन हेतु 100 करोड़ का बजट प्रावधान

किया है मेरे कुछ सुझाव है जो निम्न हैः

1. वन क्षेत्र सघनीकरण हेतु कार्यरत कार्यबल अगर आपके मंत्रालय द्वारा स्थापित मानक को पूर्ण करते हैं तो उनको पुरस्कृत करने हेतु बजट में पुरस्कार राशि प्रस्तावित करना चाहिए ।

2. सघन क्षेत्रों को और सघनीकरण हेतु वन क्षेत्र के कार्यबल के अतिरिक्त वन मित्रों को जोड़ना चाहिए इस हेतु वन मित्रों को ट्रेनिंग देने हेतु एकेडमी का गठन करने का प्रावधान बजट में करना चाहिए ।

3. गांधी सागर (चम्बल) मंदसौर संसदीय क्षेत्र में 37000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ क्षेत्र सघनीकरण के अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता है इस क्षेत्र में रेंजर कालेज या वन शिक्षा एकेडमी की स्थापना का बजटीय प्रावधान हो तो इतने बड़े क्षेत्र के लिए न्यायपूर्ण उपलब्धि होगी ।

4. वन क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पशु विशेÂाकर नीलगाय कृÂिा क्षेत्रों में आकर कृÂाकों की फसलें बर्बाद करती है उन्हें रोकने हेतु नीलगाय की पूर्ति हेतु आवश्यक वनस्पति उत्पादन हेतु निदेश देने व बजटीय व्यवस्था करे ।

***SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA):** Environment and forest include biology, geology, chemistry, physics, engineering, sociology, health, anthropology, and economics, statistics, and computers earth's environmental resources. Thus most treaties that helped traditional societies protect and as we look around at the area in which we live, we see that our surroundings were originally a natural landscape such as a forest, a river, a mountain, a desert, or a combination of these elements. Most of us live in landscapes that have been heavily modified by human beings, in villages, towns or cities. But even those of us who live in cities get our food supply from surrounding villages and these in turn are dependent on natural landscapes such as forests, grasslands, rivers, seashores, for resources such as water for agriculture, fuel wood, fodder, and fish. Thus our daily lives are linked with our surroundings and inevitably affects them. We use water to drink and for other day-today activities. We breathe air, we use resources from which food is made and we depend on the community of living plants and animals which form a web of life, of which we are also a part. Everything around us forms our environment and our lives depend on keeping its vital systems as intact as our dependence on nature is so great that we thought for subsequent generations.We cannot continue to live without protecting the Multi-disciplinary Nature of Environmental Studies Three forms of life are important for our wellbeing I began to believe that easy answers to the strains of domestic animals and crops. The industrial development and intensive agriculture that provides the goods for our increased amounts of natural resources such as water, are those which will be exhausted in the futureable resources, such as timber and water, are those which can be used but can be regenerated by natural processes such as regrowth or rainfall. But these too will be depleted if we continue to use them faster than nature can replace them. For example, if the removal of timber and firewood from a forest is faster than the regrowth and regeneration of trees, it cannot replenish the supply. And loss of forest cover not only depletes the forest of its resources, such as timber and other non-wood products, but affect our water resources because an intact natural forest acts like a sponge which holds water and releases it slowly. Deforestation leads to floods in the monsoon and dry rivers. Such multiple effects on the environment resulting from routine human activities must be appreciated by each one of us, if it is to provide us with the resources we need in the long-term. Our natural resources can be compared with money in a bank. If we use it rapidly, the capital will be reduced to zero. On the other hand, if we use only the interest, it can sustain us over the longer term. This is called sustainable utilization or development. Unsustainable utilization are using more resources than we really need. Without ever thinking about their environmentally positive, we need to look from a new perspective at how we use resources.

For every resource we use, we must ask ourselves the following questions: Development of National Parks and Sanctuaries is an umbrella scheme encompassing components of protection, habitat improvement, settlement of rights, eco-development, infrastructure development, capacity building including research and training, eco-tourism, education and awareness, etc. Priority will be given to the development of high diversity and high value areas. The environmental clearance of projects by SPCB sometimes takes a long time. There is a need for standard procedure and setting time frames. The receipts from these are not expected to be enough to meet the total running cost of the plant. In the event, municipalities have to bear a part of cost through raised sewage tax lest the investments made go to waste.

Just about every rock you pick up in the 2,600 sq km Rajmahal hills is a treasure preserved by the earth for millions of years but now turning into dust. In couple of years, this awe-inspiring wealth of Jurassic-era fossils will vanish forever, thanks to unbridled quarrying.

Hundreds of trucks, cranes and bulldozers kick up dust in a area where once dinosaurs ruled. The rocks that preserve imprints of prehistoric trees and plants are smashed up into chips to build roads in the neighborhood. At places, the hills have been sheared almost vertical 10 storey's high, destroying countless of the finest fossils ever found anywhere on the planet.

Rajmahal hills are among the finest research fields geologists and plaeobotanists can expect. Sadly, the day is not far away when you won't find even a single fossil here. The plant fossils here date back between 68 million years and 150 million years. The Rajmahal trap has fossil formations from the Mesozoic era, spread over the Triassic, Jurassic and Cretaceous ages. The quarrying is ruining possible dinosaur fossils as well. There are clear hints of the existence of Jurassic and Triassic - age reptiles in this area. If proper excavation and study is carried out, these fossils could be found. We are still hoping that we may one day find a dinosaur fossil here.

The plant fossils of Rajmahal hills are extremely well preserved - a rarity for remnants of that age - and they give an accurate record of the paleo-environment, a long before human beings walked the plant. Most such plants and trees would have turned into coal. The Rajmahal volcanic eruption, which ran up to Sylhet (now in Bangladesh), had a period of calm during which there was luxurious growth of plants. When the volcanoes erupted again, the trees were buried at just the right temperature and pressure to prevent 'coalification'.

The prehistoric remains are so well preserved that even a layman can spot the fossils from stones. The annual rings of a tree or exquisite patterns of leaves are easily identified. Fossils from here find pride of place in museums and labs across the world. But this unique treasure trove is under assault from the ones who should be protecting it.

All across the Rajmahal hills area, the Government of Jharkhand has given away mining leases indiscriminately to private companies, who are

blowing up the hills and digging the tunnels. In this free-for all, it is very difficult to identify who has a mining lease and who doesn't.

Some companies that don't have lease grease the palm of the local administration to plunder the hills. If there are 500 agencies mining and blowing up the hills, you have 2000 stone-crushing units smashing the precious fossils to nuggets - perhaps the most 'expensive' road - building material in the world.

Some of the oldest fossils belong to the Jurassic and Lower Cretaceous period, dating back 150-200 million years, will be preserved in the park.

There is an urgent need to conserve the rich fossil site. It is essential to preserve the plant fossils in ancient conditions. The park would be the fifth in India but the first in the east. It will be home to the oldest fossils found in the country. The fossils belong to the Jurassic and Lower Cretaceous age. "It is a new family of plant fossils that we found in India. Later, similar species of plants were discovered in Australia and New Zealand.

The park will comprise, among other things, an auditorium laboratory and a museum with a geological gallery displaying scientific graphics detailing the organic evolution of fossils, flora and fauna of India and Jharkhand. The maximum density of fossils is located in Mandro CD block, 32 km from Sahibganj.

With so much of heritage and cultural history attached to the whole area and Deoghar being a centre of religious significance with 5 crore people visiting annually, as also the seat of ancient learning Vikramshilla, Mandar hills nearby it assumes immense cultural significance.

I would accordingly request to direct the relevant authorities to take immediate steps to ban and prohibit the indiscriminate mining that is being carried out all across Rajmahal area.

Late Birbal Sahni well known scientist was involved in this important exercise.

This has reference to converting the forest reserve area of Koiridih as Wildlife Sanctuary/National Park. This area is having potential to attract tourist in greater number which will ultimately help increase per capital income of the people residing nearby area.

Your good office is aware that nearby town of Koiridih, Deoghar has been included in the list of prominent cities and has been declared as mega tourist destination from Ministry of Tourism, Government of India. Deoghar is the unique and extremely revesed site of one of the 51 Shaktipeeths and also of Dwadash Jyotirlinga in the country. This is a religious and cultural capital of Eastern India which catapult the holy place to an international acclaim and is visited by over 5 crore pilgrims every year. A letter of Home Minister of Government of India is attached wherein three districts namely Deoghar, Dumka and Pakur are to be included as SRE districts which upholds my concern for developing the region as naxalism is on the brink of spreading deep into this region.

By converting Koiridih forest reserve area as Wildlife Sanctuary/National Park will attract visitors of Deoghar to visit Koiridih as well.

The famous Trikut mountain is also nearby. It is said that lord Rawan use to come here to worship lord Shiva. This mountain is extensively talked about in Ramayana. The park will comprise, among other things, an auditorium, laboratory and a museum.

Forest in Jharkhand has long been under pressure from mining and for meeting the demands for fuel. Initiatives have been taken by the State Government to increase its forest cover. Forest Resource Surveys are also being conducted at district level for better management and planning. The state has also formed joint Forest Management (JFM) Committees besides forest-based livelihood development, wildlife management, biodiversity conservation, clean environment and waste disposal plans. To tackle the impacts of mining, the State Government also proposes to bring legislation in mining sector so that resources generate from mining sectors can be pumped back for local developmental activities.

Development of sustainable Forest Management Plans for different forest types in view of Climate Change : Detailed studies are recommended to understand impacts of climate change on forest productivity in different forest types using different climate and biodiversity models. This would help in developing climate resilient forest management plans. Revival of preservation plots, sample plots and yield plots is also recommended. To move from business as usual scenario, adaptation plans for each forest type of Jharkhand according to their biophysical be developed and maintained.

Promote Research to Understand the Impact of Climate Change on Forest Ecosystem - The forest department should invest resources on developing 'centres of excellence' to undertake regional analysis for the climate change related threats analysis using climate models. Researches to forecast the likely impact of climate change phenomenon in forest areas, to assess the vulnerability, carbon sequestration potential and adaptability of indigenous tree species should be undertaken on high priority.

Development of baseline methodology of carbon sequestered in the state forts - state should develop methodologies for inventorization of the carbon stock available to take advantage of the REDD+ and other forestry carbon initiatives.

Vulnerability Mapping of Forest of Jharkhand - Detailed vulnerability mapping of the forest ecosystem and livelihood of forest dependent community with reference to climate change should be taken up and accordingly the adaptation plans should be made and implemented in the state.

Forest clearance is the need of the hour for water dams (like PUNASI), industry and infrastructure.

*__SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE):__ We are currently at a juncture in world diplomatic relations with regard to environmental concerns, where countries - whether developed (and hence more industrial and thereby more polluting) or developing - have all been pledging their support to the cause of protecting the environment and stopping the phenomenon of climate change. And yet, it is saddening to note that India, which is still grouped as a developing nation, is already the world's third largest producer of greenhouse gases.

Further disturbing fact lay with regard to the utilisation of budgetary resources, in direct connection to today's point of discussion. In almost every single section that the Ministry has demanded more money for the Standing Committee Report of the Demands for Grants of the Ministry of

Environment, Forests and Climate Change shows clearly that there has been below average utilisation of resources.

India's high air pollution, ranked by the World Health Organisation (WHO) among the worst in the world, is adversely impacting the lifespans of its citizens, reducing most Indian lives by over three years, a new study has said.

Over half of India's population - 660 million people - live in areas where fine particulate matter pollution is above India's standards for what is considered safe. A study by Harvard and Yale researchers said that if India reverses this trend to meet its air standards, those 660 million people would gain about 3.2 years onto their lives. This should be the Government's responsibility, to take on the challenge of the data here presented, and draft better policies towards this direction. However, the Standing Committee reports a disturbing trend of refusal on the part of the Ministry to grant legitimacy to most of the reputed non-governmental surveys done in the country. The condition of Delhi's air pollution has been in the news often recently, and the Report states that the government had admitted that as of now there is no finalised Action Plan to tackle the situation. This is a matter of grave concern, and this pertains to other cities in India as well.

Even by the standards set by the government boards, some of the worst forms of air pollutions are found in Indian cities. The Central pollution Control Board (CPCB) considers air to be 'clean' if the levels are below 50 per cent of the prescribed standards for pollutants. During 2007 only 2 per cent cities have low air pollution on the basis of PM10. In about 80 per cent of cities (of a total of 127 cities/towns monitored under the NAMP), at least in one criteria, pollutant exceeded the annual average ambient air quality standards. This has serious public health implications. There are very few cities, which can be termed clean keeping PM10 levels (respirable particulates) as criteria, however over the years SO_2 levels have fallen sharply in many cities but the NO_2 levels are increasing in many cities.

Indian cities are reeling under heavy particulate pollution with 52 per cent of cities (63 cities) hitting critical levels (exceeding 1.5 times the standard), 36 cities with high levels (1-1.5 times the annual standard) and merely 19 cities are at moderate levels, which is 50 per cent below the standard.

This asks for the government to make an Action Plan for Indian cities, not just because it is the responsibility of the Ministry, but also because the Constitution of this country, in Article 21, guarantees to every citizen a better quality of life, and they deserve to breathe clean air.

Central Pollution Control Board itself has been seen to be severely underutilizing their funds. In 2014-15, CPCB was allotted Rs. 57.92 crores in BE, which was reduced to 40 crores in RE, and yet, by December 2014, only 26.53 crores were utilized. There was a target of setting up 700 Air Quality Monitoring stations, out of which only 244 have been set up.

Regarding noise pollution, it is important to note that India does have laws/ pace to prevent it. However, while World Health Organisation has fixed 45 decibels as the safe noise levels in a city, Indian cities on an average record 90 decibels, which is the double of the WHO standards. The committee report states that Noise Pollution (Regulation and Control) Rules 2000 is being blatantly violated all over the country. There was a target of setting up 35 Noise Monitoring stations by the CPCB, but this has been a project in progress since 2013, and as of now, nothing has been completed.

The government needs to take a stand on it, and not just formulate an action plan but also initiate awareness campaigns in this direction.

It is also significant that according to CPCB reports, the estimated sewage generation from class-I and class-II towns in the country was around 38255 million litre per day (MLD) in 2009-10, while the sewage treatment capacity was 11787 MLD, or only 30% of the sewage generation. It is saddening to note that even after five years, in 2014-15, sewage generation from urban areas is 57233 MLD against the treatment capacity of 21479 MLD - still only 37% of the generation.

Thus, it is unfortunately safe to say that India has an extremely inadequate system of sewage treatment and disposal. With regard to this, it is important to keep in mind that if this is not fixed, India's Swachh Bharat Mission is also bound to fail. The coordination between ministries in this case is of absolute importance - whether it be this particular Ministry of Environment, Forests and Climate Change, or that of Rural Development, Urban Development or Drinking water and Sanitation. The Government should, as a matter of immediate need, install more sewage treatment plants in India's cities and towns and ensure a fix to this problem. We need an Action Plan for bio-digestible toilets, better enforcement of norms at the Municipal levels of segregation of solid waste and their collection and disposal.

There are currently 302 extremely polluted stretches of 275 rivers in the country. It is important note that Rs. 1500 crore was allotted to the Ministry in the Twelfth Five Year Plan for river conservation purposes. Out of this, from 2012 to March 2015, only 388.33 crores have been allocated to the Ministry. For 2015-16, there has been zero allocation to the National River Conservation Plan. Out of a total provision of Rs. 295 crore, only 40 crore has been given to the National Clean Energy Fund for 2015-16 and even the Standing Committee does not think that this sum is even close to sufficient for river conservation.

Another concern that this government hasn't raised enough is that of e-waste. There is a huge gap between the amount of e-waste generated in India and out capacity to dispose or deal with it. CPCB's 2005 report had estimated back then that the amount of e-waste generated by India would increase by seven times by 2012. It is much higher now, and part of a huge global problem. We must keep this in mind at tandem with the fact that the use of electronics is at an all-time high in the country currently. We cannot only focus on development and technological revolution and not keep the issue of its environmental consequences in mind.

Infact, even CFL bulbs, that are widely promoted as a energy saving measure, can become toxic to the environment. The Committee report cites that in just one year, 2014-15, just in Delhi, 14.93 million CFLs releasing 74.65 kgs of mercury were disposed off unsafely.

Another important issue is that of the effect of electromagnetic Radiation from cell towers and how it is affecting the citizens. It is heartening to know that the government is funding projects and collaborating on a inter-ministerial level in order to ascertain the actual effect of this problem. The Standing Committee Report has also taken note of this issue, and I too concur with it, that there should be a definitive Action Plan to tackle this problem, and a timeframe within which the research that is being funded will be put to real use.

Despite the bold warning from the recent Inter-governmental Panel on Climate Change (IPCC) report of the catastrophic impacts of rising temperature on the global climate, the government is keen on enacting changes to weaken the existing environment. The new government has "delinked forest clearance from clearance by the National Board of Wildlife and halved NBWL clearance requirement from 10 km to 5 km around forest reserves, besides emasculating the Board by replacing eminent experts and concerned NGOs with rubber stamps. The government has relaxed procedures for the application of the Forest Conservation Act (FCA) in precisely in those areas where FCA is most required: Naxal-affected areas; linear projects in forest areas; and in eco-sensitive areas along he international border.

In this context, it is important to also mention that the government has further threatened to heavily dilute the landmark Land Acquisition Act that they themselves voted for a year ago, and amend with a view to diluting a whole on raft of environmental protection legislation ranging across the gamut of the Environmental Protection Act, the Wildlife Protection Act, the Forest Conservation Act, and the Water and Air Pollution Act, while preserving the highly discriminatory colonial legislation that is the Mother of all forest acts in its current form - the Indian Forests Act, 1927.

Again, the MoEFCC order, issued on October 28, 2014, discards the specific provision in the 2006 Forest Rights Act, which seeks "prior informed consent" of Gram Sabhas (the village council body) before acquiring forested land and clearing forests for industrial or any other non-forest activity.

Recently, the government has weakened clauses for public consultation with communities affected by mining and other infrastructure projects, and sought to dilute provisions mandating "free, prior and informed consent" of Adivasi (indigenous) communities.

In its original form while recognizing the rights of indigenous tribal communities and the non-tribal forest dwellers over the forest land, FRA empowers the communities to certify that their rights will not be violated by an upcoming project. The government must resolve this issue by consulting with the affected parties as a matter of priority.

Since 1980, a total of 1.21 million hectares (ha) of forest land have been diverted for 23,784 proposals for non-forestry purposes - primarily mining and industrial projects. Nearly 400,000 have been diverted in Madhya Pradesh alone, followed by over 100,000 hectare each in Maharashtra and Chhattisgarh. Currently, 22% of India is under forest cover. The government targeted to increase this to around 33%. However, in context of the approach of the government towards environment policies, this target does not seem to be anywhere near being completed.

It is estimated by World Wildlife Fund (WWF) that total industrial roundwood consumption in India could exceed 70 million sq mts per year by the end of the decade (350,000 large shipping containers), while domestic supply would fall short of this figure by an estimated 14 million sq mts.

Again, India is a big edible oil consumer. In fact, it is one of the three largest importers of palm oil in the world, alongwith with EU and China. Of these imports, 95% come from Indonesia and Malaysia, causing negative social and environmental consequences in these exporting countries.

Shockingly, Audit Reports by the CAG show that in 2012, the cess collected for Green energy in the country has been utilised for balancing India's fiscal deficit, and not given as due to the national Clean Energy Fund. The Government auditor, in its report, said that while Rs.3,646.01 crore (Rs. 1066.46 crore in 2010-11 and Rs. 2,579.55 crore in 2012-13) had been collected through clean energy cess, only Rs. 1,066.46 crore was transferred to NCEF. This is an example of how the governments have over the last few years prioritised other concerns over the environment.

The Ministry has taken certain good steps - India's Solar Energy programme which aims to generate 1 lakh MW electricity by 2020, and other initiatives on wind energy deployment, water conservation, and protecting coastlines and Himalayan Ecosystem, reflected government's commitment towards environment protection and sustainable development. However, these steps are beneficial only if effectively implemented.

Since 2011, from barely 20 megawatts, India has installed solar capacity upto 1,686 megawatts by the end of 2013. The government is planning on adding 10,000 megawatts of energy capacity to the renewable sector, every year - that's about half of the country's current total installed capacity. Although India is still developing domestic energy sources to satisfy the growing demand, it has imported increasing amounts of fossil fuels over the last year. With the aim of expanding its power generation by 44%, coal imports for the country were exceptionally high in 2014 and are likely rise further over the next five years., India's renewable energy targets of 100 gigawatts of solar and 175 gigawatts of total renewable sources of energy by 2022, therefore, does seem like an ambitious task.

Finally, with regard to wildlife conservation, poaching still continues and India still does not have its own standalone Conservation Act. India still relies on the Wildlife Protection Act of 1972. The 2013 Bill in the Rajya Sabha proposed to change the law for better conservation techniques. However, the Bill was withdrawn earlier this year, and the government had said that they are working on better Bill. However, it has not been introduced yet. The government should not delay such work and should promptly introduce the bill as it is crucial to the protection of environment, forests and wildlife in the country.

To conclude, I would like to point out that development today comes at a huge price - the developed countries of the world are proof of it. We too have seen flash floods in Kashmir and Uttarakhand, and distinct levels of coastal erosion in different parts of the country. Odisha has a massive coastline of 484 kms and Balasore, my constituency, has 80 kms of it. While at the Centre we map the consequences of climate change, global warming and pollution in numbers, the common people of the country are suffering the consequences in their day to day lives. Meanwhile, India formulates an industrial revolution through 'Make in India' and other efforts, but as a corollary, we should also keep in mind that we are already the world's third largest producer of greenhouse gases. This disturbing trend must be brought to a stop, for preventing environmental degradation, which now will ensure a better quality of living for the future generations.

***SHRI G. HARI (ARAKKONAM):** The environmental issue has become an issue of public importance. It is gaining in all aspects of our life. I am glad that the Government has been paying much attention to this issue whether it is conversion of forest land, pollution of river, air pollution, noise pollution, etc. The National Green Tribunal has come and are quite active now a days. I have come across with a news report that the Government is considering to create or revise many of the existing environmental laws in consultation with the state government. It is a good idea because the environmental issues have to be dealt by the state governments and overall supervision with the union government. What I have come across that

many state governments were not able to implement all the directions of the pollution control boards because of the paucity of funds. The directions of installing sewerage treatment plants is an issue because it involves huge amount of money. Therefore, it is my urge that the government should provide some sort of assistance to state governments for installation of STP.

Another issue which I would like to mention here is that the tribal people who were living in forest area, in which they were living from a period unknown, because of the rigid environmental laws, these people are deprived of developmental activities, such as laying of roads, etc. Therefore, in the interest of the tribal people, I urge upon the government to relax some of the provisions of the environmental laws, so that for the welfare of tribal people living in the forest land they can also enjoy some of the benefits which the people living in other areas are already enjoying.

*m08

□**डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) :**आजकल क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा सवाल है। पूरे विश्व में पर्यावरण की जो स्थिति पैदा हुई है, वह बहुत ही निराशाजनक स्थिति है। आजकल पर्यावरण का जो विनाश हो रहा है, जंगल को जिस तरह समाप्त किया जाता है उसके लिए सबसे बड़ी जवाबदेही विकसित देशों की वजह से हुई है। पूरे विश्व के पर्यावरण को प्रदूÂिात करने का कार्य विकसित देशों ने किया है। उसके लिए भारत जैसे देशों की जवाबदेही बहुत कम है। मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार को इस बात पर जोर देना चाहिए।

पर्यावरण क्लीयरेंस देने के बारे में हमारी सरकार ने जो लचीलापनता अपनाई है इसकी वजह से पर्यावरण एवं विकास का संतुलन बना है इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं।

जहां तक बायो-मेडिकल वेस्ट कानून का सवाल है, यह बहुत महत्वपूर्ण विÂाय है। इस विÂाय में कॉमन बायोमेडिकल फसेलीटियोंस का सवाल है गुजरात में दो कंपनियां बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। मगर अच्छे कार्य करने वाली सीबीएमडब्ल्यूटीएफ को अलग-अलग प्रकार क नए प्रावधानों के लिए मजबूर किया जाता है। उन सीबीएमडब्ल्यूटीएफ को आदर्श गाइड लाइंस के लिए सख्ताई किया जाता है। मेरा सरकार से निवेदन है कि उनमें लचीलापन लाना चाहिए तथा अच्छे कार्य करने वाली सीबीएमडब्ल्यूटीएफ की सराहना चाहिए।

भारत की संस्कृति पर्यावरण का हमेशा सम्मान करती है। मेरा मानना है कि भारतीय संस्कृति ही पर्यावरण को बचाने का उपाय है।

***SHRI NALIN KUMAR KATEEL (DAKSHINA KANNADA):** With regard to implementation of Kasturirangan report on the Western Ghats the government should take the views of local people before demarcation of ecologically-sensitive areas in their respective areas as suggested by the Committee report.

With regard to create a clean and sustainable environment, the government should frame guidelines to ensure that all the cities and towns should strictly adhere to handle their own garbage, liquid and solid waste. However, there is not proper planning made by the agencies and the authorities have not shown keen interest to take real-life challenges into account while preparing guidelines. This is not about making our cities smarter in terms of posh buildings and malls but about sustainable living. This can be possible with better planning and strict implementation of the same.

As far as Climate change is concerned, from school going children to Professor, a Layman to a leader, everyone is aware of the effects of the climate change. The country needs to develop and adopt innovative solutions to mitigate the effects of climate change. The union Government should fix a target and direct all the state government s to introduce atleast one climate change plan every year.

With regard to find out the solution to curb the increasing pollutions, the government should take some effective measures for classification of industrial units in a scientific manner. As we are aware that air pollutants, effluents and nature of waste- hazardous or otherwise- produced are part of an industrial unit's operations, the industrial units should be classified as per the severity of pollution produced by them. The government should put in a proper mechanism to conduct periodical review of the compliance of the standard norms of pollution.

In order to save fresh water industrial units should be asked to use treated water and directed to introduce zero liquid discharge system in the industries.

I welcome the proposal of the government to consider declaring at least one Biodiversity Heritage Site in 2015-16. It is very important step in order to conservation and preservation of biological resources of the particular regions. The government should put in place a transparent and effective mechanism for access to biological resources in all states and regions. There is also need to take steps to assess the animal population of various species to consider the option of their population management.

I would like to point out that the environmental governance institutions in our country are not effectively functioning to preserve and conserve the environment and forest resources. It is evident from the style of functioning of pollution control boards and wildlife trusts. The Central Pollution

Control Board (CPCB) has insufficient coordination with State Pollution Control Boards (SPCBs). Other constraints like lack of civil administrative authority, ineffective accountability, lack of stakeholder awareness, high levels of corruption and inadequate monitoring skills remain prevalent in the implementation of the various facts related to it.

As a result, forest destruction is rampant in the country. Illegal cutting and selling off timber, firewood shortage and consequential soil erosion is keeping the productivity of Indian agricultural lands low. Crop lands have expanded on to marginal lands and have reduced grazing lands. With unemployment and landlessness growing, even pro-forest tribal groups are looking to monetize forestry resources. Keeping all these shortcomings in the existing forest laws in view the Union Government should bring an effective and modern law to strike a balance between development and environment to protect all the stakeholders including forest dwellers.

SHRI T. RADHAKRISHNAN (VIRUDHUNAGAR) : Hon. Deputy-Speaker, Sir, environment needs to be protected from all kinds of pollution. We need to inculcate a sense of protecting environment in our younger generation. This is necessary because various kinds of pollution affect our air, water and sky resulting in change in climate. This comes in the way of our getting a regular rainfall. This affects the availability of water which is vital for our lives.

Pollution in our river system, both by allowing the flow of human waste as well as industrial waste is a big challenge. We have Pollution Control Board. A number of laws and rules have been framed by all the Governments over the years. But still the amount of pollution is on an increase with rising population. That is why we have a Ministry dedicated to environment, which also looks after the conservation of forests. This Ministry also extends its services as a mouthpiece of the Government in the world forums where climate change is a much talked about matter.

I wish to congratulate the Government for the lead it has taken among the developing countries with regard to the measures taken about the dent in the ozone layer. The world is today worrying about change in climate world over. The developed countries, which were emitting volumes of toxic gases all these years, have started dictating terms to the developing countries like India. We are compelled to reduce the use of fossil fuels. This will naturally affect our industrial activities in a big way.

In the name of reduction in carbon rates, that is, gas emission due to use of coal, petrol and natural gas, many restrictions are being imposed upon us. As this will slow down our economic progress, we are on the look out for alternative energy sources.

When it comes to environment, it is a part of our life cycle – one connected with the other. For instance, deforestation and depletion of forest cover have affected the rain pattern. This also adds to the misery that results out of climate change. Forests can survive only when we allow the wild animals there to survive. Only when the green cover is protected, the survival of human race and sustainability of human life is possible.

Having pointed out the inter-relation within the three responsibilities this Ministry has been entrusted with, I may now try to go into the budgetary allocation for this Ministry. The actual allocation for this Ministry in 2013-14 was Rs.2,256 crore, whereas the Revised Estimate ended up as Rs.1,764 crore. When the existing expenses in the face of price rise have increased manifold, this year's allocation is just Rs.1,681 crore.

I do not understand how the Ministry will be able to train its manpower to protect our forest cover or the wildlife. I also fail to understand the scaling down of allocation for research in this field for a vast country like ours with varying geographical conditions and the second largest population in the world.

Zoological parks in a tropical country like ours must have improvised modern facilities to carefully protect the animal species that are parked there and to nurture them. Unfortunately, the allocation for Central Zoo Authority has been cut drastically from Rs. 26.5 crore to Rs. 5.88 crore. Here, I would like to point out the compassionate gesture of our guiding spirit *puratchi thalaivi* Amma in conducting annual camps for all the temple elephants in Tamil Nadu. This annual camp held in Mudumalai Sanctuary is like the annual health camp for those animals that remain in the temples in the midst of the human population throughout the year. Hon. Minister of Environment and Forests, Shri Prakash Javadekar was highly appreciating recently this kind of continued gesture of our leader in taking care of the wild animals, especially the elephants. I recall his paying rich encomium to our beloved leader Amma in the Consultative Committee meeting held at Bandipur Forests in Karnataka.

When it comes to environmental education, training and extension, it is needless to say that such programmes with enhanced allocation must continue in the wake of rise in population. What was Rs. 47 crore in 2013-14 was actually brought down to Rs. 30 crore in 2014-15 by this Government. More than punitive measures for violation and damage control at a huge cost, creating awareness towards the protection of environment is necessary.

I fail to understand the overall trend of the Union Government to slice down the fund allocation for strategically important Ministries, like the Ministry of Environment which has to tackle various environmental issues. I am afraid that it will be too much to expect from the industries.

Recruiting adequate manpower, providing needed training with essential equipment at their disposal and ensuring coordinated action in protecting forest wealth, especially in the inter-State border areas, is necessary. The mismanagement in this area by the Centre has resulted in the recent tragic incident that happened in the Seshachalam Forest in Chittoor District of Andhra Pradesh bordering Tamil Nadu. I expect that the Union Minister currently holding the responsibility will evolve a suitable plan of action to avoid the recurrence of such unpleasant incidents. I hope that the Minister will not shirk his responsibility stating that those forests come under the purview of the State Government.

Before I could conclude, let me draw the attention of the Union Government to evolve a national policy to overcome the problems created by small

and medium scale industrial units in paper and cardboard manufacturing. The effluents from these units are polluting both air and water in the vicinity. In the proposed new GST regime manufacturing States will be getting less revenue. This, in reality, will mean that the State Government will be more hard-pressed to attend to the need to protect the environment. In our Virudhunagar Constituency, the industrial waste from paper and board units causes great havoc. I would urge upon the Union Government to study the problem and to evolve a viable method to provide a centralised effluent treatment plant. Ignoring the needs of the Ministry of Environment will end in national disaster. This may not appear so before our eyes, but the destruction will be inevitable and irretrievable. Giving this word of caution let me conclude. Thank you, Sir.

□**श्रीमती रमा देवी (शिवहर)**ः वन एवं पर्यावरण किसी भी देश के विकास एवं भविÂय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। हमारे देश में सदियों पुरानी वन एवं प्रकृति के विभिन्न रूपों की पूजा एवं संरक्षण पद्धति अपनायी गयी है। व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण के चलते वन एवं पर्यावरण पर इसका न सिर्फ हमारे देश में अपितु पूरे विश्व में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। आधुनिकता एवं जनसंख्या विस्फोट ने तो वन एवं पर्यावरण को बुरी तरह से क्षति पहुंचाया है। आज जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग एवं प्रदूÂाण के चलते विश्व में करोड़ों लोग तकलीफ झेल रहे हैं। मनुÂय क्या जानवर एवं पेड़-पौधे तक इस विनाश लीला से प्रभावित हुए हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश की अदालतें वन एवं पर्यावरण मुद्दे पर शुरू से गंभीर रही है। भिन्न-भिन्न न्यायालयों के सैकड़ों फैसलों ने सरकारों को मजबूर किया कि वे वन एवं पर्यावरण की समुचित रक्षा करें।

इसके बावजूद आज वन क्षेत्र हमारे देश में घटना ही जा रहा है। पशु-पक्षी विलुप्त होते जा रहे हैं। वनों में मिलने वाले कई प्रकार के पौधे अब दिखाई नहीं देते। लालचवश हमारे देश के लोगों ने वन एवं पर्यावरण का दोहन किया है। आजादी के बाद से कांग्रेस की सरकारों ने देश की वन सम्पदा, खादानों एवं नदियों को भी नहीं बख्शा। जिसके परिणामस्वरूप हमारे देश की स्थिति वन एवं पर्यावरण के मामले में अन्य देशों की तुलना में अच्छी नहीं है।

वÂाऩ 2014 में एनडीए सरकार के आने के बाद वन एवं पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान दिया जाने लगा है। जलवायु परिवर्तन एवं स्थायी विकास पर विश्व द्वारा किए जाने वाले नए करारों के आलोक में वÂाऩ 2015 के एक अभिप्रेरणा वÂाऩ होने की संभावना है। यह अगले 15 वÂााों के लिए वैश्विक समुदाय हेतु अंतर्राÂट्रीय विकास और पर्यावरणीय नीति संबंधी कार्य सूची के पाठ्यक्रम का निर्धारण करेगा। केन्द्र सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के संबंध में वित्त जुटाने हेतु भारत की संस्थागत संस्था को बढ़ाया जा रहा है। हाल ही में कुछ प्रमुख पहलों में सोलर मिशन को जोर-शोर से बढ़ाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बजट 2014-15 की उद्घोÂाणाओं की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक निधि से अनुकूल कार्यों की सहायता के लिए एवं कृÂिा, पानी, वानिकी इत्यादि जैसे क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से लड़ने के लिए राÂट्रीय अनुकूल निधि की स्थापना की गई है।

कार्बन बाजार में भारत की भागीदारी एक सफलता की कहानी है। भारत क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत स्थापित स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम) की कुल सात हजार पांच सौ नवासी परियोजनाओं में से 1541 परियोजनाएं भारत के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। अभी तक जारी कुल प्रमाणित उत्सर्जन ह्रास (सीईआर) 1.52 बिलियन यूनिट है। जिसमें भारत का हिस्सा 191 मिलियन यूनिट का है। इसके अतिरिक्त जो 2941 परियोजनाएं अनुमोदित हुई है उससे हमारे देश में लगभग 580000 करोड़ रुपए के निवेश में सहायता मिलेगी।

केन्द्र सरकार का वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत में जीव जन्तु सर्वेक्षण एवं अणवेक्षन में सतत् प्रयासरत है। वन प्रबंधन योजना में भी तेजी लायी जा रही है। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो स्थापित किया गया है। भारतीय वन्य जीवन संस्थान, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, हाथी एवं बाघ परियोजनाओं के द्वारा वन एवं पर्यावरण मामलों पर विशेÂा ध्यान दिया जा रहा है। केन्द्रीय प्रदूÂाण नियंत्रण बोर्ड, बायो मेडिकल कचरा प्रबंधन, ई-कचरा प्रबंधन, राÂट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम, राÂट्रीय वनरोपण कार्यक्रम, पर्यावरण शिक्षा जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा इस क्षेत्र में आशातीत सफलता पाने की कोशिश की जा रही है। ओजोन सुरक्षा पर भी विशेÂा ध्यान दिया जा रहा है। पर्यावरण मंजूरी के लिए राज्यों को ऑनलाईन मंजूरी देने को कहा जा रहा है। प्रदूÂाण फैलाने वाले उद्योगों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन कलर की श्रेणियों में रखने का फैसला किया गया है। हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आयात में कटौती पर ध्यान दे रहे है। ग्रीन एनर्जी प्रोडक्टस को पब्लिक सेक्टर बैंक पौने दो लाख करोड़ रुपए का लोन देने जा रहे है। यानि, बिजली, संकट को दूर करने में ग्रीन एनर्जी का बड़ा रोल होने वाला है। सरकार का टारगेट 2022 तक 1 लाख मेगावाट सोलर एनर्जी, 60 लाख मेगावाट विंड एनर्जी पैदा करने का है। सबसे खुशी की बात है कि 40 साल बाद हमारे देश ही नहीं पूरे विश्व में कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है। हमारे केन्द्र सरकार का संकल्प है हरियाली की हिफाजत। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने यह फैसला लिया है कि देशभर में फारेस्ट एरिया बढ़ाने और करीब 30 लाख परिवारों को रोजगार देने के मकसद से जो ग्रीन इंडिया मिशन की शुरूआत की गई है उसे मनरेगा से जोड़ा जाएगा। सरकार ने उद्योगपतियों से कहा है कि स्वच्छ जल, स्वच्छ हवा, स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ पर्यावरण और अधिक हरियाली को केन्द्र में रखकर ही उन्हें औद्योगिक उत्पाद बनाने या बेचने चाहिए।

मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार देश हित एवं जन हित में वन एवं पर्यावरण संबंधी मामलों को हल करेगी और अब हमारे देश से प्रदूÂाण, जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग जैसे नकारात्मक तत्व दूर होंगे और आदमी का जीवन खुशहाल होगा। इसमें सभी भारतीयों का साथ मिलेगा और सबका विकास होगा।

DR. MAMTAZ SANGHAMITA (BARDHMAN DURGAPUR): Thank you, hon. Deputy-Speaker, Sir. The sky, air, water, land and live inhabitants constitute our environment, and all of them are equally important to live in this world. After the world was formed, gradually the environment became congenial for life and then only from one cell different plants and animals and by further evolution process human beings came into being. They need clean water, air and also various productive animals and plants for their livelihood and for living. But due to various reasons like change in climate and natural calamities as well as with the advancement of science and urbanisation and modern life there are immense problems, which have created pollution in this world.

15.17 hrs (Shri Konakalla Narayana Rao *in the Chair*)

Now, all over the world, there is one single problem that is really worrying everybody, that is, global warming, which is due to various causes that I have already mentioned here. Among them, an important point is carbon emission in the air. Everybody is thinking about how to eliminate the carbon emission problem.

What is the effect of global warming? It affects our health in various ways, and the main thing is that air and water is warming up. So, there is unnatural climate, untimely rain and untimely weather changes that leads to various abnormalities and loss of life.

Another issue involved in this is reduction in forest area all over the world due to the reasons mentioned by me earlier. There is decrease in the animal world due to decrease in forest land, which is their inhabiting place, as a result, the number of animals and birds is either reducing or many are on the verge of extinction. What happens in such a situation? For example, birds are necessary for making flowers. Similarly, other animals are needed for various other things.

The forest land cover is decreasing. There is erosion in sea and rivers due to loss of various things. The saddest part is while we are thinking about

doing something to change the world environment for making it congenial to human life, there is a gross reduction in the Ministry's budget this year in certain things. Of course, for the Prime Minister's priority project, the Ganga Action Plan, the allocation has been increased, and also there is 100 per cent reduction in terms of taxes. My earnest request to the Minister is that along with the Ganga Action Plan, other rivers should also be saved from pollution. There should be a law to ensure that the industrial waste which now flows into rivers gets treated and the industrial effluents are not dumped in rivers, but are treated to make it pollution free.

It is sad that there is a cut in the money allocated for forest conservation. Previously, the allocation which was Rs. 5,045 crore has now been reduced to almost half, that is, to Rs. 2,099 crore. It is quite insufficient for managing wildlife in more than 650 protected areas. There is also a 15 per cent decrease in the funds allocated for Project Tiger, that is, it has been reduced from Rs. 161 crore, to Rs. 136 crore, especially when the tiger population is basically increasing in India by 30 per cent since last year.

I am from Bengal. I must say that the unique mangroves present in Sundarbans areas as well as in Andaman are congenial for the inhabitation of Bengal tigers. We are seeing a reduction there also due to pollution in those areas, especially due to plastics, soil erosion caused by various factors and the spill of oil from launches, etc. Therefore, there should be a provision of more funds for the protection of mangroves, especially in Bengal and Andaman areas.

Another very important treasure of our Indian Ocean is the coral reefs in Andaman and Lakshadweep Islands. Ecologically, they are very good for the fishes as well as human beings. However, due to tsunami and other factors, these coral reefs cover has been reduced. There was no provision made in this budget for the preservation of these coral reefs.

As you know, Bengal tiger is world famous and it is our national animal. However, instead of providing more funds for increasing their population, we are decreasing the budget allocation. Shri Satpathy is saying that you are trying to change it to 'lion', which is in the Gir Forests. As you know, you will find tigers all over India, at many places. There are eight reserve forests wherein tiger population is more and, therefore, it should remain our national animal.

Moreover, the Standing Committee in its report has said that the budget was inadequate for controlling pollution and increasing forest cover. In Bengal, the forest cover has increased by 18 per cent; it has also increased in Andhra Pradesh, North East, etc. Forest produce is the livelihood of underprivileged persons like the Adivasis and poor people living in and around those areas.

I would like to make a few suggestions. There should be forest preservation as forest produce is a livelihood for the people. It should be given more grants and there should be more vigilance in this regard. With regard to renewable energy, they have increased the budget, but still that is not sufficient. You should be vigilant in that respect. There should be strong action against the usage of plastic in coastal areas. Please do think about the birds that are becoming extinct in our country. Thank you.

□SHRI GAURAV GOGOI (KALIABOR): The Ministry of Environment, Forests and Climate Change must advocate on behalf of the environment and wildlife. Instead the Ministry is interested only in providing rapid clearances to big industrial projects. Around 450 industrial projects have been cleared. Yet the Ministry has not shown any concrete results on key issues such as poaching, air pollution, water degradation and declining bio-diversity. On these issues, the Ministry have only offered mere assurances. There is no Project to curb Rhino poaching. Poaching of small animals such as panglossian is continuing unabated. The polluted air in Delhi increasing the number of asthma cases in children. With so many critical challenges the budget cuts have only crippled the Ministry of Environment, Forests and Climate Change.

*SHRI P. KUMAR (TIRUCHIRAPPALLI): The environmental issue has become an issue of public importance. It is gaining in all aspects of our life. I am glad that the government has been paying much attention to this issue whether it is conversion of forest land, pollution of river, air pollution, noise pollution, etc. The National Green Tribunal has come and are quite active now a days. I have come a cross with a news report that the government is considering to create or revise many of the existing environmental laws in consultation with the state government. It is a good idea because the environmental issues have to be dealt by the state governments and overall supervision with the union government. What I have come across that many state governments were not able to implement the directions of all the directions of the pollution control boards because of the paucity of funds. The directions of installing sewerage treatment plants is an issue because it involves huge amount of money. Therefore, it is my urge that the government should provide some sort of assistance to state governments for installation of STP.

Another issue which I would like to mention here is that the tribal people who were living in forest area, in which they were living from a period unknown. because of the rigid environmental laws, these people are deprived of many developmental activities, such as laying of roads, etc. Therefore, in the interest of the tribal people, I urge upon the government to relax some of the provisions of the environmental laws, so that for the welfare of tribal people living in the forest land, they can also enjoy some of the benefits which the people living in other areas are already enjoying.

□**डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़)**ः जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत की पर्यावरण एवं वन नीति को लागू करने तथा झीलों, नदियों, इसकी जैव विविधता, वन एवं वन्य जीवों सहित देश के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा प्रदूÂाण रोकथाम और प्रदूÂाण कम करने के रोकथाम की देखभाल करने के लिए एक प्रमुख मंत्रालय है। मंत्रालय की नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने में सतत् विकास के सिद्धांत से निर्देशित होता है। मंत्रालय, संयुक्त राÂट्र पर्यावरण कार्यक्रम, दक्षिण एशिया पर्यावरण सहयोग कार्यक्रम, एकीकृत पर्वत विकास के लिए अंतर्राÂट्रीय केन्द्र की भी प्रमुख एजेंसी है।

भारत वन्य जीव संरक्षण से संबंधित 5 अंतर्राÂट्रीय समझौतों, वन्य जीव जंतु, वनस्पतियों के संकटापन समूहों के अंतर्राÂट्रीय व्यापार समझौता, अंतर्राÂट्रीय व्हेल शिकार आयोग, संयुक्त राÂट्र

शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन विश्व विरासत समझौता तथा वन्य पशु प्रवासी समूह संरक्षण समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला देश है। इसके तहत मंत्रालय के प्रमुख उद्देश्य वनस्पति जीव जंतु, वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण करना है तथा साथ ही प्रदूÂाण की रोकथाम एवं नियंत्रण, विकृत क्षेत्रों में वनरोपण और पुर्नउत्पत्ति, पर्यावरण संरक्षण तथा पशुओं का कल्याण सुनिश्चित करना है।

सरकार ने राज्यों को ऑनलाईन पर्यावरण मंजूरी देने के लिए पहल की है। इसके तहत केन्द्र ने राज्य सरकारों से कहा है कि वह पर्यावरण संबंधी प्रक्रियाओं की ऑनलाईन मंजूरी शुरू करें। इसके लिए परियोजनाओं को राज्यों में स्टेट एनवायरमेंट इम्पेक्ट एसिशसमेंट एथॉरिटी तथा स्टेट एनवायरमेंट एशिसमेंट से मंजूरी हासिल करनी होती है। अभी तक इसके लिए देश में पुरानी प्रक्रिया अपनायी जा रही थी। इस पहल के लिए मैं माननीय मंत्री जी का अभिनन्दन करता हूं।

इसी तरह से सरकार ने देश में विद्युत की कमी को दूर करने के लिए ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए 1.71 लाख करोड़ रुपए का ऋण देने का प्रस्ताव किया है, इसके लिए सरकार ने भरोसा दिया है कि इसके माध्यम से सोलर और विंड एनर्जी जैसे गैर-पारम्परिक स्रोतों से 34 हजार मेगावाट विद्युत पैदा की जा सकेगी। इस कार्यक्रम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 75 हजार करोड़ रुपए के कमिटमेंट के साथ अग्रणी रहा है। इससे 15 हजार मेगावाट ग्रीन एनर्जी पैदा की जा सकेगी। इसके बाद 14700 करोड़ रुपए के कमिटमेंट के साथ आईडीबीआई बैंक दूसरे नम्बर पर है। इससे 2940 मेगावाट ग्रीन एनर्जी का उत्पादन हो सकेगा। यह भी ग्रीन एनर्जी उत्पादन की दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारत सरकार द्वारा पर्यावरण अनुकूल कदम उठाने का ही परिणाम है कि अंतर्राÂट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने भारत द्वारा वैश्विक ताप वृद्धि के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार गैस कार्बनडाई ऑक्साईड के उत्सर्जन में दुनियाभर में हो रही बढ़ोत्तरी के बावजूद भारत में इसमें कमी आयी है। सरकार ने एक अन्य महत्वपूर्ण पहल करते हुए जलवायु परियोजनाएं लागू करने के लिए देश में एजेंसियों को आमंत्रित किया है जिसके तहत ग्रीन क्लाईमेट फंड के प्रयोग से जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण और उसके अनुकूल परियोजनाओं को लागू करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने एजेंसियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। जलवायु कोÂाा से संसाधनों को पाने के लिए आवेदकों को निश्चित तौर पर विश्वासी और मानक प्रबंधन वाला बनाने की दिशा में सरकार द्वारा सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं।

आज जब दुनियाभर के तमाम जलवायु वैज्ञानिक चिंतित हैं। जलवायु वैज्ञानिकों का आकंलन है कि अगर बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग को नहीं थामा गया तो जल्दी ही दुनिया गरीबी और भूखमरी की चपेट में आ जाएगी। एक अरब से भी ज्यादा लोगों पर इसका सीधा असर होगा, और इसका सबसे ज्यादा असर दक्षिण एशिया पर पड़ेगा। विश्व बैंक ने ग्लोबल वार्मिंग के असर पर अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि तापमान बढ़ने से दुनिया के कई इलाकों में फसलों की उत्पादकता में कमी आ रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक दोÂााल वे देश हैं जो सबसे ज्यादा इसका शोर मचा रहे हैं।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार का यह एक मार्गदर्शक सिद्धांत है कि सरकार समावेशी तरीके से सभी का विकास करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर विशेÂाा जोर दिया है कि गरीबों के लिए समुचित स्वच्छता, पेयजल, मातृत्व और शिशु देखभाल को सर्वोच्च प्राथमिकता सरकार दें। वैश्विक विकास में भारत की दुनिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है और वैश्विक स्तर पर सहस्त्राब्दि लक्ष्य जब तक सफल नहीं हो सकते तब तक उन्हें भारत में हासिल नहीं किया जाता।

अंत में, मैं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा देश में पर्यावरण के क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय प्रयासों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करते हुए वÂाान 2015-16 की अनुदान मांगों का पुरजोर समर्थन करता हूं।

□**श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल)**ः अंतर सरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल की वÂाान 2014 में प्रकाशित आकलन रिपोर्ट की सिंथेसिस रिपोर्ट में बताया गया है कि सूखे और बाढ़ इत्यादि जैसी जलवायु संबंधी विÂामताओं से होने वाले प्रभावों में वर्तमान जलवायु से कुछ प्रणालियों और मानव की महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होने का पता चला है। फिर भी, भारत में जलवायु प्रभाव संबंधी कोई विशेÂाट अध्ययन उपलब्ध नहीं है, जबकि सरकार का प्रयास है कि प्राकृतिक घटनाओं के वैज्ञानिक आंकलन के आधार पर अनुकूल और उपशमन कार्यों को बढ़ावा दें। सरकार ने 30 जून 2008 को राÂट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना जारी की थी, जिसमें जलवायु से होने वाली बड़ी घटनाओं की रोकथाम और पूर्व तैयारी के लिए किए जाने वाले उपायों में वृद्धि से जलवायु से होने वाली बड़ी घटना के लिए सभी पहलों को रेखांकित किया जा सके और वर्तमान में सभी राज्य सरकारें भी इसी संबंध में कार्य योजना तैयार कर रही हैं।

जलवायु परिवर्तन, वन और पर्यावरण एक महत्वपूर्ण विÂााय है, और पूरी दुनिया इस चुनौती से जूझ रही ह।ै लेकिन अभी तक इस विÂााय पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका है। इसी के चलते, पर्यावरण कानून में बदलाव करने से पहले केन्द्र सरकार राज्यों के साथ व्यापक विचार-विमर्श कर रही है और वर्तमान में पर्यावरण मंजूरी लेना एक बेहद कठिन काम बन गया है,। मंजूरी लेने के लिए लम्बे समय का इंतजार करना पड़ता है, अतः इस प्रक्रिया को ऑनलाइन किए जाने की आवश्यकता है। पर्यावरण से मंजूरी संबंधी परियोजनाओं को राज्यों में स्टेट एनवायरनमेंट अथॉरिटी और स्टेट एनवायरनमेंट असेसमेंट कमेटी से मंजूरी लेनी पड़ती है और अभी तक इसके लिए भी पुरानी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। अतः इस प्रक्रिया को बदलकर ऑनलाइन किए जाने की जरूरत है। पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए सभी राज्य नगर पालिकाओं द्वारा उत्पन्न सीवेज को 100 प्रतिशत ट्रीटमेंट करने संबंधी योजना बनायी जानी चाहिए और उद्योग को ट्रीटमेंट के लिए पानी को फिर से इस्तेमाल में लाए जाने पर जोर देना होगा।

पेड़ों के आस-पास कंक्रीट डाले जाने से हरे भरे पेड़ों के सूख जाने का मामला बेहद गंभीर है, और शहरों में इस तरह से हजारों पेड़ सूख गए हैं क्योंकि इन पेड़ों को कंक्रीट से पाट दिया गया है और सरकार द्वारा हरियाली बढ़ाए जाने के खूब दावे किए जाते हैं। इन मामलों में उन मनको का पालन नहीं किया जा रहा है जिनके तहत यह कहा गया है कि पेड़ों की जड़ों के आस-पास एक निर्धारित दूरी तक कंक्रीट नहीं डाला जाना चाहिए, इस तरह से अवसर देखने को मिलता है कि जैसी ही हवा थोड़ी तेज गति से चलती है या तेज बारिश होती है तो पेड़ गिरने लगते हैं ज्यादातर मामलों में ये पेड़ जड़ो से उखड़ जाते हैं और इस घटना से बड़े पैमाने पर पर्यावरण का नुकसान होता है। इससे जाहिर होता है कि संबंधित एजेंसी को इस ओर विशेÂाा ध्यान देने की जरूरत है। सरकार द्वारा वन्य संसाधनों की रक्षा के लिए हरित कानून को सख्ती से लागू किए जाने की जरूरत है, हमारे पास कानून तो बने हैं लेकिन हम उन्हें सख्ती से क्रियान्वित नहीं करते हैं। प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन हेतु ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है। देश में धड़ल्ले से नियमों को ताक पर रखकर प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है लेकिन हम कोई कार्यवाही नहीं करते हैं।

दुनिया के तमाम देश इस बात से चिंतित हैं कि अगर ग्लोबल वार्मिंग को यहीं नहीं थामा गया तो जल्द ही दुनिया गरीबी और भुखमरी की चपेट में आ जाएगी और एक अरब से ज्यादा लोगों पर इसका सीधा असर पड़ेगा और सबसे ज्यादा असर दक्षिण एशिया में पड़ेगा। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इसके प्रति चिंता व्यक्त की है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक दोÂाालै वो देश हैं जो आज सबसे ज्यादा इसका शोर मचा रहे हैं। यूरोप के विकसित देशों और स्वयं अमेरिका ने पिछली सदी में जबरदस्त औद्योगीकरण करके दुनिया को इस हाल में पहुंचाया है, लेकिन आज ये सब देश मिलकर भारत और चीन को अपनी औद्योगिक नीति बदलने को कह रहे हैं और मोदी जी ने इसी के तहत संयुक्त राÂट्र महासभा के अपने संबोधन में जलवायु का न केवल जिक्र किया था बल्कि यह भी कहा था कि हम इसकी संवेदनशीलता को भी जानते हैं और ग्लोबल वार्मिंग के चलते दुनिया के कई इलाकों में फसल उत्पादन में कमी हो रही है। यह भविÂाय में इस संकट के और गहराने की आशंका है और इसके लिए अगर कोई मजबूत और त्वरित कार्यवाही नहीं की गई तो यह संकट पूरे विश्व में फैल जाएगा।

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राÂट्र के मसौद के अनुसार पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन कम करने पर सहमति बनी थी लेकिन यह कैसे होगा इस पर पिछले दो दशकों से बिना किसी नतीजे में माथापच्ची जरी है इस काम में सबसे बड़ी बाधा धन की कमी है जिसे पर्यावरण हितैÂाालै प्रौद्योगिकी के विकास पर खर्च किया जाना है। इस पर 2020 तक प्रतिवÂाान 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किया जाना है, इस विÂााय पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है।

महाराÂट्र में बैल गाड़ी दौड़ प्रतियोगिता का खेल पुराने समय से चलता आ रहा है यह दौड़ महाराÂट्र के हर गाँव में होती है। इस प्रतियोगिता पर किसानों को कोई आपति नहीं थी जबकि इसमें भाग लेने वाले बैलों को किसान अच्छी तरह से पालते हैं और उनकी देखभाल करते हैं यह प्रतियोगिता एक पारंपरिक खेल था पर एनजीओ ने जानवरों पर अत्याचार का मुद्दा उठाकर खेल पर रोक लगाने की मांग की और इस बैलगाड़ी दौड़ प्रतियोगिता पर रोक लगा दी गयी। जहां एक ओर बैलगाड़ी प्रतियोगिता पर रोक लगा दी वहीं दूसरी तरफ घोड़दौड़ अभी भी देश के कई हिस्सों में रेसकोर्स मैदानों में चालू है, मेरा कहना है कि यदि इस बैलगाड़ी दौड़ प्रतियोगिता से जानवरों पर अत्याचार हो रहा है तो इसमें घोड़दौड़ प्रतियोगिता पर रोक क्यों नहीं लगी?अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि महाराÂट्र में पारम्परिक रूप से चली आ रही बैलगाड़ी दौड़ प्रतियागिता पर रोक को यथापूर्व हटाए जाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने की कार्यवाही सरकार द्वारा की जाए।

इको सेंसेटिव जोन देश के कई भागों में हैं जो कि निश्चित रूप से पर्यावरण के रख-रखाव के लिए बनाए गए हैं। लेकिन वर्तमान समय में इन इको सेंसेटिव जोन से इन क्षेत्रों में जाने वाले नागरिकों

एवं पर्यटकों को बहुत सी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मेरे संसदीय क्षेत्र में प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्र माथेरान है। यह क्षेत्र ब्रिटिश काल से ही इको सेंसेटिव जोन घोÂिात कया गया है और इको सेंसेटिव जोन घोÂिात होने की वजह से यहां पर डीजल गाड़ियों एवं अन्य वाहनों के चलने पर रोक लगी हुई है। माथेरान 25 हजार का आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ के बच्चों को कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता है। यहाँ इन सब वाहनों के नहीं होने से स्थानीय लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सेंसेटिव जोन होने के कारण यहां के लोग अपने मकानों की मरम्मत नहीं कर सकते हैं। यहां आवा- गमन के लिए कोई भी सुविधा नहीं होने के कारण यहां पर्यटकों को ले जाने के लिए हाथगाड़ी का उपयोग होता है। जो नवजवान रोजी रोटी के लिए हाथ गाड़ी खींचने का काम करते हैं वह अपनी थकान को दूर करने के लिए नशा करते हैं।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि माथेरान जैसे हिल स्टेशन में बैटरी से चलाए जाने वाले रिक्शा शुरू करने की अनुमति दी जाए और पर्यटकों को आकर्Âिात करने हेतु वहां रोप वे की सुविधा दी जाए जिससे नवजवानों को रोजगार मिलेगा और केन्द्र और राज्य सरकार से मैं इसके लिए आर्थिक मदद की मांग करता हूं।

□SHRI RAM PRASAD SARMAH (TEZPUR): I come from Tezpur Constituency of Assam. I fully support the Demand for Grants to the Ministry of Environment and Forests.

Assam, once used to be known as "Forest State" with richest bounty of forests and wild life and different types of flora and medical plants. But during the last 15 years of Congress rule in the State there has been systematic denodation of forest and killing of wild life. The world famous one-horn rhino is facing serious threat from poachers, as many as 79 rhinos have been killed in only last three years. Sand mining and illegal quarrying of valuable forest mines and minerals have been going on unabated and the State Government is a mute spectator. Smuggling of rhino horn, tiger skin, keko reptile and other wild life parts is indiscriminately going on in Assam, Kaziranga, Manas, Pobitara and Orang known for one horn rhino serious threat due to encouraged encroachment.

Tribal communities living in forest villages in forest areas are not given the rights by the State Government, as is required under the Forest Rights Act, 2006.

Therefore, I would request the Ministry to take strong steps to check forest demarcation, killing of rhinos and smuggling of animal parts and also stop illegal mining and smuggling of sand and other valuable minerals in the State. I also request the hon'ble Minister to embark on large scale plantation of trees in the areas where forest cover has been reduced due to illegal felling of tree.

The NHAI has not yet planted trees filled during 4 laning of roads in Assam.

The Environment & Forest Ministry should direct the NHAI to plant road vide trees on the stretch of 4 laning road. I may add that about 3 lakh valuable and fully grown up tree were felled by NHAI during lane conversion.

***SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL):** We, as a nation, have long ignored climate change and its effects on our environment in the name of 'development', but it's time to reconsider our objectives and goals so that they are more in sync with our biodiversity. After 100 days of the new government, a four-member high-level committee headed by former Cabinet Secretary T.S.R. Subramanian was formed to examine five laws; The Environment (Protection) Act, 1986, the Forest (Conservation) Act, 1980, the Wildlife (Protection) Act, 1972, the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. The order says that the committee would 'recommend specific amendments needed in each of these acts to bring them in line with current requirements to meet objectives.' That does not sound very encouraging . Due to the launch of the single-window environment and forest clearance system, it is highly doubtful if the government will swing in favour of environment protection and preservation.

I will concentrate my speech broadly on two things; rampant use of non-biodegradable material (namely, plastic) and effects of climate change.

Plastic was produced for the first time in 1856, during the industrial revolution. It was hailed as a major advance in the world industry. Today, we find plastics everywhere, pet bottles that contain beverages, polyester, kitchen utensils, packaging material, electronics and much more.

According to an industry summary by Indian Brand Equity Foundation (IBEF), currently, the Indian plastics industry is spread across the country, employing about 4 million people and over 2,000 exporters. It operates more than 30,000 processing units, of which 85 per cent to 90 per cent are small and medium enterprises (SMEs).

The President of All India Plastic Manufacturer's Association (AIPMA) has stated that the per capita consumption of plastic is 9.7 kg per person in India, while the global average is 27 kg. We are still far away from the global average but the consumption is steadily increasing. As the standard of living of people goes up, they start consuming more FMCG products which use plastics for packaging their products quite liberally.

This is a worrying trend because once plastic is created, it cannot be destroyed. 'Recycle plastics' is the new motto of the Plastic industry. Industry leaders has even gone so far as to say that plastic bags are 'environment friendly' in a statement issued by AIPMA on 8 February 2015. I would like to ask them whether there is any way to destroy unused plastic in an environment friendly manner?

Let me put forward a worrying scenario which is unfolding right now far in the Pacific ocean. National Geographic recently reported a story about 'The Great Pacific Garbage Patch' which proves to be quite an eye-opener. The Great Pacific Garbage Patch, also known as the Pacific trash vortex, spans waters from the West Coast of North America to Japan. It is full of non-biodegradable garbage which is stuck in a vortex, in the middle of the ocean. The garbage patch is estimated to be as big as the state of Texas.

The report says, 'A plastic water bottle discarded off the coast of California takes the California Current south toward Mexico. There, it may catch the North Equatorial Current, which acrosses the vast Pacific. Near the coast of Japan, the bottle may travel north on the powerful Kuroshiro Current. Finally, the bottle travels westward on the North Pacific Current. The gently rolling vortexes of the Eastern and Western Garbage Patches gradually draw in the bottle.'

The amount of debris in the Great Pacific Garbage Patch accumulates because much of it is not biodegradable. Many plastics do not wear down; they simply break into tinier and tinier pieces. These 'microplastics' are then ingested by sea creatures and get stuck in plants under the ocean. This is turn goes further up the food-chain and ends up in restaurants that serve sea food. Since these are micro-plastics, they are difficult to see with the naked eye. These are getting ingested by humans too.

Nobody knows exactly how much plastic is stuck in that humongous vortex, since it's really difficult to estimate the quantity. Scientists have collected up to 750,000 bits of microplastic in a single square kilometer of the Great Pacific Garbage Patch- that's about 1.9 million bits per square mile. Most of this debris comes from plastic bags, bottle caps, plastic water bottles, and Styrofoam cups. About 80% of the debris in the Great Pacific Garbage Patch comes from land-based activities in North America and Asia. Trash from the coast of North America takes about six years to reach the Great Pacific Garbage Patch, while trash from Japan and other Asian countries takes about a year.

Instances like these should immediately ring some alarm bells. The recent Kashmir and Uttarakhand floods are examples of what happens if we are flippant about protecting our environment and forests. Even after those floods, the lessen seems to be lost on us. The state government there has cleared 26 projects which will cause massive deforestation. The Central Government has given a green signal for removing the requirement of forest clearances around border areas, stating national security and defence.

Climate Change is a slow process. It is not immediately recognizable but the effects are all around us. The change in the behaviour of monsoons and the resulting crop damage being the biggest one of them. April 22 was celebrated as Earth Day throughout the world. On that day, a group of US scientists opined that a quarter of the total fossil fuel available on earth needs to remain inside the earth. Scientists warn us that climate change would accelerate beyond our control, threatening our survival and everything we love. We need to act fast to keep global temperature rise under the unacceptable dangerous level of 2 degrees C, by phasing out carbon pollution to zero. To achieve this, we must urgently forge realistic global, national and local agreements, to rapidly shift our societies and economies to 100% clean energy by 2050.

During a student interaction at Assam last year, our Prime Minister said: 'Climate change? Is this terminology correct? The reality is this that in our family some people are old. They say this time the weather is colder. And, people's ability to bear cold becomes less. We should also ask is this climate change or have we changed. We have battled against nature. That is why we should live with nature rather than battle it. ' In a United Nations conference on climate change, mere days after making this comment, Mr. Modi was a no show. Thoughts translate into action. It would be unsurprising if the Damodardass government goes on to include these untruths in curriculum across the country. This is a very real fear.

You see reports about torrential flooding and other extreme weather on the news pretty much all of the time- some may argue, but it looks like climate change caused by human activity is indeed a real thing. Polar icebergs melting at increasingly alarming rates will cause sea levels to rise in the future. On the flip side of the coin, the fire season in the hot, dry regions of the west coast of North America lasts roughly 75 days longer than it did a decade ago.

The world of climate governance is in a flux. A series of extreme weather events, from India to Australia, to the Philippines, continues to periodically ring alarm bells on climate change. The rolling release of the inter-governmental Panel on Climate Change's Fifth Assessment report provides ever more sober calls for the need for action.

Yet, in most countries, and in global dialogue, levels of political attention to climate change are declining, crowded out by the financial crisis and other short term crises. At the same time, more countries than ever before- covering an estimated 67% of global emissions - have in place some form of national legislation or strategy to address climate change. There has also been a proliferation of informal local initiatives and transnational networks.

The United Nations Climate Change Conference, COP21 or CMP11 will be held in Paris, France in November 2015. It is expected to be one of the biggest climate change conferences in the world, where 196 countries will meet to sign agreements regarding reduction of carbon emissions. This is a historic opportunity for India to show that we are serious about climate change and willing to take a stand. We are being increasingly seen as a pro-industry and anti-environment nation. Especially after this government decided to rapidly give environmental clearances on one hand and ban organizations like Greenpeace on the other, we are not seeing welcome signs which say otherwise. I urge the government to make a proper plan before going to this conference and share it with the House. There needs to be proper consultations regarding this mater and we must take a united stand against climate change.

***KUMARI SHOBHA KARANDLAJE (UDUPI CHIKMAGALUR):** The concept of Ecologically Sensitive Areas (ESAs) in the Western Ghats has been a contentious issue from the start. Dr. K. Kasturirangan Committee Report earmarked 59,940 sq. km (37%) of the Western Ghats as ESAs. The MoEF outlines a draft Notification based on this Report on March 10,2014, identifying a total of 56,825 sq. km in six states that straddle the Western Ghats. Karnataka represents the biggest chunk of the ESAs. The proposal to declare 20,668 sq. km of Karnataka's Western Ghats as ESAs has raised fears of relocation among local communities, although the report only recommends banning activities such as mining and thermal plants in these areas.

Kasturirangan Committee Report has faced opposition from various quarters including environmentalists and people living in and around the Western Ghats belt. People living in the vicinity were in the grip of fear that the implementation of the Report would adversely affect their livelihood. Government of Karnataka had requested the Union Government to keep habitations, plantations and agricultural areas in villages out of the purview of the ESAs. Of karnataka's total geographical area of 1,91,791 sq. km Western Ghats taluks measure up to 44,448 sq. km, including 1,576 villages identified as ESAs. I suggest that the Government should adopt a more liberal approach while dealing with this sensitive issue. Recently, Karnataka Government has sought extension of time to give its comments on the K. Kasturirangan Report on conservation of Western Ghats to the Centre. So far, only Kerala has submitted its objections to the Centre.

The magnanimity of pollution has been slowly, but certainly acquiring serious proportions. Protection of environment has not been accorded due

priority by the state governments, particularly in view of fact that without their support and cooperation, it would not be possible for the Government alone to ensure environmental protection. It may not be practically feasible for the Government alone to fight and tackle the menace of rapid rise in pollution witnessed all over- air, water, land, noise, etc. throughout the length and breadth of the country. Necessary cooperation and support from the state governments is definitely required in this regard. Government will always find it difficult to control the rapid pace at which the health of environment and conditions of natural resources is deteriorating day by day unless and until the state governments are made effective partners in protection of the environment.

One disturbing news appearing in the media is that air pollution was the 5th biggest killer in India, other reports related to hazardous smog like situation in the making in the Indian cities due to excessive air pollution. As per the report appearing in the media, close to half of cities are reeling under severe particular pollution while newer pollutants like Nitrogen Oxide, Ozone and air toxins are worsening public health challenge.

As per the Annual Report 2012-2013 of the Ministry, 131 cities exceed the permissible limit of PM10 which is as high as 62 per cent and 19 cities exceed the level of NO2. Continuous growth of municipal solid waste generation in urban areas of the country has also emerged as one of the biggest polluters of environment. According to a recent Survey of Central Pollution Control Board CPCB) in 60 major cities of the country, the total municipal solid waste generated is 50,592 tons per day, while the country wide generation is estimated to be of the volume of 1,50,000 tons per day. Out of the above, only a small portion is being processed and the remaining waste is dumped in an open air leading to environmental and health hazards in cities and towns. As per CPCB assessment, India generates 56 lakhs tonnes of plastic waste annually. Out of the total plastic waste generation in the country only approximately 60% is collected and recycled, while the rest remain uncollected and littered.

I suggest that the Ministry should conduct a Study of its own, on mortality due to air pollution in major Indian cities and in case the Study confirms the findings of the Report published by the Centre for Science and Education (CSE), take urgent remedial measures to prevent the adverse impacts of air pollution on health of citizens.

I wish to express my serious concerns over the rapid rise in all types of pollution and feel that unless some serious and effective steps are taken by the CPCB, the situation would continue to go from bad to worse; assume alarming proportions in days to come and prove to be detrimental for the entire country. Adequate expansion and strengthening of monitoring and enforcing agencies is the need of the hour so that the situation does not deteriorate further. Efforts should also be made to further increase the number of Zonal Offices of CPCB so that effective and successful monitoring of projects/polluting units could be undertaken.

I appreciate the measures taken by the Ministry to streamline the environment and forestry clearances which would facilitate speedy execution of large developmental projects. Smaller projects involving requirement of forestry clearance for some 5 kms. or 10 kms roads, building hospitals have been hanging fire since long. I feel that there is a need to adopt positive approach to give clearance to projects which are badly required for development.

Public hearing has been made mandatory in the schemes of things of according Environmental Clearance/Forest Clearance for some of the projects particularly those which affect the local inhabitants, the fact is that public hearing is not conducted in an objective and impartial manner. Often public hearing becomes a state managed and an eye-wash show conducted in the presence of the project proponents where their representatives use it as a platform to persuade, convince and coax the affected public to give their nod for the project to the detriment of their interest and welfare. Such instances give rise to discontentment among the public and sometimes also result in protest putting the entire project in jeopardy. Government must take necessary measures to curb such malpractices in public hearing so that public hearing serves the purpose for which these are intended. Genuine concerns of the people must find place in the environment management plan and project proponents take necessary preventive and curative measures to address the genuine concerns of the public. I suggest that the Ministry should take up monitoring in a few sample cases of actual implementation of various safeguards for public hearing laid in EIA Notification so as to find out as to what extent the provision of EIA Notifications are being adhered to in actual practice.

There is an urgent need to save the species facing extinction and reduce significantly, if not eliminate altogether, incidents that kill animals like man-animal conflict, rail or road accidents etc. the Ministry must takes all necessary measures, local inhabitants should be involved in a big way for providing protection to the wild animals, as well as, to forest cover. The incidents like man-animal conflict, death of elephants due to rail accidents, etc. continue unabated, the Ministry should conduct a comparative study so as to know as to what extent the measures taken have helped reduce killing of animals.

SHRI NAGENDRA KUMAR PRADHAN (SAMBALPUR): Sir, these Demands for Grants consist of three parts – the first one deals with forests, another with environment and the third one deals with climate change.

Let me begin with environment. Now, inklings of some of the projections have started manifesting in India in the form of devastating natural calamities, flash floods in Uttarakhand, back to back floods in Kashmir, severe cyclonic storms like Phailin and Hudhud. They are some of the recent instances. The cycle of monsoon has gone erratic affecting paddy cultivation in large parts of the country. The natural flow of major rivers including the Ganga, Yamuna, Mahanadi, Brahmani in Odisha are showing a declining trend. The condition of lakes, rivers and other water bodies continues to deteriorate day by day despite efforts made by the Government. Worsening air quality in the country in general and in Delhi in particular has been making headlines earning ignominy at the national andinternatinal levels so much so that some of the countries have reportedly reduced the tenure of their diplomats in Delhi and many Embassies have installed air purifiers in their offices and residences of their diplomats.

A study 'Lower Pollution, Longer Lives' published in the Economic and Political Weekly on 21st February 2015 has estimated that India can save up to two billion life years and about 3.2 years per person if 660 million people living in areas exceeding the National Ambient Air Quality for PM 2.5 pollution can breathe air which meets air quality standards. This should be a clarion call to proactively and effectively act in a time bound manner before it is too late because environmental damage beyond a certain level becomes irreparable and irreversible. It is most unfortunate that in a recent response filed in the High Court of Delhi, the Government has stated that there is no Action Plan so far to address the critical challenges of air

pollution in the Capital. So, I want a clarification on this point. Not only metropolitan cities but even Tier-II, smaller towns and cities are found to be reeling under the severe impact of pollution on all environmental parameters.

The State is constitutionally mandated to protect and improve the environment and safeguard our forests and wildlife. The Constitution recognises the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife. The principle of sustainable development is incorporated as an integral component of the Right to Life under Article 21 of the Constitution. Despite all this, the challenges of environmental degradation remain unaddressed.

The environmental degradation which is considered to be a major contributing factor in loss of agricultural productivity, because ecological degradation affects soil fertility, quantity and quality of water, air quality, forests, wildlife and fisheries etc. The worst sufferers of forest degradation are the poor tribal societies who live on natural resources. The loss of environmental resource base often results in these groups being made destitute which leads to alienation and exhaustion of large segment of our population.

Coal-based thermal power plants are one of the most polluting ways of producing power in the world. In India, about 70 per cent of the power is provided by coal. The high dependence on coal, however, comes at a significant cost to the environment. Not only do coal-based thermal power plants result in large scale emission of particulate matter and other pollutants such as SO2, NOx and mercury but they also produce 170 million odd tonnes of poorly managed fly ash and consume tremendous quantities of water in the course of their operations. I want to draw the attention of the hon. Minister through you whether he is thinking of any alternative like renewable energy and so on. I would like him to provide some information on this.

Now I come to the second part, that is, Forestry. The National Forest Policy, 1988 envisages the national goal of having minimum of 33 per cent of the total land area of the country under forests or tree cover. The break-up of the forest and tree cover as per India -- State of Forest Report, 2013 shows that the total forest and tree cover of 24.01 per cent comprises of 2.54 per cent of very dense forest, 9.70 per cent of moderate dense forest, 8.99 per cent of open forest and 2.78 per cent of tree cover. The percentage of very dense forest continues to be at 2.54 ever since the year 2007. Thus, the forest cover in true sense of the term as per the 2013 Report constitutes only 12.2 per cent of the total geographical area of the country.

National Afforestation Programme was launched in 2002-03 to improve forest cover and livelihood of the people living in and around forest areas for which an outlay of Rs.2,500 crore was approved for the Twelfth Five-Year Plan. Out of that, an amount of Rs.663.45 crore, approximately 1/4 th of the total approved outlay, was spent during the last three years. This year the allocation has been reduced from Rs.243.8 crore at the BE level in 2014-15 to Rs.100 crore. In all likelihood, the entire outlay earmarked for National Afforestation Programme for the Twelfth Five-Year Plan is not going to be fully utilised.

The funding pattern of the National Afforestation Programme is likely to undergo a change with the share of Centre and States at 50:50 from 2015-16 onwards instead of existing 100 per cent Central share. This change in funding pattern would definitely affect the progress of the programme as the States, owing to their own priorities, may not like to contribute to this programme as expected by the Ministry. Therefore, my humble request to you is that the earlier condition of 100 per cent funding by Government of India should continue to exist.

Of the total BE allocation of Rs.80 crore for 2014-15, only Rs.3 crore could be utilised. Yet, this year outlay for this scheme has been kept at Rs.64 crore. The hon. Minister should explain during his reply as to how this money would be spent.

Is it a fact that an amount to the tune of Rs.38,000 crore is lying with in Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA)? As per the directions of the Supreme Court, the Ministry is supposed to release the funds only to the extent of ten per cent of the principal amount of about Rs.23,800 and that also from the interest accrued. This year although the Ministry was authorised to release about Rs.2,400 crore, it could release only Rs.1,100 crore. In this connection, what is the position of this CAMPA fund?

In reply to a question the hon. Minister for Environment, Forests and Climate Change stated that one lakh hectares of forest land had been diverted for mining projects in Chhattisgarh State which is the largest patch of land. Other States must be doing things that way. Thank you.

*__SHRI K. PARASURAMAN (THANJAVUR):__ Thank you for being given an opportunity to express my views on the need to tackle environmental degradation in our country. First of all, I would like congratulate our Hon. Finance Minister for his effort, to tackle environment degradation. He has laid emphasis on the clean energy taken allocation for electrical vehicles and exempted effluent treatment plants from paying service tax. But at the same time, it is worrying that our Hon. Finance Minister has made cut in the allocation of funds for the Ministry of Environment, Forests and Climate Change to Rs.1681.60 crores from Rs.1764.60 crores in the ministry's revised estimate for 2014-2015. Environmentalists in India have expressed their anguish and alarm over this cut in the allocation and they fear that it would affect more environmental programmes in the country, which would result in the failure to address the worsening pollution and vulnerability to climate change. So, I humbly request our Hon. Finance Minister to allocate more funds, as in it western countries, for more research programmes on pollution, climate change, renewable energy and solar for rural use.

Yet another worrying and shocking matter in the Budget is that the funding to the National Mission on Sustainable Agriculture has been reduced by 80 per cent this year, from 15 billion rupees to 3 billion rupees. Agriculture is our primary source of greenhouse gas emission in India because of paddy cultivation, which produces methane through extended flooding fields and the use of cows to farm small plots of land.

Farming is also highly at risk from climate change impacts, particularly changing rainfall patterns, floods, drought and storms. I hail from the Cauvery Delta region where agriculture is main source of living of more 80 per cent of population.

I request our Hon. Finance Minister to allocate more funds to the Ministry of Environment and also allocate sufficient funds for states to implement programmes on pollution, climate change and sustainable agriculture, renewable energy, solar for rural use etc.

I request our Hon. Minister that Bio-diversity is one of the important aspects we have to consider seriously because among the 25 Hotspots present

globally, India plays vital role in the presence of varieties of fauna and flora. Gangetic plains, Gulf of Mannar Reserves, mangrove forests and western Ghats are the diversified ecosystem in India. Migratory birds which come even from Syberia to our country should be monitored carefully. Environmental pollution, poaching, destruction of habitat are the reason for bio-diversity loss.

The Vaduvur birds sanctuary is under my constituency. It should be protected to maintain the migratory birds visit from various places. If the Ministry of Environment and Forest take initiative, vaduvur bird's sanctuary will become in future as one of the important tourist attractive place as like Kodiakkaraji, Vedanthangail and Udhayamarthandapuram in Tamil Nadu.

Hence, I request the Hon. Minister for Environment and Forest to take necessary action to make the Vaduvur bird's sanctuary as one of the important Research centre as like Dr. Salim Ali's Ornithological Research Centre. It paves the way to create awareness among the public about birds bio-diversity and also to produce more number of young scientists in our country.

The Kodhandaramar Temple with beautiful Ramar idol locate in the banks of Vaduvur birds sanctuary attract thousands of pilgrims from various parts of our country. If the Tourism Ministry establishes Boat club in Vaduvur lake it will also provides facilities to the school children, pilgrims, tourist, environmentalist and general public which in turn would generate revenue to the government.

Finally, I request our Hon. Finance Minister to allocate more funds to the Ministry of Environment, allocate sufficient funds for states to implement the research centre in Vaduvur, Tamil Nadu and to develop Vaduvur Birds Sanctuary.

***SHRI ADHALRAO PATIL SHIVAJIRAO (SHIRUR):** I am thankful for giving me an opportunity to express my views on this important issue. I am sure, with the help of the balanced budget presented by the Government, the Ministry of Environment and Forests will function more efficiently and smoothly. I wish to draw kind attention of the Government towards two important issues pertaining to violation of Forest Act, 2006 with the help of Lokshashan Andolan and banning of bulls to participate in the ritual functions in the State of Maharastra.

Forest is a unique natural component of environment system. Aforestation is necessary for enrichment of forest but more important is protection of existing forest. Forest has to be protected from illicit felling of trees, encroachment, grazing, hunting and fire. Existing forest area is first to be protected from encroachment and then forest area is to be enriched by planting of seedlings. Even at places merely protection encourages natural regeneration. Increased population, industrialization and decreased forest produce are major reasons for forest degradation. Illegal encroachment on forest land should not be encouraged or regularized. Indirectly, it supports forest offences and demoralizes forest department. The forest were declared as reserved forest by following due procedure in which rights, privileges of peoples in forest have been enquired and settled.

The scheduled Tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 and Rules 2008 is an Act to recognize vesting of the forest rights and occupation in forest land in for forest dwelling scheduled tribes and other traditional forest dwellers who have been residing in such forests for generations but whose right could not be recorded, to provide for a frame work for recording the forest rights so vested of the nature of evidence required for such recognition of vesting in respect of forest land. In this Act 'forest dwelling scheduled tribes' means the members of community of the Scheduled Tribes who primarily reside in and who depend on forests lands for bona-fide livelihood needs and includes the Scheduled Tribe pastoralist communities.

Similarly, 'other traditional forest dwellers' means any member or community, who has for at least three generations prior to the 13th day of December, 2005 primarily resided in and who depend on the forest or forests land for bona fide livelihood needs.'

This Act gives only right over the forest land to Scheduled tribes and other traditional forest dwellers. Scheduled procedure has been laid down for giving these rights to them. This procedure mainly includes formation of village level, sub division level and district level committees and claims under this Act will be settled and decided at these committee level only. The deadline for giving legal entitlement was 13th December, 2005.

However, in part of Western Maharahstra particularly around Pune district Lokshashan Andolan is headed by Shri B.G. Kolse Patil and Shri P.B. Sawant, Preisent of Lokshashan Andolan. In this andolan, the so called activists are encroaching on forest land and claiming their rights which is illegal. These activists are creating law and order problem by coming in a mob including ladies, small children and old-aged persons so that even the Forest Department is not in a position to evict the mob and these mobs encroach precious forest land. Even the local leaders and people support them in connivance with the forest officials. It is a high time to reconsider the policy while implementing the spirit of the Act and to stop encroachment on forest land by unauthorized activists/people encroaching upon the forest land in connivance with the forest officials unauthorized by mis-interpreting the law. I urge to issue necessary directions to all the State Governments to register cases against these encroachers and to implement the law in its letter and spirit strictly so that only those people who are eligible can be benefited.

One more important issue towards which I wish to draw the kind attention is pertaining to inclusion of Bulls in the Notification dated 11th July, 2011, as wild animal published in the Gazette of India, issued by the Ministry of Environment and Forests. With the effect of Gazette, the training and performance of Bull is prohibited. As you are aware, there is a long practice since our ancestral days for performing a religious programme once in a year which also includes Bull for Bullock Cart Race in Maharahstra and Jallikattu in Tamil Nadu. However, special care has been taken during the occasion that the Bulls are not harmed during the religious programmes so conducted. These programmes were being taken at different places in Maharashtra and Tamil Nadu. However, after publication of the above Notification in the Gazette of India, participation of Bulls has been restricted and Bulls are not allowed to participate in the function by the local administration. This has hurt the sentiments of the local people.

Keeping in view the religious function involving Bulls fairs are being being performed since last hundreds of years from our ancestral days and also keeping in view the fact that the bulls are not harmed in any manner during the religious function, the name of the Bull may be excluded from the list of animals by bringing out necessary amendment to Section 22 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960) and accordingly the Notification dated 11th July, 2011may be amended to that extent.

□**श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला)**: मैं बजट में पर्यावरण, वन एवं क्लाइमेट चेंज मंत्रालय संबंधी अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश में 5871 सक्वेयर किमी एरिया वनों की दÂिट से बड़ा है। यह बात अलग है कि कई राज्यों में यह बढ़ा है और कई राज्यों में घटा है जैसा कि नॉर्थ ईस्ट में वनों का एरिया जो पहले 75 प्रतिशत से भी अधिक होता था वह 627 सक्वेयर किमी घटा है। भारत सरकार वनों के अन्धा-धुंध कटाव को लेकर अति गम्भीर है। इसी प्रकार से, भारत सरकार पर्यावरण व क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर भी गंभीर है।

हाल ही में जेनेवा में क्लाइमेट चेंज को लेकर जो सम्मेलन हुआ था उसमें भारत ने जोरदार ढंग से यह आवाज उठाई थी कि विकसित देशों को पर्यावरण से हो रही हानि की भरपाई करनी चाहिए और इसके लिए विकसित देशों ने यह संकल्प भी लिया था कि वे ग्रीन क्लाइमेट फंड में 10 बिलियन राशि प्रदान करेंगे। इनमें यूएस, जापान, यूके, जर्मनी, फ्रांस व स्वीडन जैसे देश शामिल थे परन्तु बड़े दुख की बात है कि इन देशों ने केवल मात्र 1.03 प्रतिशत ही ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए अपना वायदा पूरा किया। भारत ने इस बात को भी बड़े जोरदार ढंग से उठाया है। अभी 2015 में जो क्लाइमेट चेंज को लेकर पेरिस में विश्व सम्मेलन होने जा रहा है, भारत उसमें भी जोरदार ढंग से अपनी बात रखेगा। भारत ने प्रदूÂाण को कम करने की दÂिट से अपने देश की सभी नदियों को पर्यावरण से बचाने के लिए व्यापक कदम उठाए हैं जैसा कि- गंगा की सफाई के लिए व्यापक अभियान छेड़ा गया है, जिसके लिए बजट में 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी रखा गया है। परन्तु इस दिशा में अभी और ठोस कदम उठाने होंगे। क्योंकि आज भी बड़े-बड़े शहरों का 90 से 95 प्रतिशत तक सिवरेज का गंदा पानी इन नदियों में गिर रहा है। यूएनओ की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के बड़े-बड़े 20 शहर दुनिया के सबसे प्रदूÂिात शहर हैं जिनमें आज जीना दूभर हो गया है। आज हमारे देश की राजधानी को ही ले लो, आज यहां पर इतना कार्बन या इतना प्रदूÂाण है कि सांस लेना भी मुश्किल है। अगर हमने इस दिशा में कोई ठोस कदम न उठाए तो देश को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आज प्रदूÂाण हमारे देश के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। अगर हमने डीजल वाहनों से पैदा होने वाले प्रदूÂाण पर रोक न लगाई और नई टैक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी रिफाइनरीज में सुधार नहीं किया, तो हम क्लीन एनर्जी लेने में विफल रहेंगे। इसी प्रकार से, हमारे देश में कचरा मैनेजमेंट की भी एक बहुत बड़ी समस्या है और अब तो इस सोलिड वेस्ट के साथ-साथ हमारा देश ई-वेस्ट दुनिया के 5वें नम्बर पर पैदा करने लगा है। मैं बधाई देना चाहूंगा कि सरकार ने कोयले पर यू.टी 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 200 प्रतिशत प्रतिटन की है। परन्तु इससे मिलने वाली राशि को हमें अपने प्रदूÂाण को कम करने पर ही खर्च करना होगा।

अभी-अभी यूएनओ की एक रिपोर्ट आई है कि भारत को अपने देश में आने वाली आपदाओं से दस बिलियन डॉलर प्रतिवÂाऱ हानि उठानी पड़ रही है। भारत में भूकम्प से 19 मिलियन डॉलर, साइक्लोन से 447 मिलियन डॉलर, तूफानों से 727 मिलियन डॉलर, सूनामी से 1160 , बाढ़ से 4772 मिलियन डॉलर यानि की कुल मिलाकर 10 बिलियन डॉलर के लगभग प्रतिवÂाऱ हानि उठानी पड़ रही है। मोदी सरकार ने इस दिशा में ध्यान दिया है और भारत ने क्लाइमेट चेंज को लेकर हो रहे विश्व सम्मेलनों में भारत की इस प्रतिबद्धता को जताया है कि वह आने वाले 5 वÂ ाों में 9 बिलियन डॉलर अपने आपदा प्रबंधन पर खर्च करेगा। यूएनओ रिपोर्ट्स में इस बात का भी खुलासा किया गया है कि इगर हम आपदा प्रबंधन पर 6 बिलियन डॉलर खर्च करते हैं तो हम आपदाओं के मामले में 360 बिलियन का फायदा उठा सकते हैं। इससे हमारी आपदाओं में 20 प्रतिशत की कमी होगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश के 4.8 मिलियन भारतीय पर्यावरण के कारण होने वाली आपदाओं से पीड़ित हैं। अगर हमने युद्धस्तर पर इस दिशा में कदम न उठाए तो 2030 तक भारत के 19 मिलियन लोग प्रभावित हो सकते हैं।

आज नेपाल में क्लाइमेट चेंज के कारण एक भयंकर आपदा आई है। मैं बधाई देना चाहता हूं, अपने प्रधानमंत्री को, जिन्होंने पूंट पर आकर इस मामले में लीड किया है और नेपाल के पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाई है। उन्होंने आज भी अपने कई केन्द्रीय मंत्रियों को बिहार, पश्चिम बंगाल व उत्तर प्रदेश के साथ लगे इलाकों में पीड़ितों को राहत पहुंचाने में पहल की है।

हमारे देश की 50 करोड़ जनता हिमालय रीजन के क्षेत्र में रहती है। अगर हमने क्लाइमेट चेंज की ओर युद्धस्तर पर ध्यान नहीं दिया तो जिस प्रकार से, हमालय की तलहटी में चेंजिज आ रही हैं जिसके कारण हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और उसके परिणामस्वरूप हमारी नदियों में उफान आ रहा है। अगर हम समय पर नहीं चेते तो तटों पर रहने वाले हमारे शहरों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। संयुक्त राÂट्र संघ ने यह भी चेतावनी दी है कि 21वीं सदी के अन्त तक दुनिया के ग्लेशियर ग्लोबल वार्मिंग के कारण इतना पिघल सकते हैं कि समुद्र तल का स्तर 85 सेंटीमीटर तक बढ़ जाए जिसके कारण दुनिया के समुद्र के किनारे पर रहने वाले बड़े-बड़े नगरों को भी खतरा पैदा हो सकता है। हमारे देश में भी जिस प्रकार से तमिलनाडु के अंदर कई बार सूनामी आई है। यह सब हमारे देश में जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, यह एक मुख्य कारण है। आज हमें अपने देश में एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग के लिए संस्थागत ढांचा खड़ा करने की जरूरत है। मैं तो चाहूंगा कि जो वाहन ज्यादा प्रदूÂाण पैदा रकते हैं उनके प्रदूÂाण कंट्रोल के लिए नई-नई टैक्नालॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए और यहां तक कि ऐसे वाहनों पर टैक्स भी लगाया जाना चाहिए। मैं चाहूंगा कि सरकार अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रदान कराने की दिशा में भी कदम उठाए ताकि बड़े-बड़े शहरों में सांस लेना आसान हो सके।

मुझे बड़ी खुशी है कि भारत सरकार वनों को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठा रही है क्योंकि अन्धा-धुंध वनों के कटान से ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिल रहा है। हालात यहाँ तक पहुंच गए -

"अब तो थक गए पंख भी उड़ती चिड़िया के,

क्योंकि एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की दूरी इतनी तो बढ़ गई "

हमने अपनी प्रकृति का विनाश इस ढंग से किया है कि अब घरों में न कहीं चिड़िया चहकती हुई नजर आती है और न ही कहीं बईयों के घौंसलें नजर आते है।

अन्त में, मैं उन सभी मदों का समर्थन करता हूं जिन मदों के अंतर्गत पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालयों के लिए अनुदानों का प्रावधान किया गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार भारत की 125 करोड़ की जनता को प्रदूÂाणमुक्त करने एवं खुली हवा में सांस दिलाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी।

SHRI RAHUL SHEWALE (MUMBAI SOUTH CENTRAL): Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me time to speak on Demands for Grants in respect of Ministry of Environment, Forests and Climate Change.

First of all, I would like to enlighten this august House on one of the important issues concerning the overall development of wildlife sanctuaries in the country. Many precious species of wildlife are on the verge of extinction due to negligence and poor planning for the last so many years. Amongst the other wildlife species, I had been drawing attention of the Government to the extinction of resident Gyps species of vultures in the country. The number of vultures of Gyps species is declining day by day due to negligence in their conservation. Some NGOs like Bombay Natural History Society (BNHS) are working for conservation of vultures in the country in collaboration with the State Governments. Breeding Centres of vultures are being set up by the BNHS at various places in Haryana, Rajasthan and other States.

In the absence of financial aid from the Central Government, the maintenance and development work of the breeding centres are not going on well. The BNHS has also submitted its detailed proposal for conservation of vultures to the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for grant of Central financial assistance to implement their programme in the country which is awaiting approval for long.

In this connection, I would like to submit that multi-dose of veterinary use of some medicines like declofenac is also one of the reasons for extinction of this precious Gyps Vulture. I suggest immediate ban on sale of multi-dose vials of declofenac medicine which may be imposed to prevent its misuse in cattle treatment in the country.

My request to the Minister of Environment, Forests and Climate Change is to look into the matter seriously and raise the financial aid to the States and NGOs who are working for the noble cause of preservation and protection of wild species, especially conservation of vultures in the country.

There are many important issues of my constituency Mumbai South-Central which are pending for a long time for environment clearance with the Ministry of Environment, Forests and Climate Change. I would like to point out some of them briefly.

The first is the construction of a coastal road in Mumbai. Most of the coastal lines in various cities in the country are having coastal roads, whereas the most important city of Mumbai does not have it so far. Mumbai has a beautiful coastline. There is a dire need for construction of a 36-kilometre road along the coastline by reclamation in sea. This is pending due to non-clearance by the Environment Ministry for a long time. It should be expedited immediately.

Another issue is of modification of policy guidelines for implementation of slum rehabilitation scheme in CRZ-II areas. Comprehensive proposals are being submitted by the Maharashtra State Government to allow increase in permissible FSI in the slum rehabilitation schemes in CRZ-II areas at par with those in non-CRZ areas for development of slum areas in Mumbai. I request the Minister of Environment, Forests and Climate Change for early action and finalise the modification of policy guidelines for implementation of slum rehabilitation schemes in CRZ-II areas in Greater Mumbai.

There is an urgent need to amend and modify the disparities in CRZ Notification, 2011 pertaining to some of the issues like classification and redevelopment of Koliwada and Gaothan areas; redevelopment of dilapidated, cessed and unsafe buildings in Mumbai; reconstruction and repair works, belonging to fishermen and other local communities; CRZ clearance for Mumbai Metro Rail Line 2, Charkop-Bandra-Mankhurd; rationalisation of boundaries of Great Indian Bustard Sanctuary; and construction of bridges on the River Mithi at Mahim, Causeway, Dharavi, Vaitarna and Tansa.

There are many issues of Mumbai city and Maharashtra State which are pending with the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for environment clearance and granting financial aid.

The Earth Day has been celebrated on 22nd April, 2015 around the world. It is our prime duty to spread awareness of ecological balance to make our surroundings neat and clean. I appeal to the hon. Minister to increase the Central funds to the States for implementation of environment awareness campaign properly. I also request for quick disposal of proposals of the State Government at the end of the hon. Minister of Environment, Forests and Climate Change for overall development and nation building.

Thank you.

SHRI THOTA NARASIMHAM (KAKINADA): Thank you very much for giving me this opportunity. I would like to bring to your kind notice the environmental and climate changes occurring in our country.

The year 2015 is going to witness new challenges on climate change and sustainable development. The landmark environmental measures introduced in recent years at international and sub-national levels are being supplemented by policies in the light of current needs.

India has been one of the early implementers of National Climate Change Plan. The National Action Plan on Climate Change draws policies in mitigating and adapting to combat climate change.

On the domestic front, India has been working towards environmental safety without compromising on the goal of rapid economic growth. Landmark environmental measures for conservation of rivers, improvement of urban air quality, increasing afforestation, renewable energy technology and initiatives like Swachh Bharat Mission, Clean Ganga Plan, have helped in positive sustainable climatic development and growth.

Sir, mangroves are plants that survive salinity tidal regime and they control wind velocity. India has a total mangrove cover of 4662.56 kms. in the State of Andhra Pradesh. They are mainly found in Coringa, East Godavari, nearby my constituency Kakinada and Krishna districts. These mangroves play a pivotal role in supporting fishery production. As per 2011 assessment year, it is spread over 352 kms. in the State of Andhra Pradesh. Biosphere reserves are areas of terrestrial and coastal ecosystems which are rich in biological and cultural diversity. Sesachalam hill ranges in Eastern Ghats form part of Chittoor and Kadapa districts of Andhra Pradesh where designated biosphere reserves are immense. Our goal should be to facilitate conservation of these representative landscapes and their immense biological diversity, to achieve faster economic and human development and to provide support for monitoring research education and information exchange programmes. The State Biodiversity Board works according to the notified specific State rules in accordance with Section 63 (1) of the Biological Diversity Act, 2002.

Chairman, Sir, we have 27 protected areas in Andhra Pradesh which includes National Parks, wildlife sanctuaries, conservation reserves and community reserves. I would request the Government to support the protected areas by giving control assistance. I would also request the Central Government to protect the wildlife sanctuaries like Kolleru and Corinaga, which fall in Andhra Pradesh.

Under Centrally-sponsored Integrated Development of Wildlife Habitat scheme, around Rs.109.50 lakh was released for Andhra Pradesh during 2012-13. The allocation has to be increased for further development.

The Union Minister for Urban Development and Parliamentary Affairs, Shri Venkaiah Naidu Garu's ambitious Smart City Project is all set to be out by April, 2015. The Clean Ganga Project is already making steady progress. Green construction can pave the way for energy efficient buildings that are able to conserve water resources by incorporating waste management plan.

Sir, another issue which needs to be addressed is the need to mitigate and bring down the carbon emission levels to make a positive impact on global warming. Carbon Tax can be a good method in maintaining a positive impact.

My constituency Kakinada, being an industrial belt, is not untouched by the environmental issues. Most of the industrial discharges are untreated and are polluting the river and sea coast. This is the main cause of pollution. We need massive investment to set up sewage and recycle plants. I would like to request the Government to take initiatives for this along with setting up of proper garbage management system.

Chairman, Sir, I would like to request the Government to strengthen institutes like State Forest Service and Rangers College and also request to

setup one of it in my constituency Kakinada. I would also request the Indian Institute of Forest Management to deal with the issues of environment and climate change. Steps should be taken to protect and conserve forests and increase afforestation. There should be more environmental planning and coordination programmes. Institutions like Pollution Control Board should play active role in curbing different types of pollution. I would also like to request the Central Government to properly implement a National Coastal Management Programme to ensure livelihood and security to fishing community and to conserve and protect coastal stretches.

Thank you, Sir.

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY (CHEVELLA): Hon. Chairman, Sir, thank you for this opportunity to speak on the Demands for Grants for the Ministry of Environment, Forests and Climate Change.

Sir, the budgetary allocation of the Ministry belies the concern and the objectives of the Ministry's programmes and schemes. The total is just Rs.2256 crore and after devolution to States, it is only Rs.1681 crore. So, I think it deserves more importance. It is more or less the same as last year. I think the Ministry needs to be given more importance. Since it is the same as last year, I would be pointing out only the significant changes from the previous budgets.

The total expenditure on wild life preservation has come down from Rs.83 crore to Rs.47 crore. In the background of this the wild life crimes in India have gone up. I think this is something that we really need to review. A lot of species of birds and animals are becoming extinct.

A boost in prevention control and pollution management from Rs.135 crore to Rs.240 crore is really welcome. I congratulate the Ministry for this increase in the budget for pollution management. However, pollution has to do a lot with renewable energy. We have tonnes of municipal waste. We have plastic waste. We used to have *gobar* gas plants. Now we are giving more subsidy to LPG than for the promotion of *gobar* gas and biogas plants. It is said that the total biomass in India is enough to produce gas to run all the vehicles in India. It also helps our economy. We are not giving enough promotion to both the Ministry of Renewable Energy as well as this Ministry. I hope both the Ministries work together.

The other thing is that biogas is typically methane gas. But there is also a thing called producer gas which is also created from agriculture waste. We know in Delhi, there is a lot of pollution because of post-harvest burning in Haryana and other States. So the biomass gasifires can produce a gas which again can be used for fuel. I think the Ministry should promote this for pollution control.

A considerable amount of Ministry's programmes and expenditure are devoted to Mission Ganga and water related Ministries. With the Government focus on rejuvenating and cleaning water bodies, the Ministry of Environment must be giving special attention on biodiversity management, conservation, etc. which explains the boost in budgetary allocation by more than 10 times. The total allocation for biodiversity conservation programme increased from Rs.2 crore to Rs.27 crore. Immediate focus should be on wet land saving. I think Madam also mentioned that. We are actually reducing wet lands at an annual rate of 2-3 per cent.

Sir, all news is not bad news. There is some really nice and good news for a change. New species of crab spider was found in Telangana. It behaves like a crab but actually it is a spider without a web. This happened just about a month ago. The scientific community named it as 'Thomisus Telanganensis'. This is the name of this crab spider. Not only that, there are so many other species like the Coluber Bolanathi which was also discovered recently. It was almost extinct. Then there is Elachistodon westermanni. It is an egg eating snake which was long thought to be extinct. It has also been re-discovered around Telangana near Golkonda Fort. Actually, a lot of it is in Hyderabad.

In the University campuses, every quarter we find new species including several spiders. There is a lizard that was discovered. It is no wonder and not a coincidence that Mercer's Quality of Living survey rated Hyderabad as the number one city in India to live in. It rated all the cities world-wide but in India it is number one. I think one of the important factors is pollution and environment control. We have been doing well in other factors like cost of living, traffic, etc. I think the Ministry should reward the environmentally conscious cities and States. I hope the Ministry would keep this in mind.

The National Afforestation Programme has actually been reduced from Rs.28 crore to Rs.12.5 crore. I think this again goes against its very own plan of improving environment. In the background of this, let me tell you something about a programme which caught the attention of environmentalists world over and the imagination of school children in our State. It is called Haritha Haram programme initiated by the hon. Chief Minister who is fondly known as KCR. It is about 230 crore plantations in the next three years and Rs.800 crore per year is our budgetary allocation. Out of these 230 crore plants, 100 crores are in the forest and 130 crores in the non-forest areas and 10 crores are in the city of Hyderabad. We are going to spend Rs. 800 crore. About 3300 nurseries are already initiated and it is the world's largest tree plantation programme. Environment not only affects our State but also the neighbouring States. If we behave well then it helps the neighbouring States and also our country. Once again I would like to request the Central Government to help us in this project. We seek the support of the Central Government in our *Harita Haram* programme of the Telangana Government.

Sir, the Law Minister was here and the other point is regarding one very abused law and it is about the 2006 law where a tribal can actually claim right over the Forest land. It is very important that tribals have claims over the land but unfortunately it is abused more than it is used. The benefits are not going to the tribals. There is a cut off limit. If a tribal is using the land for three generations, then it becomes his, but there is no cut off date. Even today a tribal can go with an industrial backing and can claim the land of his. So, I think, there has to be a cut off date and if there is no cut off date then this has to be more seriously looked into. The law has to be tightened so that only the tribals are benefited by this law.

Sir, the Hussain Sagar lake is the most polluted lake in the country and it is in the heart of Hyderabad. The previous Government had decided to clean it. We are literally emptying it and cleaning it. That will happen in the next twelve months. Once again we need the support of the Central Government in this. I hope, the Ministry works and it is not mutually exclusive. It has to work with all the Government Departments, the Ministry of Industries, the Ministry of Water Resources, the Ministries of Surface Transport, Railways, Health and Tourism, in order to achieve its goal. The development can happen without affecting environment. The Land Bill is coming and I think, both can co-exist – development as well as environment protection. I think, the Government needs to be innovative and it has to be pragmatic also because if the Government follows the UN, then they say that India has to spend 500 billion dollars for environment protection and that is not going to happen. So, I wish the Government luck. They should

be very innovative and pragmatic in their approach. Policies need to change.

Sir, lastly I would like to give some startling facts. The Indian Blackbuck which is famous in Rajasthan where it is revered. It is found in the State of Gujarat also. There are more Indian Blackbucks in the State of Texas than both the States of India and the whole of India. There are many other examples, like there is Indian sandalwood there, but most important from our State is that we have a gene pool of Ongol Bulls. Ongol is a district in the neighbouring State. But there are more Ongol Bulls in South America than in whole of India. I think, these are some of things that we need to protect.

Thank you

***SHRI LADU KISHORE SWAIN (ASKA):**The Union Budget 2015-16 has allocated Rs.1682 crore as the total budget for the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, which wars Rs.2256 crore in the previous year. This indicates 25 per cent budget cut in this year. Within this reduced budget, now government is thinking of ensuring clean environment that includes, water, air, soil etc. The recently released Intergovernmental Panel on Climate change (IPCC) synthesis report suggests to increasingly internalize climate considerations into development planning in developing countries. The effects of global warming on the Indian subcontinent vary from the submergence of low-lying island and coastal lands to the melting of glaciers in the Indian Himalayas, threatening the volumetric flow rate of many of the most important rivers of India and South Asia. In India, such effects are projected to impact millions of lives (as has been seen in recent earthquake in Northern part of India).

In this regard, it is important to highlight that the Union Budget 2014-15 had created 100 crore National Adaptation Fund (NAF). Guidelines to operationalise this Fund are still awaited. Meanwhile, India has begun accessing funds from the Global Adaptation Fund and is ready for the Green Climate Fund (GCF) when the later is operationalized.

It is in this context that I would like to draw the attention of the Minister of Environment, Forest and Climate Change to consider following climate change issues in the budgetary provisions.

The share of Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) in National Clean Energy Fund (NCEF) transfers to various ministries was 80 per cent in Union Budget 2013-14 Revised Estimates. This share was reduced to 34 per cent in Union Budget 2014-15. This decline is largely due to transfer of Rs.1500 crore from NCEF to support National Ganga Plan under the Ministry of Water Resources. This raises a concern as to whether there could be a further decline in allocation for MNRE from the NCEF because of the financial requirements to address other pressing issues. Further, for the National Afforestation Programme, the Union Budget allocation for 2015-16 declined from Rs.235 crore in 2014-15 to Rs.75 crore with a plea of larger devolution of resources to the states. This has been a major concern in view of the positive impact that it has created in the past.

This is the first time that the Indian government has categorically earmarked domestic funds for adaptation. The National Action Plan on Climate Change (NAPCC, 2008) did sate that India spent 2.63 percent of the GDP in 2006-07 on adaptation programmes in five areas but no figures were given for subsequent years. The five areas mentioned for 2006-07 were: (a) crop improvement and research (5.93 per cent); (b) drought proofing and flood control (3.04 per cent); (c) forest conservation (0.49 per cent); (d) poverty alleviation and livelihoods preservation (44.65 per cent); (e) rural education and infrastructure (26.85 per cent); (f) health (10.75 per cent); (g) risk financing (4.83 per cent); and (h) disaster management (3.46 per cent). It has not been possible to de-construct these budgetary proportions to decipher what adaptation initiatives were funded or to what extent they reduced vulnerabilities to climate variability and built people's resilience. Probably these budgets were for business-as-usual activities under ongoing programmes that aim to safeguard a country that is anyway highly vulnerable to disasters and, as an agrarian society, is exceedingly dependent on temperature and rainfall patterns for its survival.

Subsequent to the release of the NAPCC, none of the adaptation-focused National Missions (pertaining to agriculture, water resources, forests and scientific knowledge), nor the State-level Action Plans on Climate Change (SAPCCs) that p-rioritise adaptation, have come up with clear budgets to support adaptation activities across sectors.,

Increase the corpus and broaden the scope of the National Adaptation Fund (NAF) so that it adds value to ongoing 'business-as-usual' development programems and/or activities in a transparent and measurable manner, rather than fund stand-alone adaptation projects.

Make climate change adaptation core to India's financial planning for development with all climate-sensitive ministries/State departments ear-marking a clear and measurable proportion of their spending towards building resilient components in their programmes.

Ministry of Environment, Forests and Climate Change issued order on 28 October 2014 pertaining to diversion of forest land for non-forest purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 and STs and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006, which had now exempted State Government from taking prior consent from Gram Sabhas for projects where linear diversion of use of Forest land is involved. Further to this, in case of plantations which were notified as forest on a day less than 75 years prior to the 13th December 2005 and are located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes as per Census 2001 and Census 2011, no forest rights are likely to be recognized and only a certificate from the concerned District

Collector will be sufficient without any consent from Gram Sabhas. Such an order will be counter-productive for sustainable development and is opposed to the participatory nature of the decision making process. Hence, we demand the government to reverse such orders which discards specific provisions in the Forests Right Act, 2006 which seeks 'prior informed consent' of Gram Sabhas before acquiring forest land clearing of forests for non-forest activity.

This order is released after taking consent from Ministry of Tribal Affairs, which raises concerns that whether the nodal ministry for Tribal Affairs carried out due diligence before giving such consent as there seems an ignorance of rights of tribal communities.

Order also allows for forest clearance for linear diversion of forest land such as highways, pipelines, rail tracks etc. which will cause an infringement in ecological balance of forests and may lead to rapid depletion of India' forest cover due to possible start-up of other related business activities along these linear projects in future. There is need to review this order with inclusion of cumulative impact assessment process of proposed project in view of future scenarios, along with following a participatory decision making process.

In a country where the economy is inextricably tied to climate-sensitive resources at several levels, Rs.100 crore as a national adaptation budget is just notional. This needs to be scaled up and rationalized with external funds for adaptation provided under UNFCCC and through bilateral and multilateral aid.

There is a need for capacity and skill building on better assessment of climate vulnerabilities and delivery of adaptation interventions at all levels and across all sectors- health, education, livelihoods and disaster mitigation and rehabilitation. This would include, for instance, skill in collection of climate data (including, for example, from panchayat and village-level rain gauges), assessing risks and monitoring adaptation outputs and outcomes.

The developmental budgets in agriculture, rural development and health saw drastic decline in the allocation in Union Budget 2015-16. These are the most vulnerable sectors to climate change and require robust developmental budgets with additional adaptation financing. With the creation of the National Adaptation Fund, it is high time to introduce sectoral monitoring of financial outlays based on common databases and facilitated by GIS techniques.

*__SHRI S.R. VIJAYA KUMAR (CHENNAI CENTRAL):__ I thank our beloved leader Hon. Makkalin Mudalvar Idhaya Deivam Puratchi Thalaivi Dr. Amma for having given me an opportunity to represent Central Chennai Lok Sabha Constituency in this august house and also for enabling me to express my views on the Demands for Grants for the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for the year 2015-16.

The Budget allocations for the Ministry of Environment, Forests and Climate Change stands at Rs.1,681 crores out of which Rs.1,446.00 crores for Plan outlay and Rs.235.00 crores for Non-plan outlay. The last fiscal 2014-15 outlay was Rs.2,256.00 crores out of which Rs.2,043.00 crores was for plan outlay and Rs.213.00 crores for Non-Plan outlay.

The total Budget Estimates for this Ministry has seen a decrease from the previous Budget Estimates for the last fiscal 2014-15.

While the need of the hour is to increase the allocations to the Ministry to facilitate increase the area of our forests and protect them. In line with the global concern for the environment and wildlife issues, we should strive to concentrate more on this deserving frontier area so as to see that we do not lag behind other nations in protection of the environment.

The climate change has affected our country more than any other nation. The failure of or insufficient rain, untimely rains, untimely floods, severe drought etc are due only to the global climate change. We need a more evolved policy to understand and deal with the climate change issues.

The revised guidelines prepared by the Ministry of Environment, Forests and Climate Change on the issue of forest clearance process by limiting powers of the gram sabhas to decide on the development areas is not a welcome step. Even the Ministry of Tribal Affairs has strongly objected to these revised guidelines. The Government should relook this issue and take positive steps to protect our forests.

We have heard reports that there is proposal to change the National Animal. The Tiger is our special animal to India and it should continue to be our National Animal. There is no justification to change it.

Tamil Nadu Government led by the able guidance of Hon. Dr. Amma has shown particular interest to animal welfare and particular care has been taken to conduct annual camps for temple elephants at Mudumali Wildlife Sanctuary for the rejuvenation of the temple elephants. Such good schemes should be studied by the Central Government for replication on a national scale.

I would, therefore, earnestly request the Government to reconsider all environment, forest and climate change issues and increase the present allocation to reasonable levels.

***SHRI V. ELUMALAI (ARANI):** The environment issue is an issue of public importance. It is gaining in all aspects of our life. I am glad that the government has been paying much attention on this issue whether it is conversion of forest land, pollution of river, air pollution, noise pollution, etc. The National Green Tribunal has come and is quite active now a days. I have come across with a news report that the government is considering to create or revise many of the existing environmental laws in consultation with the state government. It is a good idea because the environmental issues have to be dealt by the state governments and overall supervision with the union government. What I have come across that many state governments were not able to implement the directions of all the directions of the pollution control boards because of the paucity of funds. The directions of installing sewerage treatment plants is an issue because it involves huge amount of money. Therefore, it is my urge that the government should provide some sort of assistance to state governments for installation of STP.

Another issue which I would like to mention here is that the tribal people who were living in forest area in which they were living from a period unknown because of the rigid environmental laws, these people are deprived of many developmental activities, such as laying of roads, etc. Therefore, in the interest of the tribal people, I urge upon the government to relax some of the provisions of the environmental laws, so that for the welfare of tribal people living in the forest land can also enjoy some of the benefits which the people living in other areas are already enjoying. I would also like to bring to the notice of Hon. Minister that there were reports of people having lost their lives after consuming water from river. Such is the level of water pollution in rivers. The Government should take a note of it and assist the state governments to make the rivers clean and neat.

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): Sir, thank you very much for giving me this opportunity. This is an important Ministry and hence this discussion has got great significance. Though the Finance Ministry and the Government as a whole does not consider this as an important Ministry as is evident from the inadequate allocations made in the Budget for this Ministry, yet I feel that this is an important Ministry.

Sir, while I rise to speak on this subject, I remember a famous Malayalam poem written by a legendary poet, Jnanpith Award winner, Shri O M V Kurup and the poem is titled `An obituary for the earth'. The poem starts with these lines, *Eniyum vare marikyatha bhumi thinnu assanamrathiyul thinaku athamshanthi.* An approximate translation is like this -- `O Earth, let me pay my homage to your soul in your imminent death'. This was the apprehension and the pessimism expressed by that legendary poet and this poem was written some 25 years ago.

Since then, the situation has only worsened. Threats to environment and nature have only increased. Why is this happening and what is the real threat to environment and nature?

The real threat emanates from the unending human greed to be specific, greed for profits and that greed is led by corporates. So, the corporate greed for super profits is the real threat to our environment.

16.00 hrs (Shri Pralhad Joshi *in the Chair*)

Sir, this corporate greed is being aggressively promoted by neo liberal policies and this is being done in the name of economic growth. This Government, through its adherence to neo-liberal trajectory has precisely permitted the corporates to loot nature and make super profits.

I hope the hon. Minister will listen to me because these are some of the criticisms that I would like to make which he has to reply to.

This Government's utter disregard for environmental concern is evident from the following facts. Firstly, it was this Ministry under the hon. Minister, Shri Prakash Javadekar, which gave clearances for 190 projects worth Rs. 6.31 lakh crore in less than a year. This Ministry has been reduced to a Ministry of clearances.

I would like to request the hon. Minister not to reduce this Ministry into a Ministry of clearances but this should be a Ministry of enforcement of environmental laws.

Unfortunately, rather than enforcing existing laws in an effective manner and ensuring their compliance, the Ministry is very keen in diluting, dismantling and demolishing the existing environmental laws in favour of corporates.

I have to criticise the policies of this Government, particularly this Ministry, under the leadership Shri Prakash Javadekar. Of course, he is a good Minister with a smiling face. Despite all this, I will have to make a criticism of his policies. It was this Ministry, under his stewardship, which appointed a High Level Committee with a sole purpose of diluting all existing environmental laws to benefit the corporates.

Sir, due to paucity of time, I do not want to go into the details. It was this Ministry which is facilitating large scale diversion of forest land.

I would like to appeal to the hon. Minister to let us know and inform the House as to how much forest land you have allowed to divert in the

last one year. Large scale diversion of forest land is taking place and that also goes to the benefit of the corporates.

Sir, the double speak of this Government as far as environmental protection is concerned is evident in your hypocratic stand which you have taken in the Aranmula Airport Project.

I am coming from the State of Kerala. The majority of people in Aranmula and Kerala are opposed to this Airport Project. An environmental impact assessment study was carried out earlier and the National Green Tribunal had nullified that environmental impact study. Recently, you have again allowed fresh environmental impact assessment study. It is not only the Left Party but also your party is participating in the agitation against the Aranmula Airport Project.

So, please make your stand clear and categorical as to what is your position regarding the Aranmula airport project. ...(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

SHRI M.B. RAJESH: I will conclude within two minutes.

HON. CHAIRPERSON: You please conclude within a minute.

SHRI M.B. RAJESH: I will come to India's international position in climate related negotiations and issues. This Government is succumbing to the pressure of the United States and other developed countries. This Government is going to sacrifice India's position of 'common but differentiated responsibilities' as far as emission cuts and climate changes are concerned.

There was a report in *The Business Standard* that this Government is formulating its targets for fighting climate change for the global deal that is to be signed in Paris by the end of 2015. The hon. Prime Minister has stated that India can truly show the way to the world in mitigating the climate change. When the United States and the European Union are taking a different position, why is India unilaterally acting and unilaterally trying to set targets for emission cuts? I do not understand as to why we are taking such a position. ...(*Interruptions*) I hope the Minister will make it clear.

Not only that, the Government is thinking of fixing sector-specific targets for emission cuts. I wonder what will happen to the much-orchestrated 'Make in India' campaign. What will happen to 'Make in Inda' campaign if we are going to fix sector-specific targets for manufacturing sector? What will be its impact on manufacturing sector? What will happen to your much-orchestrated 'Make in India' campaign? So, what is the necessity of taking such unilateral action?

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

SHRI M.B. RAJESH: This is my last point.

I would like to request the hon. Minister not to deviate from our position in international forums and please make it clear as to what will be our position in the forth coming climate summit to be held in Paris at the end of 2015? All the allocations have been drastically reduced. I express my concern over this.

With these words I conclude. Thank you.

□**श्री पी.पी. चौधरी (पाली)**ः मैं सरकार का ध्यान राजस्थान राज्य की सबसे प्रदूÂिात नदी की ओर आकर्Âिात करते हुए बताना चाहूंगा कि मेरे लोक सभा क्षेत्र की बांड़ी नदी व नेहडा बांध लगातार भयानक रूप से प्रदूÂिात होते जा रहे हैं। वर्तमान में स्थिति बद् से बद्तर हो रही है। पीने के लिए भू-जल का पानी खराब हो चुका है। पानी के किनारे बसने वाले पशु-पक्षी भी नगण्य के बराबर दिखते हैं, क्योंकि वे भी जानते हैं, इस पानी को पीने के बाद उनकी मृत्यु तय है।

इस संबंध में राज्य सरकार, उच्च न्यायालय, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य प्रदूÂाण नियंत्रण मंडल व केन्द्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल आदि के द्वारा उठाए गए कदम व दिए गए निर्देश नाकाफी रहे हैं। यहां रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य में भी निरंतर गिरावट देखी जा सकती है। पाली जिले के किसानों की जमीन बंजर होती जा रही है और यदि उस जमीन पर कुछ उग भी आता है तो उसकी गुणवत्ता बहुत ही निचली किस्म की होती है, जिसे बाजार भाव में बेचा जाना संभव नहीं होता। राज्य पशुपालन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार यहां विचरण करने वाली पशुओं में बांझपन, प्रतिरोधक क्षमता व उत्पादन क्षमता में कमी आदि दर्ज की गई है। हालांकि प्रदूÂाण नियंत्रण करने के अनेक उपायों पर विचार किया जा चुका है, जो काफी नहीं रहे।

इस गम्भीर समस्या का निदान किया जा सकता है, लेकिन उसकी लागत बहुत अधिक है राज्य सरकार और औद्योगिक इकाइयां इसे वहन करने में असक्षम है। केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में आवश्यक बजट जारी करने के बाद ही इस समस्या को दूर किया जा सकता है।

अतः मेरा माननीय जल संसाधन मंत्री एवं पर्यावरण मंत्री जी से अनुरोध है कि केन्द्र सरकार द्वारा विशेÂाज्ञों की टीम को राजस्थान के पाली जिले में भेजा जाए ताकि पाली जिले की इस गम्भीर समस्या को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा विस्तृत योजना तैयार की जा सके।

मैं अरावली पर्वत श्रृंखला के उस भाग की ओर भी ध्यान आकर्Âिात करना चाहूंगा जो कि राजस्थान के मरूस्थलीय क्षेत्र से होकर गुजरता है। इसके अंतर्गत राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जयपुर आदि जिले आते हैं। पहले से ही राजस्थान में पेड़ों की भारी कमी है और अरावली पर्वत श्रृंखला पर पेड़ों की रक्षा के लिए कोई उपाय ना होने से दिन-प्रतिदिन पेड़ नहीं के बराबर दिखाई देने लगे हैं। जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है और इसकी मार राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरा हिन्दुस्तान झेल रहा है। मानसून की अनियमित और अनिश्चितता इसका एक उदाहरण है। यदि सरकार ने इस संबंध में कोई गम्भीर उपाय नहीं किए तो इसका दुÂपरिणाम जल्द ही भुगतान होगा।

मैं इस संबंध में माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे अरावली पर्वत श्रृंखला पर, विशेÂाकर राजस्थान के क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए विशेÂा कदम उठाएं तथा पर्वतों पर वृक्षों की हो रही अवैध कटाई को रोकने के लिए भी उपाय करें।

इसी के साथ, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के लिए प्रस्तुत मांगों का मैं समर्थन करता हूं।

***SHRI R. DHRUVANARAYANA (CHAMARAJANAGAR):** The importance of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change cannot be overstated enough in today's age. Given the impact of Climate change on agriculture that affects over 60% of our population and the devastating natural calamities that have happened in recent years, it is imperative that we focus on this sector. The same approach was underlined in the 12th Five Year Plan which recommended huge allocations, but that is not reflected in the budget. Up till 2013-14, allocation had been increasing every

year for the Ministry, however from 2014 onwards a complete shift in trend has happened. In 2014-15, the Government reduced allocation by 13%. Now, this year the Government has reduced the allocation again by 19%. This is absolutely worrying in the face of the challenges before us.

The Government has allocated Rs.137.06 crore for Tiger Projects, as compared to Rs. 161.92 crore allotted last year. This is a decrease of 15% from last year. This is extremely unfortunate as tiger is the national animal of our country. Yet the population of tigers in the Country as on 2014, is only 2,226. Although, the population has increased in recent years, experts believe that this 30% increase is partly due to counting errors in previous years. As per data by the Wildlife Protection Society of India, at least 110 tigers were killed in 2011-14, barely a drop from the 118 poached in 2007-10. We have 70% of the world's wild tigers on less than 25% of the world's tiger habitat. This itself suggests that we must sustain our effort to protect and conserve this habitat.

In my constituency, Chamarajnagar, there are two tiger projects being run by the government-Bandipur National Park and Tiger Reserve, and BRT Project at both these Tiger Projects. There is need for the Government's support to maintain and protect the increased population of tigers. Various experts have also called for the Government to come forward on this front.

There is also increasing number of instances of casualties caused due to human animal conflict across the country. The data of such instances is not maintained centrally but the Ministry has accepted the problem. In such instances, people who live closest to reserves, that is the tribal population is most affected. There are two issues in the Government's efforts. First is the issue of compensation being provided by the government in cases where people are killed in human animal conflict. At present, the Government is providing Rs.2 lacks as compensation under Project Tiger. However, this is not sufficient. I urge the Minister to increase this compensation. Secondly, at present, the Government's approach on human-animal conflict is more reactive than preventive. The issue requires concern effort of the Government focused on prevention of such instances. There is a need for more allocations towards solar fencing and awareness, so that the risk of human-animal conflict can be mitigated. I urge the Minister to take appropriate steps on the issue.

The Forest Rights Act, 2006 has been implemented since 2008, and provides rights to forest dwellers to own, access and take decisions regarding the forest area. Under FRA the Gram Sabha regulates access to forest resources and can stop any activity, which adversely affects the forest.

The Government recently laid down that instead of tribal village councils certifying that their rights had been settled and they had consented to projects, the district administrations would be empowered to do so in 60 days, regardless of the number of villages affected by the projects. On 28th October 2014, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change had sent out a letter to all States giving rights to the District administration to divert forest area for other purposes.

Even the Tribal Ministry has written repeatedly to the Ministry of Environment and Forest on the issue. As per reports, the Tribal Affairs Secretary, has written that there was no proof that the Forest Rights Act was delaying projects. The letter clearly mentions that the Ministry of Environment and Forest is short-circuiting the legal process of consent.

For tribals, across the country, the Forests Rights Act is the most important tool for empowerment. These are the communities that suffer most due to degradation of natural resources. This dilution, gives a message that the government is not concerned about the peace and governance of forest areas. I urge the Minister to withdraw any such notifications that dilute the Act. Clearances for environment and forest must not come at the compromise of tribal rights.

As per a report by the World Health Organization (WHO), Delhi's air pollution is the highest in the World. Besides this, as many as 13 Indian cities are the top 20 cities in terms of air pollution. As per reports from all over the World, the link between high air pollution and health concerns is clear - cut. One study by top universities in the US has claimed that Indians are losing on an average 3 years of their life span because of high air pollution. It was in the light of this, that President Obama, on his recent visit to Delhi bought air purifiers, which were installed at the Republic Day Parad. The Ministry has been dismissive of these reports on health concerns. Would the Ministry, in this case commission an independent study on the matter so that the link between health risks and air pollution can be ascertained?

At the same time, the Ministry has stated to the Delhi High Court, that as of now, there is no action plan to tackle the issue of air pollution in Delhi. I urge the Ministry, to not only come up with an action plan for Delhi but also for cities that are facing an air pollution crisis. This includes Bangalore, Delhi, Agra, Kanpur, Lucknow, Varanasi, Faridabad, Ahmedabad, Chennai and Hyderabad.

The Government has recently launched National Air Quality Index (NAQI) for monitoring air quality across 10 cities. However, in three cities the data has been found to be insufficient to monitor air quality. Across these cities, monitoring infrastructure has been found to be lacking. In some cities only one monitoring station exists while various monitoring stations are unfunctional. I urge the Minister to look into these issues so that the monitoring initiative is successful and does not merely exist on paper.

□SHRI C.R. CHAUDHARY (NAGAUR): It is my pride privilege to participate in the discussion on Demands for Grants of the Ministry of "Environment, Forests and Climate Changes". I would like to thank the hon. Prime Minister and hon. Minister for Environment, Forests and Climate Change for strengthen the Department and also for bring the innovative schemes in the last eleven months.

It is necessary that the genuine problems of the public should be addressed without disturbing the environment and ecology. I would like to appreciate the Government for clearing the long pending issues related to Railways, National Highways and Water Resources. Many projects were pending in the absence of clearance from the Forest Department. The Government has decentralized the power of clearing such cases.

At this juncture, I would like to request the hon. Minister to have a positive view over the mining of non-metallic minerals which are pending for environment clearance. Persons who want the lease of mining of limestone, chino clay or gypsum have to go for Environment clearance. They have to roam here and there and hamper the mining activities.

The Environment Ministry is doing a lot for banning the thin plastic bags. I would like to request for complete banning of it.

India is having the forest in small percentage in comparison to other countries. All that land which cannot be brought under the cultivation should be used for forestation. Desert and semi-desert areas should be brought under social forestry and farmers should be given incentives for plantation. Special package should be given to Rajasthan for aforestation under social forestry.

I would like to urge to the hon. Minister for giving due attention towards the "global warming". Schemes should be brought to maintain the ecological balance. Air pollution and deforestations are main causes of global warming and

both the elements are to be considered while framing the policies. I would like to request the Government to keep the topics related to environment in the syllabi of the elementary and secondary level education, so that the habit of conservation of environment can be developed.

I would also like to request that the Government should fill up the vacant posts of the Forest Department who look after the Reserve forest, sanctuaries and wildlife.

Lastly, I welcome the decisions and pragmatic approach of the Ministry in maintaining the ecological balance in the country. I hope and wish that under the dynamic leadership of our Prime Minister this Ministry will do a wonderful job for the people of this nation by aforestation, by securing the wildlife and by maintaining the environment.

With these words, I support the Demands for Grants presented by the hon. Minister.

*m34

SHRI P.V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): Mr. Chairman, Sir, thank you. Every civilized society has a responsibility to take care of its environment and forest. In a developing country like India we have seen how human greed has affected our forest cover and our environment. Although our forest cover has been increasing at the rate of 0.46 per cent from year 2000 till now, it is not substantial and we need to increase our forest cover. Though the social awareness level has been growing, the actual impact is very less. The 14th Finance Commission has allocated 7.5 per cent for increasing the forest cover. It is a welcome move. This 7.5 per cent is by way of devolution of union taxes to States. What we need is negative incentives so that the States are under pressure to increase their forest cover.

In my constituency, Rajampet, which is in Andhra Pradesh, we have 80 per cent of the world's red sanders tree. This is in the Seshachalam forest area. Red sanders is in the endangered list of our Central Government. Each tonne of red sanders cost Rs. 24 lakh to even Rs. 1 crore. This is the reason why a lot of smuggling is happening. These trees are being felled very rampantly. The Government is unable to control the smuggling of this red sanders. Recently the Central Government has given permission to auction and sell the confiscated red sanders.

We request the Central Government to step in and control the smuggling of the red sanders. The proceeds of this auction should be used for development of the red sanders, protecting the forest cover and protecting the red sanders throughout the State. It should not be diverted for other purposes. We also request that a comprehensive National Policy on sand mining should be there. Extensive mining of sand is depleting water resources and creating an imbalance in our ecology and environment, especially in the Rayalaseema Region, there has been a huge depletion of water table. The Government should look for alternative sources of resources which can replace sand. There must be a balance between environment and development. Faster economic growth is directly proportional to reduction of poverty. For this, our country has to grow at 10 per cent in the coming years. To sustain this 10 per cent growth, we need huge investments in infrastructure and various other manufacturing industries. We have no choice but to increase our power capacity by close to two lakh MW in the coming five years. Under pressure from the NGOs and people with vested interests, many large aluminium, steel, cement and thermal projects, for which initial clearances were given, have been stalled. This is not good for our country in the global scenario. Uncertainties like this will discourage people from coming to India.

Now, we are having slogans like "Make in India" but it will be a far-fetched reality if we do not act in time and clear all these uncertainties. Even our former Prime Minister Dr. Manmohan Singh said in one of his statements that NGOs funded by foreign companies try to stall the Koodankulam Power Project. If such is the case, we should know that even other projects would have been stalled by vested interests. At a time when we must be growing, we find projects with huge investments are stuck for environmental and forest clearances....(*Interruptions*)

Unfortunately, it is the nationalised banks and small investors who put in their life savings into these companies who are at stake. No person would oppose genuine steps to protect environment, particularly the tribal people who are dependent on the forests. But if we have economic and strategic mines in the tribal areas, we should definitely make use of these resources and use the profits for the development of the tribal people.

Coming to forests, the BK Chaturvedi Committee dealing with coal block allocations observed that only 0.75 per cent of the total forest cover is required for giving clearances to all the coal blocks of the country. The Committee also observed that it can power two lakh MW of power in our country. It suggested that instead of stopping mining, the Government can impose a tax on these mines and afforest at least 100 more degraded forests in our country.

I would conclude by saying that our Party has cautioned in the past and we are saying it again that unless the PMO, where all the Union Ministries converge, has a mechanism to monitor all major projects on a daily basis ensuring that all inter-Ministerial clearances are given on time, we will be back to square one. All our good intentions and aspirations will just remain on paper and *Achhe Din* will be very far away.

□**श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली)**ः जलवायु परिवर्तन प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मानवीय गतिविधियों के कारण होता है और यह परिवर्तन विश्व वातावरण की संरचना को बदल देता है। पृथ्वी

की जलवायु हमेशा बदलती और विकसित होती रही है। इस प्रकार के कुछेक परिवर्तन प्राकृतिक कारणों से होते हैं लेकिन अन्य के लिए मानवीय क्रियाकलाप जिम्मेदार होते है, जैसे पेड़ों की कटाई, उद्योगों तथा परिवहन से वायुमंडलीय उत्सर्जन, जिसके कारण वायुमंडल में गैस तथा ऐरोसॉल्स एकत्रित हो जाते हैं। इन गैसों को ग्रीनहाउस गैस कहते हैं क्योंकि ये गर्मी को रोक लेती है और धरातल के निकट वायु के तापमान को बढ़ा देती है और पृथ्वी की सतह पर ग्रीनहाउस की भूमिका अदा करती है।

ग्लोबल वार्मिंग ने समुद्री स्तर, बर्फ की चादर तथा वÂ०ा०ान को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। हवा के तापमान में बढ़ोतरी द्वारा जलवायु के क्षेत्रीय पैटर्न में होने वाले परिवर्तन ने विश्व के कई भागों में जल संभरण तथा पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करना पहले ही शुरू कर दिया है। यह बढ़ता हुआ तापमान और बढ़ता हुआ समुद्र स्तर मीठे पानी की उपलब्धता, समुद्री खारेपन, खाद्य उत्पादन को प्रभावित कर सकता है। यह तटीय क्षेत्रों को जलमग्न कर सकती है और जलजनित विकारों का प्रकोप बढ़ सकता है।

जलवायु परिवर्तन विकास के समक्ष एक बड़ा खतरा है, जो गरीबी मिटाने और समृद्धि को जनता में बांटने के प्रयासों को कमजोर कर सकता है। अगर कोई मजबूत और त्वरित कार्रवाई नहीं की जाती है, तो धरती के तापमान में डेढ़ से दो डिग्री की वृद्धि हो सकती है। इसकी वहज बीते समय और वर्तमान समय में ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन है। इस तापमान बढ़ोतरी के चलते समुद्र के जलस्तर में वृद्धि और चक्रवातों के जल्दी-जल्दी आने का खतरा बढ़ रहा है। मात्र दो डिग्री की वृद्धि से ब्राजील की सोयाबीन फसल का उत्पादन 70 फीसदी तक कम हो सकती है। दो डिग्री की वृद्धि से दुनिया में मक्का, गेहूं और अंगूर की फसलों के उत्पादन में 50 फीसदी की कमी आ सकती है। उत्तरी रूस में इसके कारण बर्फ के ढके क्षेत्र में लगातार बर्फ पिघलेगी जिसके चलते नुकसानदायक मीथेन गैस के उत्सर्जन में वृद्धि होगी।

वैश्विक तापवृद्धि से निपटने हेतु संभावित उपायों में शामिल हैः रसोई गैस सब्सिडी को केवल जरूरतमंद लोगों तक सीमित रखा जाना जिससे कच्चे तेल के आयात में कटौती सम्भव है। एलईडी के इस्तेमाल करने पर देश में कई अरब यूनिट बिजली की बचत हो सकती है। सरकारी बैंक देश में ग्रीन एनर्जी जैसे सोलर एवं विंड एनर्जी को प्रमोट करने के लिए सस्ता एवं सुविधाजनक लोन उपलब्ध कराए। हरित कानूनों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। हमारे देश की लगातार बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए हमें अन्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकीय कार्यक्रम की सम्भावनाओं को तलाशनें की जरूरत है। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को अपनाए जाने से भी प्रदूÂ०ाण का स्तर कम करके उत्सर्जन में कमी लाई जा सकती है। भारत में मनरेगा जैसी राÂट्रीय स्तर की योजना को ग्रीन इंडिया मिशन से जोड़े जाने से जलवायु परिवर्तन द्वारा वैश्विक तापवृद्धि पर रोक लगाई जा सकती है।

अब समय आ गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले वैश्विक तापवृद्धि से मुकाबला करने के लिए पर्यावरण हितैÂ०ाळ और कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले शहर विकसित करने पर जोर दिया जाए तथा संभाव्य जलवायु सम्बंधी खतरों से सुरक्षित रहने के लिए समयबद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाए।

*SHRI S.P. MUDDAHANUME GOWDA (TUMKUR): Environment and Forests is the subject which is directly connected to future generation of the country. Protection and improvement of the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife is the priority and paramount consideration of both states and Union Government. By looking at the figures of allocation of funds in the budged for 2015-16, the Union Government appears to have not taken this flagship programme seriously. Any Government should always think of the future of this country. Preservation of natural environment is not sufficient. The said natural wealth should be improved. We have been seeing that thick forests are day by day becoming thin. A lot of well grown trees in the forests are mercilessly cut and removed. Illegal deforestation activities are rampant throughout the country. The size of thick forests is being reduced slowly due to the illegal activities.

Plantation of saplings is not becoming an important programme to improve the forests and at least to maintain the status quo of the size and thickness of the forests. Both State and Central Government should take the rainy season of the every year on war footing to plantation of the saplings. In addition to this, the plantation programme should also be introduced at school and college level. The children should be made known about the importance of the programme of plantation of saplings.

---

* Speech was laid on the Table

Both States and Union Government should ensure some mechanism to crate awareness programme among the general public about the importance of the preservation, protection and improvement of natural environment including forests, lakes and rivers. This awareness should make the people know about their duties and responsibilities to become part of the nature taking the future of this country into consideration.

Protection and improvement of wild life is also equally important to balance the nature. This is a big challenge to both States and Central Government. Simple decisions can protect and preserve lot of wild animals. Government should evolve a long time programme for this purpose.

The existing laws to protect the wild life is neither stringent nor properly implemented. Hence the Union Government should look into this aspect also.

Illegal mining activities in forests and also mining of sand is becoming a big menace in the whole country. This act has got direct impact on the

protection of environment. Hence this illegal mining activities in the forests and also the sand mining should be viewed very seriously. Illegal sand mining is not only causing impact on the environment but also a big cause of depletion of underground water.

Pollution control is also a serious matter in the country. Pollution control Boards both in the States as well as the Centre have become toothless. They have virtually become centers for issuing certificates for fulfillment of the legal objection. The very purpose of establishment of these boards is defeated since they are not discharging their duties and responsibilities properly.

With these words I conclude.

*SHRI B.N. CHANDRAPPA (CHITRADURGA): I think this Government is attaching scant attention to this Ministry, which is very vital for sustainable development. To me this Ministry is very important. If the proper attention is not given to this Ministry, the environment of the whole Government will suffer.

I think our country is facing an ecological crisis. As we all know, every day our vehicles, our factories and our power plants are spewing carbon dioxide out into the air. Our air-conditioners and refrigerators are spewing carbons into the atmosphere as a result of which we are having a shield over the atmosphere on the earth which creates greenhouse effect and which is leading to global warming. If it is not checked, it will ultimately lead to many low-lying areas being submerged under the sea. Already the glaciers are melting very fast and the threat of climate change is looming over the world.

The other problem is that this carbon dioxide emission may be controlled by planting trees. Trees have a great capacity of absorbing carbon dioxide and converting it into oxygen.

By cutting our forests, we are destroying that means of purifying our air. Hot only that, over the years, there has always been a debate between environment and development. What is happening now is that the industrially developed countries of the West are trying to impose environmental norms on our country. So, the main question is of striking a balance.

The Environment and Forests Ministry is the nodal agency for looking into all these aspects of environment and the problem of air pollution and water pollution. Just look at our cities. We are discharging sewage into the rivers that flow by. Our factories are discharging sewage into our rivers. Now, it is high time that Government of India took a holistic view on the question of environment, climate change, water and air pollution and afforestation. Unfortunately, that is lacking.

There are many areas on which we can talk. The Environment Ministry has a big list. It has got the Botanical Survey, the Zoological Survey; it has got the Forest Research Institute. It has got a huge bureaucratic framework but ultimately the matter of environment can only be achieved by total co-operation of the people, by raising the consciousness among the people. Today, in good schools of the cities, they are teaching environment. But the large masses are not yet alert to the problem of environmental degradation.

It was mentioned by the Minister that the environmental clearances will be given online. But there should be a time-frame fixed for this purpose. We need to follow a model of sustainable development. If we want to achieve 8 per cent or above growth, then we have to ensure that it is a low-carbon growth. As it is, still at the rate that we are going, even in 2030, India's per capita carbon emission will be less than that of any of the developed countries. So, we should take care of it in time so that we follow the road of development.

KUMARI SUSHMITA DEV (SILCHAR): Sir, at the outset, I would like to say that I tabled the Standing Committee's Report as I am a Member of the Standing Committee. But, on perusing the Report in its entirety, I would say that what unfolded is a saga of benign neglect. I am sad to say and I am sad to see the kind of cut in the allocations that this Ministry has seen. What will be the impact is the very theme of this Report. I quote from the Report:

"Mother earth has enough to support our needs but not enough to support our greed."

Today, this Report is urging upon the Government to identify areas of policy and legislative improvements that will be crucial for laying down a green roadmap. There is no doubt that environment in our country is entering into a stage of deep crisis. Today, what we see when we peruse the budget? Today, we see that this Government has deliberately under-funded this Department, under-funded our environment. Today, repeatedly Members in this House have said that the meagre allocation of Rs.1,446.60 crore has been given as opposed to the demand of Rs.4,440.20 crore. Today, we have seen that the Ministry has rationalised eight schemes of the 11th Plan to five schemes in the 12th Plan. As a consequence, thematic schemes have been reduced from 22 to 18. No doubt, the scheme on climate change has become a stand alone thematic scheme. But today even Project Tiger has seen a cut of 15 per cent. Today, the only schemes that are fully supported by the Government of India are Project Tiger and Project Elephant alone.

In the light of this allocation, this Committee has requested the Finance Minister that at the stage of RE, proper allocation should be given. Why is it worrying? Today, when the Standing Committee asked the officers of this Department as to what is going to be the impact of this cut, they gave a list of whole lot of areas which are going to take the hit of this cut.

Out of that, this is from paragraph 16.14 – prevention and control of pollution. आज देश के प्रधान मंत्री देश और विदेश में जाकर स्वच्छ भारत की बात करते हैं। आज जहां हमें भारत को स्वच्छता की ओर ले जाना है, इस मिनिस्ट्री को देखना पड़ेगा – what is the condition of air and water? Today, with rapid urbanisation, I ask the hon.

Minister – does the amount of sewage generation match our treatment capacity? It does not. If 36,000 MLD sewages is expected to be produced in India, we need more than Rs.1 lakh crore to give this nation an adequate sewage system. To make matters worse, जब जावड़ेकर जी मंत्री बने तो उन्होंने स्टेटमैंट दिया - that I will change the culture of this Ministry. What he meant? I don'tknow. लेकिन मैंने जो देखा है this Government is in a hurry. Hurry for what! That India should climb up the World Bank's Ease of Doing Business Index. What is the priority of this Government? It is `Make in India'. I come from a constituency known as Silchar. Silchar to Saurashtra जो महासड़क है, आज इनवायरमैंट क्लीयरैंस is so important for development यह मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता - because the people of Barak valley are till today waiting for environmental clearance and मैं जीतने के बाद ही जावड़ेकर साहब से मिली थी। So, State has now sent everything to you. Ball is in your court, Sir. जरूर कीजिए। मैं यह उदाहरण के हिसाब से क्यों कह रही हूं ;; that a message must not go that Congress is a party of anti-industry, that Congress is a party of anti-development. Today, we want business to be easy; but we want we should also be able to breathe easy. आज सुब्रहमणियम कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई। लोग कह रहे हैं कि यह इनवायरमैंट फ्रैंडली है या इन्वैस्टर फ्रैंडली है। आज देश में यह सवाल उठ रहा है। मैंने कहा आप सुब्रहमणियम कमेटी की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो देखेंगे if you read the Subramaniam Report, you would see that they are removing the criminal liability and bringing in civil liability. Is this to help the corporates? Today, are we saying – pay and pollute? Today, I request that this Ministry must pay heed to the recommendations of the Standing Committee and no go ahead in toto with the recommendations of the TSR Subramaniam Committee.

Today, National Board of Wildlife - आज एक माननीय सदस्य ने कहा कि बहुत सारे एपूवल्स हो गए हैं। सुना है 789 एपूवल्स हो गए हैं। सवाल यह उठता है कि 140 एपूवल्स को इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने क्यों स्टे कर दिया। Have you constituted that body properly? Have you given a body of 10 individual experts? Have you included five non-Governmental institutions? Today, in the coal mining sector, where the capacity is less than 16 MT per year, have you removed the provision of no public hearing? Today, have you diluted the impact assessment, the EIA rules? Today, will you allow projects within five kms. of the protected area to go ahead without the permission of the National Board of Wildlife? Will this Government amend the Forests Rights Act discarding the need of prior informed consent of the Gram Sabha? फिर जो लैंड बिल में इस सरकार की हालत हुई है फॉरैस्ट राइट्स में भी वही होगा।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

KUMARI SUSHMITA DEV : Sir, last but not least, the National Green Tribunal is the only environmental court of this nation. It was set up to fulfill an international obligation made in the Rio Conference. So, the powers of the National Green Tribunal must not be diluted in future. This is my humble request to the Minister. आप इन्वायरमेंट के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, मेरा अनुरोध है कि protect our environment. Let the youth of India breath easy ब्रिथ इजी करेंगे तभी मेक इन इंडिया से नौकरी मिलेगी, इप्लायमेंट मिलेगी।

□SHRI PRASANNA KUMAR PATASANI (BHUBANESWAR): The year 2015 is likely to be momentous with the world set to witness new agreements on climate change and sustainable development. The global agreement on climate change under the UN Framework Convention on Climate Change applicable to all countries must ambitious, comprehensive, equitable, and balanced, taking into account the huge development needs of developing countries including access to financial resources and low carbon technological options. In India, landmark environmental measures introduced in recent years reflectiong actions both at national and sub-national levels are being further supplemented by policies in the light of new scientific findings and current needs.

Finance Minister's focus on growth and equity is incomplete. He should have acknowledged the trade-off between the need for energy and the imperative of environmental protection. The Finance Minister made no mention of natural gas. This, despite the fact that gas is the cleanest of all fossil fuels and that 20 GW of generation capacity has not been operationalised because of inadequate gas supplies and poor pipeline infrastructure.

India tries to change the game on climate change. The Indian Government has made a notable and innovative claim of late, one which might upturn the standard assumptions by which climate change negoiations are held. It has pointed out that India has moved from a carbon-subsidisation regime to the one where carbon spewing is taxed. This puts India among the very few countries that have included financial mechanisms like carbon tax in their strategies to deal with the threat of climate change. This shift has been brought about through recent government measures, such as decontrol of diesel prices and imposition of higher excise duty, and cess on petrol and diesel. These, as the government has correctly pointed out, amounting to putting a price on emissions. Finance Minister Arun Jaitley maintained while presenting the Union Budget that the country's de facto carbon tax on most petroleum products compared favourably with international norms. According to Economic Survey, the duties levied on petroleum products are equivalent to a carbon tax of $ 140 a tonne for petrol and $ 64 for diesel- substaintially above the global initial carbon dioxide (CO_2) emmission taxation norm of $ 25 to $ 35 a tonne. When translated into emission reductions, this level of taxation is tantamount to a net curtailment of 11 million tonnes of CO_2 discharge in a year, or 0.6 per cent of India's annual emissions.

To combat wildlife related crimes, a Wildlife Crime Control Bureau under the Director, Wildlife Preservation has been constituted with 5 Regional Offices viz., Delhi, Mumbai, Kolkatta, Chennai and Jabalpur and 3 Sub-regional offices at Amritsar, Guwahati and Ramanathapuram.

Wildlife Division of the Ministry provides technical and financial support to the State/UT Governments for Wildlife conservation under the Centrally Sponsored Scheme - Integrated Development of Wildlife Habitats and also through Central Sector Scheme -Strengthening of Wildlife Division and Consultancies for Special Tasks, and through Grants in Aid to the Central Zoo Authority and Wildlife Insitute of India, Dehradun.

In accordance to the Laws of Nature we are tuning our body and mind when the environment is poisoned, the entire life of human being would be jeopardised. I consider every tree is valuable than the human being. If a tree dies, who will carry the dead body to the burning ghat? The wood of any tree is very useful from the kitchen till end. Therefore, we should enact a Law that whoever is cutting the tree should be punished. We are cutting the tree, we are cutting jungle. The animal kingdom would be thirsty. There is no space for survival of animals in the forests nowadays. When the individual of the tree is green the jungle is green. When the individual is healthy the society would be healthy. Therefore we should pay special attention to protect the jungle. Our lord Jagannath is made of wood. We are cutting a tree means you are harming your God. Likewise in Christianity the cross is made out of wood. While you are killing jungle you should think about the society. A tree is donating us fruits, leaves, sheds. The government should plant more trees. It happened while the roads of national highway are already constructed. Immediate plantation should have been started to protect the fellow passengers. In our state, it is highly neglected. Old trees of hundred years are no more because of the

construction work. That is why we are facing natural calamity. Because we are spoiling the forest, jungle and the life of nature every day, the nature is punishing us. In our state, there are huge jungles. Therefore, the rain falls in time, there is no climate change and the survial of the animal kingdom. Human being are peacefully living and loving their state. Because of the environmental condition that we are not conditioning, we are facing the earthquake, drought, flood and famine. Whatever the Government is sanctioning or allocating grants for the development of forest life is totally spoiled because the environment is not secured.

SHRI DUSHYANT SINGH (JHALAWAR-BARAN): Mr. Chairman, Sir, I would like to thank you for giving me this opportunity to speak on the Demands for Grants of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change.

Sir, I would also like to commend the hon. Minister for the great work he has done in the Ministry. I would like to congratulate him on the position he has taken in the Lima Conference last year with world leaders on the privileges of negotiating a Climate Change Agreement and reached a consensus at the Conference on differentiating responsibilities and respective capabilities.

I would like to mention about the Standing Committee Report which my previous speaker was also mentioning. I would like to talk about the ease of doing business. Previously, the policies of the Government were there to stifle the investors and there was a policy paralysis in the previous Government. Since the Narendra Modi Government came to power, he has ensured that the projects which were not taken up in the past have not been cleared quickly. Thanks to the e-portal system, the Minister has received new proposals and the proposals can be tracked through the online system and the Environment Assessment Impact Reports can be seen by the people. Previously, people were not ready to invest. They were not ready to risk their money as their proposals could not go through. Now, with the new Government coming in, they can see the minutes of the Environmental Appraisal Committee Reports and I would like to thank the hon. Minister for that.

Sir, our hon. Prime Minister has talked about sustainable development. To achieve sustainable development, the hon. Minister has taken initiatives to remove all the bottlenecks to encourage participation. To ensure clean energy, the Government has ensured that 17 critically polluting sectors, like the coal sector, have been asked to install equipment to monitor effluent and emission quality on a continuous basis. The Government has doubled the cess on coal over the past year to promote clean energy. The Minister has also talked about increasing the funding for biodiversity which was not done before. It has been increased to Rs. 27.09 crore which was previously at Rs. 13.08 crore.

The Government of India has talked about cleaning of Delhi's air. The pollution problem in Delhi has been created over a period of time which we inherited. According to a study published in the Economic and Political Weekly, the pollution in Delhi will cut down about 3.2 years per person if the air pollution in Delhi is not controlled. It has affected our breathing and respiratory systems and the Government has allocated Rs. 240 crore to combat pollution in Delhi.

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

SHRI DUSHYANT SINGH: Sir, I have just begun. Please give me two or three minutes more.

The hon. Minister has talked about an Action Plan to combat pollution. He has taken measures to reduce the emission load from NTPC from two-third to one-third. They have also talked about the Asia's first plasma gasification scheme. They have also looked at air quality control; they have launched a National Air Quality Index across 10 cities which is also being expanded to 46 cities further. We are looking at clean energy by 2025. We are looking at the study by Agora Energiewende by which clean energy can reduce the carbon emissions and thereby help to reduce the pollution. They have also talked about scientific research which has been done. Funding has been done for scientific research of Rs. 130 crore. They have also looked at the Indian Council of Forest Research work.

I would like to say that the climate change has created erratic weather in different parts of India, specially Rajasthan, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. There has been a report from the Indian Council of Agricultural Research that the temperature will increase by 2 to 4 per degree. So the Government is also looking at that. The Standing Committee report has also talked about it.

My previous speaker had said what we have done for forests. We have also talked about the Green India Mission by which we can create a forest and tree cover of around five million hectares across the country. We can help giving employment to the people of India to help save the environment of this region and to help the people.

I would like to thank the Minister for looking at Project Tiger. The tiger population has increased by 30 per cent in his regime. I also thank the Minister to look at Project Elephant. I would urge the Minister to look at the CAMPA fund of Rs. 38,000 crore by which if he can create a regulatory mechanism, the States can benefit from it. He also should focus on the NTCA. The woks done by the NTCA previously were not of the optimal level. Now, with the new Government coming in, the systems in NTCA have improved.

Lastly, I would say that we need to focus on the Great Indian Bustard in Rajasthan and also to look at the Gangetic dolphins and the gharials. My previous speakers had talked about solid waste management. With the solid waste gasification system, we can create clean energy to provide energy to our systems out here. We need also to look at river basins of this country, the Chambal basin and all that.

I would like to thank the hon. Minister for the great job done by the Government.

*SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): The allocation for the Ministry of Environment and Forest accounts for Rs 1681 crores, a 25% percent decrease from the budget estimate of the 2014-15 and even below the revised estimate of 2014-15. The whole forestry and wildlife department was granted Rs. 362.84 crore, a staggering 21% less than what it was allocated in the previous financial year.

The allocation for Project Tiger, India's most celebrated wildlife conservation programme, Rs. 136 Crore, a decrease of around 15% from Rs. 161 Crore in 2014-15. The All India Tiger Estimation Report released in January said the tiger population had increased by 30% from 2010 to 2,226 in

2014. It was only through the efforts of 3 years of UPA and NDA have helped us to achieve this state. By cutting allocation, we do not want to go back to the situation. I have recently visited Tadoba and was amazed to see how it has created a lot of wealth and livelihood for the people.

Forest rangers, deputy forest rangers, foresters and forest guards are the frontline field level staff working for the protection and conservation of precious forest and wildlife wealth of our country. They are the interactive interface of the forest department with the public. While their job is tough and demanding and it involves high risk, they are poorly paid, underequipped, untrained and consequently de-motivated. Add to that they live deprived from basic facilities like clean drinking water, toilets, electricity, communication systems, protective rain/winter gear and medical aid.

I am hearing that government is considering a proposal to make lion India's national animal, pushing out the tiger that has had the coveted status since 1972. According to me, this would dilute the campaign to save tigers and pave the way for clearance of industrial projects near tiger sanctuaries. Tigers are found across 17 states in India, whereas lion is found in only one. India is home to more than 2,200 tigers, whereas the Asiatic lion population, estimated at 411, is confined to Gujarat's Gir. If we really want to make lion the national animal, you should first restore at least 10-15 natural habitats which are suitable for lions. Then the lions should be relocated there from Gir.

The International Union for Conservation of Nature's Red List, lists 374 species in India as vulnerable and 274 others as endangered, or critically endangered, and at risk of becoming extinct. From well-known mammals like elephants, leopards, rhinos to numerous less-known animals, such as pangolins, tortoises and geckos all are endangered in our country. There are just 26,000 and 30,000 elephants left in the wild in India. According to WPSI data, 18 elephants were poached between January and September last year for their tusks to meet the demand for ivory. The agency has recorded the loss of over 120 elephants due to poaching between 2008 and 2011. During the same period, WPSI has records to seizure of 781 kg ivory and 69 tusks, besides ivory pieces and carved articles. Poaching and smuggling present a huge threat to the wildlife. WPSI, a wildlife conservation organisation, has recorded over 20,000 wildlife crime cases. It is utmost important to create a safe environment to our wildlife also. I here also like to ask the Minister for the rationale for doing such drastic cut in the allocation to Central Zoo Authority from Rs 27.50 Crore to Rs 5.8 Crore. I am also worried that budgetary allocation to Indian council of Forestry research and education has been continuously decreasing. It was Rs 160.26 Crore in BE 2013-14, Rs 156.66 Crore in BE 2014-15 and now has been brought down to Rs 125.60 Crore. The council was set up with an objective to achieve the national goals of conserving forest area and to take care of the research needs. It is imperative to provide ample amount of resources to an institute of such importance.

Now talking about air pollution, I felt really sad when I read in the news piece that because of low level of Air quality, there was a speculation that the US authorities here could seek to curtail Obama's "outdoor activities" during his visit. It is said that Obama lost 6 hours of his life because he stayed in Delhi. This speaks volume of the seriousness of the situation. Industrialization and environment needs to go hand in hand. 90 per cent of coal-based thermal power plants in India fare unsatisfactorily on the environmental front. Infact the best coal plants in India are average in terms of environment performance when compared to their counterparts worldwide. There is also a need to produce clean energy. Target of renewable energy capacity has been revised to 175000 MW till 2022. Though the targets are very impressive, I am doubtful of meeting the targets especially when the cut to renewable energy sector to a mere Rs 303 crore from over Rs 550 crore in the revised budget 2014-15.

I would also like to bring attention of the Government to the concept of light pollution. Light pollution is a side effect of industrial civilization. Its sources include building exterior and interior lighting, advertising, commercial properties, offices, factories, streetlights, and illuminated sporting venues. It not only degrade photic habitat like bats, owl but also proves to be a major astronomical disruption. Awareness in this regard is extremely important. Government in public assets atleast should use full-cut off shielding in light fixtures which is the essential remedy. A lamp should send all its light more or less down where the light is intended to be used, not upward or sideways.

India generates about 60 million tonnes of trash every year. Ten million tonnes of garbage is generated in just the metropolitan cities. The landfills of most of these cities are already overflowing, with no space to accommodate fresh garbage waste. Constructing new landfill sites is one solution but more importantly the Government should be looking into innovative methods to dispose and recycle its waste. The reason why most landfill sites are over-flowing is because the current waste disposal system is inefficient. There are waste management plants, but they are not running at full capacity mainly due to the lack of waste segregation that has made waste management problematic. Segregation at source is the only solution. Recyclable waste like construction and demolition waste, organic waste like household garbage, toxic waste like medical waste, are all mixed together. The segregation of biodegradable waste from non-biodegradable waste is not done properly. Segregation of waste should occur at the colony or neighborhood level, when the waste is collected. Effective management of garbage is extremely important as it affects the health of our citizens in an extremely severe manner. Nearly 20% of methane gas emissions in India are caused by landfills. Due to the decomposition of inorganic waste, the ground water is contaminated. There is also the problem of leachate when rainfall percolates through the waste in a landfill.

Swach Bharat Abhiyan currently encourages citizens to not pollute the cities and make more use of dustbin to drive cleanliness. But awareness of segregation of degradable and non-degradable substance is still a distant dream. Before cleaning up the city, the government needs to sort out a concrete waste management system that ensures segregation and recycling. Process everything that can be processed and dump only the residue in the landfill. I would urge the government to expand the scope of the mission and start spreading awareness on the importance of waste segregation along with the cleanliness drive itself.

Furthermore the Central Board of Excise and Customs (CBEC, MoF, GoI) rather seems to be against the 'Swacch Bharat Abhiyan' as CBEC is denying the legally valid input tax credit on services used for making a Secured Landfill (SLF) to Waste Management entities in India. Rule 2 (1) of CENVAT Credit Rules, 2004 provides definition of input services means any service used by a provider of output service for providing an output service excluding construction or execution of works contract of a building or a civil structure or a part thereof. As you are aware, SLF is created as per Pollution Control Board Guidelines for dumping waste, it is neither a building nor a civil structure. So, simply speaking, Waste Management Entities, which are paying service tax on their service income, cannot claim credit on sources which are used by them. This denial of input tax credit means higher cost to Waste Management Entities. Given the above, can the Government set their internal department (CBEC) in order before telling others to follow the 'Swachh Bharat Abhiyan'.

HON. CHAIRPERSON: Shri Jai Prakash Narayan Yadav; kindly conclude within three minutes.

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : सभापति महोदय, हम तो अभी खड़े ही हुए हैं। आपको इस विÂाय पर बोलने देना चाहिए। ...(व्यवधान) आप हमें कम से कम पांच मिनट तो बोलने दीजिए। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : हमारे पास समय नहीं है। बीएसी ने जो डिसाइड किया है, उसके अनुसार ही हमें चलना है।

â€¦(व्यवधान)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: सभापति महोदय, कृÂण भगवान ने अपनी मां से कहा था कि मइया तुम इन्दू की पूजा मत करो, लेकिन मां नहीं मानी, पिता नहीं माने। जब कृÂण जी आठ साल के बालक थे, तब उन्होंने कहा कि गोवर्धन पर्वत की पूजा कीजिए। उन्होंने कहा कि तुम क्या बोल रहे हो? उस समय इन्दू भगवान ने अपना प्रकोप दिखाया। हमारे पास इतना समय नहीं है, इसलिए हम अपनी पूरी बात नहीं बोल पायेंगे। इन्दू भगवान ने अपना सारा प्रकोप दिखाया, लेकिन कृÂण भगवान ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और कहा कि इन्दू भगवान को जितना भी घमंड है, उसे प्रकृति तोड़ेगी, पहाड़ तोड़ेगा और जनता तोड़ेगी। उस समय इन्दू भगवान हारे थे। हमारा कहना है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। प्रकृति शाश्वत है, निरंतर है। आज मौसम में बदलाव हो रहा है। प्रकृति अजय है और हम उसके जीव हैं। लेकिन आज जीव प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। हमें प्रकृति का आदर करना चाहिए, उसके आंचल के नीचे रहना चाहिए, लेकिन आज हम कुदरत के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। वन, वृक्ष लगाने से हमारे पर्यावरण में सुधार हो सकता है। झील खत्म हो रही हैं। माननीय सदस्य कह रहे थे कि राजस्थान में झीलों का नुकसान हुआ है, तालाबों का नुकसान हुआ है। पहाड़ रक्षक हैं, भक्षक नहीं हैं। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो मालथस थ्योरी लागू हो जाएगी। भूकम्प आया, नेपाल से बिहार तक विनाशकारी लीला हुई। ये सब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने से हुआ है। उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर में ऐसा हुआ है। बाढ़ के समय सूखा और सूखे के समय बाढ़ आ जाती है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। नवीनतम प्रयोग हो रहे हैं, वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं कि मौसम क्यों बिगड़ रहा है। शहरीकरण हो रहा है, इसे रोकने की जरूरत है। जनसंख्या का बोझ बढ़ता जा रहा है। बर्फ की चादर खराब होती जा रही है। कार्बन बढ़ता जा रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, हमें पेड़ लगाने हैं। पेड़ हमारा भविÂय है। सरकारी संस्था और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा स्कूलों में पर्यावरण की पढ़ाई पर जोर देना चाहिए। पर्यावरण के लिए लाइसेंस दे रहे हैं, लेकिन इससे कुछ ठीक नहीं होगा, इंस्पेक्टर राज से कुछ ठीक नहीं होगा। वातावरण के सही निर्माण करने से ही राÂट्र को बेहतर बना सकते हैं। पर्यावरण को ठीक रखना हर आदमी का कर्तव्य है। फसल की बर्बादी हो रही है, जमीन की बर्बादी हो रही है। जल में आर्सेनिक और फ्लोराइड आ रहा है। जान पर खतरा बन रहा है। कैसे मेक इन इंडिया बनेगा? कैसे स्वच्छ भारत बनेगा? कैसे स्वस्थ भारत बनेगा? जब तक वन के साथ छेड़छाड़ होती रहेगी, वन के साथ छेड़छाड़ होती रहेगी, कुछ ठीक नहीं होगा।

बिहार में बाल्मिकी नगर, भीम बांध, बांका, लक्खीसराय में प्राकृतिक छटा का बहुत प्रभाव है। आज राÂट्र का पर्यावरण बिगड़ रहा है, मौसम भी बिगड़ रहा है। राÂट्र का पर्यावरण जनता ठीक करेगी और मौसम को हम मिलजुल कर ठीक करेंगे।

कबीर दास की उलटी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी।

वन, पर्यावरण, जलवायु का मिजाज बिगड़ रहा है। इस पर विशेÂा ध्यान देना होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record except what Shri Dharam Vira Gandhi is saying.

...(*Interruptions*)â€¦ □

SHRI DHARAM VIRA GANDHI (PATIALA): Thank you, Sir, for giving me the opportunity to speak on this important topic. When the entire world is talking about global warming, environmental degradation and climatic changes which endangers to the mother Earth Planet, I am very sorry to say that the number of members present in this august House is very small. This should be the matter of concern for all of us.

Many hon. Members have touched this topic from many angles. I think, they all have touched only from fringes of this topic. I would like to touch it through my brief address and through the basics of this issue. The fact of the matter is that present model of development which we call the capitalist model of development has come in direct contradiction with the mother Earth Planet and with its environment.

The capitalist model of development means profit. It is ruthless both for the human as well as for the natural resources. Therefore in its continuous pursuit of profit, the capitalism ruthlessly exploits not only the human resources, but natural resources as well. It has taken the toll of human resources, it has taken the toll of natural resources, it has taken the toll of our value system and it has taken the toll of very great professions like teaching and medicine. It has taken the toll of environment on this earth. The basic problem of environmental degradation is the present mode of production which has come in contradiction with the very nature itself. Either this model will persist or nature will remain there. So, this is the basic problem, which I would like to touch and it should be taken from that angle.

Secondly, Dr. Michael Chadwick, a well known environmentalist and a noble prize nominee, a few years back, in a Summit on the "Sustainability of Mother of Planet and Population Growth on this Earth", said that it is the developed economies which are culprits for environmental degradation and not the backward economies or the backward countries like us. The biggest parameter as to how much this mother earth planet is endangered depends upon the Resource Demand Index, (RDI) i.e. how much thrust or pressure is on the natural resources from a particular country. The Resource Demand Index of India is 0.25 per cent whereas the Resource Demand Index of the United States of America is 4.17 per cent. They consume 17 times more than the Indian consumers.

We, the people from Third World Countries, the Third Word Societies are very conservative. My mother used to keep an empty tin of oil, safe in our store to be used sometime later for some other purpose. But the 'use and throw' culture, which is classic of the Western economy, is coming into India also. So, we should not pursue that model of development with blind eyes or with that speed. We should have our own innovations, our own indigenous ideas to take our economy forward according to our culture and according to our methods and our indigenous ways.

At the end, I would like to say that in Copenhagen Conference, there was a huge banner raised by 20,000 people from sixty countries, cutting across continents saying "struggle for environment is struggle against capitalism'.

If we have to maintain our environment, if we have to protect our mother earth planet, if we have to escape from global warming and environmental degradation and if we have to save humanity, we should not follow or we should follow very cautiously the capitalist model of development.

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : माननीय सभापति जी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है और इस मंत्रालय के सामने चुनौतियां भी बहुत हैं तथा चिंताएं भी बहुत हैं। मैं समझता हूं कि चुनौती तो ग्लोबल वार्मिंग की ही बहुत बड़ी है, क्लाइमेट चेंज की है और अनएक्सपेक्टेड जो आपदाएं आती हैं, उनका सामना कैसे किया जाए, जैसे जम्मू-कश्मीर में पहले बाढ़ आई और पीछे अभी 14 प्रदेशों में बेमौसमी बारिश हुई। पिछले दिनों में नेपाल, बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेशों में भूकम्प से नुकसान हुआ। इन मुश्किलों को भी चुनौतियों के तौर पर लेना होगा।

दूसरे, जो मैं यह समझता हूं कि इस मंत्रालय में एक तरफ तो विकास की बात है और दूसरी ओर मानवीय जिंदगी की बात है। हमें उसको बैलेंस में रखकर चलना होगा। सबसे बड़ी चुनौती प्रदूÂाण की है। जब प्रदूÂाण होता है, जैसे हवा में, पानी में, जमीन में और खाद्य पदार्थों में प्रदूÂाण होता है तथा दूसरी ओर हमें विकास प्राप्ति के लिए भी प्रयत्न करने हैं, जैसे कैमिकल्स से भी प्रदूÂाण फैलता है, उसको कंट्रोल करना होगा। माननीय प्रधान मंत्री जी ने जैसे अभी सॉयल हैल्थ कार्ड की योजना चलाई है, मैं समझता हूं कि अगर यह योजना किसी तरह से पहले चली होती तो काफी नुकसान होने से बचा जा सकता था। कैंसर और जिगर की बहुत सी बीमारियों को रोका जा सकता था। मैं समझता हूं कि विकास के साथ साथ क्लिअरेंस की भी बहुत जरूरत पड़ती है।ो मैं कहना नहीं चाहता लेकिन क्लियरेंस के नाम पर पिछली सरकार में जो ब्लैक-मेलिंग होती रही, उसके कारण बहुत से विकास के काम रुके। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि मंत्री जी उसमें रिलेक्सेशन लाए और इस वजह से विकास शुरू हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि प्राथमिकता तो मानवीय जिंदगी को देनी ही चाहिए, किंतु विकास को भी देखने की जरूरत है। इसके लिए कोई अल्टरनेटिव सोचना होगा।

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। हम सड़क के लिए, फोरेस्ट के लिए क्लियरेंस देते हैं।...(व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): आप ब्लैक-मेलिंग की क्या बात कह रहे हैं? आप विÂाय पर चर्चा कीजिए।...(व्यवधान)

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजर: मैं बताना नहीं चाहता था लेकिन आपने पूछा है। पहले जो मंत्री थे, उन्होंने मेन क्लियरेंस नहीं दी थी।...(व्यवधान) उसके कारण मंत्रालय से मंत्री जी को हटाना पड़ा।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Chandumajraji, please address the Chair.

...(*Interruptions*)

श्री गौरव गोगोई : महोदय, ये विÂाय पर नहीं बोल रहे हैं बल्कि गलत आरोप लगा रहे हैं।...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Mr. Gogoi, I will examine it. If there is anything unparliamentary, we will expunge it.

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा: महोदय, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सड़क, अस्पताल, बैंक डैम्स आदि चीजों की जरूरत होती है। उसके लिए जहां भी अल्टरनेटिव फोरेस्ट लैंड पड़ी हो, उसे दिया जा सकता है। मेरा संसदीय क्षेत्र सेमी-हिल एरिया है। वहां 40 परसेंट हिस्से में दफा-4, दफा-5 लगी हुई है। मैं अपने संसदीय क्षेत्र की बात आपको बता सकता हूं। दूसरे प्रदेशों हिमाचल या उत्तरांचल के बारे में मैं नहीं कह सकता हूं। हमारे वहां अच्छे जंगल नहीं हैं और जमीन खाली पड़ी है। वहां से हमें मिट्टी का एक ढेला भी नहीं उठाने दिया जाता है। जमीन किसान की है लेकिन वह वहां कुछ नहीं कर सकता है। मेरा सुझाव है कि आप दफा-4 और दफा-5 को उठा कर कंडीशन लगा सकते हैं कि इस एरिया में 40 परसेंट फॉरेस्ट लगाना जरूरी होगा, प्लान्टेशन करनी जरूरी होगी, 60 परसेंट प्लान्टेशन करनी जरूरी होगी। आप किसान से एफिडेविट ले सकते हैं। बाकी जमीन पर आप उसे खेती करने दीजिए, क्योंकि जमीन अब कम हो रही है। चेयरमैन साहब यह महत्वपूर्ण बात है, हमारे पंजाब में विस्फोटक स्थिति बनी हुई है। हमारे पास जमीन कम है। हम उस जमीन को कल्टीवेट कर पाएं, उसके लिए आप दोनों में बैलेंस रख कर कोई उपाय कर लें।

दूसरी बात, जंगलों में से जंगली जानवर निकल कर मैदान में आ जाते हैं। किसानों की फसल का नुकसान हो रहा है और जानी नुकसान भी हो रहा है। जब हम कृÂिा मंत्री जी के पास जाते हैं, हमारी पंजाब सरकार ने एक योजना बना कर भेजी तो कृÂिा मंत्रालय ने कहा कि फॉरेस्ट मंत्रालय के पास जाओ। हमने दो सौ करोड़ रुपये की मांग की है कि या तो फॉरेस्ट को इनसर्किल कर लो या फिर किसानों के खेतों को इनसर्किल करने के लिए जालीदार तार लगाने के लिए कम से कम 50 परसेंट सब्सिडी भारत सरकार दे और 50 परसेंट शेयर पंजाब सरकार दे तो मैं समझता हूं कि किसान भी बच जाएगा और जंगली जानवरों से भी बचाव हो पाएगा। मैं एक बार फिर मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने विकास के लिए रिलेक्सेशन देकर बैलेंस तरीके से इनवायरमेंट के लिए काम किया है।

*SHRI T.G. VENKATESH BABU (CHENNAI NORTH): Though we have a separate ministry of Environment and Forest, the environmental situation in India is very pathetic. This is an area where we have failed miserably.

Air pollution in our country has gone from bad to worse. The Indian cities, which are almost 1/4th of the world cities are the worse affected through the industrial pollution, lack of waste management, transportation vehicles, etc.

The Bhopal gas tragedy of 1984 is not only the world's worst industrial disaster, but also one of the longest one going cover up 30 years on, the relief and adequate compensation to the victims of this accident is still eluding. The disastrous gas leakage in which nearly 25,000 people died and 1.5 lakh still continue to suffer from chronic illnesses. Many of them have been blinded forever. This is a classic case in which the industrial safeguards are proved to be the worst causality and in which the then Indian Government succumbed to the pressures of the MNCs. For the lack of a fool proof liability act, the US union carbide company was enabled to escape from its responsibility to the victims of the accidents.

The present Government does not seem to have learnt lessons from the Bhopal gas tragedy. The Nuclear Liability Act has been recently rendered void through a mechanism by which the international principle of "Polluter pays" is given up. Instead the Government and its agencies will pay the full compensation.

Traditional fuels like cow-dung cake and firewood kill lakhs of people every year through their poisonous fumes. Burning bio-mass as cooking fuel accounts for 3 times the carbon air pollution as all other air pollutants put together, including traffic fumes and industrial smoke. Thanks to the air pollution, Indians have 30% lower lung function than the Europeans. Every year there are 6.27 lakh premature deaths in India due to air pollution apart from the pollution related diseases like heart ailments, cardio-vascular affliction, etc. The pollution arising out of the traffic fumes in urban areas has devastating effects. Still we could not draw adequate parameters to check it. The CNGs used in Delhi vehicles as a pure and alternate fuel has not been carried through like all other experiments.

The Swachch Bharat Mission a cleanliness drive by the Government is welcome. But unless adequate measures are effected for waste disposal through recyclability and biodegradability, creating cleanliness fund involving corporates also, this Mission will end up as yet another publicity stunt. The cleanliness is related to poor conditions. For example, the open defecation which is also a slur on the country's pride can be abolished through providing adequate toilets only. Cleanliness is a luxury for the poor and not to be clean is not their choice.

The conservation of forests along with the species there is most required to maintain the eco system. Rebalancing the ecosystem will have

disastrous consequences. Linear infrastructural projects like roads, railway tracks and power lines that make long intrusions into forests are a new threat to our forests, in addition to submergence by dams or clearance for mines. The norms for such projects are gradually been subjected to dilution which may lead to severe destruction of forests, massive landslides, erosion of the soil and finally destruction of the fragile ecosystem. So, a right balance is to be struck between development and protection of ecology, which will be sustainable in the longer run.

Soil conservation is another important issue. Intensification of farming in the last century led to soil erosion. The genetically modified crops are one such phenomena of intensified farming. GM crops are not sustainable due to fast erosion of the soil, though they may yield huge profits in the initial stages. The International Agency of Research on cancer, a respected arm of UNO declared recently that the two insecticides malathion and diazinon used in the GM crops and the glyphostate in herbicide of Mansanto, in the brand name of Round Up cause cancer. So, the Tamil Nadu Government under the guidance of Madam has banned the entry of GM crops into Tamil Nadu. Even the field trials are not permitted. The UN Food and Agricultural Organization has come out which a finding that because of soil destruction, the world is on an average, has just 60 more years of growing crops. Every year 12 million hectares of cultivatable land is lost through soil degradation. Crop rotation, the use of organic fertilizers and ecologically informed technology grouped together, known as agroecology, can effectively reduce the use of chemicals and soil degradation.

Tamil Nadu Government effectively prevented the Methane project which would have converted the whole Cauvery delta into a desert. DMK which brought the project under its rule, with the permission from the Center in which it was a partner, has now to oppose the project due to the stiff resistance from the farmers.

In a brilliant sunny country like ours, we seem to have largely ignored renewable sources like solar power and wind power. Even biomass fuels like dung can be used to produce biogas, a cleaner and more efficient fuel. T. Nadu Government has achieved the distinction of being in the forefront of producing renewable energy. It has been complemented by the Central Government for this remarkable achievement.

Another major environmental issue is the most threatening global warming. If the global temperature is allowed to exceed the threshold limit of 2Â°c temperature, then the world will face catastrophic consequences. If the outcome of the Lima climate conference is any indication, in all likelihood, the agreement on the Paris summit in December 2015 will be a weak and seriously compensated one that will lead to 3Â°c rise by the turn of the century, with developing countries bearing the brunt of the effects of severe climate change. The equity principle adopted at the first Kyoto Protocol will be seriously eroded and the developed countries will escape from the hook and evade from their historical responsibility for ever.

"The common but differentiated responsibility and respective capabilities" principle adopted in the Kyoto protocol envisages that the industrialist countries which have polluted the atmosphere to the maximum have the historical responsibility to redeem it, when the other countries have common responsibility to mitigate the carbon storage. The major carbon emitter, the USA is the only country which rejected the Kyoto protocol. US is consistently rejecting any legally binding commitments and is virtually doing everything to demolish the Kyoto protocol. The advanced countries will grab most of the atmospheric space leaving developing countries little room for growth. The principle of the equity is rudely discorded. Instead voluntary pledges as pushed by the US are to be the basis of Paris agreement from 2020 onwards. Current low pledges by US and the developed countries are certain to lead the planet to 3Â°-4Â° c.

Voluntary pledges are the main basis of Intended Nationally Determined Contributions (INDCs), a new alternate formulae thrust by US and its conglomerates. These INDCs are not to include the related element of financial contributions and technology transfer to assist the developing countries in their mitigation and adaptation actions in the post 2020 period.

The core principles of Kyoto protocol are included in the adopted text and its seems to have satisfied all the parties in the Lima conference. India's minister for environment and forests has gone on record that all our concerns had been addressed and we got what we wanted. But the reality is not so. "in the light of different national circumstances" - phrase is added to the Common but Differentiated Responsibility principle of Kyoto protocol, leaving room for various interpretations, that suits one. This distortion is also found in the US - China bilateral agreement also. So it is clear that the emerging agreement is going to be centered around INDCs (Intended National Determined Contributions). The U.S is adopting a deviated course of entering into bilateral agreements on climate change which China and India instead of the unviable unilateral approach it adopted so far. This move is to nullify any multilateral agreement reached which will not be at the interest of US. Like China, India also seems to have treaded on this dangerous collusion with US. Developing countries like China and India have failed to lead from the front and betrayed the under developed countries.

The current per capita Green House Gas emission level for China is above 6.5 tonnes of CO_2 equivalent, compared with 17.6 tonnes for the US and according to estimates, it will be around 12-14 tonnes by its peaking year in 2030, similar to US per capita income. This is way above the two tonne limit required to limit the average temperature increase to 2Â°c.

Ultimately the apparent success of the Lima conference from the perspective of the developing countries is only symbolic. The original draft is improved only in form but not in substance. Developing countries, particularly the poor and vulnerable ones, which are already facing the impacts of 0.85Â°c increase since industrialization began, will bear the brunt of the disastrous effects of severe climate change. Kolkata, Chennai and Mumbai the seaside metropolis of India are facing the threat of submersion, since the total increase in sea level in the 20th century is 0.17 meter.

Hence Indian government has to find an alternative path to overcome the disaster of environmental and climate neglects.

*m46

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): सभापति महोदय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

यह एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है और वर्तमान की चुनौतियों और विकास के बीच में किस प्रकार से साम्यता लायी जाए, यह भी एक गंभीर मुद्दा है, जिसको उन्हें देखना है। इस मंत्रालय के अंतर्गत वनस्पति, जीव-जंतु, वन और वन्य जीवों के संरक्षण और सर्वेक्षण का, प्रदूÂाण की रोकथाम और उसके नियंत्रण, वनरोपण और उसकी पुनरूत्पति, पर्यावरण संरक्षण तथा पशुओं के कल्याण आदि से संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

16.45 hrs (Hon. Deputy Speaker *in the Chair*)

महोदय, जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके दो प्रमुख कारण हैं- एक प्राकृतिक कारण है और दूसरा मानवीय कारण है। अंधाधुंध वनों की कटाई, अवैज्ञानिक विकास की सोच और परिवहन तंत्र के कारण भी वायुमंडलीय उत्सर्जन के कारण भी वायुमंडल में गैस और एरोसौल्स एकत्रित हो जाते हैं, जिसने ग्रीन हाऊस इफेक्ट की स्थिति पैदा की है और इससे धरती का तापमान भी बढ़ा है। ग्लोबल वार्मिंग हम सबके सामने एक चुनौती है क्योंकि समुद्र के जलस्तर का बढ़ना, चक्रवाती तूफानों में तेजी आना, आज पूरा उत्तर भारत बेमौसम बारिश और ओलावृÂिट की चपेट में है। किसानों की फसलें उससे प्रभावित हुई हैं। भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज अपने-आप में एक गंभीर चुनौती बनकर आया है। हम सबके सामने महत्वपूर्ण चुनौती यह है कि लगातार वनों का क्षेत्रफल घटा है। कभी यह रेशियो 60 : 40 का था, आज इस देश में मात्र 23 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल ही वनों से आच्छादित है। स्वाभाविक रूप से पर्यावरण के सामने यह एक गंभीर चुनौती है और ये एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन हैं, इनको हम एक-दूसरे से अलग करके नहीं रख सकते हैं। जो अच्छी बातें सामने आयी हैं, वे ये हैं कि अगले पाँच वÂाऩ के लिए ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए मंत्रालय के द्वारा एक प्रयास प्रारंभ हुआ है कि 1.7 लाख करोड़ रुपये सरकारी बैंकों से सोलर और विंड एनर्जी पर खर्च करने के लिए जो व्यवस्था की गयी है, मुझे लगता है कि इससे लगभग 34 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन हो सकता है। आज सुबह ही माननीय मंत्री जी ने यहाँ पर कहा कि सरकार का टारगेट वÂाऩ 2022 तक एक लाख मेगावाट सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन और लगभग 60 हजार मेगावाट विंड एनर्जी के प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा गया है। स्वाभाविक रूप से इससे कोल पर निर्भरता कम होगी और उसका प्रभाव पर्यावरण के लिए अनुकूल होगा क्योंकि जब हम कोल पर निर्भरता कम करेंगे तो उतना ही हमारे लिए अच्छी स्थिति होगी। ग्लोबल वार्मिंग हम सबके सामने एक चुनौती है। यदि समय रहते हमने इस पर नियंत्रण नहीं किया तो दुनिया की बड़ी आबादी भुखमरी की चपेट में आने वाली है और इसका सर्वाधिक दुÂप्रभाव भारत जैसे विकासशील देश पर पड़ने वाला है क्योंकि आज भी तमाम प्रयासों के बावजूद देश में गरीबी की स्थिति 32 प्रतिशत तक बनी हुई है।

हम विकास की बात तो कर रहे हैं, लेकिन विकास के चलते इस देश के अंदर तापमान में वृद्धि की बात आ रही है। उस पर भी हमें अवश्य विचार करना चाहिए और इसीलिए मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्Âिात करना चाहूंगा, जो हाल में ही खास तौर से अभी हम लोगों को देखने को मिले हैं। हमारे हिमालयन क्षेत्र ने अभी दो वÂाऩ पूर्व केदारनाथ में उत्तराखण्ड की त्रासदी को झेला है। अभी पूरा उत्तर भारत जलवायु परिवर्तन, जिसमें अति वृÂिट, ओलावृÂिट की परिस्थितियों को किसानों को झेलने के लिए मजबूर होना पड़ा है। नेपाल में 25 अप्रैल को आये हुए भूकम्प की त्रासदी से न केवल उत्तर भारत, बल्कि पूरा नेपाल आज तबाही की कहानी रच रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि हिमालयन परिक्षेत्र के पर्यावरण के बारे में अवश्य विचार होना चाहिए क्योंकि अगर हिमालय की परिस्थिति के विÂाय को अभी से हम लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया तो भारत के उत्तरी क्षेत्र के लिए हिमालय से आने वाली सदानीरा नदियों के कारण रेगिस्तान बनने का खतरा आने वाले समय में पैदा हो सकता है।

माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नमामि गंगे के रूप में गंगा की अविरलता और निर्मलता के बारे में जो बातें कही हैं, गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए आवश्यक है कि गंगा और उसकी सहायक नदियों को हम प्रदूÂाण से मुक्त रखें और उनकी अविरलता को बनाए रखें। उसके लिए वहां से जितनी नदिया आती हैं, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश को देखता हूं, वहां पर आमी नदी, रोहिनी नदी, वरुणा नदी आदि सभी नदियां पूरी तरह से प्रदूÂिात हो चुकी हैं, उनका जल पीने लायक नहीं है, लेकिन राज्य सरकार का प्रदूÂाण नियंत्रण बोर्ड प्रभावी भूमिका का निर्वाह नहीं कर पा रहा है। जब तक हम लोग उद्योगों का कचरा नदियों में जाने से नहीं रोकेंगे, जो ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाते हैं, उनका उपयोग नहीं होता है। हमारी नगरपालिकाओं ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या तो लगाए नहीं हैं, अगर लगाए हैं तो उनका उपयोग नहीं कर पाती हैं और पूरा कचरा नदियों में जाता है जिससे नदियों का जल प्रदूÂिात होता है। हमें इन नदियों की अविरलता और निर्मलता के लिए ट्रीटमेंट प्लांट की कार्रवाई को करना होगा क्योंकि जल प्रदूÂाण तमाम प्रकार की जलजनित बीमारियों का कारण बन रहा है। प्रति वÂाऩ पूर्वी उत्तर प्रदेश में हम लोग हजारों बच्चों को इंसेफेलाइटिस बीमारी की वजह से खोते हैं। इस बीमारी का जो नया विÂाणु वर्तमान में चिन्हित हुआ है, उसका कारण प्रदूÂिात जल है। राज्य सरकार की प्रदूÂाण के लिए बनाई गयी इकाइयां और बोर्ड हैं, उनको प्रभावी भूमिका निभानी होगी।

प्राकृतिक झीलों के संरक्षण के लिए जो एनएलसीपी की योजना है, गोरखपुर में रामगढ़ ताल परियोजना के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने कुछ राशि उपलब्ध कराई थी। उसी प्रकार से, रामगढ़ ताल की तर्ज पर बखिरा झील है, महेशरा ताल है, इन सभी के संरक्षण की भी योजना इसमें बनाई जाए।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please conclude. The Minister has to reply. Guillotine is there. Therefore, I am sorry.

योगी आदित्यनाथ: अंत में, जो वन्य ग्राम हैं, उनके निवासियों के पुनर्वास की व्यवस्था हो। पिछली बार एक योजना बनी थी कि 75 वÂाऩ से अधिक समय से वन्य ग्रामों में जो लोग निवास कर रहे हैं, उनके लिए सरकार पुनर्वास की व्यवस्था करेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऐसे 56 गांव हैं, उनका पुनर्वास अभी नहीं हो पाया है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस बजट में रामगढ़ ताल, बखरा ताल एवं अन्य तालों के संरक्षण के साथ-साथ उन वन्य ग्रामों के निवासियों के पुनर्वास की व्यवस्था करने के लिए भी प्रावधान किया जाए।

*SHRI P.R. SUNDARAM (NAMAKKAL): I thank you for permitting me to express my views on the demands of Grants of Ministry of Environment and Forest for the year 2015-16 on behalf of my party All India Anna Dravida Munnetra Khazhagam.

Unlike the earlier years, the central government has reduced the budgetary allocation for the ministry of environment and Forest and comparing to the previous years the allocation has been reduced by about 8 percent from Rs.2043 crore in 2014 to Rs.1,681.60 crore this year.

It is strange to me that the government has allocated just one per cent of the total Budget for protecting forests that account for 23 per cent of the country's geographical area and is proposed to be increased to 33 per cent.

The allocation for some other allied schemes like Project Tiger have also been reduced drastically. Nowadays, the contaminated atmosphere, pollution and its related diseases are main concerns with the government. Particularly, the pollution level has increased to alarming level in recent years in metro cities. Therefore, the government should concentrate on the schemes for controlling the pollution across the country. I am also concerned about the limited response given by the government for National Coastal Management Programme, and National Aforestation Programme and the allocation is very less of Rs. 100 crores and Rs. 150 crores respectively.

The area of forest lands is depleting year by year. In this situation, the government should initiate effective deforestation programmes and should give target to the state governments providing necessary allocation of funds for the Aforestation. Major part of forest lands are being occupied for various development programmes which are affecting the ecology of the nation.

Declining forest areas will lead to further worst climatic condition in the country which in turn create negative impacts on the other important sectors like agriculture, industries. Therefore, I would like to urge the government to increase the allocation for the National Afforestation Programme and incentivize the state governments to implement the afforestation programmes effectively.

Here I would like to bring before the notice of the Government about nexus of some rose wood smugglers of Andhra Pradesh with the police. The smuggling of rose wood is estimated to minimum 1000 crores of rupees and are smuggled to various countries especially to Japan and China. But, some of the innocent people are victimized for the benefit of rose wood smugglers and the victims are taken by the state of Tamil Nadu on the pretext of wood cutting works. Generally, the people who are murdered by the Andhra Police are daily wagers struggling to make both ends meet every day. But, to satisfy some mysterious one, these people were killed. I would like to request the government to take action against those who killed the innocents as well as take action to protect rare species of rose woods from traffickers and mafia.

In short, the Government should increase the budgetary allocation and should give equal importance for development for forest areas in the country. It is the need of the hour to protect the existing forest areas as well as protect some of the rare species from the clutches of anti social factors.

□**श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा)**ः मैं पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। बजट में पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर सरकार ने जो पहल की है, वह स्वागत योग्य है। विश्व आज ग्लोबल वार्मिंग से विशेÂाा चिंतित है। हमें खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने इस विÂााय पर उल्लेखनीय कार्य करने की योजना बनाई है। सौ स्मार्ट शहरों की स्थापना व नवीनीकरण सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना इसके प्रमुख अंग के रूप में है। हमें अपनी योजनाएं इस प्रकार से बनानी चाहिए कि विकासशील भारत को विकास की गति के साथ-साथ कार्बन उत्सर्जन कम से कम हो। सोलर मिशन को 20 हजार मेगावाट से 5 गुना बढ़ाना एक लाख मेगावाट करना इस विÂााय पर एक सार्थक कदम है।

वन के क्षेत्र का घटना चिंताजनक है। इसमें से मनरेगा को जोड़कर जो नया प्रावधान किया गया है, उससे वन क्षेत्र को बढ़ाने व उन्हें संरक्षित रखने में मदद मिलेगी। देश में अवैध वनों के कटान को रोकने की और पर्याप्त योजना बनाए जाने व निचले स्तर के तंत्र को सक्रिय करने की जरूरत है। वन संरक्षण अधिनियम के कारण कोई विकास परियोजनाएं लंबित भी न हो तथा इसका कड़ाई से पालन भी हो, इस पर संतुलन रखने की जरूरत है। आज प्लास्टिक कचरा एक बड़ी समस्या है। कानून के दायरे में इसे लाने के बाद भी यह समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। इससे जमीन अनुपजाऊ हो रही है तथा जानवर प्लास्टिक को खाकर बीमार होकर मर रहे हैं। जगह-जगह प्लास्टिक के कचरे के ढेर राÂाट्रीय स्वच्छता अभियान को प्रभावित करने के साथ पर्यावरण को प्रदूÂिात कर रहे हैं। अस्तु इस ओर सरकार को प्रभावी कदम उठाने की यथाशीघ्र जरूरत है। इसी के साथ, मैं पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं।

ओश्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला) : पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-16)पर कुछ सुझाव निम्न प्रकार हैं ः-

1. गांवों में एम्बुलेंस रोड़ बनाने, स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, विद्यालय, महिला मंडल व अन्य छोटी-छोटी चीजों के लिए स्थान उपलब्ध नहीं हो पाता और गांवों के आस-पास जंगल की जमीनें पड़ी हैं और जमीनों के भाव इतने बढ़ गए हैं कि कोई भी इस प्रकार के कामों को भूमि नहीं दे रहे है । इसलिए सरकार ग्राम पंचायत की ग्राम सभा को यह अधिकार दिया जाए कि यदि ग्राम सभा पारित करती है तो सीधे ग्राम पंचायत को यह अधिकार हो कि इन छोटे-छोटे स्थानीय कामों को कोई भी सरकार की स्वीकृति लेने की आवश्यकता न हो ।

2. आज देखने में आ रहा है कि जंगली जानवर किसानों की फसलों को बुरी तरह तबाह कर रहे हैं खासकर बंदर, सुअर, नीलगाय आदि । आवारा पशु भी किसानों की फसलें तबाह कर रहे हैं । इस कारण किसानों ने अपनी खेती करनी बंद कर दी है । दूसरी ओर आवारा कुत्ते भी आज काफी समस्याएं पैदा कर रहे हैं । इन्हीं आवारा कुत्तों ने लोगों को काटना शुरू कर दिया है । गत दिनों आवारा कुत्तों ने कई स्थानों पर हमलाकर उन्हें जख्मी किया है । एक बच्ची जो शौच के लिए खेतों में गई थी उसे बुरी तरह काट कर मार दिया और उसू पूरी तरह खा लिया । कई स्थानों पर पागल कुत्तों का भारी आतंक है और वहां का प्रशासन उन्हें मार नहीं सकते, कानूनी तौर से । इसलिए सरकार को Wild Animal (Protection) Act, 1972 को संशोधित करना चाहिए ।

□**श्री देवजी एम. पटेल (जालौर)**ः भारत में ग्रामीण समुदाय जिसका जीवन-आधार वन कृÂिा व उसके उत्पादन पर निर्भर है, अवसर कानूनी मान्यता के बिना इस संसाधन का प्रभावी विनियोग-व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में समुदायिक भागीदारी में भी अलग-अलग कानूनी प्रावधान हैं। बिना लाभ भूमि ग्राम सहकारी समिति को आवंटित की जा सकती है। चारागाह भूमि पर पंचायत का हक है और वन भूमि पर सामुदायिक प्रबंधन के लिए संयुक्त वन प्रबंधन अधिनियम 1990 और हाल में आए वन अधिकार अधिनियम, 2006 है। देश की लगभग दस प्रतिशत भूमि के साथ राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान राज्य चार भौगोलिक क्षेत्रों में बंटा हुआ है। पश्चिमी रेतीले क्षेत्र अरावली पर्वत माला और अन्य पहाड़ियां और पूर्वी मैदानी और दक्षिण पूर्वी राजस्थानी पठार। राज्य में स्थित अरावली पर्वतमाला देश को अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी के दो जलग्रहण क्षेत्रों में विभाजित करती है।

कृÂिा और पशुपालन राजस्थान में आजीविका के प्रमुख स्रोत होने के कारण एक खास महत्व रखते हैं तथा आजीविका संवर्धन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक का कार्य करते हैं। राज्य के वर्तमान भू-उपयोग में लगभग 20 प्रतिशत भूमि बंजर श्रेणी में मानी जाती है, जो कि काफी खेद का विÂााय है। राÂाट्रीय वन नीति अनुसार जहाँ 33 प्रतिशत जमीन वनभूमि होनी चाहिए, वहीं राज्य में वर्तमान में वन क्षेत्र मात्र 7.71 प्रतिशत है, जो पारिस्थितिकीय मानदंड के अनुसार अपर्याप्त है। चारागाह भूमि कुल क्षेत्र का सिर्फ 4.95 प्रतिशत है, जो राज्य के 540.34 लाख जानवरों के पोÂाण के लिए अपर्याप्त है। राज्य में 7.35 प्रतिशत जमीन बंजर है, जिसमें खेती नहीं की जा सकती। कृÂिा योग्य भूमि मात्र 13.88 प्रतिशत है तथा 6.77 प्रतिशत भूमि अन्य श्रेणी में आती है।

अपने चारों ओर के परिवेश को हमने इस कदर छेड़ा है कि बात अगर पर्यावरण की उठती है तो प्रदूÂाण का सवाल अपने आप ही आगे आ जाता है। मानव एवं सभी प्रकार के जीवन को ढोने वाली पारिस्थितिकी तंत्र में हलचल मचाने वाली समस्या और प्रदूÂाण के व्यापक प्रभाव वाले क्षेत्र निम्नलिखित हैः (क) विलुप्तप्राय जंतुओं का संकट, (ख) जल प्रदूÂाण, (ग) वायु प्रदूÂाण, (घ) स्थल एवं मृदा प्रदूÂाण, और (ड.) ध्वनि प्रदूÂाण

जल ही जीवन है वाली कहावत और इसकी सच्चाई में अगर हम विश्वास करते हों तो जलीय पर्यावरण की पवित्रता का दायित्व भी हमारा ही है। पिछले दशकों में विश्व की जनसंख्या में हुई भारी वृद्धि, शहरी जीवन जीने के प्रति ललक तथा विकास के नाम पर जल में बहाई जाने वाली गंदगी की नालियों को साफ करने की जिम्मेदारी सरकार पर छोड़कर निश्चिंत हो लेते हैं। नतीजतन, समुद्री जल का बहुत बड़ा भाग और विश्व की लगभग सभी नदियां आज जीव संसार के लिए जीवन की तरलता नहीं बल्कि मौत की कठोरता लेकर बह रही हैं। यही स्थिति मेरे संसदीय क्षेत्र की भी है। सम्पूर्ण जिले में लूनी बेसिन का एक भाग है। उसकी सहायक जवाई सूकड़ी खारी बाण्डी तथा साग नदियां जिले के प्रवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। दुर्भाग्य से यह सभी नदियां बरसाती है जो मानसून के बाद सूख जाती हैं जिले में कोई बाराहमासी नदी नहीं है।

हानिकारक गैसों, अतिसूक्ष्म धूलकण या सूक्ष्म रूप से विसरित तरल पदार्थों का वायुमंडल में उसके अपसरन की दर से ज्यादा मात्रा में छोड़ा जाना वायु प्रदूÂाण कहलाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वायु प्रदूÂाण एक ऐसी स्थिति है जिसके बाह्य वातावरण में मनुÂाय और उसके पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले तत्व सघन रूप में एकत्रित हो जाते हैं। मानवीय छेड़छाड़ या प्राकृतिक घटनाओं के आधार पर इसका विस्तार स्थानीय, क्षेत्रीय , महादेशीय अथवा ग्लोबल रूप में हो रहा है। हालात यही रहे तो वह दिन दूर नहीं जब बाजार से शुद्ध ऑक्सीजन का पैकेट लेकर हम सांस लेते फिरेंगे। कुछ वÂाार्ा पूर्व क्या हम यह सोचते थे कि पानी खरीद कर पीना पड़ेगा?

समाज के विकास की घड़ी की सुईयों को थोड़ा पीछे की ओर घुमाकर देखें तो कुछ दशक पूर्व इस स्थल में प्रदूÂाण का कहीं कोई नामो-निशान नहीं था। औद्योगिक कचड़ों तथा प्लास्टिक कहे जाने चमत्कारिक वैज्ञानिक खोज ने अपना यह जलवा दिखलाया है कि शहर की कौन पूछे। आज गांव में भी आप चले जाएं तो स्थल प्रदूÂाण की बानगी दिखाई दे जाएगी। टीन के डब्बे, प्लास्टिक, कागज, सीसे की बनी छोटी वस्तुओं से लेकर लोहे की बनी कार या ट्रक तक के कचड़ों का एक स्थान पर जमाव या विसराव भूमि प्रदूÂाण कर रहे हैं।

मैं राजस्थान के माउंट आबू क्षेत्र से आता हूं। माउंट आबू गुजरात और राजस्थान का दिल है। जैसे भारत के लिए कश्मीर है उसी तरह से माउंट आबू राजस्थान का कश्मीर है। आज माउंट आबू में सबसे बड़ी समस्या 1982 से वहां नक्शे के लिए कोई परमिशन नहीं मिली है। जो वहां के रहने वाले हैं, उनका परिवार बड़ा हो रहा है लेकिन मकान नहीं बना सकते हैं। ईको सैंसिटिव जोन बना कर हमारे साथ अन्याय किया गया है। जब ईको सैंसिटिव जोन से छूट्टी मिली और मास्टर प्लान बनाने की बात हुई तो पहले की सरकार ने कोई इंटेरेस्ट नहीं लिया और आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज भी वहां हजारों पर्यटक आते हैं। वहां रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी मास्टर प्लान लागू करके माउंट आबू की जो रौनक है, उसे वापिस लौटाई जाए। वहां के लोगों को रहने के लिए जो घर बनाने की परमिशन चाहिए। यह घर की बात है और घर नहीं होगा तो सभी बेघर हो जाएंगे। वÂाऩ 1982 के बाद से जिन बच्चों ने जन्म लिया है, उसे रहने के लिए तो घर चाहिए। 1982 से अब तक कोई परमिशन नहीं मिल रही है, बच्चे कहां रहेंगे? क्या कोई सास-ससुर और बाप-बेटा साथ में रह पाएंगे। मेरा निवेदन है कि जो भी कार्यवाही हो, वह जल्द से जल्द लागू हो।

आज दुनिया भर में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। औद्योगिक क्रान्ति के दुÂपरिणामस्वरूप दुनियाभर के लोग प्रकृति का कहर झेलने को मजबूर हैं। 23 साल पहले 1992 में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज बना था। तभी से जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपायों पर चर्चा शुरू हुई, लेकिन अब तक हम इन खतरों से निपटने के लिए कोई ठोस रणनीति पर क्रियान्वयन शुरू नहीं हो पाया है। जो भी निर्णय हुए, केवल सैद्धान्तिक स्तर पर ही टिके हैं। उनका जमीनी धरातल पर उतरना बाकी है। आज गर्मियों में तापमान बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण बिना मौसम के बरसात हो जा रही है। प्रकृति के साथ लगातार छेड़-छाड़ के कारण अत्यधिक बाढ़, सूखा, भूकम्प, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाएं अपना विकराल रूप दिखा रही हैं। आज धरती के बारे में अत्यधिक गंभीरता से सोचने की जरूरत है।

□**श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा)**ः मैं वन तथा पर्यावरण मंत्रालय की अनुपूरक मांगों पर अपने विचार प्रकट करना चाहती हूं। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हमारा पृथ्वी के प्रति प्रेम, आत्मचिंतन और संजीदगी का दिन है। पृथ्वी हमारे जीवन का केन्द्र है इसलिए इसे महज एक दिन के लिए करके अपने कर्तव्यों की इतीश्री नहीं की जा सकती।

पिछली सदी में बड़े पैमाने पर पर्यावरण क्षरण हुआ और इसके नवें दशक तक विकासशील देशों और छठे, सातवें दशक तक विकसित देशों में वायु प्रदूÂाण और ट्रैफिक की समस्या शायद ही देखी गई हो। आठवें दशक के अंत तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को गंभीर मामले के रूप में देखना शुरू हुआ।

ओजोन परत के क्षरण के अलावा पिछली सदी में बड़े पैमाने पर पर्यावरण क्षरण भी देखा गया है। लगभग 80 प्रतिशत उपभोग की वस्तुएं मसलन जीवाश्म ईंधन से लेकर स्टील ऐल्युमिनियम, तांबा जैसे खनिजों और कार जैसी चीजों का उपभोग विकसित देशों की 20 प्रतिशत आबादी कर रही है। आज इन्हीं सबका नतीजा जलवायु परिवर्तन और ओजोन परत के क्षरण के रूप में दिखाई दे रहा है।

आज मानव लोभ से धरती के संसाधनों का क्षय और क्षरण जारी है। प्राणवायु दमघोटू हो चली है। अमृत समान जल मौतों और रोगों की बड़ी वजह बन चुका है और हमारी पृथ्वी को विÂाक्त रसायन से नÂट होती जा रही है। प्राकृतिक आपदाओं की आवृति और आकार में इजाफा हो रहा है। धरती पर बढ़ते इन खतरों ने जन जीवन पर अपना दुÂपरिणाम डालना शुरू किया तो इंसानों को चेतना आई।

अंतरराÂट्रीय संस्था आईपीसीसी के अध्ययन के मुताबिक धरती का औसत तापमान 1.4 फारेनहाइट बढ़ चुका है। अगले सौ साल के दौरान इसके बढ़कर 2 से 11.5 फारेनहाइट होने का अनुमान है। इसीतरह धीरे-धीरे पृथ्वी गरम हो रही है। यह मामूली वृद्धि जलवायु और मौसम प्रणाली में व्यापक रूप से विनाशकारी बदलाव ला सकती है।

यह बढ़ता हुआ तापमान केवल इंसानी जीवन पर ही असर डाल रहा हो ऐसा नहीं है। इसका असर हमारी फसलों पर भी पड़ रहा है। 5-15 प्रतिशत तक फसल की पैदावार कम हो रही है। 3-10 प्रतिशत भारी बरसात के दौरान बारिश की मात्रा में वृद्धि जारी है। 5-10 प्रति नदियों के बहाव में कमी है और 200-400 प्रतिशत जंगलों में लगने वाली आग से प्रभावित खतरों में होने वाली वृद्धि है।

मेरा सभी देशवासियों से अनुरोध है कि यदि पिछली सदी इंसानी जरूरतों के चलते धरती को हुए सर्वाधिक विनाश के लिए जानी जाएगी तो हम आज से ही मिलकर कुछ ऐसा करें कि वर्तमान सदी उन चूकों, उन गलतियों को सुधारने के लिए जानी जाए। इसके साथ ही 15 साल पुराने, जिसके कारण हमारे पर्यावरण और धरती पर सबसे ज्यादा प्रदूÂाण का असर होता है, इन वाहनों पर रोक लगाकर हम अपनी धरती को तोहफा दे सकते हैं।

जैसे कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी जी ने बीते सप्ताह एयर क्वालिटी इंडैक्स का प्रारम्भ करवाया। अमेरिका, चीन, मैक्सिको और फ्रांस के बाद भारत पांचवां देश बना जहां यह तय होगा कि हवा श्वास लेने लायक है कि नहीं। मेरी मांग है कि दिल्ली की तरह ही हर राज्य में पुराने वाहनों पर रोक लगाई जाए। इसके साथ ग्लोबल वार्मिंग तथा प्रदूÂाण को रोकने के लिए कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए कार्बन रहित व न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन पर आधारित तकनीकों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जैसेकि सोलर सेल। कोयला और अन्य जीवाश्म आधारित ईंधन का इस्तेमाल कम किया जाना चाहिए।

परिवहन, वायुमंडल में कार्बन का उत्सर्जन बढ़ाता है। ऐसी स्थिति में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में बढ़ोतरी करने के लिए कुछ रियायतें देनी चाहिए। निजी वाहनों की संख्या घटाई जानी चाहिए। अक्षय ऊर्जा की जरूरतें पूरी करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। विकसित देशों को आगे आकर विकासशील देशां की मदद करनी चाहिए, जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के लिए।

पर्यावरण के तहत भारत के सामने कई गंभीर चुनौतियां हैं। भारत शहरीकरण की ओर बढ़ने की दहलीज पर खड़ा है। 2030 तक भारत में 59 करोड़ लोग बसते हैं।

भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सितंबर 2014 में यूएन की महासभा में कहा था कि चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह ईमानदारी से करना चाहिए। वैश्विक समुदाय, सामूहिक कार्यवाही-समान किन्तु भिन्न-भिन्न जिम्मेदारियों के सुंदर संतुलन पर सहमत है। यह हमारे अनवृत कार्य का आधार होना चाहिए।

विश्व के पृथम जलवायु सम्मेलन 1979 में जलवायु परिवर्तन को एक तात्कालिक वैश्विक समस्या के रूप में पहचाना गया। 1992 में जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त संÂट्र संरचना अभिसमय नामक अंतरराÂट्रीय संधि में कई देश शामिल हुए और 1997 में क्योटो सम्मेलन में अतिरिक्त विकसित देशों के लिए उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्यों वाली बाध्यता हुई।

ग्लोबल वार्मिंग ने समुद्री स्तर, बर्फ की चादर, वÂाऩ को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। जलवायु परिवर्तन पर सुझाए गए महत्वपूर्ण साधनों में कार्बन करों का प्रारम्भिक महत्वपूर्ण साधन है। भारत में 2010 मे कोयले पर एक स्वच्छ ऊर्जा उपकर का प्रारम्भ किया है। 2015-16 के बजट में भी यह 100 से बढ़ाकर 200 करने के प्रस्ताव की मैं सराहना करती हूं।

पर्यावरण संबंधी प्रक्रियाओं की ऑन लाइन मंजूरी करने का केन्द्र सरकार ने राज्यों को कहा, वह भी एक सराहनीय कदम है। जिससे निवेश बढ़ेगा, निवेश से रोजगार बढ़ेगा। पर्यावरण कानूनों में बदलाव के तहत पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर समिति की अध्यक्षता में उच्च समिति गठित की गई। उस समिति ने पर्यावरण मंजूरियों के संबंध में देश में इंस्पेक्टर राज खत्म करने के लिए सिफारिश की है और मंत्रालय वन शब्द की परिभाÂाा भी पुनः तय करने पर विचार कर रहा है। यह भी एक सराहनीय सोच है, मैं इसका स्वागत करता हूं।

अंतरराÂट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के अनुसार कार्बन डाइआक्साइड गैस का उत्सर्जन वÂाऩ 2013 की तुलना में घटकर 2014 में 323 अरब टन रह गया है। यह भी अच्छे भविÂय को प्रतीत करता है। ग्रीन इंडिया मिशन के साथ मनरेगा को जोड़ने की बात भी अत्यंत प्रभावी कदम है। जिससे फारेस्ट एरिया बढ़ेगा और रोजगार भी बढ़ेगा। हरियाली की हिफाजत करनी अत्यंत जरूरी है क्योंकि सभी जगह सीमेंट, कंक्रीट के कारण हरे भरे पेड़ सूख जाने का मामला सामने आया है।

वन मंत्री जी आपके द्वारा हरित कानूनों को सख्ती से लागू करने की बात भी धन्यवाद की पात्र है। प्लास्टिक अपशिÂट के बारे में वन मंत्रालय के प्रयास सराहनीय है।

दुनिया के तमाम जलवायु वैज्ञानिक चिंतित हैं। उन वैज्ञानिकों का आंकलन है कि ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को थामा न गया तो जल्दी ही दुनिया गरीबी और भुखमरी की चपेट में आ जाएगी।

2020 तक 100 गिगावाट सौर ऊर्जा और 100 स्मार्ट सिटी हासिल करने के लिए सरकार की ओर से की गई पहल एक उल्लेखनीय कदम है। सितम्बर 2015 में पेरिस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन पर एक अंतरराÂट्रीय समझौता होने की उम्मीद है जिस पर सबकी निगाहें लगी हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर वैश्विक नजरिया बदलने का आह्वान किया है वह भी समयोचित है। उन्होंने कहा कि दुनिया को कार्बन क्रेडिट की सोच छोड़ कर ग्रीन क्रेडिट की सोच अपनानी चाहिए। सौर ऊर्जा की अपार संभावनाओं वाले देशों का एक कंसार्टियम (संघ) बनाने की जरूरत है। आरकिटैक्ट और सिविल इंजीनियरिंग कॉलेजों के पाठ्यक्रम में बदलाव लाकर उससे ऊर्जा संरक्षण को व्यापक ढंग से समाहित करने पर बल भी दिया है।

मेरी मांग है कि गुजरात राज्य में स्टेचू ऑफ यूनिटी सुलापानेश्वर अभ्यारण को इको सेन्सेटिव जोन बनाया जाए। सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा का निर्माण शुरू हो गया है। इसके पास सुलपानेश्वर अभ्यारण पड़ता है। वहां वन्य प्राणी अभ्यारण की सरहद से 10 किलोमीटर के अंदर रहते हैं। पर्यावरणीय सुरक्षा कदमों के तहत सुलपानेश्वर अभ्यारण जो पहले दुमखल रीच अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था। उसका क्षेत्रफल 150.8 के चौरस किलोमीटर से बढ़ाकर 607.7 चौरस किलोमीटर किया गया है। गुजरात सरकार के वन पर्यावरण विभाग ने सुलपानेश्वर अभ्यारण को इको सेंसेटिव जोन जाहिर करने की दरख्वास्त 2010 और 2013, 2015 में की है।

सीएनजी की पाइप लाइन की मंजूरी के तहत राज्य सरकार को सत्ता मुहैया करवाई जाए। जो भोपाल से कार्यवाही होती है, उस क्षेत्रीय आफिस का बोझ हल्का करने के लिए गुजरात सरकार को सत्ता दी जाए।

एशियाटिक लायन का संरक्षण करने के लिए केन्द्रीय आर्थिक सहायता मिलें, जिसमें 90 प्रतिशत केन्द्र और 10 प्रतिशत राज्य सरकार का हिस्सा होता है। इसके तहत सूचित प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए कुल धनराशि 150 करोड़ की है। इसमें केन्द्र का हिस्सा 135 करोड़ की दरख्वास्त भारत सरकार के पास लंबित है।

अभ्यारण क्षेत्र के आस-पास इको सेंसेटिव जोन जाहिर करने की गुजरात सरकार की कुल 12 दरख्वास्तें (थोल, बालाराम-अंबाजी, बरडा, सुलपानेश्वर, बेलावदर, गोगा, शिवडिया, जेसोल, पोरबंदर, रामपरा, हिंगोलगढ़, नल सरोवर) 2013-14 तक केन्द्र सरकार को पत्राचार हुआ है। लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया। इस पर निर्णय लेना अत्यंत जरूरी है।

रिकवरी प्लान फॉर ग्रेट इंडियन बसटार्ड (गोराड) के लिए केन्द्रीय आर्थिक धनराशि 187.13 करोड़ की दरख्वास्त केन्द्र में निर्णय के लिए पेंडिंग है। यह दरख्वास्त 10 साल के लिए तैयार की गई है, जिसमें गोराड पक्षी का संरक्षण, संवर्धन, आवास सुधारण, राÂट्रीय स्तर का संवर्धन केन्द्र बनाना, इको डवलेपमेंट तथा उनके लिए पानी और खुराक की सुविधा के तहत आर्थिक सहायता मंजूर की जाए।

गिर वाइल्ड लाइफ इंटरप्रिटेशन जोन आम्बरडी के लिए सीजेडए की मंजूरी के लिए 2013-14 से केन्द्र सरकार के पास दरख्वास्त लंबित है। इस पर कार्यवाही की जाए।

मेरा यह सुझाव है कि भारतीय वन रिपोर्ट 2013 के अनुसार देश का कुल वन क्षेत्र 7,71,82 वर्ग किलोमीटर है जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 23.48 प्रतिशत है उसको बढ़ाकर 33 प्रतिशत लाने का प्रावधान करना चाहिए।

श्री दुÂयंत चौटाला (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एवं क्लाइमेंट चेंज मिनिस्ट्री की डिमाण्ड्स फॉर ग्राण्ट्स पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं, पिछले साल भी जब हमने इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा की थी तो हरियाणा के विÂाय में एक ही चीज आई थी कि यमुना नदी में बहुत ज्यादा ताादाद में सिल्ट आता है। निरंतर उसकी माइनिंग की जरूरत है, अन्यथा फ्लड एरिया हरियाणा की ओर बढ़ता जा रहा है, उत्तर प्रदेश में माइनिंग खुली पड़ी है। उस समय भी निवेदन किया गया था कि आपकी मिनिस्ट्री अगर एनओसी देने में थोड़ा सा ईज़-आउट कर देगी तो हमारे यहां के हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। उसी तर्ज पर फरीदाबाद, गुड़गांव, महेन्द्रगढ़, भिवानी जिलों में जो नॉन-अरावली हिल्स हैं, वहां पर भी कई ऐसे एरियाज हैं जो अरावलीज में नहीं आते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अंतर्गत नहीं आते, लेकिन मातृ आपकी गाइडलाइन्स में जो सख्ती है, हार्डनेस है, उसके कारण आज बहुत से युवा बेरोजगार बैठे हैं। बहुत से ऐसे एरियाज हैं, जहां पर सात रुपये से दस रुपये फुट के रेट पर बजरी मिलती थी, सिर्फ आपकी एनओसीज के कारण आज वह 40 रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि वहां एनओसीज के प्रति थोड़ी सी लिनिएन्सी आप बरतें, जिससे जो बीस-तीस हजार युवा यूपीए की सरकार में पिछले दस साल में बेरोजगार हुए थे, वे दोबारा अपने हाथ में रोजगार ले पाएं। आपकी सरकार के एक साल हो चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा कि वहां पर आपकी सरकार गाइडलाइन्स को कुछ ईज़ी करे। जहां नेचर की बात आती है, हम हर रोज टीवी पर देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और दिल्ली सबसे पोल्यूटेड सिटी है।

मैं निवेदन करूंगा और एक आइडिया आपको देता हूं कि जैसे हम विदेशों में जाते हैं तो वहां देखते हैं कि एकाध गली ऐसी होती है जहां गाड़ियां नहीं आती-जातीं, ट्रैफिक फ्री जोन रहता है। उसी तरह से दिल्ली में भी ट्रायल बेस पर आप ऐसी कोई गली या सड़क लें, जहां ज़ीरो ट्रैफिक हो। लोग वहां पैदल जाकरक क्लीन इन्वायरन्मेंट में चाहे शॉपिंग करें या भोजन करें।

जहां तक पर्यावरण की बात आती है हरियाणा में पूरे देश में सबसे कम फारेस्ट एरिया है। अगर लैंड की पर्सेंटेज कम्पेयर करें तो लगभग सवा तीन प्रतिशत एरिया हरियाणा का फारेस्ट के रूप में है। मैं निवेदन करूंगा कि वहां आपकी सरकार है, उसे गाइडलाइंस दें, जिससे प्रदेश के अंदर फारेस्ट एरिया को बढ़ाने का काम किया जा सके। वहां काफी एरिया ऐसा है, जो फारेस्ट एरिया के तहत विकसित हो सकता है, मगर वहां सरकार का ध्यान नहीं गया है। अभी मेरे से पूर्व स्वामी जी भी पर्यावरण के बारे मेंबता रहे थे। जहां हम सोलर और क्लीन एनर्जी की बात करते हैं, महेन्द्रगढ़, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा का बहुत सा एरिया रेगिस्तानी है। आपकी प्रदेश सरकार द्वारा वहां रिनुवल एनर्जी के प्लांट्स लगाए जाएं, जिसके तहत वहां के लोगों को रोजगार मिले और साथ ही साथ जो वेस्ट या डेजर्टेड लैंड है, रिनुवल एनर्जी जेनरेट हो सकती है और जो हम थर्मल के माध्यम से प्रदूÂाण बढ़ाते हैं, उससे भी आपकी सरकार को फायदा हो सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अंत में एक और आइडिया देना चाहूंगा। हमारे यहां फारेस्ट ट्यूरिज्म आपकी हरियाणा सरकार द्वारा एक भी जगह नहीं बनाया गया। वहां मोरनी हिल्स हैं, शिवालिक की डाउन हिल्स हैं, जैसे आपने काजीरंगा और अन्य जगहों पर ट्यूरिस्ट स्पॉट्स बनाए हैं, मोरनी को भी विकसित करने का काम करे, जिसके तहत मोरनी के आसपास पहाड़ों में रहने वाले लोगों को भी ट्यूरिज्म के आधार पर फायदा होगा।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : उपाध्यक्ष जी, मैं अपनी पार्टी जनता दल (यू.) की तरफ से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जनता दल (यू.) ऐसी पार्टी है, जिसने विगत सात पहले यह तय किया था कि यदि कोई व्यक्ति एक पेड़ लगाता है और उसकी फोटो लेकर जाता है, तब ही वह इसका सदस्य बनता है। इसलिए बिहार के मुख्य मंत्री नीतीश कुमार जी को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने पर्यावरण की चिंता पहले से की है। आज पूरी धरती पर पर्यावरण का खतरा साफ नज़र आ रहा है और पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में है। उससे कैसे निपटा जाए, यह

हमारे सामने चिंता का विÂाय है।

हम लोगों ने कभी यह नहीं सोचा कि वृक्ष धरती की अमूल्य धरोहर हैं और लगातार हम उसे काटते चले गए। सरकार ने इसे गम्भीरता से कभी नहीं लिया। प्रकृति की भयावह स्थिति आज भूकम्प की त्रासदी के रूप में, चक्रवर्ती तूफान के रूप में, ओले के रूप में, बेमौसम बरसात और बेमौसम बाढ़-सुखाड़ के रूप में हम सब पर लगातार प्रहार कर रही है। जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है, तो हम सब कुछ तहस-नहस होता देखते रहते हैं। अगर हम वृक्षों को सहेज कर रखें तो प्रकृति में आ रहे बदलाव को रोकने में कामयाब हो सकते हैं। साथ ही साथ पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने में भी कामयाब हो सकते हैं।

महोदय, सब यह भी जानते हैं कि वन की कटाई के कारण जीव-जंतुओं पर असर हुआ है। इसका सीधा प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है। आज बाघ, हाथी और चील आदि जीव-जंतु लुप्त होते जा रहे हैं। सरकार पर्यावरण की रक्षा के लिए जो भी कदम उठा रही है, यहां मंत्री जी बैठ हुए हैं, उनकी तरफ से भी इस बारे में सुझाव आए हैं कि कैसे हम 2020 तक पर्यावरण को सुधार कर अपने इस विशाल देश को आगे ले जाएंगे। मैं भी इस बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

आज तमाम राज्यों की समुचित मदद करने की जरूरत है। आज ऋतु परिवर्तन हो रहे हैं। पहले की अपेक्षा आज ऋतुएं आगे-पीछे हो रही हैं। जिसके कारण जाड़ा, गर्मी या बरसात समय से पहले या समय के बाद आ रही हैं। जैव विविधता संरक्षण की ग्रामीण आजीविका सुधार परियोजना सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। इसमें और भी सुधार करने की जरूरत है। वायु और जल प्रदूÂाण की रोकथाम के लिए उचित प्रबंध करने की जरूरत है। देश की नदियों और झीलों में जो प्रदूÂाण है, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

17.00 hrs

सबसे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण वृक्षारोपण है। सरकार इन परियोजनाओं में हमारे नवयुवकों को जोड़कर कार्यक्रम चलाए ताकि प्रदूÂाण को रोकने के साथ-साथ स्थानीय युवकों को रोजगार के साधन भी उपलब्ध हों। मेरा

सुझाव होगा कि एनएच और रेलवे लाइन्स के दोनों तरफ वृक्षारोपण का कार्य बड़े पैमाने पर चलाने की जरूरत है।

अंत में मेरा सुझाव होगा कि सरकार देश के नवयुवकों को इस कार्यक्रम से जोड़े और वृक्षारोपण के लिए लोगों को प्रेरित करे। धन्यवाद।

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, the Government has already started implementing the T.S.R. Subramanian Committee Report through an Executive Order. This T.S.R. Subramanian Report has gone beyond its mandated review. It has called for a review and complete overhaul of green laws, including National Green Tribunal and Forest Acts. If T.S.R. Subramanian Report is implemented, 97 per cent of our forest area will be opened for mining and only three per cent will remain. Is this the federal approach of the Government in respect of issues which are on the Concurrent List and State List?

Sir, the Government has said that it will have an easy process to provide clearance to industries, but have strict monitoring of compliance. The Ministry of Environment has got Rs. 500 less in comparison to the last year. Their ten regional offices are under staffed. What kind of strict compliance will be there regarding environmental norms? Instead of augmenting manpower and providing funds, now the Government is discussing third-party and self-verification by industries regarding their compliance with environmental norms. This twists the Prime Minister's *mantra* of 'zero effect and zero defect' whereby manufacturing would mean that we shall as a country stop monitoring affects. So, we shall have none.

Sir, Green India Mission requires thousands of crores of rupees. This was a flagship programme to show to the whole world what our efforts are to meet the impact of the climate change. It requires thousands of crores of rupees, but they have given Rs. 64 crore.

What they have given for cleaning up of critical rivers is Rs. 40 crore against a demand of Rs. 294 crore. This is the sum given by them for their conservation. This cannot even be enough to set up one sewage treatment plant.

Paucity of funds is a different thing, but the Government does not even have the political intent or clarity. The Government said that they would not allow any hydro-dam to come up in the eco-fragile area of the River Ganga. Now, they are going to go to the court and saying that there is no need of comprehensive one year study and they will allow the dams to come up. I want to know from the Government categorically whether they have not given to the World Bank their own statement that they are against the consent clause which is required from a Gram Sabha if a forest land is taken. They have given a written document to the World Bank. Is it also not true that this Government has issued a draft order by the Environment Ministry to the Tribal Ministry saying that the consent clause is not required from a Gram Sabha? Why are they doing this? Why are they creating this difference when Schedule VA says that everything there is a forest area? This is the duplicity of this Government that the Minister says something outside and the draft order and the written submissions made to the World Bank say a completely different thing.

This Government came on a promise of creating jobs. Why is it that out of 675 industries identified in Kanpur, Uttar Pradesh, 310 belong to Muslim minority and dalits? Do they want to close them? They employ four to five people. They are asking them to install a reverse osmosis system which will cost anything between Rs. 30 lakh and Rs. 40 lakh while their yearly turnover is between Rs. 10 lakh and Rs. 12 lakh. What sort of promises have they made to the people? They are making small industries, which employ ten to twelve people, jobless. This will have a great social impact.

Sir, these are the important issues I wanted to raise. I hope that once the Minister stands up, he will reply to these points raised by me.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, we are discussing the Demands for Grants under the control of the Ministry of Environment and Forests at a time when an earthquake has taken place in Nepal and more than 4,000 people are dead.

Yesterday also, the whole House unanimously expressed their concern and also expressed grief and sorrow on the disaster. From Kohima Dam disaster to Nepal Dam disaster, it is very clear that we are not considering or we are not giving significance and prominence to the environment and ecology of our country.

So, keeping this aspect in mind, let us examine the Indian environment scenario. The Government of India is fully honouring the

recommendations of the Stockholm Conference of 1972, and you may also kindly see that we are having a very strong constitutional system as well as legal system in order to protect the environment system in our country. The Forest Conservation Act of 1980, Environment Protection Act of 1986, Water Act of 1974, Wildlife Protection Act of 1972, Air Act of 1981 and Forest Act of 1927, these six Acts are the pyramid legislations as far as protection of the environment system in our country is concerned.

In the 42nd Amendment, we have also incorporated a new Article in Directive Principles of State Policy in Part 3 of the Constitution as 48 A directing the Government to protect the forest / wildlife in our country. Another new Article is also incorporated by virtue of the 42nd Amendment, that is, 51 A of the Constitution - fundamental duties of the citizen, and providing that it is the fundamental duty of a citizen to protect the environment, wildlife and our nature. If that be the case, I would like to know this from the hon. Minister, Mr. Prakash Javadekar and from the Government. What is the policy of the Government of India? I reasonably apprehend that there is a drastic shift in the policy of environment protection. Why am I saying this? It is because in the global scenario almost all the countries are making stringent laws for protecting the environment and ecology. But what is happening in India? After this Government has come to power, my apprehension is that more prominence is given to industry and investment in the name of development ignoring environment protection. This is the apprehension, which I would like to make before this House.

Why is it so? If we go through the Demands for Grants, we find that it is not aiming to address any of the core environmental issues, which is being faced by our country. There is no strategy and perspective, and the only green initiative of the Budget is to increase the cess on coal from Rs. 100 to Rs. 200 per tonne. This is the only green initiative, which we can see in the Budget that was presented by the hon. Finance Minister, Mr. Arun Jaitley. There is no allocation or fiscal measures to control air pollution also.

So, the intention of the Government is very clear, and the intention became clearer when Mr. Owaisi has just now pointed out regarding the TSR Subramanian Committee. First of all, I would like to urge upon the Government to please not to accept any of the recommendations of the TSR Subramanian Committee. If the TSR Subramanian Committee recommendations are accepted, then it will be an environmental disaster for this country. Why this Committee has been appointed? Kindly see the constitution of the Committee. A former Cabinet Secretary, Mr. TSR Subramanian is there, and there is no other environmental expert; no experienced person is there; and within two-and-a-half months they have submitted the Report without having any examination, scientific study, field visit analysis, etc.

Sir, kindly see the terms of reference. The first term of reference is that 'the environment law has to be redefined so as to meet the existing necessity'. The terms of reference of that Committee itself is vague, ambiguous and with some other motive or intention. I am saying this because what is the existing necessity? The existing necessity is not mentioned in the terms of reference. The Committee has found out as to what is the existing necessity. The Committee Report goes to say that 'to speed up the procedure in giving clearance to the projects'. This is the existing necessity as far as the recommendation is concerned.

The High-Level Committee worked in tune with the interest of the Government to 'ease of doing business', and accordingly submitted the Report with certain recommendations. Kindly see the number one recommendation. If I am wrong kindly correct me. The term forest has to be redefined? What is the existing definition? The existing definition is that 'existing natural forest or any area, which is declared as a forest by the Government'. The recommendation goes to show that areas within a canopy cover of more than 70 per cent should be treated as forest. What would be its impact? Just now, Mr. Owaisi has stated that the National Forest Survey of India Report is there. In the National Forest Survey of India Report, it is very clear. It is 2013 Report; kindly go through it. Above 70 per cent canopy covered forest area is only three per cent. It means 97 per cent is out of the dense forest area. That will be the impact.

The second recommendation is to have a comprehensive legislation which will be called the Environment Law Management Act (ELMA). What is the intention? It will prevail over all contradictory judgments issued by the courts during the past decades and all the provisions of any environmental law which is prevailing in the country. In order to override the Supreme Court verdicts or the judicial verdicts as well as to override the existing provisions of the environmental laws, this Environment Law Management Act is being enunciated.

Another recommendation is to abolish the Central Pollution Control Board and the State Pollution Control Boards. In their places, new authorities will be coming into existence – one is NEMA and another one is SEMA. 'NEMA' stands for 'National Environment Management Authority' and 'SEMA' stands for 'State Environment Management Authority'. The entire authority and powers are being vested with these two authorities so as to give clearance to the projects.

There is no appeal provision against the orders of NEMA and SEMA. There is only a provision for review. Also, the wings of the National Green Tribunal have been curtailed and there is no original jurisdiction, as far as the NGT is concerned. There also, only the review power is there.

Finally, another recommendation speaks about 'utmost good faith'. It means whatever application for clearance of projects being submitted to the Government, the Government should take into consideration in utmost good faith of the project developers. What does that mean? It means 'ease of doing business'. Further, in *toto*, the High Level Committee Report is a clear attempt to insulate the Government decision from the judicial scrutiny.

If this Report is accepted, it will be a disaster to the country. It will be infringing the constitutional right to a balanced eco system, clean air and clean water to the society. In the name of eliminating Inspector Raj, the High Level Committee reposes complete trust and confidence in the industry and views of the people have no place in this country. It is a clear violation of India's commitment in international treaties and conventions. My only submission to the hon. Minister and the Government is not to accept this Report. I urge upon the Government to reject the Report in *toto.* With these words, I thank you for giving me this opportunity to participate in the debate.

*SHRI ARKA KESHARI DEO (KALAHANDI): I come from district Kalahandi in Odisha. There are many forest areas and wild life sanctuaries. I want to raise a very important issue on wildlife and environment because they are the future and for the next generation to me. The government should give more funding for saving and replanting trees and forestation in Odisha and neighbouring areas. There is a sanctuary named Sonabeda tiger

sanctuary which is effected by the Maoists and its being disturbed by timber mafias cutting down the trees. So I request the Minister to take immediate action and give more forces for petrolling those areas.

You must be knowing that natural calamities like cyclone, earthquakes, have been occurring quite often because one of the reasons is cutting of trees and illegal mining and drilling of unwanted borings so the government should take serious steps to stop illegal mining and take serious action against the timber mafias who are main destroyers of environment and forests. I want to request the Minister to declare special package to Sonabeda and Karlapat sanctuaries in Kalahandi district which are being destroyed by timber mafias and increase the patrolling and make check points and give CRPF jawans in every 10 kms. There is a very important mangrove forest Bitharkanika in Odisha which is famous for crocodiles and bird sanctuary. So I request the government to look into those areas and protect the sanctuary.

Recently in Chilka lake which is 180 kms from Bhubaneswar and the biggest lake of India and famous tourist spot and the largest bird sanctuary is being affected by illegal fishing and poaching of migratory ducks which comes from Siberian countries. I must thanks Shri Navin Patnaik ji our CM who has taken special interests in saving wildlife and forest and taken special interest to grow trees besides the highways. One suggestion from my side to the Minister is to make a rule for all the gram panchayats and villages to leave 30 acres of land for growing mango orchards and valuable trees. I also like to say the farmers must be encouraged by the government and allow them to grow more orchards, fruit bearing trees like there is rule of coffee growers and tea growers there is no sealing of land for coffee growers and tea growers. The government should think seriously to make a rule for mango or any fruit growing orchards should not be limited to certain acres of land. They should be allowed to grow fruit growing trees and herb trees without any sealing of land. There is a major problem for naxals in deep reserve forests. I must request the Home Minister to give more IAP funds in the affected districts of Maoists and specially for growing of trees.

SHRI C.N. JAYADEVAN (THRISSUR): I thank you for giving me an opportunity to participate in the discussion on the Demands for Grants of the Ministry of Environment and Forests. I would also like to make some comments relating to the Ministry of Environment and Forests.

The present earthquake in Nepal and North India rings an alarm of the great disasters waiting to happen to humanity due to our complete negligence of environmental and ecological security. In the name of development, Governments all around the world are pursuing a disastrous course. None of us are against development. We all want to have sustainable development which will ensure minimum satisfactory component for dignified human survival. Unfortunately, the proponents of development are on a course to maximize their profits. We are witnessing an era of complete corporate loot of nature and natural resources and thereby the very existence of humanity itself.

The NDA Government and its hon. Prime Minister, Mr. Modi, and their policies are detrimental to the very environmental and ecological security of India. When you have promulgated the Land Acquisition Ordinance, you have put another rail on the coffin of India's environmental and ecological security. Your intention in regard to environmental impact assessment and social impact assessment, while acquiring large tracts of agricultural land, is a clear negation of environmental and ecological security. All your grand ideas of huge industrial corridors and smart cities have never thought of its environmental and ecological impacts. While you are forcing the State Bank of India to pay Shri Adani, the largest amount in the history of banking by the public sector State Bank of India for their coal mine project is another clear example of utter disregard on environmental and ecological issues.

A vast majority of Kerala people, cutting across their political and religious differences, oppose the proposed Aranmula Airport. It may be interesting to note that this is the one and the only issue on which the Communists, the BJP, the RSS and all religious organizations stand together in Kerala. I would request the Government not to trample upon the interest of vast majority of people. I would request that for the sake of environment security, such an unwanted project should never be permitted. I would request him to declare it in the Parliament itself.

ओश्री अजय टम्टा (अल्मोड़ा) : किसी भी जीवन को जीने के लिए आक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसके लिए वनों की आवश्यकता होती है । अतः वन ही जीवन है ।

मैं भारत सरकार व माननीय वन मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मांगों में इसकी काफी चिंता की गई है ।

सभी माननीय सदस्यों के द्वारा काफी चिंता की जा रही है । प्राकृतिक आपदाये बढ़ रही है । इसमें चिंतन करने की आवश्यकता भी है । मेरा मानना है कि पूरे देश में प्रत्येक प्रदेश को अपने कुल भू-भाग से 40औ भू-भाग को वन क्षेत्र घोÂि◌ात करना चाहिए । प्रदेशों में वृक्षारोपण अभियान चलाकर प्रकृति संतुलन बनाना आवश्यक है ।

मेरा उत्तराखंड प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां देश से भिन्न है । मेरे प्रदेश में लगभग 65औ भू-भाग वनों से आच्छादित है । अतः इसका श्रेय उत्तराखंड की जनता को जाता है कि उन्होंने वनों को कटने नहीं दिया । वन क्षेत्र का संरक्षण किया है । इस प्रकार से पूरे भारत की चिंता उत्तराखंड राज्य कर रहा है । इसकी कारण से हिमालय सुरक्षित है । जिससे निकलने वाली नदियों से भारत का बहुत बड़े भू-भाग सिंचित होता है । पीने का पानी मिलता है । भारतीय उपग्रह डेटा के अध्ययन से पता चला है कि संपूर्ण हिमालय क्षेत्र में 75.779 वर्ग किमी. हिमाच्छादित क्षेत्र में 34.919 हिमनद है । इसी कारण से पूरे देश में गलेशियर आधारित नदियां बहती है ।

जहां उत्तराखंड राज्य देश को इतना कुछ देता है वहीं विकास से पिछड़ता जा रहा है । इसका कारण है कि भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की सारी नियमावली उत्तराखंड राज्य में सख्ताई (कड़ाई) से पालन की जाती है जिससे विकास में पिछड़ता जा रहा है ।

राज्य के मोटर मार्ग/स्वास्थ्य अस्पताल/स्कूल भवनों, जलविद्युत परियोजनाओं से संबंधित फाइलें पत्रावली वÂ◌ा◌ां-वÂ◌ा◌ां तक स्वीकृति नहीं मिलने के कारण उत्तराखंड वासियों को सुविधाएं न मिलने के कारण पिछड़ता जा रहा है । अतः मेरा अनुरोध है कि पर्यावरण व वनों की रक्षा करने वाले लोगों को भी सुविधाएं मिले । इसे भी ध्यान देने की आवश्यकता है । अतः मैं वन एवं पर्यावरण की अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं ।

□**श्रीमती संतोÂ◌ा अहलावत (झुंझुनू)**◌ः मैं डिमांडस फॉर ग्राण्टस अण्डर द् कंट्रोल ऑफ द मिनीस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एण्ड क्लाइमेंट चेंज के पक्ष में अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में माननीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करती हूं। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियानों जैसे पर्यावरण

संरक्षण, वनस्पति जीव-जन्तु, वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण तथा सर्वेक्षण, प्रदूÂाण की रोकथाम एवं नियंत्रण, विकृत क्षेत्रों में वन रोपण एवं पुर्नोत्पति आदि को सुचारू ढंग से चलवाने के लिए बधाई देती हूं।

मेरा संसदीय क्षेत्र झुंझुनू एक शुÂक क्षेत्र है। यहां पर हरित कानूनों को सख्ती से लागू करवाया जाना चाहिए। झुंझुनूं में रिन्यूएबल एनर्जी की पूर्ण भौगोलिक संभावनाएं मौजूद हैं, इस कारण यहां सोलर एनर्जी, पवन ऊर्जा, को लागू करने के लिए मांग करती हूं।

वर्तमान दौर में रेडिएसन एक गम्भीर समस्या है अतः आप इस समस्या से निजात दिलाने के लिए मोबाइल टावर्स को पब्लिक एरिया से दूर स्थापित करने के लिए कदम उठाए।

वन एवं पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण जरूरत पानी की होती है। अतः इसके लिए सरकार झुंझुनूं को नदियों से जोड़ने के लिए कदम उठाए। नगरपालिका क्षेत्रों में होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रदूÂाणों से निजात दिलाने के लिए पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए जो भी उचित योजनाएं हैं उनको लागू कराने के लिए मदद करें।

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : महोदय, मैं पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय की अनुदान माँगों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हमारे विरोधी दलों के लोग बहुत सी बातें कह रहे थे कि मोदी जी की सरकार बहुत तेजी से काम क्यों कर रही है? मैं उनको कहना चाहता हूँ कि लोक सभा चुनाव के बाद जिस हालत में देश हम लोगों को अस्त-व्यस्त स्थिति में मिला था, उसके लिए अगर इतनी तेजी से काम नहीं किया जाए तो परिस्थितियाँ इतनी जल्दी सुधरती नहीं हैं। आज निश्चित रूप से पृथ्वी की जलवायु को लेकर बहुत सारी चिंताएं हैं। जलवायु हमेशा बदलती है, कुछ प्राकृतिक कारणों से बदलती है, कभी-कभी कटाई, उद्योग और परिवहन के कारण भी वायुमंडल में परिवर्तन आते हैं। आज पूरी दुनिया में पर्यावरण को लेकर चिंता है। निश्चित रूप से आज सबसे ज्यादा वही देश ग्लोबल वार्मिंग के लिए चिंतित हैं, जो इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। हम सब जानते हैं कि यूरोप के तथाकथित विकसित देश और स्वयं अमेरिका ने पिछली सदी में जबरदस्त औद्योगिकीकरण करके दुनिया को इस हालत में पहुँचाया है, लेकिन आज वही देश सबसे ज्यादा भारत और चीन के ऊपर पर्यावरण के इस असंतुलन के लिए उंगलियाँ उठा रहे हैं।

मैं निश्चित रूप से यह कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार पर्यावरण की शुद्धता के लिए प्रतिबद्ध है और उसके लिए काम कर रही है। अभी मोदी जी जब संयुक्त राÂट्र संघ में गए थे, उन्होंने अपने भाÂाण में पर्यावरण के शुद्धिकरण के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की थी। हमारे प्रधानमंत्री जी अभी फ्रांस और कनाडा गये। वहाँ उन्होंने यूरेनियम के आयात के लिए इन दोनों देशों से जो बड़े समझौते किए, वह भारत के पर्यावरण को सुधारने में, जलवायु को ठीक करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम भारत सरकार का सिद्ध होने जा रहा है।

महोदय, हमारे देश में जलवायु परिवर्तन हेतु राÂट्रीय कार्य योजना भी हमने बनाई हे, जिसमें आठ मिशन को लिया गया है। उसमें एक मिशन के अनुसार हम लोग वृक्षारोपण और वनावरण, जमीन में ज्यादा से ज्यादा वनों का आवरण हो, इसके लिए हमारी सरकार चिंतित है। 7 लाख 71 हजार 821 वर्ग किलोमीटर में अभी इस देश में वन हैं, जो कुल भू-भाग का 23.48 प्रतिशत ही है। हमारी सरकार ने मनरेगा को ग्रीन इन्डिया मिशन के तहत जोड़ा है। जिसमें हम लोगों ने तय किया है कि वÂाऩ 2020 तक एक करोड़ पौधों का रोपण किया जाएगा, जिससे 30 लाख लोगों को रोजगार भी मिलने वाला है। यह भारत सरकार की योजना है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से यहाँ पर सरकार से कुछ बातें कहना चाहता हूँ। हमारे क्षेत्र में जो वन हैं, वनों के अन्दर बहुत सारे गाँव बसे हुए हैं। जिनमें परम्परागत तरीके से बहुत सारे लोग निवास करते हैं, लेकिन उन गाँवों को राजस्व गाँव का दर्जा नहीं प्राप्त है, जिसके कारण वहाँ का विकास नहीं हो पा रहा है। वहाँ सड़कें नहीं बन पा रही हैं, वहाँ पर हैंडपम्प और शुद्ध पेय जल उपलब्ध नहीं कराया जा सका है, वहाँ विद्युतीकरण नहीं हो पा रहा है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से सरकार से यह माँग है कि उन गाँवों को जो जंगलों में परम्परागत रूप से बसे हैं, उनको राजस्व गाँव का दर्जा दिया जाए। जंगल तथा उसके आसपास जो गाँव बसे हैं, वहाँ पर रहने वाले लोगों को घास-फूस, जलौनी लकड़ी और जो वन के उत्पादन होते हैं, उन्हें लेने की छूट दी जाए। उसके साथ-साथ जंगली जानवरों से अपनी फसलों की रक्षा और अपनी जान-माल की रक्षा का अधिकार दिया जाए। जब भी जानवरों के द्वारा घरेलू पशु, गाय-भैंस आदि या मानवों का शिकार होता है, उसका ठीक-ठाक मुआवज़ा दिया जाए। जो फसलें नÂट हो जाती हैं, उनका मुआवज़ा दिया जाए। पिछले कुछ समय से जो सर्वेक्षण और रिपोर्ट आ रही हैं, वह इशारा करती हैं कि देश और दुनिया की आबो-हवा व जलवायु पर इसका खराब प्रभाव पड़ रहा है, तथा धीरे-धीरे स्थिति भयावह होती जा रही है। परंतु हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि हम अपने देश की जलवायु के साथ साथ पूरी दुनिया की जलवायु को शुद्ध करने के लिए जो संभव होगा, वे सारे प्रयास करेंगे और ऐसी प्रतिबद्धता हमारी सरकार और हमारे प्रधान मंत्री जी ने भी दर्शायी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

□**श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर):** आज वन एवं पर्यावरण संबंधित अनुदान मांगो पर मैं अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। सर्वप्रथम, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

आज मानवता के समक्ष पर्यावरण प्रदूÂाण की समस्या भयावह रूप में खड़ी है। शहरीकरण, औद्योगिकरण, ऑटोमोबाइल्स के बढ़ते प्रयोग, न्यूक्लियर पदार्थों की समस्या, जनसंख्या वृद्धि, वाहनों से निकलने वाला धुंआ और शोर, कल कारखानों से उठने वाला धुंआ, वन संपदा का विनाश, कीटनाशक औÂाधियां, रासायनिक खाद, अनियोजित व अवैज्ञानिक विकास, विलासी जीवन आदि कारणों से निरंतर पर्यावरण प्रदूÂिात हो रहा है। नित्य जीवन में बढ़ते प्लास्टिक का प्रयोग तथा मानवता का प्रकृति से दूर होते चले जाना इत्यादि कारणों ने समस्या को अत्यंत भयावह बना दिया है। ग्रीन हाउसिस गैस के उत्सृजन से ओजोन परत को खतरा उत्पन्न हो गया है। संपूर्ण विश्व इस विÂाय में चिंता व्यक्त कर रहा है। हमारी प्राचीन संस्कृति में पर्यावरण की रक्षा पर विशेÂा बल दिया जाता था।

पांच भूतों (तत्वों) से सृÂिट का निर्माण होता है। इसे मूल प्रकृति भी कहते हैं। ये हैं अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। इन तत्वों में जल, वायु व पृथ्वी ये तीन ऐसे तत्व हैं जिनका सीधा-सीधा प्रभाव हमारे शरीर पर होता है। ये दोनों ही हमारे प्रमुख आहार हैं। इसके अतिरिक्त, अन्न, फल, शाक, सब्जी आदि पृथ्वी पर उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी में उपस्थित खनिज व रसायनों का प्रभाव इन सभी खाद्य पदार्थों में आता है। अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता है तथा जैसा मन होता है वैसा ही कर्म होता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है आहार-शुद्धो सत्व शुद्धि।

हमारे प्राचीन शास्त्रों में भूमि को माता कहा गया है। वेद कहता है "माता भूमि पुत्रोहम् पृथिव्याः।" वेदों में भूमि को माता के समान पवित्र माना गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा घोÂिात कार्यक्रम स्वच्छ भारत अभियान से भूमि की पवित्रता के लिए ही है।

इसी प्रकार जल को पवित्र माना गया है। जल का मुख्य स्रोत नदी है। ऋग्वेद में नदी को भी माता की तरह श्रेÂठ माना गया है। कहा है "नद्यो मातृतयाः।" शायद इसी से प्रेरणा लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने गंगा की सफाई का अभियान किया है। वृक्ष भी वायुमंडल की पवित्रता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मत्स्य पुराण में एक वृक्ष को दस पुत्रों के समान माना गया है - कहा है - दशपुत्रसमं तरः।

इसी पुराण में औÂाधियों व वनों के विÂाय में इन्हें नमन किया गया है। वनानां पतये नमः। औÂाधीनां पतये नमः। वृक्षाणां पतये नमः। अरण्यानां पतये नमः।

वैदिक ऋÂिायों ने वायु को आहार कहा है। वायु को पिता के समान रक्षा करने वाली कहा गया है। - प्रण आयूंÂिा तारिÂात्।

आकाश में शब्द विचरण करते हैं। अतः ध्वनि प्रदूÂाण का प्रभाव भी हमारे जीवन पर पड़ता है। अतः ध्वनि में पवित्रता तथा नियंत्रण होना भी आवश्यक है।

अथर्ववेद के भूमि सूक्त में इन पंच तत्वों की पवित्रता तथा प्रकृति महत्व पर विशेÂा बल दिया गया है।

पर्यावरण संतुलन में जीव जंतुओं का भी विशेÂा महत्व है तथा इन सबकी रक्षा हेतु जंगलों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। प्रकृति के अनुचित दोहन का परिणाम ही है कि नित्य प्रति अकाल, अति वृÂिट, तूफान तथा भूकंप जैसी त्रासदियां हमें झेलनी पड़ रही है। अतः विकास की सोच के साथ-साथ प्रकृति संतुलन पर गंभीरता से विचार करना होगा। भारत सरकार इस विÂाय में कार्य कर रही है

। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि इस विÂाय में महत्वपूर्ण कदम है। अतः मानावता की ही नहीं अपितु प्राणी मातृ की रक्षा हेतु वन एवं पर्यावरण की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके लिए हमें आधुनिक विज्ञान के साथ-साथ प्राचीन ऋÂिायों द्वारा प्रदत ज्ञान को ध्यान में रखना होगा।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र सीकर व प्रांत राजस्थान में पर्याप्त वन क्षेत्र है परंतु उसमें वृक्षों का अभाव है। इसके अतिरिक्त जहां वन है वे सुरक्षित नहीं है। इन वनों को सुरक्षित करने हेतु तथा गायों की रक्षा हेतु तो अभयारण्य विकसित किए जावे। वनों में ऐसे वृक्ष लगाये जावें जिनसे पक्षियों को भोजन मिल सके तथा औÂाधि प्राप्त हो सके जैसे नीम, पीपल, वट, बिल्व, जामुन, हरड़, बहेड़ा, आंवला इत्यादि।

*SHRI GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT (JODHPUR): There are many environmental issues in India. Air pollution, water pollution, garbage, and pollution of the natural environment are all challenges for India. The situation was worse between 1947 through 1995. According to data collection and environment assessment studies of World Bank experts between 1995 through 2010, India has made one of the fastest progress in the world, in addressing its environmental issues and improving its environmental quality. Still, India has a long way to go to reach environmental quality similar to those enjoyed in developed economies. Pollution remains a major challenge and opportunity for India. Environmental issues are one of the primary cases of diseases, health issues and long term livelihood impact of India.

Some have cited economic development as the cause regarding the environmental issues. Others believe economic development is key to improving India's environmental management and preventing pollution of the country. It is also suggested that India's growing population is the primary cause of India's environmental degradation. Systematic studies challenge this theory. Empirical evidence from countries such as Japan, England and Singapore, each with population density similar or higher than India, yet each enjoying environmental quality vastly superior than India, suggests population density may not be the only factor affecting India's issues.

Major environmental issues are forest and agricultural degradation of land, resource depletion (water, mineral forest, sand, rocks, etc.), environmental degradation, public health, loss of biodiversity, loss of resilience in ecosystems, livelihood security for the poor.

The major sources of pollution in India include the rampant burning of fuelwood and biomass such as dried waste from livestock as the primary source of energy, lack of organised garbage and waste removal services, lack of sewage treatment operations, lack of flood control and monsoon water drainage system, diversion of consumer waste into rivers, cremation practices near major rivers, government mandated protection of highly polluting old public transport, and continued operation by Indian Government of government owned, high emission plants built between 1950 to 1980.

Air pollution, poor management of waste, growing water scarcity, falling ground water tables, water pollution, preservation and quality of forests, biodiversity loss, and land/soil degradation are some of the major environmental issues India faces today. India's population growth adds pressure to environmental issues and its resources.

There is a long history of study and debate about the interactions between population growth and the environment. According to a British thinker Malthus, for example, a growing population exerts pressure on agriculture land, causing environmental degradation, and forcing the cultivation of land of poorer as well as poorer quality. This environmental degradation ultimately reduces agricultural yields and food availability, causes famines and diseases and death, thereby reducing the rate of population growth.

Population growth, because it can place increased pressure on the assimilative capacity of the environment, is also seen as a major cause of air, water, and solid-waste pollution. The result, Malthus theorised, is an equilibrium population that enjoys low levels of both income and environmental quality. Malthus, suggested positive and preventative forced control of human population, along with abolition of poor laws.

Malthus theory, published between 1798 and 1826, has been analysed and criticised ever since. The American thinker Henry George, for example, observed with his characteristic piquancy in dismissing Malthus: "Both the jayhawk and the man eat chickens; but the more jayhawks, the fewer chickens, while the more men, the more chickens." Similarly, the American economist Julian Lincoln Simon criticised Malthus's theory. He noted that the facts of human history have proven the predictions of Malthus and of the Neo-Malthusians to be flawed. Massive geometric population growth in the 20th century did not result in a Malthusian catastrophe. The possible reasons include: increase in human knowledge, rapid increases in productivity, innovation and application of knowledge, general improvements in farming methods (industrial/agriculture), mechanization of work (tractors), the introduction of high-yield varieties of wheat and other plants (Green Revolution), the use of pesticides to control crop pests.

More recently scholarly articles concede that whilst there is no question that population growth may contribute to environmental degradation, its effects can be modified by economic growth and modern technology. Research in environmental economics has uncovered a relationship between environmental quality, measured by ambient concentrations of air pollutants and per capita income. This so-called environmental Kuznets curve shows environmental quality worsening up until about $5,000 of per capita income on purchasing parity basis, and improving thereafter. The key requirement, for this to be true, is continued adoption of technology and scientific management of resources, continued increases in productivity in every economic sector, entrepreneurial innovation and economic expansion.

Other data suggests that population density has little correlation to environmental quality and human quality of life. India's population density, in 2011, was about 368 human beings per square kilometre. Many countries with population density similar to higher than India enjoy environmental quality as well as human quality of life far superior than India. For example: Singapore (7148/km2), Hong Kong (6349/km2), South Korea (487/km2), Netherlands (403/km2), Belgium (355/km2), England (395/km2) and Japan (337/km2).

India has major water pollution issues. Discharge of untreated sewage is the single most important issue for pollution of surface and ground water in India. There is a large gap between generation and treatment of domestic waste water in India. The problem is not only that India lacks sufficient

treatment capacity but also that the sewage treatment plants that exist do not operate and are not maintained. The majority of the government-owned sewage treatment plants remain closed most of the time due to improper design or poor maintenance or lack of reliable electricity supply to operate the plants, together with absentee employees and poor management. The waste water generated in these areas normally percolates in the soil or evaporates. The uncollected wastes accumulate in the urban areas causing unhygienic conditions and release pollutants that leaches to surface and groundwater.

According to a World Health Organization study, out of India's 3,119 towns and cities, just 209 have partial sewage treatment facilities, and only 8 have full wastewater treatment facilities. Over 100 Indian cities dump untreated sewage directly into the Ganges River. Investment is needed to bridge the gap between 29000 million litre per day of sewage India generates, and a treatment capacity of mere 6000 million litre per day.

Other sources of water pollution include agriculture run off and small scale factories along the rivers and lakes of India. Fertilizers and pesticides used in agriculture in northwest have been found in rivers, lakes and ground water. Flooding during monsoons worsens India's water pollution problem, as it washes and moves all sorts of solid garbage and contaminated soils into its rivers and wetlands.

Air pollution in India is a serious issue with the major sources being fuelwood and biomass burning, fuel adulteration, vehicle emission and traffic congestion. Air pollution is also the main cause of the Asian brown cloud, which is causing the monsoon to be delayed. India is the world's largest consumer of fuelwood, agriculture waste and biomass for energy purposes. Traditional fuel (fuelwood, crop residue and dung cake) dominates domestic energy use in rural India and accounts for about 90% of the total. In urban areas, this traditional fuel constitutes about 24% of the total. Fuel wood, agri waste and biomass cake burning releases over 165 million tonnes of combustion productions into India's indoor and outdoor air every year. These biomass-based household stoves in India are also a leading source of greenhouse emissions contributing to climate change.

The annual crop burning practice in northwest India, north India and eastern Pakistan, after monsoons, from October to December, are a major seasonal source of air pollution. Approximately 500 million tons of crop residue is burnt in open, releasing smoke, soot, NOx, SOx, PAHs and particulate matter into the air. This burning has been found to be a leading cause of smog and haze problems through the winter over Punjab, cities such as Delhi, and major population centers along the rivers through West Bengal. In other states of India, rice straw and other crop residue burning in open is a major source of air pollution.

Vehicle emissions are another source of air pollution. Vehicle emissions are worsened by fuel adulteration and poor fuel combustion efficiencies from traffic congestion and low density of quality, high speed road network per 1000 people.

On per capita basis, India is a small emitter of carbon dioxide greenhouse. IN 2009, IEA estimates that it emitted about 1.4 tons of gas per person, in comparison to the United States' 17 tons per person, and a world average of 5.3 tons per person. However, India was the third largest emitter of total carbon dioxide in 2009 at 1.65 Gt per year, after China (6.9 Gt per year) and the United States (5.2 Gt per year). With 17 percent of world population, India contributed some 5 percent of human-sourced carbon dioxide emission; compared to China's 24 percent share.

The Air (Prevention and Control of Pollution) Act was passed in 1981 to regulate air pollution and there have been some measurable improvements. However, the 2012 Environmental Performance Index ranked India as having the poorest relative air quality out of 132 countries.

Trash and garbage is a common sight in urban and rural areas of India. It is a major source of pollution. Indian cities alone generate more than 100 million tons of solid waste a year. Street corners are piled with trash. Public places and sidewalks are despoiled with filth and litter, rivers and canals act as garbage dumps. In part, India's garbage crisis is from rising consumption. India's waste problem also points to a stunning failure of governance.

In 2000, India's Supreme Court directed all Indian cities to implement a comprehensive waste-management programme that would include household collection of segregated waste, recycling and composting. These directions have simply been ignored. No major city runs a comprehensive programme of the kind envisioned by the Supreme Court.

Indeed, forget waste segregation and recycling directive of the India's Supreme Court, the Organisation for Economic Cooperation and Development estimates that up to 40 percent of municipal waste in India remains simply uncollected. Even medical waste, theoretically controlled by stringent rules that require hospitals to operate incinerators, is routinely dumped with regular municipal garbage. A recent study found that about half of India's medical waste is improperly disposed of. Municipalities in Indian cities and towns have waste collection employees. However, these are unionised government workers and their work performance is neither measured nor monitored.

Some of the few solid waste landfills India has near its major cities are overflowing and poorly managed. They have become significant sources of greenhouse emissions and breeding sites for disease vectors such as flies, mosquitoes, cockroaches, rats and other pests. In 2011, several Indian cities embarked on waste-to-energy projects of the type in use in Germany, Switzerland and Japan. For example, New Delhi is implementing two incinerator projects aimed at turning the city's trash problem into electricity resource. These plants are being welcomed for addressing the city's chronic problems of excess untreated waste and a shortage of electric power. They are also being welcomed by those who seek to prevent water pollution, hygiene problems, and eliminate rotting trash that produces potent greenhouse gas methane. The projects are being opposed by waste collection workers and local unions who fear changing technology may deprive them of their livelihood and way of life.

Along with waste-to-energy projects, some cities and towns such as Pune, Maharashtra are introducing competition and the privatization of solid waste collection, street cleaning operations and bio-mining to dispose the waste. A scientific study suggests that public private partnership is, in Indian context, more useful in solid waste management. According to this study, government and municipal corporations must encourage PPP-based local management through collection, transport and segregation and disposal of solid waste.

Continuous deforestation and increasing the abuse to natural resources is a big point of concern not only in our country but in the entire world. It is our cumulative responsibility which all of us in this era have to understand that we need to transfer the nature without disturbing it or minimally disturbing to our coming generations. Here we have a point to cheer that From 1990 to 2000, FAO finds India was the fifth largest gainer in forest coverage in the world; whilst from 2000 to 2010, FAO considers India as the third largest gainer in forest coverage but still we have to walk miles

together with passion to protect the environment and save the earth.

□**श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत)**ः अगर हमारे देश की फोरेस्ट विभाग की समस्याओं को देखा जाए तो जहां तक मेरी जानकारी है हमारे देश में 20.55 प्रतिशत विस्तार कवर होता है। जबकि आवश्यकता 33 प्रतिशत की होती है। अपने देश में वन्य उत्पादन की जो डिमांड है उससे उत्पादन कम होता है। जैसे कि अपने जंगलों की वार्Âिाक पैदावार 0.5 क्यूबिक मीटर प्रति हेक्टर है जबकि अमरीका में 1.25 क्यूबिक हेक्टर और जापान में 1.8 क्यूबिक मीटर प्रति हेक्टर और फ्रांस में 3.9 क्यूबिक मीटर प्रति हेक्टर है। इस कारण से जो वन्य चीजों की कटाई होती है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में होती है। मेरा मान्यवर मंत्री महोदय से आग्रह है कि वन्य पेदाशों को बढ़ाने हेतु एवं उसके ऊपर का अवलंबन कम करने हेतु प्रयास किए जाए। साथ ही साथ, वन्य क्षेत्र में उनको मुख्य ग्रामीण एवं शहरी विस्तार से जोड़ने हेतु उचित प्रबंध किए जाए। साथ ही वन्य क्षेत्र में रहने वाले लोगों को क्षेत्र के अनुरूप उत्पादन एवं चीजों को बनाने का प्रशिक्षण दिया जाए।

वन्य क्षेत्र में इतनी बारिश होती है वह आम तौर पर पता ही नहीं चलता। जिसके कारण वह पानी जब एक साथ बहता है तो पुर की नौबत आती है। जिसका अनुभव पिछले दिनों में हो चुका है और वन्य संपदा का भी काफी नुकसान हमें झेलना पड़ता है। मेरा आग्रह है कि वन्य विस्तारों में गेज स्टेशनों जैसी व्यवस्था खड़ी करनी चाहिए ताकि ज्यादा बारिश के बाद होने वाली तबाही से बचा जा सके।

हमारे देश का बहुत ही बड़ी मात्रा में वन्य संपत्ति का नुकसान वन में लगने वाली आग से होता है। मेरा सुझाव है कि वन में रहने वाले एवं आस-पास रहने वाले लोगों को इस विÂाय में शिक्षित और जागृत किया जाए। जिस तरह से आदमी बीमार होता है उसी प्रकार पेड़-पौधे भी और वन्य जीव जन्तु भी बीमारी का शिकार होते हैं। उस का ध्यान में रखते हुए संशोधन, मैपिंग एवं व्यवस्था खड़ी करनी चाहिए। साथ ही साथ ,वनों के संरक्षण हेतु ज्यादा से ज्यादा विज्ञान का सहारा लेकर व्यवस्था खड़ी करनी चाहिए। वन में रहने वाले लोगों को उनके आस-पास के पेड़-पौधों को रख-रखाव, उस के प्रोडक्ट के ऊपर अधिकार का शिक्षण एवं लाइसेन्स देना चाहिए।, ताकि वन में रहने वाला व्यक्ति ही वन का संरक्षक बने।

SHRI D.K. SURESH (BANGALORE RURAL): Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on the Demands for Grants under the control of Ministry of Environment, Forests and Climate Change.

Protecting the environment and forests is essential for our survival. Unless we protect our forests, wildlife, water bodies, and control pollution, we will have nothing for our future generations. As you can imagine, there are many challenges in protecting the forests and environment in India. Without adequate budget, the challenge has become bigger. Sir, I would like to continue my speech in my mother tongue Kannada.

□Sir, I would like to draw the kind attention of the Hon'ble minister of Environment and forests and also the august house towards the problems faced by the state of Karnataka.

Sir, while presenting the budget Hon'ble union finance minister has mentioned that as per the recommendations of the 14th finance commission the union govt has increased the devolution of Central grants to the states by 10%. Accordingly, the state of Karnataka has got Rs 24,000 Crores in the current financial year. If we go by the allocation made under the Centrally Sponsored Schemes my state is losing nearly Rs. 8146 Crores this year. It is due to reduction in allocation of funds to various Centrally sponsored ongoing schemes. Now the burden is on the state government to fund all those programs to complete the works. In this way Karnataka has not been benefited from the 14th finance commission recommendations but facing huge financial burden.

Hon. Deputy Speaker, I would like to mention that the state of Karnataka has abundant forest and wild life resources. I wish to give all the details of the impact of cutting down the allocation of funds. But due to paucity of time I am not going into the details of all these figures. However I would mention certain facts on the floor of the house. The latest tiger census shows that Karnataka has the

highest number of tigers in the country. There is about 25% increase in the tiger population in Karnataka state. But the allocation for the project Tiger is reduced by 25%. In the 2015-16 budget, for the Project Tiger you have allocated only Rs. 136.46 Crores. This is a very important project. Therefore, sir, through you, I request the Hon'ble minister to increase the allocation to preserve and conserve the tiger population in the country including Karnataka.

Sir, my next point is about the allocation for Forest Survey. In this budget Rs. 17.61 Crore is allocated for Forest Survey. Whereas it was Rs. 20.39 Crores in the year 2014-15. There has been constant conflicts between the farmers, Revenue and Forest authorities over the land issues in the absence of clear demarcation of boundaries between Revenue and Forest land in the country. Farmers and tribals are suffering for no fault of theirs. Therefore I urge upon the union government to conduct a joint survey involving both Revenue and Forest departments to resolve the issue once for all. This is not possible with the meager allocation of Rs. Rs. 17.61 Crore. Hence I request the hon'ble minster to increase the allocation for the joint survey to demarcate boundaries of Revenue and Forest land.

Sir, I would like to draw the attention of the government towards the need for effective implementation of the provisions of very important legislation passed by the UPA government i.e. the Forest Rights Act-2006. The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of ***Forest Rights***) ***Act, 2006***, is a key piece of forest legislation brought by the UPA Govt under the visionary leadership of Smt. Sonia Gandhi ji. Our government enacted the law to protect the rights of livelihood of thousands of forest dwellers, tribals, Scheduled Caste and poor people dependant on the forests over the decades. Now, the NDA Govt is not taking any step to change the irregularities in the provisions of the existing law to ensure the benefits to forest dwellers, tribals and Scheduled Castes.

Sir, there were about 2, 60,000 poor people made claims on the forest lands as their cultivating area for decades. Out of this, only 6,800 people were granted the right to those land. Remaining applications were rejected. In this connection I would like to point out that it is quite evident that the present NDA Govt is not at all working for the poor people and farmers, but favouring the private parties and corporates. That is why I would say this is an anti farmer and anti-people government. It is a matter of great concern that the Govt is not keen on these issues and this has been expressed by all the Hon'ble members who have spoken prior to me. Therefore, I urge the government to take steps to implement this Act under the Vigilance Monitoring Committee (VMC) to ensure that the real beneficiaries are benefitted.

HON. DEPUTY SPEKAER: The Minister has to reply. We are getting late.

SHRI D.K.SURESH: Sir, I am making some observations on a very important issue of the livelihood of our ANNADATA, the farmers. Please give me some more time to finish my speech.

HON. DEPUTY SPEKAER: Now, the Minister may start his reply.

SHRI D.K.SURESH: To save our forest, we need to mitigate the agonies of farmers who are depending on the forest. Sir, It is the first and foremost duty of any Government to protect farmers, forest dwellers and tribals. So I urge upon the Government through you to grant the land rights to forest dwellers without any further delay.

Sir, another very important issue is the increasing incidents of man-animal conflicts. Particularly the Wild Boar menace has created a havoc in Karnataka. The wild boars destroy the standing crops and causing severe loss to farmers. It is a matter of great concern that the government has not made any provision for compensation to farmers in case the crops are destroyed by Wild Boars. Wild Boar is listed in the Wild Life Schedule Even though there is no provision for compensation to a farmer if he or she suffers due the wild boar menace. This is very unfortunate. Therefore, I urge the union government to look into the issue and take steps to provide compensation to the farmers in case the crop is damaged due to wild boar attack.

Similarly there is no provision made to give compensation to people who suffers from Bear attacks and snake bites. Therefore I request the union government take steps to give compensation to these victims, irrespective of where the incidents take place.

Sir, with regard to Masheer fish I would like to mention that Shivanasamudra and Mekedatu are situated on the banks of river Cauvery, which flows through my constituency. It is widely known for famous masheer fish. The Wild Life Association of Southern India (WASI) has protected the Masheer and other wild animals in this region for several decades. In the past decade people from all over the world used to come for Masheer Sport Fishing. It used to provide employment to local people and also generate revenue to the Government. Now, the Cauvery Wildlife Sanctuary has come up and the Forest department has imposed a ban on Masheer fishing sport in the area. Therefore, I urge the government to look into this issue and take steps to encourage masheer fishing and also to promote eco-tourism in this area. Nowadays, the population of Urban areas is increasing rapidly. The unplanned expansion is causing water, air and noise pollution all over the country. The pollution control board has to be given more funds to tackle these issues. In my constituency, there are two rivers near Bangalore City, the Vrishabhavathi and South Pinankini rivers. All the waste and sewage from Bangalore City go into these rivers. As a result Lead/Mercury content is seen in these waters. However, these rivers are not identified as polluted rivers by the Ministry. You have to provide funds for the rejuvenation of these rivers.

Sir, there are incidents of people killed by wild animals while collecting firewood or while they are grazing their cattle. There is no provision to give compensation to such victims. The forest officials deny them compensation saying that the forest area is considered as protected area. In this connection I would like to mention that the forest authorities allowed cattle and sheep grazing and also collecting fire wood. When such unfortunate incidents of deaths of people due to wild animal attack the very same forest authorities deny compensation saying that it takes place in the protected area. Therefore I urge the union government to contemplate the issue and take steps to give compensation to those people who are losing their lives due to attacks of wild animals in forests, along with protecting the rights of forage and grazing their cattle in these areas.

Sir, Another important issue I would like to mention is that the compensation to people who lost his/ her life due to wild animal attack is fixed at Rs. 2 lakhs. Sir, this is very inadequate and therefore I urge the union Govt to increase the compensation from 2 lakhs to Rs 5 lakhs in case of death of a person due to wild animal attack.

Sir, I would like to point out that there is Hakki-Pikki tribal colony near Bennargatta national park in Bengaluru. It is in the jurisdiction of my Parliamentary constituency. The tribals of this colony have been allotted about 360 acres of land more than50-60 years ago. However there is no entry made in records of both Forest and Revenue authorities. Till date these tribals do not have any piece of document to claim their land, which has been enjoying by them for decades. Now the forest authorities are harassing them and trying to evict them from their land. I wrote several letters to hon'ble minister to look into this issue and ensure the rights of the tribals.

HON. DEPUTY SPEKAER: Cut motions are also there. you have already take more than five minutes.

SHRI D.K.SURESH: Sir I would like to mention that the Hon'ble minister of chemicals and fertilizers Shri. Anant Kumar, who is representing Bangalore South Lok Sabha Constituency, has selected Ragihalli village located near the said colony under the Sansad Adarsh Gram Yojana.

HON. DEPUTY SPEKAER: Please conclude.

SHRI D.K.SURESH: Sir, I am talking about a very important scheme of the hon'ble Prime Minister i.e. Sansad Adarsh Gram Yojana. Kindly allow me to complete my speech.

HON. DEPUTY SPEKAER: Mr. Minister, he is concluding. Please sit down.

SHRI D.K.SURESH: Sir I urge upon the union government to take steps to grant land rights to the tribals living in the Hakki -Pikki colony.

In our country, there are 18 States where there are tigers. Since 1973, tiger is our national animal. There are recent reports that the newly constituted Animal Welfare Board is recommending lion as national animal. Lion is found only in Gujarat. India is not just about Gujarat. So, kindly look into this matter.

Thank you. With these words, I will conclude.

*ADV. JOICE GEORGE (IDUKKI): Given the importance and necessity to protect the environment, ecology and forests, there is an approved outlay of

Rs. 17,874 crore for the Ministry during the 12th plan over and above 79% of the previous plan. Till the end of third plan year, only Rs. 6903 crore against Rs. 10,724.24 cr. has been allocated, whereas, actual utilization has been only Rs. 5200 crore from these figures, it is evident that the Government is reluctant in allocating funds to the greater cause of environmental concerns and the ministry is apathetic in attitude to utilize the allocated funds.

When we are proceeding from 1997 Kyoto protocol under the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCC) to the Paris Convention in the end of this year, there is greater need to bring clarity as regards the utilization of carbon markets to the benefits of our country especially the indigenous people, the farmers and the marginalized. This is because, under the market based mechanisms of carbon trading, the developed nations are trying to impose environmental colonialism or assisted colonialism in our land. On one end, big industries and governments, in hand with big conservation organizations and financial institutions, are able to buy cheap credits and gain profits whereas the communities, affected by the projects would be affected by land and human right violations, displacement, land grabbing and so on. The conservation initiatives in the Western Ghats through Western Ghats Ecology Expert Panel (WGEEP) Report and High Level Working Group (HLWG) Report is a classical example of conservation aiming at colonization. I urge upon the Government to drop all steps taken on the basis of WGEEP and HLWG Report as regards the conservation of Western Ghats.

The Prime Ministers council on Climate Change convened on 19 January 2015 had discussed the proposal of cutting the emissions from agriculture sector. Over the past few years, the developed countries have been campaigning to force the developing countries to cut emissions from agriculture and livestock. We have been vehemently opposing to bring farm emissions within the ambit of climate action to safeguard our farmers who are mostly small and marginal landholders. This has been the important component of our international climate position for long. If the new proposal is accepted, the same will dilute our position on the matter. The total contribution of agriculture to the Green House Gas emission is only 14% out of the 2486 million tons of carbon dioxide emitted. We vehemently oppose the US and the European Union proposal to adopt emission targets for agriculture sector during the 2013 Warsaw Climate Change Summit. The historical responsibility of the developed countries should be focused on the negotiation and unfortunately the negotiations are now deliberately focused on the current emission denying the developing countries their basic right to grow and develop. Therefore, we have to act together in securing our right to develop and be energy sufficient.

It is also important to amend various forest and environmental laws to meet the challenges of conservation as well as to meet the aspirations of the people. Since, the forest is not defined in the Forest Conservation Act 1980, the term forest is being interpreted according to the whims and fancies of the concerned and therefore an amendment should be brought in giving clear and unambiguous definitions to 'forest' excluding plantations, farmlands and inhabited areas. The wildlife protection act should be amended incorporating the provision to contain the wildlife, both prey and predators, within the carrying capacity of the sanctuaries, national parks and forests in a scientific manner to avoid man-animal conflicts and ensure sustainable development and sufficient compensation to the farmers in the event of damages due to crop raids by wild life.

The NGT Act 2005 is to be amended preventing legal illiterates from participating in the judicial process being the expert members representing various NGOs and other interest groups.

The wildlife department under the ministry has been used for getting international funding and appropriates the same for the benefit of a privileged few. In my constituency, the wildlife department was trying to implement a project namely India High Range Mountain Landscape (HRML) with financial aid from Global Environmental Facility (GEF) routed through UNDP, with an objective to deny the right of the agrarian community over their land by way of restrictions and controls. The activities carried out in PTR and other nearby national parks and sanctuaries with the aid of international agencies have no exceptions. The wildlife department is acting as a mafia and the forest department is running a parallel government. If the unruly and clandestine acts of the forest department are not prevented, the same will lead to massive agitations and resistances, and ultimately the initiatives would be counterproductive.

I urge upon the Government to have a comprehensive approach in conserving the nature, environment and ecology giving due consideration to the livelihood options of the farming community by safeguarding their right over the land. I also request the Minister to keep a vigil on the interested groups and organizations trying to impose environmental colonialism or assisted colonialism eyeing on the international funds.

□**डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार)**ः मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने मौसम परिवर्तन जैसे ज्वलंत समस्या से निपटने हेतु व्यापक रणनीति बनाने और उसे क्रियान्वित करने हेतु सरकार की संकल्पबद्धता और प्रतिबद्धता जतायी है। भारत के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के श्रीÂान नेतृत्व द्वारा मौसम परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर पूरी गम्भीरता से स्पÂट और सकारात्मक रुख अपनाया जाना हम सबके लिए गौरव का विÂाय है।

मैं माननीय वन और पर्यावरण मंत्री जी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं जिनके कुशल नेतृत्व में उनके मंत्रालय द्वारा मौसम परिवर्तन हेतु बजट को बढ़ाकर 10 करोड़ से 16 गुणा बढ़ाकर 160 करोड़ कर दिया गया है।

हमें देश में प्रदूÂाण नियंत्रण के लिए सरकार के पूर्ण समर्पण का पता इस बात से लग सकता है कि प्रदूÂाण को कम करने के लिए सरकार द्वारा इस वÂाान 240 करोड़ रुपए आवंटित किए गए जो कि गत वÂाान से 148 करोड़ अधिक है। इसी शृंखला में मैं यह बताना आवश्यक समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी अरुण जेटली जी ने विभिन्न प्रदूÂाण नियंत्रण कार्यक्रमों में कोयले पर 100 मीट्रिक टन पर स्वच्छ ऊर्जा सेस को 100 रुपए बढ़ाया है जिससे कि देश में स्वच्छ ऊर्जा के लिए चल रहे प्रकल्पों को मदद दी जा सके।

मैं सामरिक और संवेदनशील सीमावर्ती प्रदेश से आता हूं। जहां यह प्रदेश दो-दो विदेशी सीमाओं से घिरा है वहीं यह प्रदेश नियमित रूप से प्राकृतिक आपदा की मार झेलता है। ऐसे में सीमावर्ती क्षेत्रों में ढांचागत विकास की गम्भीर समस्या है। प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मैंने इस कठिनाई को कई बार तत्कालीन प्रधानमंत्री एवं पर्यावरण व वन मंत्री के समक्ष उठाया था। यह अत्यंत हÂाान का विÂाय है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र से सटी सड़कों के निर्माण हेतु पर्यावरण संबंधी अनुमति की कठिनाइयों को दूर कर दिया गया है। इससे सीमा क्षेत्रों में रह रहे हमारे वे लोग लाभान्वित होंगे जो द्वितीय पंक्ति में देश की रक्षा करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी को अपना हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उनके इस कदम से सीमाक्षेत्रों की हमारी संपर्क मार्ग की योजनाएं बिना विलंब के पूरी हो सकेंगी। संवेदनशील और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तराखंड राज्य में जहां 67 प्रतिशत से अधिक वन क्षेत्र हैं वहां पर्यावरण की रक्षा के लिए लगभग 12500 वन पंचायतों का गौरवमयी इतिहास रहा है। इन बारह हजार पांच सौ वन पंचायतों में ढाई लाख से अधिक नागरिक तमाम खतरों का सामना करते हुए अपने निजी वनों को सुरक्षित रखते हैं। अपने सीमित संसाधनों में भी लोग बल्बों से ज्यादा अपने वनों की चिंता करते हैं। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वन पंचायतों को सशक्त बनाने हेतु एक व्यापक कार्य-योजना तैयार की जाए और अन्य पर्वतीय राज्यों में भी पर्यावरण संरक्षण के लिए वन पंचायतों की अनूठी योजना तैयार की जाए।

मैं वन संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु अभिनव योजनाएं सृजित और क्रियान्वित किए जाने की ओर ध्यान आकर्Âि◌ात करना चाहता हूं। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैंने पर्यावरण संरक्षण से प्रदेश की जनता को जोड़ने के लिए कई सफल और अभिनव प्रयोग किए। धर्म और अध्यात्म का विश्व प्रसिद्ध केन्द्र बद्रीनाथ धाम में हमने एकता वन की स्थापना की जिसमें विभिन्न राज्यों के लोगों में अपने राज्यों की तरफ से वृक्ष लगाने हेतु प्रोत्साहित किया गया। पर्यावरण के क्षेत्र में जिलास्तर पर महत्वपूर्ण कार्य करने वाले विद्यालय और महाविद्यालय को सम्मानित करने की अनूठी योजना बनाई गई। प्रदेश में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने हेतु एनसीसी और एनएसएस समेत विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग लेते हुए मेलों का अयोजन किया गया। विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को विभिन्न एजेंसियों द्वारा अनेक प्रकार के फलदार पौधे उपलब्ध कराकर उन्हें वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया गया। प्रदेश के सभी विद्यालयों में ईको क्लबों की स्थापना कर विद्यार्थियों को जहां एक ओर पर्यावरण संरक्षण हेतु जागरूक किया गया, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की गई। भारतीय सेना के ईको टास्क फोर्स के साथ मिलकर बद्रीनाथ जैसे दुर्गम क्षेत्रों के वृक्षारोपण का व्यापक अभियान हाथ में लिया गया जिसमें सकारात्मक परिणाम निकले हैं। मेरा मानना है कि वन और पर्यावरण मंत्रालय को सतत पर्यावरण विकास के लिए जन सहभागिता सुनिश्चित कर नवीन और अनूठी योजनाओं का क्रियान्वयन करना चाहिए।

सम्पूर्ण हिमालय क्षेत्र में आ रही भीÂाण प्राकृतिक विपदाओं के चलते एवं पर्यावरण के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए एवं मौसम परिवर्तन के दुÂप्रभावों को बचाने के लिए हिमनद विकास प्राधिकरण की स्थापना की जाए। इससे न केवल विदेशी शोध पर हमारी निर्भरता समाप्त होगी और हम अपनी योजनाओं और संसाधनों का समुचित क्रियान्वयन और विकास भलीभांति कर पाएंगे। इस संस्था के माध्यम से जहां हम एशिया के जल टावर का संरक्षण कर पाएंगे, वहीं डैम, जल विद्युत परियोजना, सिंचाई परियोजना, पर्यटन की विभिन्न योजनाओं हेतु संसाधनों का समुचित उपयोग कर पाने में सफल होंगे। सम्पूर्ण हिमालय क्षेत्र में आ रही भीÂाण आपदाओं के चलते पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु, हिमनदों को मौसम परिवर्तन के दुÂप्रभावों से बचाने के लिए देश में हिमनदों का व्यापक सर्वेक्षण और अध्ययन की नितान्त आवश्यकता है। अपने सर्वेक्षणों और अध्ययन के आधार पर हम अपने जल संसाधनों संबंधी योजनाओं का उचित सृजन एवं क्रियान्वयन कर पाएंगे। यह प्राधिकरण सफलतापूर्वक राज्य सरकारों के साथ मिलकर निगरानी नेटवर्क की स्थापना कर समुदाय आधारित प्रबंधन मानव संसाधन का विकास करके आपदा प्रबंधन की सफल रणनीति का सृजन एवं क्रियान्वयन कर पाएगा। चूंकि वाटर टावर हिमालय के जल अपवाह में उत्तराखंड के हिमनदों का महत्वपूर्ण योगदान है। मेरा अनुरोध है कि यह महत्वपूर्ण प्राधिकरण उत्तराखंड में ही स्थापित किया जाए। मैंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में हिमनद प्राधिकरण बनाया था लेकिन वर्तमान उत्तराखंड की सरकार उसे आगे नहीं बढ़ा सकी जिसका मुझे दुख है।

जैव वैविध्य के क्षेत्र में हिमालय सबसे अधिक विविधता वाले क्षेत्रों में आता है जो कि देश में 2387590 (तेईस लाख सतासी हजार पांच सौ नब्बे) वर्ग कि.मी. के भू-भाग को आच्छादित करता है। विश्व के 130 करोड़ लोग हिमालयीय संसाधनों और अपवाह पर निर्भर हैं। वनों से आच्छादित इस क्षेत्र के क्षेत्रीय पारिस्थितिकीय के अनुकूल विकास हेतु अलग से योजना का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है।

हमें यह समझना होगा कि बेहद संवेदनशील हिमालय क्षेत्र की जहां एक ओर अपनी विÂाम पारिस्थितिकी है, वहीं दूसरी ओर यह सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुर्गम परिस्थितियों एवं आपदा की निरन्तर मार सहती उत्तराखंड की जनता पूरी तरह से ग्रस्त है। जहां हम दो-दो विदेशी सीमाओं से घिरे हैं वहीं प्राकृतिक आपदा के कारण व बेरोजगारी के कारण पलायन कर रहे हैं। प्रदेश में 67 प्रतिशत वन क्षेत्र होने के कारण कृÂि◌ा और उद्योग धंधों की काफी कमी है। भीÂाण आपदाओं और वन्य जन्तु संरक्षण के तहत जो गांव पूरी तरह प्रभावित होकर पुनर्वास होकर उन्हें तत्काल प्रभाव से पुनर्वासित किए जाने की एक व्यापक कार्य योजना बनाए जने की आवश्यकता है।

जैसाकि आपको विदित है कि ईको टास्क फोर्स एक विशेÂा बल है जिसका मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिकी की दÂिट से संवेदनशील क्षेत्रों के संरक्षण के साथ स्थानीय जनता को पर्यावरण की रक्षा के लिए जागरुक करना है। इसके अतिरिक्त देश की सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले हमारे जाबांज सैनिकों के लिए सेवानिवृति के बाद यह सम्मानजनक पुनर्वास सुनिश्चित करने का उत्तम माध्यम है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि पर्यावरण मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत गठित किए जाने वाले ईको टास्क फोर्स की नई बटालियनें सृजित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

मैं आग्रह करना चाहूंगा कि पिछले बजट में प्रस्तावित हिमालयीय मिशन की स्थापना अविलंब की जाए ताकि हिमालय क्षेत्रों के अध्ययन के साथ समग्र विकास हेतु नीतियों का उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। हिमालय क्षेत्र में आ रही भीÂाण विपदाओं के मद्देनजर ऐसे संस्थानों की स्थापना अति आवश्यक है। चाहे वह केदारनाथ की 2013 की जल प्रलय रही हो या जम्मू कश्मीर की भयंकर अतिवृÂि◌ट या फिर हाल ही में आया नेपाल का विनाशकारी भूकंप। इन सभी त्रासदियों से हमें हिमालय स्थित प्राकृतिक संसाधनों के पारिस्थितिकी के अनुरूप दोहन का संदेश मिलता है। हिमालयीय मिशन का यह प्रस्तावित संस्थान क्षेत्र के सुनियोजित विकास की अवधारणा को साकर कर पाएगा।

यह अत्यंत चिंताजनक विÂाय है कि प्रदेश में कितनी ही जल विद्युत परियोजनाएं कई सौ करोड़ रुपए खर्च करने के बाद बंद कर दी गई हैं। ऐसे में हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं एवं ऊर्जा संकट से निपटने की सरकार की मुहिम को गहरा धक्का लगा है। मेरा आग्रह है कि ऊर्जा मंत्रालय और राज्य सरकारों से समन्वय स्थापित करते हुए पर्यावरण और वन मंत्रालय देश में मिनी एवं माइक्रो हॉइडल परियोजनाओं को बढ़ावा दें ताकि पर्यावरण की रक्षा के साथ-साथ हम ऊर्जा संकट से निजात पा सके।

मैं बताना चाहूंगा कि मेरे प्रदेश में जहां 67 प्रतिशत भाग वन आच्छादित है वहीं लगभग 30 प्रतिशत से कम भूमि कृÂि◌ा योग्य बचती है। इस बची-खुची भूमि पर हमारे किसानों को बंदर और सुअरों सहित अनेक जंगली जानवरों के आतंक को झेलना पड़ता है। एक ओर इससे हमारे कृÂि◌ा उत्पादन पर विपरीत असर पड़ा है, वहीं दूसरी तरफ इन जानवरों के हमलों से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है।

प्रदेश के कई अंचलों में सड़कों की योजनाएं पर्यावरण स्वीकृति के कारण लटकी पड़ी है। मेरा आपसे अनुरोध है कि सड़क निर्माण हेतु स्वीकृति लेने की जटिल प्रक्रिया को सरल बनाया जाए और उसका समय पर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि सामरिक और संवेदनशील दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों की सड़क योजनाओं की स्वीकृति वरीयता के आधार पर दी जाए।

भीÂाण आपदाओं और वन्य जन्तु संरक्षण अधिनियम के तहत जो गांव पूरी तरह प्रभावित होकर पुनर्वास के लिए भटक रहे हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से पुनर्वासित किया जाए। ऐसे में राज्य सरकारों के साथ मिलकर वन भूमि के समुचित उपयोग हेतु अभिनव योजनाएं भी बनाई जानी चाहिए।

अन्त में, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि वनों से आच्छदित हिमालयीय प्रदेशों में क्षेत्रीय पारिस्थितिकीय के अनुकूल विकास हेतु अलग से योजाना का प्रावधान ग्रीन बोनस के रूप में किया जाए ताकि वनों से प्रभावित या उन पर निर्भर लोग पलायन न करें। दुर्गम परिस्थितियों और अपदा की निरंतर मार सहती जनता के लिए ग्रीन बोनस के रूप में प्रोत्साहन दिया जाए। इससे न केवल देशभक्त क्षेत्रीय जनता राÂट्र के उत्थान के लिए प्रोत्साहित और समर्पित होगी बल्कि वह संवेदनशील हमालयीय पारिस्थितिकी के संरक्षण में बढ़-चढ़कर अपना योगदान देगी। मेरा मानना है कि हिमालयीय प्रदेशों में पर्यावरण संरक्षण और संवर्द्धन में मील का पत्थर साबित होगी।

अन्त में, मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करते हुए विश्वास प्रकट करता हूं कि वह मेरी उपर्युक्त मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

□**श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर)**◌ः बहुत-बहुत धन्यवाद कि मुझे डिमांड्स फॉर ग्रांट्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इनवायरनमेंट एण्ड फॉरेस्ट्स पर अपने विचार रखने का मौका दिया।

हमारी सरकार का लक्ष्य है- देश को समृद्ध बनाना, किन्तु साथ ही अपनी माँ भूमि एवं पर्यावरण की पूर्ण रूप से रक्षा करना। हमारी सरकार ने , यूपीए सरकार के उलट, पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से गरीबी का दूर करना और गरीबी दूर कर पर्यावरण को संरक्षित करने का जो इस बजट में काम किया है, इसके लिए मैं सांसद के ही नाते नहीं बल्कि एक भारतीय नागरिक के नाते भी उन्हें बहुत-बहुत नमन और साधुवाद देता हूं। मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि वन और पर्यावरण से संबंधित जो भी समस्याएं आ रही हैं, उनसे निपटने के लिए हमें जन भागीदारी बढ़ाने के उपायों पर गंभीरता से विचार करना होगा क्योंकि इस मामले में बिना जन भागीदारी के कुछ भी करना संभव नहीं हो सकेगा। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नारा किया- "सबका साथ, सबका विकास। " यह हमारे देश को आपसी सामंजस्य और सतत् विकास की ओर ले जाने वाला सबसे ठोस कदम होगा।

मैं एनवायर्नमेंट एण्ड फॉरैस्ट मिनिस्ट्री की डिमांड फॉर ग्राण्ट्स का पूर्ण समर्थन करते हुए अपनी बात को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के एक ट्वीट के साथ समाप्त करता हूं कि "आइए, हम ट्रस्टी के रूप में काम करें, जहां वर्तमान में अपने प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करें और इसका इस्तेमाल करते वक्त आगामी पीढ़ियों की खुशियां भी सुनिश्चित करें। "

□**श्री रमेश चन्द्र कौशिक (सोनीपत)**ः मैं माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र सोनीपत की ओर दिलाना चाहता हूं।

यमुना नदी मेरे संसदीय क्षेत्र सोनीपत से होकर गुजरती है। यमुना नदी का पानी यमुनानगर में नीला रंग का होता है और यह सोनीपत आते-आते काला, दूÂिात और जहरीला हो जाता है। जिसके कारण पीने के पानी तथा सिंचाई का पानी दूÂिात होने के कारण पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है।

उद्योगों का गंदा पानी यमुना नदी में गिरने के साथ-साथ नदी में खनन की गतिविधियों का कार्य बहुत अधिक जोर पर चलता है। जिससे बहुत बड़े-बड़े गड्डे बन जाते हैं और आस-पास के पेड़-पौधे भी उखाड़ दिए जाते हैं। इससे भविÂिय में और अधिक पर्यावरण को खतरा बढ़ता जा रहा है और पर्यावरण अधिक दूÂिात होता जा रहा है।

खनन व दूÂिात पानी के कारण पेड़ों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। जमीन पेड़ विहिन तथा ऊंची-नीची होती जा रही है। जिस कारण पर्यावरण को सुदृढ़ बनाने में कठिनाई पैदा हो रही है।

पर्यावरण में बदलाव के कारण ही भूकम्प और बिन मौसम की बरसात जैसी प्राकृतिक आपदा आती है। जिसके कारण वहां की जनता के साथ-साथ देश को भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। इसलिए स्वच्छ पर्यावरण का होना अत्यंत आवश्यक है।

अतः मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में पर्यावरण को दूÂिात करने से बचाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाए।

*SHRI BADRUDDIN AJMAL (DHUBRI): Our country has various kinds of environmental issues including air pollution, water pollution, garbage, and pollution of the natural environment. According to a survey, nearly 30% of India's gross agricultural output is lost every year due to soil degradation, poor land management and counterproductive irrigation. The wetlands and lakes are also being hit hard. Mainly by the industrial boom that hit India a decade ago, the main problems being improper disposal of industrial waste like chemicals etc. this is very alarming revelation for our country.

Air pollution is a serious issue in our country with the major source being fuelwood and biomass burning, fuel adulteration, vehicle emission and traffic congestion. Air pollution is also the main cause of the Asian brown cloud, which is causing the monsoon to be delayed. We need to keep eye on this problem and also create awareness among the people.

We need development, we should set up factories, industries and plants for economical growth of the country but at the same time we need to preserve the environmental issue. We must not ignore the protection of environment that may cause the disaster for the country. We must take action against those who violate the law and rules regarding protection of environment.

The rivers are on the front line of pollution in India. Millions of people depend on them for their livelihoods but they are slowly being polluted and destroyed by sewage, chemicals and other agricultural and industrial waste. Discharge of untreated sewage is the single most important cause for pollution of surface and ground water in the country. The uncollected wastes accumulate in the urban areas cause unhygienic conditions and release pollutants that leaches to surface and groundwater.

According to a World Health Organization study, out of India's 3,119 towns and cities, just 209 have partial sewage treatment facilities, and only 8 have full wastewater treatment facilities. Over 100 Indian cities dump untreated sewage directly into the Ganges River. Flooding during monsoons worsens water pollution problem, as it washes and moves all sorts of solid garbage and contaminated soils into its rivers and wetlands. So we need to find out solution of these problems.

We talk about attracting tourists from all over the world to our country but it is a bitter fact that due to polluted environment, tourists hesitate to come to our country. Tourist centres such as Goa, Mumbai, Delhi and other cities suffer badly due to lack of environmental management and preventing pollution measure. I request Hon'ble Minister to come out with the measures to protect the environment especially in these cities.

The deforestation is another highly serious environmental issue in India. It is predicted that almost 5.3 Million hectares of forest have been destroyed since the Independence. Most of it, being chopped down for housing, industrialization and river projects. It is estimated that the number of Mangrove \forests have more than halved in the last 20 years.

Mountains, Hills and Forests have very importance in their existence. The mountains protect the earth from earthquake and the forests pass the fresh air for the human being. Similarly the animals are important to keep the environment fresh and pure because they eat various types of waste that can affect the pollution and also they filter the air for human beings.

But unfortunately in the name of industrial growth, we are destroying mountains and forest. Similarly, we have failed to protect the animals like tigers and Rhino etc. The poaching of tigers and Rhinos is going on in the country especially in Kaziranga National Park of Assam. Kaziranga National Park is home to the largest population of the endangered one horned rhino in the world. But the poaching at the park has become a big problem over the years.

According to the record, the Kaziranga National Park has 2,186 rhinos out of a total population of 2,505 in Assam. A total of 524 rhinos have been killed for their horns in that state during last decade. Around 22 rhinos have been killed just this year so far.

I request Hon'ble Minister to give special attention to the issues raised by me and take necessary steps to protect the environment. I also request

Hon'ble Minister to pressurize the state governments to implement the existing laws regarding protection of environment and forest.

☐**श्री दहन मिश्रा (श्रावस्ती)**ः मैं अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

सामान्य धारणा यह है कि पर्यावरण और वन अनंत प्राकृतिक उपहार हैं, जिसमें पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों की सेवा, सहायता तथा उन्हें जीवित रखने की एक चिरकालिक क्षमता है, चाहे उनके साथ कितना भी क्रूर, अपमानजनक और अवेहलनात्मक बर्ताव किया जाए। इस तरह की संतोÂाजनक अवधारणा तथा निश्चिंततापूर्ण रवैये का परिणाम न केवल अवश्यंभावी बल्कि तत्काल आपदा को निमंत्रण देना है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पर्यावरण और वनों में अलौकिक और अंतर्निहित सामर्थ्य तथा शक्ति यह है कि उनका पुनर्जागरण, पुनर्जन्म, पुनर्मरण तथा पुनरूत्थान हो जाता है, परन्तु यह सामर्थ्य अनंत और चिरकालिक नहीं है। यह प्रक्रिया उतनी तेजी से नहीं हो सकती है, जितनी तेजी से हमारी आवश्यकता के कारण नहीं बल्कि लालच के कारण इस पर निर्भरता और असावधानीपूर्वक कहर ढाया जा रहा है। यहां तक कि आज के परिदृश्य में यदि इसी प्रकार अंधाधुंध बर्बादी होती रही तो वह दिन दूर नहीं है कि जब न केवल मनुÂय बल्कि सभी जीवों को जीवन के लिए गंभीर और निश्चित खतरा पैदा हो जाएगा।

मैं देश के उन चंद सौभाग्यशाली लोगों में से हूं, जिनको प्राकृतिक वन संपदा से परिपूर्ण प्रकृति की गोद में पलने-बढ़ने का अवसर मिला है। मैं उत्तर प्रदेश के जिस श्रावस्ती क्षेत्र में आता हूं, उसके अंतर्गत आने वाले दोनों जिले श्रावस्ती एवं बलरामपुर वन एवं खनिज सम्पदा से परिपूर्ण हैं। श्रावस्ती में जहां 17 हजार 186 हेक्टेयर रिजर्व फारेस्ट है, वहीं 23 हजार हैक्टेयर सेंचुरी फारेस्ट भी है। इसी प्रकार बलरामपुर में 5 हजार हैक्टेयर रिजर्व फारेस्ट एवं 45 हजार हैक्टेयर सेंचुरी फारेस्ट है।

मैं वनों के बीच पला बढ़ा हूं, इसलिए जंगल एवं वन से हमको बड़ा लगाव है। परन्तु आज जब मैं वनों के चौतरफा ही रहे विनाश को देखता हूं तो हमें बहुत ही हार्दिक पीड़ा एवं कÂट होता है। क्योंकि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो इसकी रखवाली तथा इसको बचा पाना बहुत ही मुश्किल है।

आज उत्तर प्रदेश में भ्रÂट अधिकारियों, सत्ता पक्ष के नेताओं एवं वन माफियाओं का एक बहुत ही मजबूत गठजोड़ का कॉकस बन गया है जो वनों के लिए विनाशकारी साबित हो रहा है। आज हम देखते हैं कि वनों की अंधाधुंध अवैध कटाई एवं अवैध खनन उक्त गठजोड़ की अवैध कमाई का प्रमुख साधन बन गया है। अगर इसी तरह से अंधाधुंध अवैध कटाई होती रही तो वह दिन दूर नहीं जब वन एवं जंगल सिर्फ किताबों और किस्से कहानियों में पढ़ने और सुनने को मिलेंगे, जिसका दुÂपरिणाम हमारी आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। आज उत्तर प्रदेश में न तो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन हो रहा है और न ही सेवा नियमावली का पालन किया जा रहा है। भ्रÂट अधिकारी एक ही स्थान पर 20-20 साल जमे रहकर वहीं से प्रमोशन लेकर के रिटायर भी हो जाते हैं। मेरी सरकार से मांग है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का तथा सेवा नियमावली का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करा करके वनों को बचाने एवं संरक्षित करने का काम करें।

हमारे क्षेत्र के भिनगा वन प्रभाग में विजयशाल नामक पेड़ पाया जाता है, जिसकी लकड़ी का गिलास बना करके उसमें पानी भरकर रख दिया जाता है तो वन पानी सुबह लाल रंग का हो जाता है और वह पेट संबंधी बीमारियों की रामबाण दवा है। इसको भी अंधाधुंध अवैध कटाई वन माफियाओं द्वारा की जा रही है, जिसको संरक्षित करने की व्यवस्था की जाए।

भिनगा वन प्रभाग में ही उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है, उनको भी संरक्षित करने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुदान की मांगों का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

☐**श्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर)**ः मैं पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करते हुए अपने निम्नलिखित सुझाव देना चाहता हूं।

पर्यावरण परिवर्तन और कृÂिा दो संबंधित प्रक्रिया है जो एक वैश्विक पैमाने पर अपनी जगह बना रहे हैं। पर्यावरण परिवर्तन कृÂिा को अलग-अलग तरीकों जैसे औसत तापमान, वÂाान, कीट और रोगों में परिवर्तन, वायुमंडलीय कार्बन डाईऑक्साइड और जमीनी स्तर पर ओजोन सांद्रता में परिवर्तन और समुद्र के स्तर में परिवर्तन से प्रभावित करता है।

भारत में कृÂिा और संबद्धित क्षेत्र करीब 18 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पादन में योगदान देते हैं और करीब 70 प्रतिशत भारतीय जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृÂिा पर निर्भर करती है।

जलवायु परिवर्तन विश्व स्तर पर किसानों के लिए सबसे दीर्घकालिक चुनौतियों में से एक है। जलवायु जोखिम भारतीय कृÂिा के लिए आम हैं। यह सूखे के लिए अत्यधिक संवेदनशील है क्योंकि 2/3 कृÂिा भूमि वÂाान पर आधारित है और सिंचित प्रणाली भी मानसून पर निर्भर है। बाढ़ भी बार-बार कई भागों में विशेÂा रूप से पूर्वी भारत में होती है। उत्तर पश्चिमी भारत में ठंड मध्य और उत्तरी भागों में गर्म तरंगों और पूर्वी तट में चक्रवात का काफी कहर अक्सर पाया गया है।

मेरे संसदीय क्षेत्र 44 अकबरपुर लोक सभा में जनपद कानपुर नगर की कल्याणपुर, महाराजपुर, बिठूर एवं घाटमपुर तथा जनपद कानपुर देहात की अकबरपुर रनिया विधानसभा सम्मिलित है। मेरी लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत जी.टी. रोड़, कानपुर-सागर राजमार्ग, कानपुर-आगरा राजमार्ग एवं कालपी रोड़ पर कई औद्योगिक क्षेत्र हैं, जिनमें सैकड़ों औद्योगिक संस्थान स्थापित हैं। इन औद्योगिक संस्थानों से प्रतिदिन 500 टन से अधिक अपशिÂट पदार्थ एवं लाखों लीटर प्रदूÂिात जल के साथ-साथ धुएं की धुंध एवं डस्ट निकलती है। पर्यावरण एवं प्रदूÂाण के निस्तारण के मानकों के लगातार उल्लंघन एवं मिल मालिकों व विभागीय अधिकारियों की सांठ-गांठ से पूरे क्षेत्र में जनजीवन अस्त-व्यस्त एवं गंभीर घातक बीमारियों से ग्रस्त हो गया है।

ज्ञात हो कि कानपुर नगर के ग्राम बिनौर में स्थित महादेव पेपर मिल एवं पी.आर. इंडस्ट्रीज तथा कानपुर देहात के औद्योगिक क्षेत्र रनिया में स्थित कानपुर एडिबल ऑयल, आर.एस.पी.एल. व जैनपुर औद्योगिक क्षेत्र में रनिया में पेप्सिको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कंसायी नेरोलैक आदि सहित सैकड़ों ऐसी औद्योगिक इकाइयां हैं जिनके द्वारा अपशिÂट पदार्थों, प्रदूÂिात जल, पानी के खनन एवं कचरे का यथाउचित निस्तारण न किए जाने के कारण पूरे क्षेत्र में गन्दगी का साम्राज्य कायम हो गया है। जहरीला धुंआ, उगलती चिमनियों से आम आदमी का सांस लेना दूभर हो गया है, जिसके संबंध में मैंने जिलाधिकारियों एवं राज्य प्रदूÂाण नियंत्रक बोर्ड को दिनांक 15.10.2014 को पत्र लिखकर औद्योगिक इकाइयों द्वारा मानकों के विपरीत की जा रही कार्यवाहियों को तत्काल रोके जाने का आग्रह किया था। परन्तु अत्यंत खेद का विÂाय है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा अभी तक इस गंभीर परिस्थिति को नजरअंदाज कर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

निÂकÂाल स्वरूप पर्यावरण, परिवर्तन फसल उत्पादन को अधिक अविश्वसनीय और कम उम्मीद के मुताबिक कर देगा। आने वाले समय में ज्यादातर फसलों की पैदावार कम होने की संभावना है एवं हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा भयंकर बीमारियों के कारण आमजन के जीवन पर अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अनुकूल प्रथाओं को प्रभावी बनाने के लिए समय लिया जाए। अतः हमें अब अभिनय की जरूरत है।

☐**श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा)**ः मैं वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के अनुदान की मांगों 2015-16 के समर्थन में अपनी बात रख रहा हूं।

वÂाान 2015-16 में प्लान मद में 1446.60 करोड़ रुपए और नॉन प्लान में 235.00 करोड़ सहित 1681.60 करोड़ रखा गया है। आज जलवायु परिवर्तन और स्थायी विकास का मुद्दा वैश्विक हो गया है। 2013 में सम्पूर्ण कार्बन डाईऑक्साइड उर्त्सजन के संबंध में चीन, यूएसए और यूरोपीय संघ पहले तीन स्थानों पर हैं, जबकि भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों का स्थान 196 देशों में से नीचे के 100 देशों में आता है। भारत जलवायु परिवर्तन संबंधी राÂट्रीय कार्य योजना (एन.ए.पी.सी.सी.) को सबसे पहले अपनाने वाले देशों में है। हमने अनुकूलन कार्यों के सहायतार्थ 100 करोड़ रुपए की आधारभूत निधि के साथ "राÂट्रीय अनुकूलन निधि " स्थापित की है, ताकि कृÂिा, जल और वन आदि जैसे क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना किया जा सके।

समग्र और एकात्म विकास के लिए आवश्यक है कि एथिक्स, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स और इकोलॉजी का समन्वय और संतुलन मानवीय जरूरतों के अनुरूप हो। मानव समाज और आने वाली

पीढ़ियों के विकास के लिए प्रकृति के प्रति सरकार का और हमारा दÂिष्टकोण संतुलित होने के साथ-साथ व्यवहारिक होना चाहिए। पर्यावरण के संरक्षण और संतुलन से ही चिरस्थायी विकास की मानववादी संकल्पना साकार हो सकती है।

मेरा लोक सभा क्षेत्र चतरा झारखंड प्रदेश का वन बहुलता वाला क्षेत्र है। मेरे ही क्षेत्र में पलामू टाईगर रिजर्व और बेतला नेशनल पार्क अवस्थित है। कृपया इस क्षेत्र में मानव वन्य प्राणी संघÂाऩ को कम करने के लिए सुविधा और मुआवजा बढ़ाया जाए। रिजर्व वन क्षेत्र में रहने वाले निवासियों की सुरक्षा और आजीविका की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी और वन्य पशु अवलोकन हेतु पर्यटन को बढ़ावा देने का कार्यक्रम बनाएं। इसमें स्थानीय आबादी की भागीदारी से पर्यावरण और वन जीवों के विकास में सुविधा होगी। वन्य जीवों और पारिस्थितिकीय विकास समर्थित आजीविका को बढ़ावा देने की योजना बनानी चाहिए। संरक्षित वन क्षेत्र (बेतला) में ही स्थित राजा मेदनीराय का किला और कमलदह झील हैं और यहां पूतिवÂाऩ मेला लगता है। कृपया स्थानीय लोगों की जागरूकता पर्यावरण के प्रति बढ़े, इस दÂिष्ट से पालमू किला, कमलदह झील और मेले को वन पर्यटन की दÂिष्ट से बढ़ावा देने की योजना बनाई जाए।

लातेहार, चतरा और पलामू में वन उत्पादकता, उत्पादन और जैव विविधता के दीर्घकालिक प्रबंधन में सुधार लाया जाए और इसमें स्थानीय लोगों का साथ लाभ में समान भागीदारी के आधार पर हो, वह योजना बने। वन क्षेत्र की भूमि एवं चारागाह का पुनरूद्धार हो तथा वन के किनारों पर बसे गांवों के आसपास सामुदायिक चारागाह और खेल के मैदान विकसित किया जाना चाहिए। वन पर्यटन और वन संसाधनों के प्रबंधन के लिए ग्राम वन समितियों और संयुक्त वन क्षेत्र प्रबंधन समितियों का निर्माण करना चाहिए।

मेरे लोक सभा क्षेत्र चतरा का पर्यावरण के संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने की दÂिष्ट से ग्रीन बोनस की राशि उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि भविÂाय में उस राशि से वन और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ सके।

मैं माननीय पर्यावरण और वन मंत्री का ध्यान अपने क्षेत्र में स्थित नेतरहाट की ओर आकृÂट करना चाहता हूं। नेतरहाट नैसर्गिक प्राकृतिक सौन्दर्य का अन्यतम उदाहरण है, पर आज अपनी उपेक्षा का दंश झेल रहा है। नेतरहाट को पर्यावरण और वन पर्यटन की दÂिष्ट से विकसित करने की योजना बनाई जाए। इसमें नेतरहाट का प्रसिद्ध नेतरहाट विद्यालय सहायक होगा, जिसके छात्र आज समाज-जीवन के हर क्षेत्र में अग्रणी स्थान पर हैं। कृपया नेतरहाट में वन एवं पर्यावरण से संबंधित संस्थान की स्थापना की पहल की जाए।

प्रकृति और विकास एक-दूसरे के विरोधी नहीं है। इसलिए मेरे क्षेत्र में उत्तरी कोयल नदी पर मंडल जलाशय योजना जो 1972 से ही प्रस्तावित है और इसका कार्य अधूरा पड़ा है उसे वन विभाग से स्वीकृति देने की कृपा करें। इस योजना से वन का ही संरक्षण होगा। साथ ही, चतरा लोक सभा जो अत्यंत पिछड़ा और चरम उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र है उसकी बिजली से संबंधित अनेक योजनाएं स्वीकृति के अभाव में लंबित हैं, उन्हें स्वीकृति प्रदान करें।

उत्तर कोयल नदी के जलग्रहण क्षेत्र का विस्तार 10574 वर्ग किलोमीटर है जबकि उपलब्ध जल की क्षमता 2227 मिलियन घनमीटर है और भूगर्भ जल की क्षमता 680 मिलियन घनमीटर है। इससे 111800 हेक्टेयर जमीन का सिंचन होगा, जिसमें से झारखंड का 11200 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगा। साथ ही लातेहार और पलामू, जहां जल का संकट है, वहां भूगर्भ जलस्तर में सुधार होगा और पेयजल संकट से छुटकारा मिलेगा।

वन भूमि पर स्थानीय लोगों के अधिकार को सुनिश्चित कर उन्हें इसका लाभ दिलाया जाए। बाघ एवं हाथी द्वारा किए गए नुकसान यथा - जीव, कृÂिा भूमि, फसल इत्यादि में मुआवजा बाजार दर पर दें और इन मामलों का शीघ्र निपटारा हो।

इसके साथ में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन द्वारा सदन में रखे गए अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं।

□**श्री ओम बिरला (कोटा)**ः मौजूदा आकलनों के अनुसार भारत में वन क्षेत्र लगभग 78.29 मिलियन हैक्टेयर है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 23.8 प्रतिशत है। यदि 2009 की तुलना में वÂाऩ 2011 में जारी की गई रिपोर्ट के आधार पर तुलना की जाए तो देश में लगभग 367 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र की कमी आई है।

भारत में वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सर्वप्रथम 1952 में पहली नीति बनी थी तथा उसके पश्चात् बदलते परिवेश को देखते हुए 1978 में दूसरी वन नीति बनाई गई। 1978 के पश्चात् औद्योगीकरण व विभिन्न कारकों के चलते वर्तमान वन नीति की पुनः समीक्षा कराया जाना आवश्यक है। भारत में खनन, कोयला, राजमार्ग, रेल सेवा, ऊर्जा व अन्य इफ्रास्ट्रक्चर के विभिन्न प्रोजेक्ट एवं वर्तमान वन एवं पर्यावरण संबंधित नीतियां एक दूसरे की पूरक न होकर प्रायः अर्न्तद्वंद्व प्रकट करती है, जिसके कारण कई महती परियोजनाएं वन विभाग के क्लीयरेंस के अभाव में सालों साल लम्बित हो रही है।

वर्तमान में वाईल्ड लाईफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, 1927, सहित विभिन्न अधिनियमों में किए गए कुछ प्रावधान वन्य क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों /वनवासियों के मौलिक अधिकारों की भी उपेक्षा करते हैं। इन क्षेत्रों में सदियों से बसे नागरिकों को बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा एवं चिकित्सा की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में वन विभाग के नियम आडे आते हैं। इनकी समीक्षा किया जाना अत्यंत आवश्यक है ताकि वन सीमा में रह रहे नागरिकों को भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके।

इसी प्रकार, दुर्लभ एवं लुप्तप्रायः वन्य जीवों के संरक्षण वाले रÂट्रीय पार्कों एवं अभयारण्यों को अंतर्रÂट्रीय स्तर पर पर्यटन मानचित्र में लाने हेतु गंभीर प्रयास किए जाना आवश्यक है, जिसके कारण न केवल वन्य जीवों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकेगी, वहीं पर्यटकों के आगमन से ईको टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा एवं स्थानीय नागरिकों को रोजगार मिलेगा।

राजस्थान सहित देश के कई कृÂिा प्रधान इलाकों में रोजडों (नील गाय), जंगली सुअर आदि जानवरों द्वारा बड़ी मात्रा में किसानों की फसलें नÂट कर दी जाती है जिससे उनको गंभीर आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। इस समस्या पर मुझे सहित देश के कई सांसदों ने सरकार का ध्यान आकर्Âिात किया है। इस संबंध में मेरा आग्रह है कि वन्य जीवों से फसलों की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले विभिन्न उपायों जैसे बाड़ा बंदी, तारबंदी आदि प्रबंधों के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया जाए और फसल बीमा में भी उक्त जोखिम को शामिल करने का प्रयास किया जाए।

मैं सरकार का ध्यान मेरे निर्वाचन क्षेत्र कोटा से जुड़े कुछ लम्बित विÂायों की ओर आकर्Âिात करना चाहता हूं। कोटा, बूंदी, झालावाड व चित्तौड़गढ़ जिलों में दरा अभयारण्य, जवाहर सागर अभयारण्य व रÂट्रीय घडियाल अभयारण्य का क्षेत्रफल जोड़कर मुकुन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व की घोÂाणा की गई थी। उक्त रिजर्व में वर्तमान में कोई भी टाईगर बसाया नहीं गया है। वहीं राजस्थान के दूसरे नेशनल टाईगर रिजर्व, सवाई माधोपुर बाघों की बढ़ती हुई संख्या के कारण बाघों के आपसी झगड़े व विस्थापन की समस्या से जूझ रहा है। ऐसी स्थिति में सरिस्का के समान यहां भी बाघों का विस्थापन सवाई माधोपुर से कर दिया जाए तो न केवल बाघों का संरक्षण अच्छे से किया जा सकेगा, वहीं पर्यटन की दÂिष्ट से एक नया क्षेत्र विकसित होगा।

कोटा के इटावा क्षेत्र, बूंदी के केशवराय पाटन क्षेत्र को जोड़ने के लिए प्रस्तावित महत्वाकांक्षी गेंता मास्विदा की पुलिया के निर्माण की स्वीकृति लम्बे समय से लम्बित चल रही है। उक्त स्वीकृति से संबंधित समस्त औपचारिकताएं कई बार पूरी करके राज्य सरकार द्वारा प्रेÂिात की जा चुकी है। किंतु विभिन्न छोटे-छोटे आक्षेपों के चलते अब तक स्वीकृति न मिलने से क्षेत्र के लोगों को 130 किलोमीटर की अनावश्यक यात्रा करने को विवश होना पड़ता है। कोटा से मध्य प्रदेश की ओर जाने वाला नेशनल हाईवे संख्या 12 के फोरलेन का कार्य भी वन विभाग की स्वीकृति के अभाव में लम्बित है। जिसका निस्तारण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। बूंदी शहर का अधिकांश भाग जो कि रामगढ़ अभयारण्य की सीमा में आने से सभी मूलभूत आवश्यकताओं व विकास कार्यों से वंचित है, उक्त संबंध में केन्द्रीय समिति द्वारा निरीक्षण करके शहर को वन्य सीमा से मुक्त करने के संबंध में अपनी रिपोर्ट मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत भी कर दी है जो कि विचाराधीन है। उक्त क्षेत्र को यदि वन्य सीमा से मुक्त कर दिया जाए, तो लगभग डेढ़ लाख की आबादी को सीधा-सीधा लाभ मिलेगा।

चम्बल नदी पर घडियालों को संरक्षित करने के दÂिष्टकोण से उत्तरी भारत के मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश के तीन राज्यों के कुल 425 किलोमीटर लम्बाई तक फैले क्षेत्र को रÂट्रीय

चम्बल घडियाल सेन्चुरी के रूप में वÂान 1979 में घोÂिात किया गया। चम्बल नदी पर बनाए गए कोटा बैराज की डाउन स्ट्रीम से केशवराय पाटन के बीच के हिस्से को घडियाल सेन्चुरी से मुक्त रखा गया है। किन्तु चम्बल नदी की अपस्ट्रीम से जवाहर सागर की ओर का हिस्सा अभी भी घडियाल सेन्चुरी में आता है। वहां निवास कर रहे लोगों को विभिन्न मूलभूत सुविधाओं जैसे बिजली कनेक्शन, पट्टे व अन्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण बड़ी आबादी प्रभावित हो रही है। अतः कोटा बैराज के अपस्ट्रीम वाले क्षेत्र तथा केशवराय पाटन से सुल्तानपुर, इटावा वाले क्षेत्र का सर्वे कराकर घडियाल सेन्चुरी का पुर्नसीमांकन कराया जाए और ऐसा क्षेत्र जो कि अत्यधिक जनसंख्या का दबाव और घडियालों के प्रजनन के अनुकूल नहीं है उसे सेन्चुरी से मुक्त किया जाए।

अतः मेरा माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्Âिात करते हुए आग्रह है कि उक्त विÂायों के संदर्भ में कार्ययोजना बनाई जाए, तो वन एवं वन्य जीवों के संवर्धन सहित वन क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय नागरिकों के जीवन में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेगी।

□**श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर)**ः प्रकृति के पांच तत्व जल, अग्नि, वायु, आकाश एवं पृथ्वी पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं जिनका आपस में गहरा सम्बन्ध है। इन पांचों तत्वों में किसी एक का भी असंतुलन पर्यावरण के लिए अपूर्णनीय क्षतिकारक और विनाशकारी है। पर्यावरण दो शब्दों परि और आवरण से बना है, जिसका अर्थ है चारो ओर का घेरा। हमारे चारों ओर जो भी वस्तुएं, परिस्थितियां या शक्तियां विद्यमान हैं, वे मानवीय क्रियाकलापों का प्रभावित करती है और उसके लिए दायरा सुनिश्चित करती है। इसी दायरे को पर्यावरण कहते हैं।

पर्यावरण के अंग्रेजी शब्द इनवायरमेंट का उद्भव फ्रांसीसी भाÂाा के इनविरोनिर शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है घेरना। इनवायरमेंट का समानार्थक शब्द हैबिटैट है, जो लैटिन भाÂाा के हैबिटायर शब्द से निकला है। हैबिटैट शब्द पर्यावरण के सभी घटकों को स्थानीय रूप से लागू करता है इसका प्रभाव आवास स्थल तक सीमित है, जबकि इनवायरमेंट शब्द हैबिटैट की तुलना से अधिक व्यापक है।

देखा जाए तो पर्यावरण को दो प्रमुख घटकों में विभाजित किया जा सकता है। पहला जैविक अर्थात बायोटिक जिसमें समस्त प्रकार के जीव-जन्तु व वनस्पतियां (एक कोशिकाय से लेकर जटिल कोशिकीय तक) हैं।दूसरे प्रकार के घटक में भौतिक अर्थात् अजैविक जिसमें थलमंडल, जलमंडल व वायुमंडल सम्मिलित हैं। इन सभी घटकों में सृÂिट में मानव जीवन की सर्वश्रेÂठ जीव के रूप में उत्पति की है। अतः मानव सम्पूर्ण जीव जगत का केन्द्र बिंदु है। पर्यावरण के सभी महत्वपूर्ण घटक मानव को परावृत करते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी पर्यावरण के प्रभावों को परिलक्षित करती है। वस्तुतः अनुवांशिकी एवं पर्यावरण ये दो महत्वपूर्ण कारक मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। समस्त जीवों में सर्वश्रेÂठ जीव होने के नाते मनुÂय ने प्रकृति की प्राकृतिक सम्पदाओं का सदियों से भरपूर दोहन किया है। लेकिन वर्तमान दौर में बढ़ती जनसंख्या, पश्चिमी उपभोक्तावाद एवं वैश्विक भूमण्डलीकरण के मकड़जाल में फंसकर मनुÂय प्रकृति के नैसर्गिक सुख को खोता जा रहा है। वह नहीं जान पा रहा कि कंकरीट का शहर बसाने की चाहत के बदले में वह अपना भविÂय दांव पर लगा बैठा है।

प्रकृति के समस्त संसाधन प्रदूÂाण की चपेट में हैं। हवा, जल और मिट्टी जो हमारे जीवन के आधार हैं, जिनके बिना जीवन की कल्पना बेमानी है, आज अपना मौलिक स्वरूप एवं गुण खोते जा रहे हैं। पर्यावरण की छतरी अर्थात् ओजोन परत जो हमें सौरमंडल से आने वाली घातक किरणों से बचाती है उसमें छेद होना, वातावरण में बढ़ती कार्बन डाई-ऑक्साईड की मात्रा से उत्पन्न समस्या, ग्लोबल वार्मिंग, दिनोंदिन घातक बीमारियों का प्रादुर्भाव व स्वास्थ्य संकट ये सब मानव के समक्ष एक विकराल दानव का रूप ले चुके हैं जो भस्मासुर की तरह समस्त मानव जाति को लीलने को आतुर हैं, जिसमें सावधान होना बहुत जरूरी है।

जैव मंडल में मौजूद संसाधनों में जल सर्वाधिक मूल्यवान है क्योंकि यह केवल मानव ही नहीं अपितु सभी जीवों तथा वनस्पति के लिए उपयोगी है। प्रकृति में जल तीन रूपों में विद्यमान है ठोस, तरल एवं गैस। ठोस के रूप में बर्फ जल का शुद्ध रूप है। इसके बाद वÂाान का जल, पर्वतीय झीलें, नदियां एवं कुएं शुद्धता क्रम में आते हैं। धरातल पर प्रवाहित तथा झीलों, तालाबों आदि के रूप में उपलब्ध स्वच्छ जल की मात्रा केवल 7 प्रतिशत है। लेकिन बढ़ती संख्या, कुकरमुते से उगे बहुमंजिला इमारतों, खेती में रसायनों का उपयोग तथा रासायनिक फैक्ट्रियों से निकला पानी नदियों, तालाबों, झरनों को प्रदूÂिात कर रहा है, जो मानव जाति सहित जीव-जन्तुओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो रहा है। जल को प्रदूÂिात करने वाले तत्व जल में मौजूद ऑक्सीजन के स्तर को कम कर जल को पीने योग्य नहीं रहने देते।

वसुन्धरा को माता का दर्जा दिया गया है जो अपने गर्भ में मौजूद तमाम आवश्यक धातुओं, अधातुओं, खनिज लवणों के सहयोग से बीज का पोÂाण कर खाद्य पदार्थ के रूप में विकसित करती है जो समस्त जीव जन्तुओं में जीवन का संचार करते हैं। भूमि या मिट्टी भी जल की भांति सर्वाधिक मूल्यवान संसाधन हैं, क्योंकि विश्व के 71 प्रतिशत खाद्य पदार्थ मिट्टी से ही उत्पन्न होते हैं। यह संसाधन इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता कि सम्पूर्ण ग्लोब के मात्र 2 प्रतिशत भाग में ही कृÂिा योग्य भूमि है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या के पोÂाण के लिए खाद्यान्नों की बढ़ती मांग के कारण कृÂिा उर्वरता बढ़ाने के उद्देश्य से आधुनिकतम टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। जिसके कारण विश्व में खाद्यान्न की समस्या पर काफी हद तक काबू किया जा सका है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी के प्रयोग, नित नए रासायनिक उर्वरकों, रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग के कारण धरती की उर्वरता कम हो गई है। शहरों व महानगरों से निकला अपशिÂट पदार्थ जैसे पॉलीथिन, कूड़ा-करकट, राख, औद्योगिक अपशिÂट, दफ्ती, चमड़ा, शीशा, रबड़ आदि के कारण मिट्टी के प्रदूÂाण को तेजी से बढ़ावा दिया है।

पृथ्वी के चारों ओर गैसों का घेरा है जिसे वायुमंडल कहते हैं। यह वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है जिसमें लगभग 73 प्रतिशत नाइट्रोजन, 21 प्रतिशत ऑक्सीजन एवं .03 प्रतिशत कार्बन डाई-ऑक्साइड है। ये सभी तत्व पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में सहायक है। पृथ्वी पर मौजूद पेड़-पौधे वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाई-ऑक्साइड को अवशोÂिात कर प्रकाश की उपस्थिति में एवं जड़ों के माध्यम से जल एवं आवश्यक खनिज लवण लेकर अपना भोजन तैयार करते हैं। बदले में ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। यही ऑक्सीजन वायुमंडल में मिलकर मानव जाति के लिए प्राणवायु का काम करती है। मनुÂय एवं जीव-जन्तु भी जब वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो कार्बन डाई-ऑक्साइड छोड़ते हैं जो कि पेड़-पौधों के लिए भोजन बनाने में सहायक होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पर्यावरण में मौजूद सभी घटक सिम्बायोटिक तरीके से एक दूसरे से सम्बद्ध हैं और इस प्रकार पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। लेकिन विकसित देशों की प्रभुता की लालसा ने अंधाधुंध परमाणु हथियारों का जखीरा खड़ा करने, रासायनिक हथियार बनाने की होड़ ने मनुÂय को अंधा बना दिया है। बढ़ती जनसंख्या के कारण मनुÂय ने वनों को काटकर कंकरीट की बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर ली। ऐसा कर उसने अपने भविÂय का नाश कर दिया। पेड़ों के कटने के कारण कार्बन डाई-ऑक्साइड का संतुलन बिगड़ने से ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिला है। वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाई-ऑक्साइड वातावरण के तापमान को भी नियंत्रित करती है। पेड़ों के कटने के कारण वायुमंडल में कार्बन डाई-ऑक्साइड की निरंतर बढ़ती मात्रा के कारण वातावरण के तापमान को दिनोंदिन बढ़ाती जा रही है जो अप्रत्यक्ष रूप से वÂाान, सर्दी, गर्मी के चक्र को भी प्रभावित कर रही है। निकट भविÂय में ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का जलस्तर इस हद तक बढ़ जायेगा कि समुद्र के किनारे बसे समूचे शहरों को लील जाए तो अतिश्योक्ति न होगी।

पर्यावरण के इस असंतुलन की जिम्मेदारी हमारी समस्त मानव जाति है। यदि समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो विनाश अवश्यंभावी है। इसीलिए वेद मनीÂिायों ने भी द्यूलोक से लेकर व्यक्ति तक शांति की प्रार्थना की है।

ऊँ द्यौः शांतिरन्तरिक्षं शांतः पृथ्वी शान्तिरापः

शान्तिरोÂाधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः

शान्तिर्ब्रह्म शान्तः सर्वशान्तः शान्तिरेव

शान्तः सा मा शान्तिरेधि।। (शुक्ल यजुर्वेद)

□**श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर):** राजस्थान में खेजड़ी महत्वपूर्ण वृक्ष है । खेजड़ी आस्था और शुद्धा का भी विÂाय है राजस्थान के रेगिस्तान इलाके के लोग खेजड़ी को पूजते भी हैं । खेजड़ी

पर उगने वाली सांगरी मनुÂय भी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली भी है । अतः खेजड़ी की सुरक्षा व संरक्षण के लिए कोई पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है ।

*m76

□**श्रीमती कमला पाटले (जांजगीर-चाम्पा)**○: पूलूÂाण देश के समक्ष एक बड़ी समस्या है और इसके साथ ही विकास की चुनौतियां है। ऐसी विÂाम स्थितियों में भी सरकार पर्यावरण रक्षा का झंडा और विकास एजेंडा लिए चल पड़ी है। मैं ऐसी सरकार को धन्यवाद देती हूं।

पर्यावरण की रक्षा को जन आन्दोलन का रूप दिया जाना चाहिए। देश में वन क्षेत्रू दिनोंदिन कम होता जा रहा है। जंगलों में अवैध कटानों एवं अतिक्रमण पर तत्काल प्रतिबंध लगायी जाए, घने वन और अच्छी वÂाान एक सिक्के के दो पहलू हैं, अधिक से अधिक क्षेत्रू पर वनों का विकास करें तथा सामाजिक वानिकी पर विशेÂा ध्यान दें। वनीय क्षेत्रों को गैर-कानूनी खनन से बचाने तथा दुर्लभ औÂाधीय पौधों को बचाने के लिए कार्ययोजना तैयार की जानी चाहिए। भू-क्षरण को रोकने हेतु प्रभावी इंतजाम जरूरी है। पौध रोपण की महत्ता और जरूरत के बारे में आम लोगों के बीच जागरूकता पैदा की जानी चाहिए। स्कूल कॉलेजों के पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों के दैनिक आचरण एवं क्रियाकलापों में शामिल होना चाहिए। स्थानीय लोगों के कल्याण हेतु वनों का सतत् प्रबंधन किया जाना तथा वनों का संरक्षण करना हमारा दायित्व होना चाहिए। कैम्पा फंड की राशि राज्यों को मिलनी चाहिए, वन बंधु योजना का विस्तार किया जाना चाहिए। पर्यावरण के संरक्षण और संतुलन से ही स्थायी विकास संभव है आज छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्य हाथियों की समस्या से ग्रसित हैं - क्यों?

पर्यावरण संबंधी सरकारी मानदंडों का कड़ाई से पालन करते हुए ही परियोजनाओं को मंजूरी दिया जाना चाहिए। जो उद्योग नदियों को प्रदूÂिात करते हैं उन पर भारी दंड लगाना चाहिए, उनके लाइसेंस रद्द किए जाने चाहिए। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाने पर उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। औद्योगिक प्रदूÂाण नियंत्रित करने के लिए कानूनों के प्रभावी पूवर्तन आवश्यक है। उद्योगों की स्थापना में अपनी अप्रयुक्त श्रम शक्ति को रोजगार प्रदान करना चाहिए।

वायु प्रदूÂाण मानसून में विलम्ब का कारण है और ग्रीन हाउस का प्रमुख स्रोत है। ध्वनि प्रदूÂाण में नियंत्रण आवश्यक है।

मैं आपका ध्यान छत्तीसगढ़ की ओर ले जाना चाहती हूं जो धान का कटोरा है, प्रचुर मात्रा में खनिज सम्पदा है। बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकरण से जंगली जानवरों विशेÂाकर हाथियों के कारण जशपुर, सरगुजा, कोरबा जैसे कुछ क्षेत्रों में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

मेरे संसदीय क्षेत्रू जांजगीर-चाम्पा, प्रदेश में सबसे अधिक 76 प्रतिशत कृÂिा सिंचित है, पावर प्लांटों के कारण वायु एवं जल प्रदूÂाण की समस्या सामने आ रही है।

सरकार औद्योगिक प्रदूÂाण कम करने, वायु गुणवत्ता बनाए रखने, ठोस अपशिÂटों का उचित उपयोग करने, सड़कों का डाबरीकरण करने, वृक्षारोपेणी करने, नेशनल ग्रीन कोर कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के चार हजार स्कूलों में इको क्लब गठन करने, पालीथीन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए।

मैं सरकार से पर्यावरण संवर्धन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से जो बजट डिमांड है, उन्हें अनुपूरक मांगों में शामिल किए जाने की मांग करती हूं।

*DR. KULMANI SAMAL (JAGATSINGHPUR): Over a period of time it has been observed that our earth is facing a very deteriorating climatic condition from the view point of environmental pollution, deforestation subsequently leading to the climate change. The reason is industrialization, urbanization and lack of steps initiated for sustainable development of natural resources along with the regaining of forest cover. We are talking about development by planting industries all over the country which is helpful for any country to generate growth and employment, but that should not be at the cost of our environment and health. Forest management practices which includes afforestation, reforestation and forest restoration, etc. is not being followed by the policies and programmes appropriately. We know that sustainable management practices can ensure to maintain the capacity to provide benefit for current as well as future generations. Hence, management practices need to be actively planned, tailored to each specific ecosystem and evolving situations, so as to avoid overexploitation and forest degradation. Forest management plans and practices will also need to be adapted to modifications caused by climate change. As far as I am concerned, the adaptive forest management will be essential to address arising challenges and reduce forest vulnerability.

I have come across the situation in my own Parliamentary Constituency, Jagatsinghpur, where the industrial set ups like Fertilizer companies, Indian Oil Companies Limited etc. have been polluting the environment severely but they are not meeting the expected policies of corporate social responsibilities. They are also not installing the latest technology to reduce the level of pollution. So it is necessary on part of Government as well as various industrial set ups to look into the problems in order to save the environment. Now days the scenario of natural calamities is taking place everywhere thereby affecting the very nature of our earth. In this deteriorating process the most affected section is the poor people of our country as they do not get any profit out of that rather they suffer from health hazards directly and indirectly too. Hence, my sincere request is that the Government should come forward to be vigilant from the viewpoint of pollution caused by the industrial set ups and remedial measures are invited with adequate amount of funds to the concerned States.

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सारे सदन का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि बहुत से लोगों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया है। आज मुझे बहुत खुशी है कि सदन में सभी पार्टियों के हमारे 22 साथियों ने भाÂाण दिये। श्री निनोंग ईरिंग हमारे मित्रू हैं, उन्होंने शुरूआत की, श्री भगत सिंह कोशियारी, श्री राधाकृÂणन, श्रीमती ममता संघमित्रा, श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान, श्री राहुल शिवाले, श्री विष्वेष्वर रेड्डी, श्री एम.बी. राजेश, श्री पी.वी. मिथुन रेड्डी, कु. सुÂिमता देव, श्री दुÂयन्त सिंह, श्री जयप्रकाश नारायण यादव, श्री धर्मवीर गांधी, प्रो. प्रेमसिंह चन्दूमाजरा, योगी आदित्यनाथ, श्री दुÂयन्त चौटाला, श्री कौशलेन्द्र कुमार, श्री ओवेसी, श्री एन.के. प्रेमचन्दून, श्री जयदेवन, श्री अजय मिश्रा, श्री डी.के. सुरेश, I am really thankful to all of you because you have expressed your opinion and given your valuable suggestions which we value much.

जो मुद्दे यहां उठाए गए हैं, उनमें से बहुत से मुद्दों का तो मैं जवाब दूंगा, लेकिन अभी बीस मिनट का ही समय है। जिसका जवाब यहां नहीं दिया जा सकेगा, उसे हम लिखित रूप में भेजेंगे। चार-पांच माननीय सदस्यों ने लिखित भाÂाण भी दिए हैं। कल ही पार्लियामेंटरी स्टैण्डिंग कमेटी की रिपोर्ट आयी है, जिसके चेयरमैन अश्विनी कुमार जी हैं। इस रिपोर्ट का भी मैंने पूरा अध्ययन किया है। सभी ने पर्यावरण के प्रति जो चिंता जताई है और प्रेम व्यक्त किया है, यही मुझे आगे जाने का आधार लगता है।

सभी ने एक चिंता और व्यक्त की है कि इसमें बजट कम हो गया है। बजट के कम होने का दो-तीन रेफरेंस है। इसे समझना चाहिए। पहला तो यह है कि हमारे पास गंगा नदी के रिवर बेसिन डेवलपमेंट का कार्यक्रम है। लेकिन, नई सरकार के आने के बाद गंगा नदी के लिए अलग मंत्रालय बना तो हमारे मंत्रालय का गंगा का बजट 800-1000 करोड़ रुपये का होता था और गंगा का बजट अब उस नए मंत्रालय में गया है। इसलिए हमारा बजट कम नहीं हुआ है, बल्कि यह बढ़ा है। यह कैसे बढ़ा है, यह भी मैं बताऊंगा। जिन कार्यक्रमों में बजट कम हुआ है, ऐसा लगता है, उसमें मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि दो बार पूरक मांगें होंगी। पर्यावरण की रक्षा के लिए इस देश में फण्ड्स की कमी नहीं होगी, यह भी मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं।

एक और भी बात कहना चाहता हूं कि नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज को 100 करोड़ रुपये, क्लाइमेट चेंज एण्ड अडैप्टेशन के लिए 175 करोड़ रुपये, नेशनल कोस्टल मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए 100 करोड़ रुपये, नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम के लिए 164 करोड़ रुपये और 539 करोड़ रुपये नए कार्यक्रमों के लिए है। जब हम सबको मिलाकर देखते हैं तो बजट में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। एक ही बदलाव हुआ है कि 14वें वित्त आयोग के बाद सेंट्रल स्कीम्स को स्टेट्स के साथ फण्डिंग शेयर करने का पैटर्न बदल गया है। उतना ही बदलाव आया है और बाकी कोई कमी नहीं की है। मैं आपको बताऊंगा कि पर्यावरण के प्रति हम ज्यादा सजग हैं। आपके साथ चलकर हम और आगे बढ़ना चाहते हैं और उसमें फाइनैंस की कोई कमी नहीं होगी।

17.32 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

हमारे राÂट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था - "We have not inherited this earth from our ancestors. It is on loan from future generations. And, therefore, we must return them the earth as we inherited or actually making it better". That is what Mahatma Gandhi ji said. That is our ideal principle on which we want to 'Walk the Talk'. पांच तत्वों - आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि - का अनेक लोगों ने उल्लेख किया। इसी से हम बने हैं, सारी सृÂिट बनी है। प्राणी, वनस्पति, हम सब इसी से बने हैं। मुझ से अगर कोई पूछता है कि आपके इनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का मैनडेट क्या है तो मैं हमेशा एक जवाब देता हूं कि इन पांच तत्वों की रक्षा करना और इन पांच तत्वों के बीच संतुलन पैदा करना - यही हमारा मैनडेट है। अगर इसे दूसरी भाÂाा में कहूं तो अभी-अभी वेंकैया जी आए हैं और जैसे वेंकैया जी कहते हैं - 'एक हाथ में पर्यावरण का झंडा, दूसरे हाथ में विकास का एजेंडा।' इसका एक बड़ा मिथ तैयार किया गया कि मानो विकास पर्यावरण के खिलाफ है। पर्यावरण की रक्षा का मतलब विकास को बंद करना - ऐसा नहीं है। हमारी धारणा है - environment protection and development both. Development without destruction is our motto. इसलिए इसका कार्यक्रम क्या है? जो आप सभी ने बताया, वही इसका कार्यक्रम है - clean air, clean water, clean energy, clean environment and more green. मुझे लगता है कि ये ही हमारे पांच सूत्र हैं, जिनके आधार पर हम चलना चाहते हैं।

अब मैं लीगेसी की बात नहीं करूँगा कि कैसे मिला, लेकिन कभी-कभी गलत जानकारी के आधार पर या असत्य जानकारी के आधार पर लोग कुछ भी कहना शुरू करते हैं तो उससे बहुत प्रॉब्लम आती हैं। वे बोले कि आप आने के बाद क्लियरेंस ही देने लगे हैं। मैं केवल तीन आँकड़े बताता हूँ और जिन्होंने यह उठाया है, वे इसे ध्यान में रखें। वÂाऩ 2012 में 1,522 परमीशंस दी गई और एरिया डायवर्ट हुआ 25 हजार हैक्टेअर, वÂाऩ 2013 में नम्बर ऑफ प्रपोजल्स 1,317 को मान्यता दी गई, एरिया डायवर्टेड किया 41 थाउजेंड हैक्टेअर्स, वÂाऩ 2014 में नम्बर ऑफ प्रपोजल्स सैंक्शंड 783 हैं, क्योंकि पिछले साल चुनाव भी था और बाद में हम आए तो इतना ही हुआ है। पहले तीन महीने में वीरप्पा मोइली जी थे और एरिया डायवर्टेड 35 हजार हैक्टेअर, यह कम हुआ है तो 1500, 1300 और 783 हुए हैं। लेकिन क्या परमीशन देना गुनाह होता है? पर्यावरण की रक्षा की शर्तें रखकर, पहले क्या होता था और आज फर्क इतना ही हुआ कि हमने प्रोसेस ट्रांसपेरेंट किए हैं। हमने प्रक्रियाएं पारदर्शी तरीके से की हैं, ऑनलाइन कर दी हैं, ऑफिस-ऑफिस खेल बन्द कर दिया है। इसलिए लोगों को जो टैक्स देना पड़ता था, वह नहीं देना पड़ता है। ...(व्यवधान) This is mission without commission. That is the difference. That is what we are doing. ...(व्यवधान)

गौरव भाई, मैं इस पर भी आता हूं। मैं मूल मुद्दे पर कहना चाहता हूं कि हम काम क्या कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि फारेस्ट राइट डाइलूट किया। अरे भाई, फारेस्ट राइट के मंत्री इधर बैठे हैं, फॉरेस्ट राइट का डोमेन उनका है, मैं उनके कानून बदल नहीं सकता हूं। कहीं भी वर्ल्ड बैंक को हमने कुछ लिखकर नहीं दिया। कुछ भी पेपर में आ गया, उसे सच समझकर हम बोलने लगें तो जरा गड़बड़ होती है। एनबीडब्ल्यूएल के लिए कहा कि यह पूरी हुई ही नहीं, एनबीडब्ल्यूएल पूरी हो गई। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन जी मुझे मिले। हमने स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग की। मनमोहन सिंह जी ने 17 प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करके रखा था। एनबीडब्ल्यूएल की 17 महीने बैठक ही नहीं हुई थी, मैंने बैठक की। ...(व्यवधान) पहले ही दिन, मैं झगड़े के मूड में नहीं कहना चाहता, आपसे अपील कर रहा हूं, ...(व्यवधान) आप समझ लीजिए, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। ये 17 प्रोजेक्ट्स पहले ही दिन, क्योंकि पहले से ही एजेंडा था, पूर्व प्रधानमंत्री जी के प्रायोरिटाइज 17 प्रोजेक्ट्स देश के हित के थे, लेकिन उनके समय में मान्यता नहीं मिली थी, हमने वह पहले ही दिन दे दी। हमने क्या गलत किया?

अब रक्षा की बात आती है। पूरे भारत की सीमा, सीमा सुरक्षा के रास्ते, बार्डर रोड्स 6 हजार किलोमीटर के पेंडिंग थे। Why are they pending for years? हमने कहा कि पॉलिसी डिसीजन होना चाहिए, देश बचेगा तो पर्यावरण बचेगा। हमने पॉलिसी डिसीजन लेकर सारी बार्डर रोड्स को जनरल अप्रूवल दे दिया, 6 किलोमीटर की रोड्स दिए, लेकिन पर्यावरण की शर्तों के साथ समझौता नहीं किया।

कारवार में आपरेशन सी-बर्ड प्रोजेक्ट है, जो नेवी के लिए महत्वपूर्ण है। दस साल से नेवी उसे मांग रही है। आपके भी सदस्य मेरे साथ रक्षा मंत्रालय की कमेटी में थे। हम देख रहे थे कि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। कभी भी हमला होता है, we need two centres other than Mumbai. इसलिए एक कारवार का करना था, इसके प्रोजेक्ट की फाइल तीन साल पेंडिंग रही, मैंने तीन दिन में क्लियर किया, मुझे नहीं लगता है कि हमने कोई गलत काम किया। यह देश कि लिए किया। इसमें क्या गलत है? This must be done. हम सबको करना चाहिए।

फॉरेस्ट डेफिनिशन की बात की गई। हमने कोई फॉरेस्ट डेफिनिशन नहीं बदली है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि फॉरेस्ट की डेफिनिशन क्या होनी चाहिए? हम स्टेट को पूछ रहे हैं। सभी स्टेट्स के जवाब आए हैं। सब राज्यों के जवाब को हम सुप्रीम कोर्ट को सौंपेंगे कि सभी राज्यों ने यह कहा है कि ऐसा होना चाहिए। कोई व्यक्ति खुद प्लांटेशन करेगा, उसको भी फॉरेस्ट मानोगे, ऐसा पहले कोई अर्थ लगाया था। यह गलत है। Green cover is outside the forest.

यह कहा गया कि ट्राइबल की ग्राम सभा का राइट रद्द कर दिया, हमने ऐसा नहीं किया। Show me one document where we have done away with the Gram Sabha. हमने ऐसा नहीं किया है। आदिवासियों के लिए मैंने काम किया। ...(व्यवधान)

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Madam, with your permission, I would like to submit that earlier there was a decision that we will have Guillotine at six o'clock today and by that time the hon. Minister has to complete his reply. But many of the hon. Members had met me in the morning and also in the afternoon and just now saying that Health is also an important subject and the Government is not taking up discussion on the Demands of the Health Ministry and instead it is being guillotined. What I am suggesting is that we will continue the discussion and we will take up discussion on the Demands of the Health Ministry also and then we will have Guillotine at the same time tomorrow and then take up the Finance Bill day after tomorrow...(*Interruptions*) We may complete this by 5.30 p.m. tomorrow and then take up other business...(*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Madam, I have a point...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Venugopal, I have not called your name. झगड़ा नहीं। But first I have called Shrimati Teacher.

SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER (KANNUR): I want to speak for a few minutes on the discussion for Demands of Grants for the Ministry of Health and Family Welfare...(*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL: Madam, the Business Advisory Committee already decided that Guillotine will take place at 6 p.m. on 28th April, 2015. It has even been listed in today's Order Paper. Since yesterday we have been arguing for a detailed discussion but the Government argued that there is scarcity of time and that it is not possible to discuss the Demands for the Health Ministry. What is the urgency now for the Government to go for the discussion on the Demands for the Health Ministry?...(*Interruptions*) Now the Government is saying that the discussion on the Demands for the Health Ministry will be taken up tomorrow and every time the Government is doing that. The House is being taken for granted. The Business Advisory Committee has no role...(*Interruptions*) Is there any inconvenience for the Government to bring the Finance Bill tomorrow? Let them tell that...(*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Instead of appreciating the Government you are blaming the Government...(*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL: Is there an inconvenience on the part of the Government to bring the Finance Bill tomorrow?...(*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: This is surprising. The Members and the Parliament is supreme. When the hon. Members of the House want to discuss the Demands for the Health Ministry and I am agreeing to that, what is your problem?...(*Interruptions*) I am not able to understand...(*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL: I am putting a question. Earlier we argued for it and at that time the Government did not agree for it...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट, मेरी बात सुनिए। मैं हाउस की राय ले लेती हूं। Shri Venugopal, I have heard you as well. No more discussion on that. Not only Shrimati Teacher, there were so many requests for this. The hon. Members wanted that the discussion on the Demands for the Ministry of Health and Welfare should also be taken up. I discussed that matter with the Minister of Parliamentary Affairs, or, you can say the Government.

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :मैंने उनसे भी बात की है और कहा है कि अगर हाउस के बहुत सारे माननीय सदस्य इस विÂाय पर चर्चा करना चाहते हैं, आप इसके लिए तैयार हैं, आपका इस पर कोई ऑब्जैक्शन नहीं है और हाउस इसके लिए एग्री करता है तो we will have Guillotine tomorrow and day after tomorrow the House will take up the Finance Bill. That is why they have agreed. Now, if the House agrees today we will complete this Ministry.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): A decision was taken in the Business Advisory Committee and if that comes to the House, then the House will take a decision. House is supreme and we have time till the 30th of this month to pass the Finance Bill. So time is there. If the Government is agreeing to have discussion on Demands for Grants of the Ministry of Health and Family Welfare, it is well and good.

HON. SPEAKER: For you I actually discussed with him and he has agreed to it and if you want then we will complete it.

...(*Interruptions*)

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): I had previously requested that the Demands for all the six Ministries have to be discussed in the House. Therefore, let us take up the Demands for the Ministry of Health and Family Welfare also. As was said, this House is supreme. The House is meant for discussion. The Minister in that case will find an opportunity to reply. It is here that the Reports of the Standing Committees are presented. The Minister is not a part of the Standing Committees. This time we have taken up six Ministries. I would like to request the hon. Speaker to take up more Ministries in the next Budget Session so that the Members get more opportunities to discuss the Demands in the House and the Minister concerned will reply, which will help Members get information. ...(*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Madam Speaker, it is not a unilateral decision. Some hon. Members met the hon. Speaker; some Members met me and talked with me.

HON. SPEAKER: I made a request because you were also requesting.

...(*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: I can share with Shri Venugopal that I have a practical problem. Our Minister has been asked to go to Bihar tomorrow for looking after relief measures. Still, I told him that, as this is a popular demand from the Members, he may stay back and participate in the discussion on the Ministry of Health and Family Welfare. That being the case, when the Members make a request, the House is supreme and it can decide about it....(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri Venugopal, I am not allowing you to speak.

...(*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL: Then you have more time for the discussion on the Ministry of Environment and Forests. You could have extended the time for it....(*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Health is wealth....(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I would like to take the sense of the House now. If the House thinks it proper, we may take up the discussion on the Demands for Grants relating to the Ministry of Health and Family Welfare and then, around 5.30 p.m. tomorrow, we will have the guillotine.

Is this the sense of the House?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

श्री प्रकाश जावड़ेकर : दो-तीन मुद्दे और उठाए गए। मैं उनके बारे में भी बताऊंगा। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं जानकारी देने के लिए जवाब दे रहा हूं। It is because I do not want to win argument here; I want to win your confidence because all of us have to protect environment. That is why, I am telling you the true story. Regarding T.S.R. Subramanian Committee Report, लोगों को ऐसे लगा जैसे कानून बन गया है। नहीं बना है। This is one major input. कहीं तो शुरुआत होगी। बीस-बीस साल पुराने कानून हो गए हैं। परिस्थितियां बदल गई हैं। इनवायरमैंट पर ज्यादा खतरा है। कानून में सख्त बदलाव जरूरी है कि इनवायरमैंट की रक्षा करें। उसके लिए अगर हम एक कमेटी नियुक्त करते हैं तो Committee becomes the basis of our discussion. मैंने सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को लिखा, सुब्रह्मणियम कमेटी की रिपोर्ट भेजी, सबकी राय ली है। जिनकी नहीं आई है, 30 अप्रैल तक वह भी आ जाएगी। So, we are consulting everybody. This is not the law.

Regarding Aranmula Airport, my friend from Kerala knows the situation that there is the Indian Constitution. यूपीए सरकार ने अरनमुला एयरपोर्ट को परमिशन दी थी। एनजीटी ने उसे निरस्त किया। The Supreme Court also upheld the NGT's decision. लेकिन कानून में उन्हें पुन: ऐप्लीकेशन देने की परमिशन है। उसे मैं नहीं निकाल सकता।

So, they have applied but we have not approved even the TOR. कहीं मुद्दा है। एयरपोर्ट से हवाई जहाज तुरंत दौड़ने लगे, ऐसे मत कहिए। कुछ नहीं हुआ है। ओवेसी जी हमारे मित्र हैं। टेनरी, कानपुर, गंगा मैली हो गई। पहले गाना था कि गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते-धोते। यह सच नहीं है। गंगा मैली इसलिए हो गई है या देश में सभी नदियां मैली हो गई हैं। सीएजी की एक रिपोर्ट है। हमने सीएजी के 2जी, कोल और बाकी रिपोर्ट पढ़ीं, लेकिन Water pollution status in India, यह बेहतरीन रिपोर्ट तीन साल पहले दी। उसमें उन्होंने कहा है that nearly one-third of the industrial pollution goes untreated into the water bodies; one half of domestic waste, because it is not properly managed, ultimately goes into the water bodies; two-thirds of agricultural waste caused due to excessive use of fertilisers, pesticides percolate down below and goes to the water bodies. This is the cause of water pollution in India. फ्लोराइड बढ़ा है, आर्सेनिक बढ़ा है, पानी जो खराब हुआ है, उसकी यह कहानी है। आप सीएजी की रिपोर्ट पढ़िए। मुद्दा है कि अगर इसे ठीक करना है तो हमें नदी में सारे प्रदूÂाण आने से रोकने चाहिए। टेनरी की स्थिति मालूम है कि सब बड़े उद्योगपति नहीं हैं। टेनरी के लिए हमने स्पैशल पैकेज किया। उनके साथ मीटिंग हुई। राज्य सरकार भी साथ है। 40 प्रतिशत केन्द्र सरकार दे रही है। वह कुछ कौन्ट्रीब्यूट कर रही है, कुछ स्टेट गवर्नमैंट देगी। यह सब मिलकर होना है। जहां लोन्स की फैसीलिटी है, वह होगी। लेकिन पानी शुद्ध रखना है या नहीं। आपने आह्वान किया कि पानी शुद्ध रखिए। उसके लिए उपाय करेंगे तो थोड़ी कॉस्ट लगेगी। लोग कॉस्ट भी देने के लिए तैयार हैं इसलिए आप दिक्कत पैदा न करें। आज देश और दुनिया की हवा बहुत ही खराब है। सारी दुनिया में पोल्यूशन है। ऐसा नहीं है कि केवल दिल्ली में ही पोल्यूशन है और दुनिया के बाकी शहर पाक-साफ हैं। यह सैंकड़ों शहरों की बीमारी है। हर पांच से आठ साल में व्हिकलों की संख्या बढ़ जाती है। दिल्ली के आसपास जो स्टबल बर्निंग होता है उससे भी पोल्यूशन होता है। दिल्ली की हवा में खराबी आने का एक और कारण कंस्ट्रक्शन से निकलने वाली डस्ट है। आप सभी को सदन से पूछना चाहिए कि इसकी रोकथाम के लिए आप क्या कर रहे हो?

मैं बताऊंगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने दो सप्ताह पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स लांच किया, जिसमें केवल एक पैरामीटर नहीं है बल्कि आठ पैरामीटर बनाए गए हैं। जिसका उल्लेख मेरे एक मित्र ने किया है, इसमें एसओएक्स-नॉक्स, बेंजाइन, पीएम पार्टिकल 2.5 सबको मिलाकर एक कम्प्रिहेन्सिव एयर क्वालिटी, एक कलर, एक कोड में मिलता है। दस शहरों में इसकी शुरूआत हुई है। हम एक साथ सात शहरों का बुलेटिन रोज सुबह 12 बजे देंगे कि पिछले 24 साल की हवा कैसी थी। उसका पूरा विस्तार से बुलेटिन होगा, उसे भी आप छापें। यह ऑफियल डाटा होगा। हमें जनता से कुछ भी छिपाना नहीं है। जनता को अवेर करना है, उन्हें भी पार्टिसिपेट कराना है, इस एक्शन में उनकी भी सहभागिता जरूरी है। हमने कंस्ट्रक्शन के रूल्स तैयार किए हैं। हमने अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई। हम मैट्रो का काम देखने गए थे। मैट्रो में रोज ट्नेलिंग होती है, लेकिन उससे धूल नहीं निकलती है, क्यों? श्रीधरन ने उसके लिए नियम-कानून ठीक बनाएं। अगर मैट्रो का कारोबार अच्छी तरह से चलता है तो हम क्यों नहीं कंस्ट्रक्शन बेस्ड रूल्स बना सकते हैं? हमारा ड्राफ्ट भी तैयार हो गया है, वह जल्द ही वेबसाइट पर आ जाएगा और जल्द ही कंस्ट्रक्शन बेस्ड रूल्स लागू हो जाएंगे। कंस्ट्रक्शन बेस्ड धूल दिल्ली की हवा खराब नहीं कर पाएगी। हरियाणा और पंजाब सरकार ने स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए प्रोत्साहन दिया। उत्तर प्रदेश के मंत्री ने इसे रोकने के लिए काम करने का भरोसा दिलाया है। स्टबल बर्निंग नहीं होने से हम स्वच्छ हवा ले सकते हैं। हरियाणा में तीन जगहों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। हम सब को मिलकर एक्शन लेना है। मैंने दो मीटिंग की, डीडीए, दिल्ली गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार, राजस्थान सरकार, तीनों कॉरपोरेशन और ट्रैफिक पुलिस इन सभी का इसकी रोकथाम मे अह्म रोल है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक दिन साइकिल चलाओ, साइकिल चलाना चाहिए। इन्होंने शुरू भी किया है, इनकी सेहत भी अच्छी हो गई है। जनता को भी लेन डिसीजन का पालन करना चाहिए। It is a public action which will clear the air. सीमेंट इंडस्ट्री के नियम को हमने काफी स्ट्रीन्जेंट किया है, पहले यह काफी पोल्यूटेड इंडस्ट्री थी। 1,75,000 रिन्यूएबल इनर्जी क्रिएट करने के लिए हमने सात साल का कार्यक्रम बनाया है। दुनिया में किसी देश ने ऐसा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम नहीं बनाया है। इससे 350 मिलियन टन इमिशन कम होगा। हम एनर्जी एफीशेंसी बढ़ा रहे हैं।

मैडम आपको पता होगा कि अंडमान में 70 मेगावाट बिजली लगती है, जो डीजल से पैदा होती है। उससे प्रदूÂाण होता है। अंडमान में हम बायो मास एनर्जी को वुडवेस्ट से रिप्लेस कर सकते हैं। We are starting a pilot project this year. मुझे विश्वास है कि दो साल में हम दुनिया को ग्रीन कोल क्या होता है, यह दिखायेंगे। हम अंडमान को पूरी तरह से बायो मास एनर्जी दे सकते हैं। हम इस तरह के कार्यक्रम करना चाहते हैं और यह हमारी प्रतिबद्धता है। मैंने भी इसमें काम किया है। मैंने जल संवर्धन का काम किया है। मैं देहात में रहा हूं और मैंने आदिवासियों के साथ भी काम किया है। मैं जंगल में भी रहा हूं। ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है। मैं दुनिया के दूसरे ग्रह से नहीं आया हूं। मैंने पानी की शुद्धता के बारे में बात की। कुछ लोगों ने तालाब, झील, वेटलैंड्स आदि बहुत अच्छे सुझाव दिये। इनकी रक्षा के लिए भी जन-आंदोलन, जल साक्षरता चाहिए, क्योंकि लोगों को पानी की बचत करने के बारे में सीखना चाहिए। साथ ही साथ पानी को साफ रखने के लिए भी प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए। हम नया तंत्र ज्ञान में भी लायेंगे, नये कार्यक्रम भी लायेंगे और जनता का भी सहभाग लेंगे। हम नदियां भी साफ करेंगे। गंगा की सफाई तो अभी शुरूआत है। बाकी नदियों की सफाई भी क्रम से शुरू होगी। स्वच्छ भारत का यही अर्थ है। हमारा मिशन ही क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया है, इसलिए हम इसे करेंगे।

महोदया, पानी के बाद वेस्ट बड़ा प्रॉब्लम है। हम समझ नहीं रहे, जैसे एक बहन ने सीवरेज ट्रीटमैंट का उल्लेख किया। उन्होंने सच कहा कि हमारे देश में कैपसिटी कितनी है? हमारे देश में लगभग 35-40 फीसदी ट्रीटमैंट की कैपेसिटी है और वे भी आधी-अधूरी चल रही हैं, यानी सब नहीं चल रही हैं। सीवरेज ट्रीट नहीं होता, तो वह नदियों में जाकर मिलता है, इसलिए पानी खराब है। हमने इसका बड़ा कार्यक्रम लिया है। प्रधान मंत्री जी ने शौचालय के निर्माण में बहुत जोर दिया। वह भी हैल्थ का मुद्दा है। हमे इसे भी करना है। अब हम सॉलिड वेस्ट कैसे करेंगे? मैं आपसे कहूंगा कि आप आज कृपया हमारी वेबसाइट एमओईएफ पर जाइये। इस मिनिस्ट्री का पहले मिनिस्ट्री ऑफ एन्वायरन्मेंट एंड फॉरेस्ट नाम था, इसलिए अभी तक वेबसाइट का नाम वही है। आप एमओईएफ.ओआरजी में जाइये। मैं आपको सर्कुलेट करूंगा। हमने अपनी मिनिस्ट्री वेबसाइट पर पांच नये ड्राफ्ट रूल्स प्रकाशित किये हैं--सॉलिड वेस्ट रूल, बायो मेडिकल वेस्ट रूल, ई वेस्ट रूल, अब ई वेस्ट की समस्या भी हमें समझनी चाहिए। हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारे देश में सौ करोड़ मोबाइल फोन हो गये। अब सौ करोड़ मोबाइल फोन हो गये तो तीन साल में ये सौ करोड़ मोबाइल कचरे में जाने वाले हैं। यदि आज वे कूड़े में जाते हैं, तो वे उसका कूड़े में केवल प्रैशियस मेटल निकालते हैं और बाकी सारी चीजें लीच करके सारे वातावरण को प्रदूÂिात करती हैं। इस ई वेस्ट को कौन ठीक करेगा? हम नये रूल्स लेकर आये हैं। प्लास्टिक वेस्ट, जैसे मैंने कहा था कि 15 हजार टन रोज प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है, जिसमें से नौ हजार टन कलैक्ट होता है और छः हजार टन वैसे ही पड़ा रहता है। हमने इस पर काम नहीं किया तो हमें आगे बताना पड़ेगा। आपसे कोई पूछेगा कि अरे, आप कहां रहते हो, तो हम कहेंगे कि वह प्लास्टिक का बड़ा ढेर है, हम उसके पीछे रहते हैं। हमें यह काम करना पड़ेगा। हमने प्लास्टिक वेस्ट के रूल किये हैं, बायो मेडिकल वेस्ट के रूल किये हैं, हैज़र्डस वेस्ट के रूल किये हैं। ये सारे ड्राफ्ट्स हैं। अभी डेढ़ महीना उसका बाकी है, इसलिए आप भी उसे पढ़िये और सुझाव दीजिए। यह कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा नहीं है, यह देश है। हमें देश के वेस्ट को ट्रीट करना है। यही पर्यावरण की रक्षा है। मैं और किरीट सौमेया मुम्बई के डंपिंग ग्राउंड में गये। वहां 10 हजार टन वेस्ट इकट्ठा होता है। इस 10 हजार टन वेस्ट पर हजारों रैगपीकर्स थे। मैंने उन सबसे बात की। मैंने कहा कि आप प्लास्टिक क्यों नहीं उठाते, तो उन्होंने कहा कि छोटा प्लास्टिक जो पतली पन्नी का है, उसे यदि हम चार सौ इकट्ठा करेंगे तब जाकर हमारा एक किलो वजन होता है। उससे हमारा पेट नहीं भरता और चार सौ बार हमें झुकना पड़ता है। देश में जब कोई व्यवस्था नहीं थी तब से रैगपीकर्स ने इस देश में अच्छे कूड़े-कचरे की व्यवस्था की। मैं रैगपीकर्स को सम्मानित करना चाहता हूं। हम उन्हें सम्मान देंगे, सुरक्षा देंगे और स्किलिंग भी करेंगे। यह करने की जरूरत है। ...(व्यवधान) वे दोनों बैठे हैं और एक दूसरे का दर्द भी समझते हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक का लेफ्ट हैंड है और दूसरे का राइट हैंड है।

...(व्यवधान)

श्री प्रकाश जावड़ेकर : हां, स्वास्थ्य मंत्री जी उनकी देखभाल कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

18.00 hrs

सबने उल्लेख किया, हम कैबिनेट के सामने कैम्पा बिल ला रहे हैं। 35,000 करोड़ रुपए जमा हैं। दस साल प्रश्न क्यों नहीं उठा, यह मुझे आप सबसे पूछना है।

माननीय अध्यक्ष : छः बज गए हैं। अगर आप सबकी अनुमति हो तो यह पूरा होने तक हाउस एक्सटैंड कर देते हैं।

कुछ माननीय सदस्य: जी हां, कर दीजिए।

श्री प्रकाश जावड़ेकर: कैम्पा फंड का 35,000 करोड़ रुपया राज्यों को बांटा जाएगा। 35,000 रुपए राज्यों को बांटने की चर्चा हो रही थी, इसमें से 90 परसेंट बांटने की बात थी। ...(व्यवधान) बिल क्यों लाना पड़ रहा है क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हम राज्यों का पैसा राज्यों को देना चाहते हैं, वहां एफोरेस्टेशन होगा, वाइल्ड लाइफ के केयर होगी, बाकी स्कीम्स में पैसा मिलेगा। राज्य सरकार के बजट का कुछ भी हिस्सा कम नहीं करना चाहिए। एडीशनल फंड एडीशनल एफोरेस्टेशन के लिए होना चाहिए। उत्तराखंड के बारे में पूछा गया, 35,000 करोड़ रुपए में से इसके लिए 2400 करोड़ है, आंध्र प्रदेश के लिए 2700 करोड़, अरुणाचल प्रदेश के लिए 1400 करोड़ रुपया है। हर राज्य का पैसा मिलेगा। मुद्दा यह है कि हम कैम्पा फंड को बांटना चाहते हैं क्योंकि हम एक्शन

में बिलीव करते हैं। हम ग्रीनरी ज्यादा एग्रेसिवली चाहते हैं इसलिए डिग्रेडिड फॉरेस्ट को ग्रीन करने की अनेक योजनाएं बना रहे हैं। हमें इसमें आप सबका सहयोग चाहिए।

एक बड़ी दिक्कत यह थी कि जंगल की प्रोटेक्टिड एरिया की सीमा कितनी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जब तक राज्य और केंद्र सरकार बफर जोन का सही सीमांकन नहीं करेंगी तब तक दस किलोमीटर का दायरा होगा। दस किलोमीटर तो ठप्प हो गया। हमने इस प्रॉसेस को जल्दी शुरु किया। हमने सब राज्यों से बात की, वर्कशाप्स ली। मैंने कहा कि पत्राचार से काम नहीं होगा, सबको बुलाओ, आमने-सामने बैठकर जो कमियां हैं उसे दूर करो लेकिन जस्टीफाइड बफर जोन तैयार करो। बफर जोन तैयार हुआ, हमने 130 बफर जोन की परमिशन दी है और डिफाइन किया है। इसकी सराहना कोर्ट ने भी की कि ऐसे काम होना चाहिए था, इतने सालों से नहीं हुआ, अब हो रहा है, अच्छा है।

माननीय सदस्य ने कार्बन क्रेडिट का उल्लेख किया। हम तो ग्रीन क्रेडिट देना चाहते हैं। कोश्यारी जी ने इसका सुझाव दिया। यह तो ऐसे हुआ कि पाप करो, कार्बन पैदा करो, हवा में छोड़ो और पैसे देकर पाप से मुक्ति पाओ। ऐसे नहीं होता है। आपको ग्रीन क्रेडिट ग्रीन एक्शन से मिलेगा, हम इस ग्रीन क्रेडिट के बारे में सोच रहे हैं। फॉरेस्ट कवर कैसे बढ़े? इसमें एन्क्रोचमेंट की समस्या है। डिग्रेडिड फॉरेस्ट लैंड लगभग तीन करोड़ हैक्टेयर है। हमें तीन करोड़ हैक्टेयर लैंड को ग्रीन करना है। शहरों में जंगल जमीन पर एन्क्रोचमेंट होता है। हमने कम्पाउंड करने का निर्णय लिया। जनता की सहभागिता से स्मृति वन का काम शुरु किया। लोग पैसा भी देंगे, पेड़ भी लगाएंगे। प्रिय लोग, जो आज दुनिया में नहीं हैं, उनके स्मरण में लगाएंगे। अर्बन ग्रीन, रूरल ग्रीन करेंगे। डिग्रेडिड फॉरेस्ट को घना करेंगे और कैम्पा फंड भी देंगे। एफॉरेस्टेशन का काम करेंगे क्योंकि सारे देश को हरा भरा करना है।

वाइल्ड लाइफ की चिंता यहां पर अनेक लोगों ने की। यह सही है कि हमने अभी दो नये टाइगर पास किये। एक देश को अभिमान होना चाहिए कि आज दुनिया के 70 फीसदी बाघ अपने भारत देश में हैं और भारत दूसरों को दे भी सकता है क्योंकि 2026 हैं और उसमें 1700 बाघों की तस्वीरें हमारे पास हैं। यह आइडेंडिटी अलग अलग होती है। ये आज एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। आपने बजट की बात पूछी। एक्सटिंक्ट होने वालों के लिए हम पब्लिक सैक्टर और प्राइवेट कंपनियों के पास भी गये और हरेक ने एक एक बर्ड के रीहैबिलिटेशन का काम लिया है, इंटरेस्ट दिखाया है। हम इसको आगे ले जाएंगे। एक एक जो एक्सटिंक्ट होने वाली प्रजाति है, उसकी हमें रक्षा करनी है। यह पब्लिक पार्टिसिपेशन से भी होगा। हम भी उस पर ध्यान देंगे, कोआर्डिनेट करेंगे।

अब जैसे ह्यूमन एनीमल कांफलिक्ट है, यह भी एक बहुत बड़ा विÂाय है। वÂाऩ 2014 में 500 लोग प्राणियों के हमले में मरे हैं। हम लोग उस बारे में कोई चर्चा कभी नहीं करते। क्या मनुÂय जीवन का कोई महत्व नहीं है? किसी अन्य देश में 500 लोग मरे होते तो उन देशों ने क्या किया होता? लेकिन हम इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे? मुझे लोगों ने बताया कि सर, प्राणी इसलिए बाहर आ रहे हैं क्योंकि अंदर पानी नहीं मिल रहा है या घास नहीं मिल रही है तो इस कारण से वहां प्रे नहीं आते हैं। इसलिए हम अभी यह व्यवस्था कर रहे हैं कि जंगल में घास ज्यादा पैदा हो और पानी ज्यादा रहे। हम इस वाइल्ड लाइफ की तरफ ध्यान देंगे। हम इसको अच्छा बनाएंगे।

हमें एक प्रैशर समझना चाहिए। आप सब लोग इस बात को कृपया याद रखें कि दुनिया का केवल 2.5 प्रतिशत ही लैंड मास हमारे पास है। We have only 2.5 per cent of the land mass. But we have 17 per cent of human population and 17 per cent of cattle population of the world. दुनिया की 17 फीसदी आबादी ढ़ाई फीसदी जमीन पर रह रही है तो प्रैशर तो बनेगा। लेकिन इसका मतलब जंगल की एक इंच जमीन भी हम किसी को नहीं दे रहे हैं। जंगल की जमीन अगर हम नहीं देंगे और अगर कहीं डाइवर्ट होता है तो उसके बदले में दुगुनी जमीन उसको देनी पड़ती है। वह नियम कायम है और यह बॉयोडाइवर्सिटी ऐसी है कि दुनिया की आठ फीसदी बॉयोडाइवर्सिटी हमारे देश में है। कितनी प्रजातियां हैं? कितने प्राणी और कितने फूल हैं तथा कितने नये प्राणियों की जानकारी तेलंगाना में दी गई।

मैं अभी श्रीशेलम में गया था। वह बॉर्डर में है। वह थोड़ा आंध्र प्रदेश में है और थोड़ा तेलंगाना में है। मैं वहां पर गया और वहां पर भी मैंने नयी प्रजातियां देखीं। यह नोगोया प्रोटोकोल जो हुआ, अभी 6 महीने पहले नोगोया प्रोटोकोल में बॉयोडाइवर्सिटी का प्रोटैक्शन और बैनेफिट एक्सैस तथा हमारे देश में इतनी अपार सम्पदा है, उसका फायदा भी हमें मिलेगा अगर दुनिया उसका यूज़ करेगी। इसलिए नोगोया प्रोटोकोल को भी पचास देशों ने रैटिफाइ किया है, वह लागू हो गया है। हम राज्यों को ताकत देना चाहते हैं। 40 हेक्टर फॉरेस्ट का अगर डाइवर्जन करना है तो हर फाइल मेरे पास आती थी। एक हैक्टर, दो हैक्टर, मैंने कहा कि यह क्या हो रहा है? ये राज्यों के पास क्यों नहीं होता? वहां व्यवस्था विकेन्द्रित होनी चाहिए। इस पर एक अधिकारी ने कहा कि सर, अपने पास फिर फाइल ही नहीं आएगी। मैंने कहा कि नहीं आने दो। मुझे फाइल में इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट काम जल्दी होने में है।...(व्यवधान) इसलिए हमने सारी रीजनल कमेटियां बनाई जिसमें हर राज्य के प्रिंसिपल सैक्रेटरी, जिसमें फॉरेस्ट के और रेवेन्यू के दोनों अधिकारी उसके मैम्बर्स रहेंगे। हमने एक मल्टी स्टेट होल्डर कमेटी बनाई। उस कमेटी के आधार पर Ninety per cent of the file work is now delegated to Regional and State Centres. That is what we are doing. हम अपने पास नहीं रख रहे हैं। हमने काम खुला किया है कि काम प्रामाणिकता से करो। लोगों ने चिंता व्यक्त की कि हम कहीं विश्व मंच के दबाव में तो नहीं आ रहे हैं। ओबामा जी के सामने एक पत्रकार ने मोदी जी से पूछा: 'Mr. Prime Minister, is there any pressure?' The Prime Minister said, 'There is no pressure and we do not take pressure. But there is a pressure, pressure of climate change and pressure on future generations.' उसके लिए हम काम करते हैं और उसमें हमारे जो एक्शंस हैं, आज दुनिया सराह रही है कि आज भारत इतना एक्शन कर रहा है तो हमें भी करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लीमा में जो लड़ाई आखिरी दो दिन हुई, मैं बाकी किसी के लिए नहीं कहता कि कौन क्या करता था, मैं पहले दिन से सुबह 9 बजे से रात तक जब भी समाप्त होगा, मैं वहां बैठा रहा। सब देशों से बात करता रहा। सबसे नाता जोड़ा, नैट-वर्किंग की। पिछले महीने में 58 अफ्रीकन देशों की कांफ्रेंस हुई। उनके सभी पर्यावरण मंत्री थे। उन्होंने अफ्रीका के बाहर के केवल दो नेशंस बुलाए। उसमें एक फ्रांस था क्योंकि वह पेरिस का होस्ट है और एक ही कंट्री बाहर की बुलाई जो कि भारत था। हमें अभिमान होना चाहिए क्योंकि उनको लगता है कि ये हमारे हमदर्द हैं। हमने हमदर्दी दिखाकर वह काम किया और नेटवर्किंग की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेंट चेंज (UNFCCC) का मेनडेट है, जो सीबीडीआर है, जो इक्विटी है, इन प्रिंसीपल्स को ही हमने दुनिया को बताया है कि इसके अलावा नहीं चलेगा। फाइनल ड्राफ्ट में वही आया है। यूएनएफसीसीसी की इक्विटी भी आई, सीबीडीआर भी आया, मिटिगेशन भी आया, रेपुटेशन भी आया, फाइनेंस भी आया, टेक्नोलोजी भी आया, कैपेसिटी भी आया। आज हम काम करके बताते हैं कि हम 2020 के पहले इतना एक्शन ले रहे हैं। हम कहते हैं कि आप भी आगे जा कर यह काम करो इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पर्यावरण भारतीय लोगों की 'वे आफ लाइफ' है और इसे आगे ले कर जाना हम सब का काम है। पृथ्वी का और पांच तत्वों की रक्षा करना और संतुलन करना हमारा काम है। विकास बनाम पर्यावरण रक्षा का झगड़ा मत पैदा कीजिए, ऐसा नहीं है। दोनों काम साथ हो सकते हैं, दोनों की जरूरत है और हम दोनों एक साथ करेंगे। धन्यवाद।

HON. SPEAKER: I will allow one clarification only from one Member. Shri Gaurav Gogoi.

SHRI GAURAV GOGOI : Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, the Minister had talked about the Government's proposal to introduce the Air Quality Index which is being introduced in 10 cities in 37 different locations. The proposal seems to be incomplete because already the Ministry of Earth Sciences has its own air monitoring device. The category of air pollution of the Ministry of Earth Sciences is different from the Air Quality Index of the Ministry of Environment. The categories of air pollution of these two Ministries are different from the global standards. जनता कन्फ्यूज़ है कि वह अर्थ साइंसिज़ पर, पर्यावरण पर या ग्लोबल हैल्थ पर किस पर विश्वास रखे। अगर हम यह सब डेटा ले भी लें तो हमें जनता को बताना पड़ेगा कि इतने प्रदूÂाण का उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या जनता मास्क पहनना शुरू करे? जनता को कैसे प्रिकाशन और पोटेक्शन चाहिए The air is quite hazardous. हमें इस बात से भागना नहीं चाहिए। We should have the courage to confront it. हमें सिटिजन्स में मास अवेयरनेस पैदा करनी है, उसके लिए इस बजट में क्या प्रोग्राम है। जो खतरनाक हवा है, उससे हम जनता को कैसे बचा सकते हैं, इसे जनता को बताना पड़ेगा।

DR. A. SAMPATH (ATTINGAL): Madam Speaker, I would like to seek a clarification from the hon. Minister. My heart is with him. He is the brain; that is why I am seeking a clarification from one of my best friends.

Our nation is using more and more electronic gadgets and electronic materials. Not only that, we have started using the CFL bulbs all over the nation. Constantly we have been promoting the use of the CFL lamps. In the schools also, the teachers tell to the school children, 'Do not use the *gundu* bulbs; you use the CFL lamps'. So the clarification I seek from you, through the hon. Speaker, is this. When we are using more and more mercury lamps and CFL lamps, anyway that creates another ecological hazard. It is because, as you have stated in the House, mercury is a highly poisonous and hazardous material. So a CFL lamp which has become defunct, which cannot be used any more, which cannot be lit, what the people do is that they throw it outside the house. They dump it somewhere on the ground or in the water resource. Even a small piece of mercury lamp or a CFL lamp can create hazardous waste for the coming generations also by polluting land and also water. If there are any laws, those laws are not

being implemented. So, I would like to know whether we can adopt a method just like in some European nations. There, the Government asks the sellers to collect back the material, to give some incentive to the people to bring it back to the shops. So such a type of user-vendor relation, such a method can be adopted here in India also.

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल (दमोह) : माननीय अध्यक्ष महोदया, देश में बमुश्किल 30-35 ऐसे जिले होंगे, जिन्होंने रिज़र्व फॉरेस्ट रखा है। मैंने चार क्षेत्रों से चुनाव लड़ा है, जहाँ पर रिज़र्व फॉरेस्ट है। 48 प्रतिशत फॉरेस्ट वाला क्षेत्र- बालाघाट, छिन्दवाड़ा, सिवनी और वर्तमान में दमोह है, जहाँ पर दो अभ्यारण्य हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आप ग्रीन क्रेडिट की बात करते हैं, ऐसे जिले देश में बमुश्किल 50 होंगे, क्या इनको ग्रीन क्रेडिट मिलेगी? हमें सड़क के परमिशन के लिए भी आना पड़ता है।

दूसरी बात, जो टाइगर रिज़र्व हैं, सर्वाधिक टाइगर रिज़र्व मध्य प्रदेश में हैं, उसके बावजूद भी, पुरानी परम्परा है कि लोग उसकी हत्या करते हैं, इसलिए उसकी तस्करी होती है और अमूल्य चीजों को जलाने का काम करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि उन जिलों को उनके विकास के लिए वही रास्ता मिलेगा और जो शेरों के अंग-प्रत्यंग जलाये जाते हैं, क्या उनको सरकार प्रेज़र्व नहीं कर सकती है? इतनी बहुमूल्य चीजों को क्यों जलाना चाहिए? सिर्फ इस डर से कि उनकी तस्करी होगी। इस कारण से ऐसे कानून बनते हैं, क्या मंत्री जी इस पर विचार करेंगे?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much Madam Speaker. I fully appreciate the efforts made by the Government of India in the Lima Conference. I do appreciate the stand taken by the Government as well as the efforts personally made by the hon. Minister Mr. Javadekar. But I would like to express the concern that we are experiencing in our country. All the environmentalists and the entire nation would like to know whether the TSR Subramanian Committee recommendations will be accepted by the Government. I specifically spoke in my speech that if this TSR Subramanian Committee Report is implemented or accepted by the Government it will definitely be an environmental disaster to the country. It will be a violation of the Constitutional obligations as well as the legal obligations which we have committed to the international forum.

I would like to seek a clarification or a specific answer from the hon. Minister as to what is the response of the Government in respect of TSR Subramanian Committee recommendations.

DR. M. THAMBIDURAI: The hon. Minister knows very well that India is facing the problem of shortage of drinking water. Why are we facing this problem? It is because all the rivers are polluted. It is not only Ganga and Cauvery but other rivers in India are also polluted. Why are they polluted? It is because the industries are discharging their effluents into the rivers. Apart from that, whatever drainage we have in our municipalities that also is going into the rivers.

I want to know from the hon. Minister whether the Government is going to bring any legislation at the national level to stop the industries from discharging their effluents into the rivers and to get pure drinking water for the future generation.

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में एक नैशनल पार्क, एक टाइगर रिज़र्व और एक अभ्यारण्य- ये तीन फॉरेस्ट रिज़र्व हैं और लगभग 50 प्रतिशत क्षेत्र वन भूमि है। लेकिन माननीय मंत्री जी ने कहा कि घास और पानी की व्यवस्था करूँगा। मेरे क्षेत्र में उन जंगलों को खड़ा रखने के लिए एक सिंचाई योजना पिछले 42 साल से वन कानूनों के कारण लम्बित है। उससे 1,11,800 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी साथ ही साथ जंगल भी बचेंगे। लेकिन उस योजना को वÂ○ान 1972 में स्वीकृति मिली थी, तब टाइगर प्रोजेक्ट नहीं लगा था। आज टाइगर प्रोजेक्ट के नाम पर उस योजना को पिछले 42 वÂ○ा○ा○ॉ से लम्बित रखा जा रहा है। यह चतरा में लातेहार जिले की योजना है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस प्रकार के योजनाओं की स्वीकृति कैसे होगी?

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): I would not have asked you time, if you were allowing us to speak on one of the Cut Motions given by us. That is why I have to ask time from you. I had given a Cut Motion at serial no. 3.

माननीय अध्यक्ष : नहीं, कट मोशन पर नहीं बोलना है।

PROF. SAUGATA ROY : I will not read the Cut Motion. There is a need to take effective measures to control vehicular pollution in the metropolitan cities including New Delhi. The hon. Minister has taken us on a trip around the world including what happened in Lima, in South America and how he stayed up till 2 o'clock at night from the morning. I appreciate all that.

HON. SPEAKER: Hon. Member, just ask your clarification.

PROF. SAUGATA ROY: Madam, please listen to me. I am quoting from the Report of the Standing Committee.

It says:

> "The concentration of PM 2.5 fine respirable particles which is considered most dangerous for health is highest in Delhi at 153 micrograms per cubic meter as against the WHO standard of 10 micrograms per cubic meter. The concentration of PM 10 (coarse particles) in Delhi is about 286 micrograms per cubic meter, â€¦."

HON. SPEAKER: Prof. Saugata Roy ji, you can ask only one clarification.

PROF. SAUGATA ROY: Madam, I shall finish it in one minute. I am speaking on a very limited subject, on which I have given a Cut Motion.

I would just like to ask the Minister one question. As per the Report of the Standing Committee, the Ministry, in a recent affidavit filed before the Delhi High Court, has stated that as yet, there is no finalized Action Plan to tackle the challenge of air pollution in New Delhi. The Standing Committee also suggested that there should be an effective public transportation system. ...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You conclude now.

PROF. SAUGATA ROY: Please allow me to speak. ...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You are reading it from the Standing Committee Report. You can ask only a clarification. That is all.

PROF. SAUGATA ROY: Madam, unless I create the context, how can I ask? ...(*Interruptions*) I do not ask any irrelevant question. It is not my habit.

I would like to know specifically from the hon. Minister about the steps that are being taken to reduce air pollution in New Delhi according to the standards set by the World Health Organization. Is there any plan to reduce vehicles to improve public transport? How can you make the life of the citizens of Delhi a little healthier?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam, very recently, the tiger enumeration result had come out. In that enumeration result, it was mentioned that the tiger population has gone exorbitantly high. We have no quarrel with that but it all mentioned that the population of tigers in Odisha had come down which was there three years earlier. Our Forest Department and the Odisha Government objected to that, and categorically stated – I think, the hon. Minister is aware of this – that these are three forests - Satkoshia Forest of Nawapara, Similipal Biosphere of Mayurbhanj, Keonjhar and Balsore – where actual enumeration has not taken place and the method in which the tigers are being counted is doubtful.

Madam, I have given a notice for a discussion on this issue and drew the attention of the Minister but anyway that has not come. We are taking so much credit on enumeration that has taken place. The statement that our tiger population has increased manifold within this period has become doubtful by our own Forest Department. To make it more relevant, will the Minister take steps and come out with a foolproof enumeration and also come up with the facts which State is having how many tigers today?

श्री लक्ष्मी नारायण यादव (सागर): अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहता हूं कि गांवें से लगे हुए वनों में इस वक्त रोज़ और सुअरों की संख्या बहुत बढ़ गयी है, क्योंकि उनमें छः महीने में पूजनन होता है। रोज़ नीलगाय को कहते हैं। उनका पूजनन इतना ज्यादा हो गया है कि वे किसानों के लिए समस्या बन गए हैं। इस समस्या के बारे में क्या माननीय मंत्री जी कोई समाधान कर रहे हैं?

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : अध्यक्ष महोदया, मैं उसी क्षेत्र से आता हूं जो वन का इलाका है - बांका। वन की कटाई से, जलवायु में परिवर्तन से तथा पर्यावरण में प्रदूÂाण से देश का भारी नुकसान हो रहा है। इसकी रोकथाम के लिए कौन से व्यापक एवं बड़े उपाय किए गए हैं? क्या दुनियाभर के वैज्ञानिकों से समन्वय करके इससे बचाव के उपाय करने के बारे में सरकार कोई विचार रखती है, क्योंकि तभी मेक इन इंडिया सफल होगा?

DR. BOORA NARSAIAH GOUD (BHONGIR): Madam, I take this opportunity to thank the hon. Minister, Shri Javadekar. Telangana is an electricity deficient State. We had a 6,500 Mega Watt Ultra Mega Thermal Power Project. All the hon. Members may note that the hon. Minister has given the forest clearance for 2,000 acre in only 45 days. I am really thankful to the hon. Minister.

At the same time, his Department is working north and south. The Environment Minister is working so fast in clearing the projejcts. In my own Constituency, there is a black top road. In Hyderabad there is a forest area. For the last eight years, in the black top roads, a lot of pits were there. Our Government has released the Budget for the black top road. I have talked to the DFO. It is already an existing road. It is a BT road. But they never allow the road on the existing road. It is a contradictory Department, I think. His style of action should percolate down to the ground level also. That is my appeal.

SHRI ARVIND SAWANT (MUMBAI SOUTH): Madam, I have a specific question. In Mumbai, Sanjay Gandhi Rashtriya Udyan is there. A lot of encroachment has taken place there. The compound wall is also broken. Encroachment is continuing. Doors are being constructed. But no measures are being taken there. That is one primary question, on which I would like to know from the hon. Minister.

My second query is regarding the Nuclear Power Plant. In Ratnagiri District, Jaitapur Nuclear Power Project is coming up. That Nuclear Project is under seismic zone. This is the Report of the Geological Department of the Government which says that ninety-two earthquakes have taken place ranging form 3.5 to 5.5 Richter scale from 1985 to 2005. I want the response from the hon. Minister.

श्री विÂणु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : अध्यक्ष महोदया, अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह विश्व में बायोडायवर्सिटी में नम्बर एक पर है। अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में 90 प्रतिशत फारेस्ट है, करीब छः से सात प्रतिशत अंडमान में रेवेन्यू/फारेस्ट लैंड पर आबादी है। मेरे दो सवाल हैं। नितिन गडकरी जी ने हाल ही में वहां का दौरा किया था, तो उन्होंने कहा था कि देश में एक लाख करोड़ पाम ऑयल पड़ोसी देशों से आयात किया जाता है, जिसमें थाइलैंड और म्यांमार प्रमुख हैं। मेरी मांग है कि अंडमान में निकोबार आइलैंड में ग्रीन गास लैंड है, डेजर्ट लैंड है, क्या वहां वृक्षारोपण की इजाजत देंगे या पोर्टब्लेयर में इसकी इजाजत देंगे? अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पर डीम्ड फारेस्ट की घोÂाणा की थी कि उसे दोबारा डीरिजर्व किया जाएगा, करीब 61 हेक्टेयर लैंड है, क्या उसे डीफारेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे? अंडमान-निकोबार के फारेस्ट को बचाया जाए, यह मेरा तीसरा प्रश्न है।

श्री बदरुद्दीन अजमल (धुबरी): काजीरंगा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। मंत्री जी अभी असम गए थे, तो हमने उनसे कहा था कि असम में राइनो जो कि बहुत ही रेयर स्पीशीज है, उसे मारकर खत्म किया जा रहा है। पिछले दस साल में कितने ही राइनो मारे गए हैं। आप वहां के न्यूज़पेपर्स में पढ़ सकते हैं कि रोजाना दो-तीन राइनो की हत्या होती है। इसके अलावा टाइगर्स मारे जा रहे हैं, हाथी मारे जा रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि इस मामले में मंत्री जी क्या एक्शन ले रहे हैं?

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Madam, with regard to Climate Change, there is one Panchayat in my Parliamentary Constituency, which is called Mandru Islands. Recently, the sea water has entered into the habitat area. A lot of houses have been demolished. Roads have also been damaged. May I know from the hon. Minister, whether the Government of India, Ministry of Environment, Forests and Climate Change has conducted any study there and found out any solution.

SHRI K.N. RAMACHANDRAN : There is a panic and pathetic situation regarding e-waste. We are at the fifth place in the globe in regard to e-waste. I would like to know from the hon. Minister whether there is any concrete solution to this panic and pathetic situation of e-waste.

0

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सवाल पूछना चाहता हूं कि हजारों-लाखों सालों से यह माना गया है कि अगर हवा की शुद्धि करनी है, हवा को अगर प्योरिफाई करना है तो उसके लिए सबसे बड़ा साधन यज्ञ और हवन है। यह कोई धार्मिक विधि नहीं है, लेकिन हवा और पर्यावरण को शुद्ध करने का सबसे इफैक्टिव मैथड है।

क्या माननीय मंत्री जी यज्ञ और हवन को ऑफिशियल रूप से मान्यता देंगे और उसे बढ़ावा देंगे?

1

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला) : महोदया, हमारे देश में वाइल्ड लाइफ एनिमल प्रोटैक्शन एक्ट 1974 है। हिली एरियाज में जंगली जानवर खासकर बंदर, सूअर और नीलगाय बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। मैं हिमाचल की बात कहूं तो आज वहां पर 70 प्रतिशत किसानों ने खेती करना बंद कर दिया है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आवारा कुत्ते इतने ज्यादा बढ़ गये हैं कि वे लोगों पर हमला कर रहे हैं और अगर कुत्ते पागल हो रहे हैं तो वहां की म्युनिसिपैलिटी या पंचायत उन पर काबू नहीं पा रही है। अभी हाल ही में पिछले महीने शिमला के मॉल रोड पर, जो सबसे ज्यादा प्रोटैक्टिड एरिया है, वहां पर पचास लोगों को पागल कुत्ते ने काट लिया और वहां की लोकल म्युनिसिपैलिटी कुछ नहीं कर सकी। क्योंकि वहां का कानून उन्हें मारना अलाऊ नहीं करता है।

इसलिए मंत्री जी मेरा यह कहना है कि वाइल्ड लाइफ एनिमल प्रोटैक्शन एक्ट के तहत जो जंगली जानवरों को बचाया जा रहा है, क्या उसमें आप कोई संशोधन करेंगे?

2

SHRI SURESH C. ANGADI (BELAGAVI): It is a very important issue in regard to the human beings. The Khanapur has a very dense forest in Karnataka. It is surrounded by Maharashtra, Goa and Belgaum. Two months ago, a tiger had come to the fields in the open area from the forest. Some elephants had also come on the road. I want to know whether any protection is being given to those farmers. Already one lady was killed because a tiger attacked the lady. Still the Government has not made any enquiry. A CBI inquiry should be made in this regard.

श्री प्रकाश जावड़ेकर : मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज बैठिये, सबकी बात आ गई है।

3

श्री प्रकाश जावड़ेकर : मैं बहुत लम्बा उत्तर नहीं दूंगा, लेकिन सब मुद्दे बताऊंगा। CPCB has already developed guidelines for safe disposal of CFL lamp. इसके अलावा जो ई.-वेस्ट रूल्स है, जो ड्राफ्ट है, उसे सम्पत जी आप भी पढ़िये। सम्पत जी, आप अच्छे हो तो उसे पढ़ो और हमें सुझाव दो और अगर कुछ बदलाव करना है तो बताइये, हम वह करेंगे।

दूसरी बात यह है कि दिल्ली की एयर क्वालिटी का जो मुद्दा है, एक्शन यह तय किया है। यहां चार कारणों से पॉल्युशन होता है, एक व्हीकुलर पॉल्यूशन, दूसरा स्टबल बर्निंग, तीसरा कंस्ट्रक्शन वेस्ट और चौथा जो धूल आती है, जो रेगिस्तान से भी आती है, ऐसे बहुत से कारण हैं। इसके अलावा दिल्ली में जो बायोमास जलाते हैं तो हम दिल्ली में बायोमास न जलायें, इसके लिए स्वीपर्स के प्रशिक्षण का कार्यक्रम दिल्ली सरकार और कारपोरेशंस ने तय किया है। उसमें सबको अवेयर भी करेंगे और लोगों को यह भी कहा गया है कि व्हाट्स एप पर तुरंत लेकर बताइये और लोगों ने दिखाना शुरू भी किया है और उस पर तुरंत एक्शन भी हो रहा है। ...(व्यवधान) व्हीकुलर पॉल्यूशन की बाबत फ्यूल की एफिशिएंसी और यूरो नॉर्म्स को लीपफ्रॉग करना है, यह एक बड़ा इश्यु है। Both the Minister concerned and Ministries are seized of the matter. Let us hope that it will bring a good news very soon. That is second thing.

एन.एव.ए.आई. और हरियाणा सरकार ने जो रिंग रोड बनाने की जरूरत है कि नॉन-डेस्टाइन व्हीकल्स दिल्ली में नहीं आने चाहिए, जो दस हजार की संख्या में आते हैं। वे बाहर से ही जाएं, इसके लिए दो साल में यह रास्ता पूरा होगा, तब होगा। सौगत राय जी आपको मालूम है कि दिल्ली की हवा दस महीने में नहीं बिगड़ी। यह बहुत सालों का परिणाम है। इसलिए अब हमने एक्शन शुरू किया है और इसका परिणाम आएगा, आप देखेंगे। पहला परिणाम तीन महीने का एक्शन प्रोग्राम है, उसका रिव्यु हम जुलाई में ले रहे हैं। ...(व्यवधान)

PROF. SAUGATA ROY: You bring it up to WHO standards.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: That is what I tell you. Saugata Roy Ji, I have highest regard for you. हमारी साइक्लॉजी ऑविसर इलाज की है। एक बार दिल्ली के प्रदूÂाण की बहुत चर्चा हुई, उस समय जगमोहन जी मंत्री थे, लोगों ने कहा उद्योगों से प्रदूÂाण होता है, उन्होंने उद्योग बाहर किए। ...(व्यवधान) दूसरी बार फिर हुआ कि प्रदूÂाण बढ़ता रहा तो फिर कोर्ट ने आदेश दिया कि सीएनजी लागू की जाए तो सीएनजी आ गई, फिर लोगों को लगा कि अब प्रदूÂाण का खतरा खत्म हुआ है। ऐसा नहीं होता है। फिर आया कि पब्लिक ट्रांस्पोर्ट को बदलना चाहिए तो मैट्रो आई। अब तीस लाख लोग मैट्रो से जा रहे हैं। It is a clean travel but still that does not rein the problem. You have to do everyday reforms and action, and we will continue to do that in association with you. यह हम करेंगे। एयर क्वालिटी के बारे में गौरव जी ने पूछा है। इन दोनों विभागों में कोई अंतर नहीं है, हम एक साथ काम कर रहे हैं। जो अभी नए इंडेक्स की सारी जानकारी आ रही है, we are in sync with that. कभी-कभी पेपर में आधी जानकारी के आधार पर न्यूज़ आती है, उस पर हमें अपनी राय नहीं बनानी चाहिए। दूसरा, सबने सवाल पूछा है कि जंगलों में जब प्राणी बढ़ते हैं तो खेती के किसानों को नुकसान होता है, यह एक सही प्राब्लम है, इसके लिए हमने आदेश दिया है कि राज्य सरकार स्पेसिफिक क्षेत्र में स्पेसिफिक महीनों के लिए या एक साल के लिए अगर कहेगी कि तो हम इसको करेंगे। पहले तो यह ब्लू बुल है, उसको गाय मत कहो, वह रोज है, जो भी शब्द यूज़ करना है करो, लेकिन वह गाय नहीं है। ...(व्यवधान) इसलिए इनको वर्मिंग डिविलयर करने का प्रस्ताव राज्य सरकार भेजती है तो हम तुरंत बंदर हो या रोज हो, जहां आतंक है, वह तुरंत हम उसको मंजूरी दे रहे हैं। उस पर लोकल एक्शन होगा। ...(व्यवधान) आपने जंगल में सड़क के बारे में पूछा है, जो उदाहरण आपने हैदराबाद का बताया है, मैं तुरंत चेक करूंगा, क्योंकि छह महीने पहले हमने आदेश निकाला है। National Board of Wildlife की मीटिंग हुई, पहले यह नियम बनाया था कि जंगल में अगर सड़क बनी है तो कभी भी उसे रिपेयर भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए उसमें गड्ढे हो गए हैं। मैंने बैठक में पूछा कि यह तो आदिवासियों के ऊपर अन्याय है। आदिवासी रहते हैं, क्या उसको अच्छा रास्ता नहीं चाहिए? पॉलिसी डिसीज़न ले कर upgradation of existing roads को हमने अलाऊ किया है, जहां पर नैशन हाईवे बहुत जरूरी हैं, अगर वहां नैशन हाईवे हैं, तो उसकी वाइडनिंग को भी मंजूर किया है, with adequate mitigation measures. उसमें रेलवे भी है। All linear projects, चाहे इरिगेशन के लिए पानी ले जाना हो, पीने के लिए पानी लेना हो या ट्रांसमिशन तार ले जानी हो, transmission lines or all pipelines और रोड़ एण्ड रेल, ये लीनियर प्रोजेक्ट्स हैं, जो जाएंगे। मिटिगेशन मेज़र्स लेंगे और दोनों की रक्षा करेंगे, तो इसमें अभी यह नहीं रखा है। रिवर पॉल्युशन एक अहम मुद्दा है। इसके लिए हमने दो मैथड बनाए हैं। जो नदी के किनारे उद्योग हैं, उनको हम 24/7 घंटे चलने वाली pollution monitoring devices, से जोड़ेंगे। यह नई टैक्नोलॉजी है, ये 11 यंत्र अलग-अलग टाईप के अभी आए हैं, लोग चूज़ कर सकते हैं, तो ये यंत्र लगा कर जहां से एफ्लुवेंट बाहर निकलता है, वहां लगा सकते हैं। आपको मालूम है कि पॉल्युशन बोर्ड के अधिकारी जब जाते हैं, उस दिन एकदम साफ पानी बहता है। जब वे वापस जाते हैं तो फिर गंदा पानी निकलना शुरू हो जाता है। यह न हो इसलिए उस टैक्नोलॉजी से 24 घंटे स्टेट पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड में और हमारे पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड में दोनों जगह दिखेगा और अगर पांच मिनट भी उसका पॉल्युशन ज्यादा हुआ तो एसएमएस जाएगा और 15 मिनट ज्यादा होगा तो उस पर तीसरा एक्शन शुरू होगा। टैक्नोलॉजी के आधार पर भी कप्शन को खत्म कर सकते हैं। यह जो फजिंग था, उसको भी समाप्त कर सकते हैं, यह मैकेनिज्म हम ला रहे हैं। इरिगेशन के बारे में जो पूछा, वह एकदम सही है। मैं तेलंगाना में गया था तो कृÂणा-भीमावरम् प्रोजेक्ट है, उसमें यह हुआ कि प्रोजेक्ट तैयार है, इरिगेशन डैम तैयार है, आदिवासियों को पानी मिलना है, पानी है, सब कुछ है, कैनाल रेडी है, लेकिन पांच साल से पड़ा है, उपयोग में हो रहा है। एक कैनाल बनाने में एक जंगल की जमीन जा रही थी, तो परमीशन लेने के पहले उन्होंने काम शुरू कर दिया, वाइलेशन हो गया। अब किसी अधिकारी पर क्रिमिनल जिम्मेदारी डालनी है, अधिकारी खुद थोड़े ही क्रिमिनल जिम्मेदारी लेते हैं, वह फाइल घूम रही है, लोगों पर क्राइम हो रहा है, हमने इसको बदला है, हमने परमीशन दी है। इस तरह के वाइलेशन का कोई अर्थ नहीं होता है।

दूसरा, एक रिवर रेग्युलेटरी मैनेजमेंट जोन यानी रिवर रेग्युलेशंस भी कुछ कर रहे हैं कि किनारे पर क्या हो और क्या न हो। टाइगर का जो है ओडिशा का, उसके संबंध में एक क्वेश्चन राज्य सभा में भी है, हम उसका डिटेल उत्तर परसों दे रहे हैं, लेकिन उसमें कैमरा ट्रैप में और जो तीन प्रकार से उसकी काउंटिंग चलती है, वह काउंटिंग सारे देश में ठीक हुई, लेकिन एक जंगल में जहाँ बाघ ज्यादा है, वहाँ फॉल्ट समझ में भी आया और उसके करेक्शन के लिए ऑलरेडी सरकार को बताया है। वहाँ के अधिकारी वह काम कर रहे हैं। उनकी रिपोर्ट आते ही वह एजेंडा जोड़ा जाएगा।

टेक्नॉलाजी के संबंध में मैंने कहा। संजय गाँधी पार्क और जैतापुर का ईश्यू है, वह कोई नया प्रपोजल नहीं है, यह इनक्रोचमेंट है, यह एक बड़ा ईश्यू है। देश में लगभग तीन लाख हेक्टेअर वन जमीन पर अतिक्रमण हुआ है और यह अतिक्रमण बढ़ रहा है। यह नहीं बढ़ना चाहिए, इसके लिए हमने बहुत कुछ सोचा है और वह आप सबके सहयोग से करेंगे।

काजीरंगा के बारे में माननीय सदस्य ने जो कहा, पिछले साल 22 डेथ्स हुई हैं, लेकिन हमारे पास संख्या भी तीन हजार है। वहाँ 20 राइनो का पोचिंग हुआ, लेकिन 22 पोचर्स को भी मार गिराया गया है। बंदूकों का उपयोग करके पोचर्स को मार भी गिराया है तो सख्त एक्शन भी चल रहा है, यह भी हमें समझना चाहिए। जो मनरो आइलैंड के बारे में आपने कहा, सुंदरवन के बारे में भी चर्चा में कहा, इन आइलैंड्स को बचाने के लिए हम जरूर अलग से काम कर रहे हैं। मेरी वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से बात भी हुई है। सुंदरवन के लिए भारत और बांग्लादेश, दोनों को मिलकर कुछ काम करना पड़ेगा, इसके बारे में भी हमारी चर्चा चल रही है। सारे विÂायों का मैंने जवाब दिया है, जो बचे हैं, उनका जवाब मिलेगा।...(व्यवधान) अंडमान के बारे में मैंने कहा है। अंडमान में पॉम का ट्री लगाने में मुझे नहीं लगता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई मुद्दा है।...(व्यवधान) अगर है तो आप जरूर प्रपोजल भेजिए, आप आइए, हम चाय पिएंगे और आपको सोल्यूशन भी देंगे।...(व्यवधान) बहुत-बहुत धन्यवाद।

HON. SPEAKER: A number of cut motions have been moved by Members to the Demand for Grant relating to the Ministry of Environment, Forests and Climate Change. I shall now put all the cut motions to the vote of the House together.

If you agree, I will put them separately.

SHRI JAI PRAKASH NARAYAN YADAV: Yes, Madam am pressing my Cut Motion No.1. ...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I shall now put Cut Motion No.1 moved by Shri Jai Prakash Narayan Yadav to the vote of the House.

The cut motion was put and negatived.

...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I shall now put Cut Motion Nos.8 to 13 moved by Shri Kodikunnil Suresh to the vote of the House.

The cut motions were put and negatived.

...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I shall now put Cut Motion No.14 moved by Shri K.C. Venugopal to the vote of the House.

The cut motion was put and negatived.

...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I shall now put all the other Cut Motions, which have been moved together to the vote of the House.

The cut motions were put and negatived.

...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I shall now put the Demand for Grant relating to the Ministry of Environment, Forests and Climate Change to the vote of the House.

The question is:

> "That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President, out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2016, in respect of the head of Demand entered in the Second column thereof against Demand No. 32 relating to the Ministry of Environment, Forests and Climate change."

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: The Demand for Grant relating to the Ministry of Environment, Forests and Climate Change is passed.

18.46 hrs

OBSERVATION BY THE SPEAKER